देशप्राण

भगवान भरोसे चलते स्कूल

यह देश की विडंबना ही कही जाएगी कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकारें कामचलाऊ नीतियों के भरोसे ही रहती हैं। एक तरफ देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दस लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, वहीं देश में अथाह बेरोजगारी बनी हुई है। निस्संदेह, बच्चों की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की बुनियाद होती है, यदि बुनियाद ही कमजोर होगी तो राष्ट्र की इमारत कैसे मजबूत होगी? हाल ही में संसद की शिक्षा, महिला, बाल और खेल मामलों की स्थायी समिति ने खुलासा किया कि देश के शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के दस लाख पद खाली हैं। विडंबना यह है कि पांच साल पहले भी शिक्षामंत्री ने देश में दस लाख साठ हजार शिक्षकों के पद रिक्त होने की बात कही थी। यह भी जानकारी सामने आयी है कि वर्ष 2019 से इन पदों पर भर्ती हुई ही नहीं है। यानी आधे दशक में हम इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं। विडंबना यह है कि पिछले साल आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में एक लाख ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां एक ही शिक्षक नियुक्त है। सोचा जा सकता है कि एक शिक्षक कैसे सभी कक्षाओं के बच्चों को सारे विषय पढ़ाता होगा? विसंगति यह भी है कि इतने शिक्षकों की कमी के बावजूद सेवारत शिक्षकों को विभिन्न सरकारी अभियानों का जिम्मा भी दिया जाता है। जिसका खामियाजा छात्र ही भुगतते हैं। आखिर हम अपनी प्राथमिक शिक्षा की ये कैसी बुनियाद रख रहे हैं? चिंताजनक स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों को समय की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव रहता है। कोरोना संकट ने सरकारी शिक्षण व्यवस्था की पोल खोली थी कि गिने-चुने स्कूलों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। एक ओर देश के निजी स्कूलों में एआई और आधुनिक शिक्षण तकनीकों से ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिये भी तरस रहे हैं। इन स्कूलों के पाठ्यक्रमों को समय की चाल में नहीं ढाला जा सका है। वहीं कौशल विकास की शिक्षा देना तो दूर की कौड़ी है। आखिर हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का कैसा भविष्य बना रहे हैं? क्या वे स्कूल-कॉलेज से निकलकर वैश्विक चुनौतियों के साथ कदमताल कर पाएंगे? हम अपने छात्रों को वह आधुनिक ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं जो आगे चलकर उन्हें बेहतर जीवनयापन के अवसर दे सके। सही मायनों में हम सरकारी स्कूलों के नाम पर बीमार भविष्य के कारखाने चला रहे हैं। जो कालांतर छोटी-मोटी नौकरी ही पा सकते हैं या फिर बेरोजगारी की अंतहीन श्रृंखला में खड़े हो जाते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को भी समय की जरूरत के हिसाब से नहीं ढाला जा रहा है। उलटे पाठ्यक्रमों को राजनीतिक दलों की विचारधारा के हिसाब से ढालने का उपक्रम लगातार किया जाता रहा है। निश्चय ही ये स्थितियां इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ही कही जाएंगी। अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि हम भारत का कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं।

जटिल होता आम आदमी का जीवन

अशोक मधुप
(वरिष्ठ पत्रकार)

सरकारों का काम आदमी के जीवन को सरल बनाना है। तकनीक के माध्यम से उसे ऐसी सुविधाएं देना है कि वह परेशान न हो, किंतु भारत में हो इसके विपरीत रहा है। उन्हें अलग-अलग काम के लिए थोड़ी-थोड़ी बात के लिए परेशान किया जा रहा है। उनके जीवन को दुरूह किया जा रहा है।

आज सबसे बड़ी परेशानी हैं बैंकों में जाकर खाते की केवाईसी कराने की। बैंकों की केवाईसी के नाम पर बैंक खाताधारक को परेशान किया जा रहा है। हालत यह है कि केवाईसी करानी है, इसकी उसे सूचना भी नहीं मिलती। उसे उसके लिए बैंक की ओर से मैसेज भी नहीं आता।

अभी तक बैंक खाते चालू रखने के लिए केवाईसी करानी थी। अब बिजली विभाग के मैसेज आ रहे हैं, कि अपने कनेक्शन की ईकेवाईसी कराइए। आज जहां चारों ओर धोखे का जाल फैला है। ठग आपको फंसाने में लगे हैं, ऐसे में किस मैसेज को सही माना जाए, किसे गलत यह कैसे पता चले। अभी परिवहन विभाग का मैसेज आया है कि आधार ऑथराइजेशन माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। समझ नहीं आ रहा कि क्या-क्या कराएं। हम पर ये सब करना नहीं आता। इसका मतलब ये की रोज जनसेवा केंद्र पर जाइये। लाइन में लगे और पैसा भी दीजिए। लगता है कि कहीं ये जनसेवा केंद्र की आय बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। अभी पिछले दिनों आदेश आया कि अपना आधार कार्ड प्रत्येक दस साल में अपडेट कराना है। मैं छोटे शहर में रहता हूं। यहां कि आबादी दो लाख के करीब है। पूरे शहर में आधार कार्ड अपडेट कराने का एक ही सेंटर है। मुख्य डाकघर। उसमें आधार कार्ड बनवाने वालों की सवेरे आठ बजे से लाइन लग जाती है। हम 75 साल से ऊपर के पति-पत्नी कैसे उस लाइन में लगें, ये कोई सोचने और बताने वाला नहीं है। दूसरे केंद्र का दरवाजा खुलने पर इस तरह धक्का-मुक्की होती है कि हम लाइन में लगे तो हाथ-पांव तुड़वा कर जरूर अस्पताल जाएंगे। केंद्र सरकार/रिजर्व बैंक को आदेश करना चाहिए कि बैंक अपने यहां अतिरिक्त स्टाफ रखे। उसके कार्य सिर्फ खाते धारकों से समय लेकर उनके खातों की केवाईसी कराना हो।

मेल आनी चाहिए। किंतु ऐसा हो नहीं रहा। वैसे प्रत्येक ट्रांजेक्शन के मैसेज आते रहते हैं। केवाईसी कराना है, इसका पता तब चलता है जब खातेधारक के चैक का भुगतान रोक दिया जाता है। वह पेमेंट नहीं कर पाता। भुगतान रोकने के कारण चेक जारी करने वाले पर संबंधित बैंक या संस्था चार सौ से आठ सौ रुपये तक का जुमार्ना लगा देती है। मैंने पिछले साल ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए चेक दिया। चेक बैंक गया तो भुगतान रुक गया। मैं बैंक गया। बैंक प्रबंधक ने खाता देखकर कहा कि खाता आपका जारी है। चैक का भुगतान कैसे रूका पता नहीं। उनके एक स्टाफ ने देखकर बताया कि खाता बंद किया हुआ है। बैंक प्रबंधक ने कहा कि अब सब कंप्यूटराइज है। हमें पता नहीं चलता और खुद जाता है। बैंक स्टाफ के पता है या नहीं। इससे खाताधारक को क्या लेना। मेरे से तो इंश्योरेंस कंपनी ने चेक डिस ओनर होने के छह सौ रुपए अतिरिक्त वसूल लिए। मुझे तो फालतू का छह सौ रुपये का दंड पड़ गया।

अभी लॉकर ऑपरेट करने बैंक जाना पड़ा तो बैंक स्टाफ ने कहा कि इसकी केवाईसी कराइये। हमने कहा कि अभी खाते की तो कराई है। उनका कहना था कि बैंक लॉकर की भी करानी है। लॉंकर बैंक के खाते से जुड़ा है, यह बताने पर भी बैंक कर्मी नहीं माने। यदि आपके पास चार-पांच बैंक खाते हैं तो प्रत्येक दो साल से केवाईसी कराने जरूर जाना होगा।

अभी तक बैंक खाते चालू रखने के लिए केवाईसी करानी थी। अब बिजली विभाग के मैसेज आ रहे हैं, कि अपने कनेक्शन की ईकेवाईसी कराइए। आज जहां चारों ओर धोखे का जाल फैला है। ठग आपको फंसाने में लगे हैं, ऐसे में किस मैसेज को सही माना जाए, किसे गलत यह कैसे पता चले। अभी परिवहन विभाग का मैसेज आया है कि आधार ऑथराइजेशन माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। समझ नहीं आ रहा कि क्या-क्या कराएं। हम पर ये सब करना नहीं आता। इसका मतलब ये की रोज जनसेवा केंद्र पर जाइये। लाइन में लगे और पैसा भी दीजिए। लगता है कि कहीं ये जनसेवा केंद्र की आय बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जा रहा।

अभी पिछले दिनों आदेश आया कि अपना आधार कार्ड प्रत्येक दस साल में अपडेट कराना है। मैं छोटे शहर में रहता हूं। यहां कि आबादी दो लाख के करीब है। पूरे शहर में आधार कार्ड अपडेट कराने का एक ही सेंटर है। मुख्य डाकघर। उसमें आधार कार्ड बनवाने वालों की सवेरे आठ बजे से लाइन लग जाती है। हम 75 साल से ऊपर के पति-पत्नी कैसे उस लाइन में लगें, ये कोई सोचने और बताने वाला नहीं है। दूसरे केंद्र का दरवाजा खुलने पर इस तरह धक्का-मुक्की होती है कि हम लाइन में लगे तो हाथ-पांव तुड़वा कर जरूर अस्पताल जाएंगे।

केंद्र सरकार / रिजर्व बैंक को आदेश करना चाहिए कि बैंक अपने यहां अतिरिक्त स्टाफ रखे। उसके कार्य सिर्फ खाते धारकों से समय लेकर उनके खातों की केवाईसी कराना हो। सरकार जिस तरह वोट बनवाती है। वोटर का वेरिफिकेशन कराती है। उसी तरह से केवाईसी कराई जाए। इसके बैंक खाताधारकों को सुविधा होगी। केवाईसी कराने के लिए रखे जाने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही काम राज्य की बिजली कंपनी कर सकती हैं। विभागीय मीटर रीडर माह में एक बार रीडिंग लेने उपभोक्ता के घर जाते हैं। वे ही उपभोक्ता से केवाईसी के पेपर लेले। मीटर रीडर को उपभोक्ता जानते हैं उन्हें पेपर देते किसी उपभोक्ता को परेशानी भी नहीं होगी। मीटर रीडर आफिस आकर इस कार्य में लगे स्टाफ को पेपर देकर केवाईसी कराए। हो यह रहा है कि संबधित विभाग बैंक/ बिजली अपना कार्य उपभोक्ता पर डाल उसके जीवन को कठिन बना रहे हैं, जबकि उन्हे अपने ग्राहकों को सुविधांए देनी चाहिए थीं। ऐसा ही आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। हां इसके लिए उपभोक्ता से थोड़ा बहुत चार्ज लिया जा सकता है। अभी एक मैसेज आया कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अभी रिटर्न भरा नहीं, सो ये मैसेज बेटे को भेज दिया कि शायद उसने रिटर्न भरा हो। उसका जवाब आया कि पापा इस मैसेज के लिंक पर क्लिक मत करना। ये गलत लगता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

आज सबसे बड़ी समस्या है कि सही और गलत का कैसे तय हो। किसी न किसी तरह धोखे में लेकर रोज हजारों व्यक्ति रोज ठगे जा रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए? ऐसे हालात में जीवन दुरूह होता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को आम आदमी का जीवन को सरल बनाने के लिए काम करना चाहिए।

मुंशी प्रेमचंद भी 'मुरीद' थे आचार्य चतुरसेन के

कृष्ण प्रताप सिंह
(वरिष्ठ पत्रकार)

आचार्य चतुरसेन शास्त्री की जयंती पर विशेष

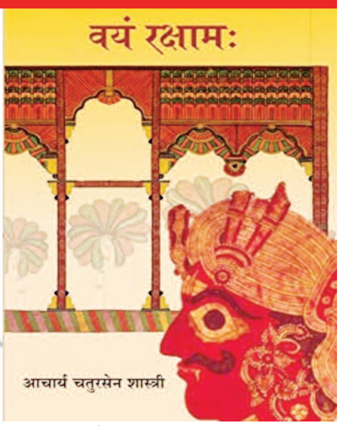

कि इसे हिंदी जगत की विस्मरण की प्रवृत्ति का विषफल ही कहा जायेगा कि उसे इतिहास की दृष्टि से लिखा गया पहला उपन्यास 'वैशाली की नगरवधू' देने वाले आचार्य चतुरसेन शास्त्री को अब उनकी जयंती व पुण्यतिथि पर भी याद नहीं किया जाता। यह तब है, जब आचार्य के जीते जी ही उनकी झोली प्रशंसकों और प्रशंसाओं से भरी हुई थी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद भी उनके मुखर प्रशंसक थे, जिन्होंने एक समय उनके सृजन पर रीझकर उनसे कहा था कि ह्यलिखते तो आप हैं, मैं तो कलम रगड़ता हूं।'

दिलचस्प है कि वैशाली की नगरवधू को आचार्य स्वयं भी अपना 'एकमात्र' उपन्यास मानते थे। उन्होंने घोषित कर दिया था कि यह उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। उन्हीं के शब्दों में मैं अब तक की सारी रचनाओं को रद्द करता हूं और वैशाली की नगरवधू को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूं। रचना प्रक्रिया के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी आत्मकहानी में लिखा है कि 1938 में उन्हें उपचार के सिलसिले में बिहार जाना पड़ा तो वहां पहाड़ियों में भटकने और जल स्त्रोतों में घंटों स्नान के दौरान वे एक जाग्रत स्वप्न देखने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई ग्रंथ लिख रहे हों। आंखों के सामने दृश्य बनने लगे। पत्तों की बातचीत प्रत्यक्ष कानों में पड़ने लगी। यह नित्य होने लगा तो एकबारगी तो वे डर गए कि कहीं उनको किसी मानसिक व्याधि ने तो नहीं घेर लिया है।

उन्होंने लिखा है, मेरे शरीर के संपूर्ण जीवकोष कल्पना के वशीभूत हो गए और मैंने कहा- नाचो अम्बपाली (उपन्यास की नायिका) और अम्बपाली नाची। मैंने अपनी आंखों से उसे नील गगन में चंद्रमा के उज्ज्वल आलोक में नाचते देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे मैं भी आकाश में उसके निकट पहुंच गया हूं।...फिर...एकाएक... वेग से नीचे आ गिरा।...मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि मैंने स्वप्न नहीं देखा था। मैंने जो कुछ देखा- जागते हुए देखा, सब सत्य। उस समय रात्रि के दो बजे थे।... मैंने तुरंत उठकर उस नृत्य का वर्णन लिखा, जिसका संशोधित रूप ह्यवैशाली की नगरवधूह्ण में कलमबद्ध है। उनके अनुसार वे यह उपन्यास लिखते थे तो उनको महसूस होता था कि आकाश से दो नेत्र उनके कंधों के पीछे से हर अक्षर को पढ़ रहे हैं।

वर्ष 1891 में 26 अगस्त को उ.प्र. के बुलंदशहर जिले के चांदोख गांव में पिता केशव राम वर्मा के घर माता नन्हीं देवी की कोख से जन्म हुआ तो उनका नाम चतुर्भुज रखा गया था। आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने 1915 में आयुवेर्दाचार्य व संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कैरियर आरंभ करने से पहले कुछ वक्त तक एक धर्मार्थ औषधालय में 25 रुपये माह पर नौकरी की। बाद में वे डी.ए.वी. कॉलेज, लाहौर में आयुर्वेद के प्राध्यापक नियुक्त हो गये थे, लेकिन प्रबंधन से खटपट के चलते कुछ ही सालों बाद इस्तीफा दे दिया। आयुवेर्दाचार्य के तौर पर उनको अनेक तत्कालीन राजे-महाराजाओं, महामना मदनमोहन मालवीय व बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकारों का उपचार करने का अवसर भी मिला था।

आलोचकों के अनुसार भले ही आचार्य 'वैशाली की नगरवधू' को अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बता गये हैं लेकिन उनकी सोमनाथ और वयं रक्षामः जैसी औपन्यासिक कृतियों की चर्चा के बगैर उनकी रचनाओं का मूल्यांकन अधूरा है। सोमनाथ के केंद्र में सोमनाथ की ऐतिहासिक लूट और पुननिर्माण की गाथा है जबकि वयं रक्षामः का केंद्रीय पात्र राक्षसराज रावण है। यों, उनके खाते में आत्मदाह, बहते आँसू, दो किनारे, नरमेध, अपराजिता, बगुला के पंख, मोती, पूणार्हुति, रक्त की प्यास, आलमगीर, लाल पानी, सह्याद्रि की चट्टानें, हरण निमंत्रण, सोना और खून (चार खंड) जैसे अन्य उपन्यास भी हैं। उन्होंने आयुर्वेद पर आधारित लगभग एक दर्जन ग्रंथों का लेखन भी किया, जिनमें आरोग्य शास्त्र, स्त्रियों की चिकित्सा, योग चिकित्सा, नीरोग रहने के सरल उपाय और सुगम चिकित्सा आदि प्रमुख हैं।

1936 में उन्होंने उस वक्त आयुर्वेद चिकित्सा की अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़ दी थी, जब उन्हें उससे महीने में तीन हजार रुपए तक की आय हो जाती थी। उन दिनों यह बहुत बड़ी रकम थी। तिस पर उनकी व्यस्तता इतनी थी कि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को भी उनका परामर्श पाने के लिए कई-कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में साहित्य और आयुर्वेद दोनों में से एक को चुनने का वक्त आया तो उन्होंने एक झटके में साहित्य को चुन लिया । वर्ष 1909 से 1948 के चार दशकों में उन्होंने अपने निजी जीवन में अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद 84 छोटी-बड़ी पुस्तकें और पत्रिकाओं के लिए सैकड़ों लेख लिखे थे।

उन्होंने लिखा है, मेरे शरीर के संपूर्ण जीवकोष कल्पना के वशीभूत हो गए और मैंने कहा- नाचो अम्बपाली (उपन्यास की नायिका) और अम्बपाली नाची। मैंने अपनी आंखों से उसे नील गगन में चंद्रमा के उज्ज्वल आलोक में नाचते देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे मैं भी आकाश में उसके निकट पहुंच गया हूं।...फिर...एकाएक... वेग से नीचे आ गिरा।...मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि मैंने स्वप्न नहीं देखा था। मैंने जो कुछ देखा- जागते हुए देखा, सब सत्य। उस समय रात्रि के दो बजे थे।... मैंने तुरंत उठकर उस नृत्य का वर्णन लिखा, जिसका संशोधित रूप वैशाली की नगरवधू में कलमबद्ध है। उनके अनुसार वे यह उपन्यास लिखते थे तो उनको महसूस होता था कि आकाश से दो नेत्र उनके कंधों के पीछे से हर अक्षर को पढ़ रहे हैं। वर्ष 1891 में 26 अगस्त को उ.प्र. के बुलंदशहर जिले के चांदोख गांव में पिता केशव राम वर्मा के घर माता नन्हीं देवी की कोख से जन्म हुआ तो उनका नाम चतुर्भुज रखा गया था। आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने 1915 में आयुवेर्दाचार्य व संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कैरियर आरंभ करने से पहले कुछ वक्त तक एक धर्मार्थ औषधालय में 25 रुपये माह पर नौकरी की। बाद में वे डी.ए.वी. कॉलेज, लाहौर में आयुर्वेद के प्राध्यापक नियुक्त हो गये थे, लेकिन प्रबंधन से खटपट के चलते कुछ ही सालों बाद इस्तीफा दे दिया। आयुवेर्दाचार्य के तौर पर उनको अनेक तत्कालीन राजे-महाराजाओं, महामना मदनमोहन मालवीय व बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकारों का उपचार करने का अवसर भी मिला था। आलोचकों के अनुसार भले ही आचार्य 'वैशाली की नगरवधू' को अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास बता गये हैं लेकिन उनकी ह्यसोमनाथह्ण और वयं रक्षामः जैसी औपन्यासिक कृतियों की चर्चा के बगैर उनकी रचनाओं का मूल्यांकन अधूरा है। सोमनाथ के केंद्र में सोमनाथ की ऐतिहासिक लूट और पुननिर्माण की गाथा है जबकि वयं रक्षामः का केंद्रीय पात्र राक्षसराज रावण है। यों, उनके खाते में आत्मदाह, बहते आँसू, दो किनारे, नरमेध, अपराजिता, बगुला के पंख, मोती, पूणार्हुति, रक्त की प्यास, आलमगीर, लाल पानी, सह्याद्रि की चट्टानें, हरण निमंत्रण, सोना और खून (चार खंड) जैसे अन्य उपन्यास भी हैं। उन्होंने आयुर्वेद पर आधारित लगभग एक दर्जन ग्रंथों का लेखन भी किया, जिनमें आरोग्य शास्त्र, स्त्रियों की चिकित्सा, योग चिकित्सा, नीरोग रहने के सरल उपाय और सुगम चिकित्सा आदि प्रमुख हैं। 1936 में उन्होंने उस वक्त आयुर्वेद चिकित्सा की अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़ दी थी, जब उन्हें उससे महीने में तीन हजार रुपए तक की आय हो जाती थी।

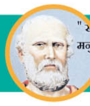

" जो देशसेवा करना चाहता है, उसके पास सोचने के साथ ही काम करने की इच्छाशक्ति का होना जरूरी है। - प्लूटो

भारत पर अतिरेक टैरिफ लागू कर अपनी अहंमन्यता और दोहरे आचरण का सच पूरी तरह उजागर करने वाले अमेरिका की ही रेटिंग एजेंसियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताना एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, यह सतर्क नीति-निर्माण की मांग भी करता है।

भरोसा और चुनौतियां

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के आज लागू होने के पहले अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों-पहले एस एंड पी और अब फिच का यह संकेत कि अमेरिकी टैरिफ का हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिहाज से आश्वस्त करता है। दुनिया को दूसरे शीतयुद्ध काल में ले जाने पर तुले अमेरिका को बेशक लगता हो, कि इन हथकंडों से वह भारत को दबाव में ले आएगा, लेकिन वस्तु-स्थितियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अमेरिका को भारत से होने वाला निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज दो फीसदी है। इसके अलावा, भारत बहुत तेजी से विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रहा है, जो यकीनन नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देंगे। दरअसल, रूस से तेल खरीदने का मामला बताकर भारत पर अतिरेक टैरिफ लागू कर अमेरिका ने अपनी अहंमन्यता और दोहरे आचरण का सच पूरी तरह उजागर कर दिया है, तो दूसरी तरफ अगर अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही हैं, तो यह अकारण नहीं है। रूस-यूक्रेन और इस्राइल-हमास/ ईरान युद्धों की शुरुआत के बाद से ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मंडरा रहे संकट के बावजूद हम देख चुके हैं कि वैश्विक रेटिंग एजेंसियां लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताती रहीं। एस एंड पी रेटिंग एजेंसी ने करीब दो हफ्ते पहले अठारह वर्ष में पहली बार भारत की साख में इजाफा किया है, तो इसका कुछ अर्थ है। फिच रेटिंग ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जो 'बीबीबी' श्रेणी के अन्य देशों के औसत से कहीं अधिक है। यह मजबूत आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च, निजी उपभोग और अनुकूल जनसांख्यिकी से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 695 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो करीब 11 महीनों के आयात को कवर करने में सक्षम है। ये आंकड़े देश की आर्थिक स्थिरता को रेखांकित करते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनकी ओर फिच भी इशारा करती है। फिच का अनुमान है कि 2026 तक भारत का सरकारी कर्ज जीडीपी के 56.1 फीसदी तक पहुंच सकता है, जो भले ही कई विकसित देशों से कम हो, लेकिन भारत जैसे उभरते बाजार के लिए चिंता का विषय है। वजह यह है कि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश की जरूरत है, जिससे राजकोषीय संसाधनों पर दबाव पड़ना तय है। ऐसे में जरूरी है कि नीति-नियंता कर्ज प्रबंधन का एक स्पष्ट रोडमैप बनाएं। फिच की स्थिर रेटिंग से स्पष्ट है कि भारत हर तरह की चुनौती झेलने में सक्षम है, लेकिन यह सतर्क नीति-निर्माण की मांग भी करती है।

भू-राजनीति में मनमानी नहीं चलती

आज अमेरिका जो भी कर रहा है, वह उसकी कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि ट्रंप दो कदम आगे, तो तीन कदम पीछे और कुछ कदम दाएं-बाएं चलते दिखाई दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर राष्ट्राध्यक्ष मनमानी करने लगें, तो इससे दुश्मन डरे न डरे, दोस्त जरूर दूर होने लगते हैं।

यह कयास लगाया जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, तो इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन, जो हुआ वह अमेरिका और यूरोप के कुछ नेताओं को काफी निराशा दे गया और पुतिन के कद को और ऊंचा बना गया। यूरोपीय नेताओं की निराशा जायज हो सकती है, लेकिन उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि ट्रंप की विदेश नीति उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से चलती है, जिसमें दुनिया में घट रही घटनाओं और वैश्विक उथल-पुथल के लिए कोई खास जगह नहीं है।

इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। 14 फरवरी, 1972 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने चीन की यात्रा कर निक्सन को सलाह दी थी कि रूसियों की तुलना में चीनी उतने ही खतरनाक हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि, '20 साल बाद आपका उत्तराधिकारी, यदि वह आपकी तरह बुद्धिमान हुआ, तो चीनियों के विरुद्ध रूसियों की ओर झुक जाएगा।' ट्रंप 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी शुरुआत में रूस की तरफ झुकते दिखे थे, लेकिन बाद में बदल गए। अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी कुछ वैसा ही दिख रहा है।

रहीस सिंह
वैदेशिक मामलों के जानकार

1950 के दशक में आइजनहावर प्रशासन ने चीन के नेता माओ त्से तुंग और सोवियत संघ के निकिता ख्रुश्चेव के बीच दरार डालने की कोशिश में रूसियों से बेहतर संबंध रखे। अक्तूबर 1959 में, जब ख्रुश्चेव आइजनहावर से कैंप डेविड में मुलाकात कर लौटे, तो वे बीजिंग पहुंचे और यह संदेश दिया कि चूंकि अमेरिका के साथ सोवियत संबंध सुधरे हैं, इसलिए मास्को चीन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का समझौता तोड़ देगा। इसके दस साल बाद निक्सन ने आइजनहावर की नीति पलट दी और अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बीजिंग को शामिल कर लिया। कुछ साल बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इस नीति को और आगे बढ़ाया।

सोवियत प्रभाव को दक्षिण-पूर्व एशिया में फैलने से रोकने के लिए कार्टर प्रशासन ने चीन के वियतनाम पर आक्रमण को मौन स्वीकृति दे दी। इसके बाद की अमेरिकी सरकारों-चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, ने अंगोला, अफगानिस्तान और कंबोडिया में सोवियत संघ के खिलाफ चीन के साथ मिलकर प्रॉक्सी युद्ध लड़े, जिसने सोवियत शक्ति को बुरी तरह कमजोर किया। यानी आज अमेरिका जो भी कर रहा है, वह उसकी कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन ट्रंप दो कदम आगे तो तीन कदम पीछे और कुछ कदम दाएं-बाएं चलते दिखाई देते हैं। यह दिख रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की विदेश नीति गहन जानकारी और विशेषज्ञता के बजाय उनकी गट फीलिंग पर आधारित है।

इस समय ट्रंप ने जो माहौल निर्मित किया है, उससे ऐसा लगता है कि सभी को अमेरिकी बाजारों तक पहुंच चाहिए। वैसे यह सच भी है, तभी तो ट्रंप ने अपनी विदेश नीति को टैरिफ हथियार के जरिये चलाना शुरू किया। लेकिन, यह हथियार व्यक्तिगत तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हित में भले ही हो, अमेरिका के हित में नहीं है। ट्रंप अगर 'माइट-मेक्स-राइट' के सार्वभौमिक सिद्धांत पर चलने का निर्णय ले चुके हैं, तो उनके लिए यह नुकसानदेह है, क्योंकि यह दोस्तों को दूर कर देगा और दुश्मनों को डरा नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रपति की मनमानी नहीं, बल्कि सुसंगत सिद्धांत होने चाहिए। मनमानी जियो पॉलिटिक्स में प्रायः अप्रत्याशित व खतरनाक परिणाम देती है।

वैसे भी ट्रंप न तो विश्ववादी (ग्लोबलिस्ट) हैं, न एकांतवादी (आइसोलेसनिस्ट) हैं और न ही क्षेत्रीय प्रभाव वाले क्षेत्रों (रीजनल स्फेयर्स) के समर्थकों पर विश्वास रखने वाले हैं, वह सिर्फ ट्रंपवादी हैं। उनकी विदेश नीति को तीन श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में चीन और रूस जैसी शक्तियां आती हैं। दूसरी में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को रखा जा सकता है और तीसरी श्रेणी में वे गरीब देश आते हैं, जिन्हें बड़ी शक्तियां 'ग्रेट गेम' का हिस्सा बनाए रखना चाहती हैं। रूस व चीन से अमेरिकी संबंध जटिल और टकरावपूर्ण रहे हैं। आज के समय में यदि इनके साथ यूक्रेन, इस्राइल, ईरान, सीरिया, तुर्किये, उत्तर कोरिया और ताइवान जैसे देशों को भी जोड़ दें, क्योंकि इनके 'हेड या टेल' वहां तक हैं, तो मामला और जटिल हो जाता है। ऐसे में ट्रंप की जिम्मेदारी यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने और इस्राइल पर नियंत्रण स्थापित कर फलस्तीन में शांति लाने की हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया मान लेगी कि ट्रंपिज्म सफल है। हो सकता है कि यह उन्हें नोबेल पुरस्कार तक भी पहुंचा दे। लेकिन, निष्कर्ष तक पहुंचते हुए यह ध्यान रखना होगा कि पुतिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक भूमिका निभाना चाहते हैं और चीन हिंद-महासागर में अपना जाल बिछाते हुए इसे क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए इस्तेमाल करने का हुनर सीख चुका है। यानी ट्रंपिज्म की राह में दीवार ही नहीं सीधे पर्वत खड़ा है। वैसे भी ट्रंप चीन से डरे हुए लग रहे हैं। तभी तो पहले चीन को टैरिफ से डराने की कोशिश की, लेकिन जब चीन ने पलटवार कर दिया, तो इतना डर गए कि एक बार फिर समयसीमा बढ़ा दी। यही नहीं उन्होंने एनवीडिया चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध हटाकर अपनी ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को कमजोर कर दिया।

ट्रंप भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका को एक संदिग्ध की तरह देख रहे हैं और भारत के साथ बना हुआ तालमेल कमजोर पड़ता दिख रहा है। संभव है कि ब्रिक्स इस तालमेल को और मजबूत करे। हां, गरीब या छोटे देशों जैसे अजरबेजान और आर्मीनिया तथा कांगो और रवांडा में ट्रंप कामयाब रहें। अजरबेजान-आर्मीनिया में शांति समझौता और कांगो-रवांडा के बीच संघर्ष विराम ट्रंप की उपलब्धियों के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप की विदेश नीति एक तरफ मास्को और बीजिंग की मनुहार, पाकिस्तान से क्रिप्टो डील के बदले नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन में सहयोग और कतर के साथ गिफ्ट डिप्लोमैसी (विमान) तक सिमटी दिख रही है। इससे ट्रंप के हित भले ही सध जाएं, लेकिन अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगेगा, बल्कि दुनिया इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी कि अमेरिकी शक्ति अब न तो बेजोड़ है और न ही निर्विवाद।

जीवन धारा

फ्रेडरिक नीत्शे

जीवन का आनंद दूसरों के साथ आता है। प्रेम, दोस्ती और रिश्ते, ये वे रंग हैं, जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं। सच्चा प्रेम वह है, जो हमें मजबूत बनाए और हमारे असली स्वरूप को खोजने में मदद करे।

अपनी कहानी के कैनवास पर खुद ही रंग भरना है

__जीवन__ एक अनोखा सफर और एक ऐसा रंगमंच है, जहां हर इन्सान अपनी कहानी खुद लिखता है। जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। धर्म, समाज, और परंपराएं हमें अक्सर बताती हैं कि जीवन का मकसद क्या है, लेकिन उनके नियमों पर आंखें मूंदकर भरोसा न करें। जीवन एक खाली कैनवास, तो हम ही वह चित्रकार हैं, जो इसे रंगों से भर सकते हैं। यह एक मौका है, जब अपने लिए एक नया अर्थ, एक नया रास्ता बनाने के लिए अपने जीवन की कहानी के कैनवास में रंग भर सकते हैं। क्या हम अपने सपनों को सच करने की हिम्मत कर सकते हैं? अपने डर को गले लगाकर उसे ताकत में बदलने की?

जो समाज के बनाए बेबुनियादी नियमों से ऊपर उठता है, जो अपनी कमजोरियों को चुनौती देता है, और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोजता है। वही अपने सपनों तक पहुंच पाता है। हम सबके भीतर वह शक्ति है कि हम सामान्य से असाधारण बन सकें, लेकिन इसके लिए हमें अपने डर, अपने शक और समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ना होगा, जो हमें जकड़ती हैं। अपने आप को बार-बार नया बनाएं, हर दिन एक बेहतर इन्सान बनने की कोशिश करें। हर दिन खुद से पूछें कि क्या मैं आज वह इन्सान हूं जो कल था? अगर जवाब नहीं है, तो हम सही रास्ते पर हैं। जीवन में दुख और पीड़ा से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इनसे भागने की जरूरत नहीं है। पीड़ा हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि गुरु है। हर दुख, हर असफलता, हमें कुछ सिखाती है। जब जीवन नीचे गिराए, तो उठें, और मुस्कराकर आगे बढ़ें। दुख को गले लगाएं, क्योंकि यह हमें वह ताकत देता है, जो सुख कभी नहीं दे सकता। जीवन एक नृत्य है, एक संगीत है, जिसे हमें अपने तरीके से जीना है। समाज हमें नियमों में बांधना चाहता है, यह करो, वह मत करो, लेकिन अपने दिल की सुननी चाहिए।

जीवन का आनंद उसकी आजादी में है, उसकी रचनात्मकता में है। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो अपने दिल की आवाज को सुनने की? जीवन का आनंद अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ है। प्रेम, दोस्ती और रिश्ते, ये वे रंग हैं, जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं। प्रेम वह नहीं, जो हमें कमजोर बनाए। सच्चा प्रेम वह है, जो हमें और मजबूत बनाए, जो हमें हमारे असली स्वरूप को खोजने में मदद करे। अपने रिश्तों में ईमानदार रहें और उन लोगों को चुनें, जो हमें ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। क्या तुम ऐसे लोगों के साथ हो, जो सपनों को पंख देते हैं? अपने कर्मों को इतना बड़ा करें कि वे समय की सीमाओं को पार करें। हमारा हर कदम, हर मेहनत, हर सपना हमें अमर बना सकता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी कहानी दुनिया को प्रेरणा दे। जीवन एक चुनौती है, एक अवसर है, और सबसे बढ़कर, एक उपहार है। इसे बेकार न गंवाएं। अपने भीतर की आग को जलाए रखें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

सपनों का पीछा करें

जीवन के अवसर अनंत हैं और हम अपने कर्मों, विचारों और अनुभवों से अपने जीवन की तस्वीर बनाते हैं, इसे मूल्यवान और सुंदर बनाते हैं।

सूत्र

हर पल अपने आप को पहले से बेहतर करें। सपनों का पीछा करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस राह में बाधाएं भी बहुत आती हैं।

दूसरा पहलू

हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ तो कुछ और ही कहते हैं।

दूध से कितनी मजबूत होती हैं हमारी हड्डियां

बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। स्कूली पोषण कार्यक्रमों और विज्ञापनों में भी बताया जाता है कि दूध स्वस्थ आहार का एक आवश्यक हिस्सा है। एक कप दूध में 300 मिलीग्राम पोषक होते हैं। इसलिए करीब तीन कप दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। इस संबंध में एमिडिमियोलॉजी और न्यूट्रीशन विशेषज्ञ डॉ. वाल्टर विलेट का कहना है कि यह नैरेटिव सीमित अध्ययनों और डेयरी उद्योगों के आधार पर गढ़ा गया है। पोषण वैज्ञानिक डॉ. क्रिस्टोफर गार्डनर कहते हैं, 'अमेरिका के एक तिहाई से ज्यादा लोगों को लैक्टोज (दुग्धशर्करा) पचाने में परेशानी होती है, इसलिए किसी को भी गाय का दूध पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन, कई उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बेहतर स्रोत भी हो सकते हैं।'

सिमर बजाज

विशेषज्ञ कहते हैं कि दूध पीने से फ्रैक्चर नहीं होता, यह नैरेटिव सीमित अध्ययनों और डेयरी उद्योगों के हितों के आधार पर गढ़ा गया है।

कैल्शियम तंत्रिका, मांसपेशियों, हृदय के कार्य के साथ-साथ हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अमेरिका में एक वयस्क के लिए 1,000 से 1,200 मिलीग्राम व ब्रिटेन में 700 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन जरूरी बताते हैं। डॉ. विलेट कहते हैं कि 1999 से 2023 के बीच दूध पर 79 पेपर प्रकाशित हुए, जिनमें एक तिहाई से अधिक डेयरी उद्योग से संबंधित थे। 2020 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, जो दूध नहीं पीते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रेने रिजोली कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने का दूध से शायद ही कोई संबंध है? इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं हैं कि दूध का सेवन फ्रैक्चर रोकता है। डॉ. रिजोली के अनुसार, व्यायाम व आहार स्वस्थ हड्डियों के लिए जरूरी है। न्यूट्रीशनल एमिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. जेरी नीव्स कहती हैं कि दूध, प्रोटीन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे अन्य पोषक तत्वों के साथ, कैल्शियम के सबसे सुविधाजनक स्रोतों में से एक हो सकता है। आपको दूध अच्छा लगता है, तो इसे पिएं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है या इसके लैक्टोज को पचाने में दिक्कत है, तो टोफू, बोनी फिश, पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड संतरे का जूस या पौधों पर आधारित दूध भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।

2020 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, जो दूध नहीं पीते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रेने रिजोली कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने का दूध से शायद ही कोई संबंध है?

आंकड़े

ऊर्जा आपूर्ति

ऊर्जा की वैश्विक स्तर पर की जाने वाली आपूर्ति में दुनिया के कई देशों की हिस्सेदारी है, लेकिन इस मामले में चीन सबसे ऊपर है।

देश	हिस्सेदारी
चीन	26.8%
अमेरिका	15.5%
भारत	6.5%
रूस	5.4%
जापान	2.8%

आंकड़े वर्ष 2024 में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति हिस्सेदारी के, प्रतिशत में | स्रोत : Energy Institute

गणेश जी कुबेर के यहां बना पूरा भोजन खा गए, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। धन के स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शंकर से मदद मांगी।

गणेश जी ने तोड़ा कुबेर का घमंड

आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश से संबंधित अनेक कथाएं हैं, उन्हीं में से एक कथा के अनुसार, उन्होंने धन के स्वामी कुबेर के घमंड को नष्ट किया था। अत्यधिक धन और संपदा होने के कारण कुबेर को खुद के ऊपर पर बहुत अभिमान था। एक दिन कुबेर ने सभी देवी-देवताओं समेत भगवान शंकर और माता पार्वती को भी भोजन पर बुलाया। भगवान शंकर कुबेर का मंतव्य समझ गए थे। भगवान देवों और भक्तों का घमंड चूर करने में देर नहीं लगाते हैं।

इसलिए भगवान महादेव और माता पार्वती ने अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को कुबेर के यहां भेज दिया। गणपति को कुबेर का घमंडी व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुबेर का घमंड तोड़ने का निर्णय ले लिया। गणेश जी ने कुबेर के महल में उपलब्ध सारा भोजन खा लिया और बाकी देवों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बावजूद गणेश जी की भूख नहीं मिटी। उन्होंने कुबेर से और भोजन की मांग की। यह देखकर धन के स्वामी कुबेर चिंतित हो गए और भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। गणपति की भूख अब तक शांत न हुई थी, तब भगवान शिव ने गणपति को एक कटोरे में अनाज खाने के लिए दिया और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई। इसके बाद कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी संपन्नता को अन्य प्राणियों में बांटने का निर्णय किया।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

हरमंदिर साहिब में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना

प्रत्येक धर्म में ग्रंथों को पवित्रतम स्थान हासिल है। हिंदुओं में गीता, मुसलमानों में कुरान, ईसाइयों में बाइबिल की तरह ही सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब पूजनीय पवित्र ग्रंथ है। सिख इतिहास में 27 अगस्त का विशेष महत्व है। दरअसल सिखों के लिए सर्वाधिक श्रद्धेय अमृतसर के हरमंदिर साहिब में 1604 को 27 अगस्त के ही दिन गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई थी। देश-दुनिया के इतिहास में 27 अगस्त की तारीख पर दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:- 1556: रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने अपने भाई फिंडनेंड प्रथम के लिए गद्दी खाली की। 1604 : अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना। 1870 : भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई। 1781 : हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा। 1789 : फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 'मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा' की। 1908 : क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाज सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन का जन्म।

क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं

राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष में भारत से संबंध सुधारने के लिए चीन का आगे बढ़ना और सीमा विवाद सुलझाने हेतु गंभीर होना शुभ संकेत है।

सुजान चिनॉय | **अंतरराष्ट्रीय**

चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हाल की दिल्ली यात्रा भविष्य की संभावनाओं का एक संकेत है। पिछले वर्ष के अंत में, वाशिंगटन में राजनीतिक बदलाव से ऐन पहले स्थितियां बदलनी शुरू हो गई थीं। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रक्रिया को और आगे ले जाते दिखते हैं। बीते अक्तूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बनी सहमति ने जून 2020 में हुए तनाव के बाद संबंधों को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया को गति दी है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने और चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा देने के फैसले से आपसी समझ बेहतर हुई है। सीधी उड़ानें शुरू करने और पर्यटकों, व्यवसायों, मीडिया एवं अन्य आगंतुकों को वीजा की सुविधा प्रदान करने पर सहमति एक सकारात्मक संकेत है। साझा नदियों के संबंध में, चीन आपातकालीन स्थितियों के दौरान जल विज्ञान संबंधी जानकारियां साझा करने पर भी सहमत हुआ है। व्यापार और निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के प्रति एक नई प्रतिबद्धता है, जो भारत को इन कठिन समय में निर्यात को वैकल्पिक बाजार की ओर मोड़ने में मदद कर सकती है। लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रे के रास्ते होने वाले सीमा व्यापार को फिर से खोलना एक ऐसा कदम है, जिससे दोनों तरफ के सीमावर्ती निवासियों को लाभ होगा।

चीनी पक्ष ने तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति का स्वागत किया है। एससीओ की सफलता ब्रिक्स जैसे मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत अगले वर्ष और चीन 2027 में करेगा। भले ही द्विपक्षीय संबंधों में सुधार आ रहा है, फिर भी दोनों पक्षों को इस बात का एहसास है कि सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। उल्लेखनीय रूप से, दोनों पक्ष भारत-चीन सीमा मामलों से संबंधित मौजूदा परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत एक विशेषज्ञ समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं, ताकि 'भारत और चीन के बीच के सीमावर्ती इलाकों में सीमा निर्धारण के मामले में शीघ्र हल' तलाशे जा सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता पश्चिमी क्षेत्र में व्यवस्थित कोर कमांडर-स्तरीय बैठकों की तर्ज पर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में 'जनरल स्तर के तंत्र' की स्थापना से संबंधित है। लिहाजा, मौजूदा मॉडल के आधार पर, मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड से सटे) और पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से सटे) के संबंध में उच्चस्तरीय सैन्य वार्ता के लिए एक अलग तंत्र की स्थापना अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। डब्ल्यूएमसीसी के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन दोनों पक्षों द्वारा सीमा निर्धारण के मामले में प्रगति हासिल करने को दिए गए महत्व को रेखांकित करता है। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार, सीमा निर्धारण एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें सीमा को एक बड़े पैमाने के स्थलाकृतिक मानचित्र पर रेखांकन किया जाता है और लिखित विवरणों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसके बाद मानचित्र पर रेखांकन और मिलान विवरण अंततः जमीनी स्तर पर सीमांकन की दिशा में एक अभिन्न कदम बन जाते हैं। संबंध सुधारने के लिए चीन की आगे बढ़ने की इच्छा एक शुभ संकेत है। एक कार्य समूह के जरिये कारगर सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाना भी एक स्वागत योग्य कदम है। कुछ विश्वास बहाली के उपायों (सीबीएम) में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी अन्य उपायों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत हो सकती है। एजेंडे में संचार संपर्कों में सुधार एवं वृद्धि, अग्रिम चौकियों के बीच हॉटलाइन की संख्या बढ़ाना, सीमा कर्मियों की बैठकों (बीपीएम) के लिए अतिरिक्त बैठक बिंदु निर्धारित करना और गश्ती दल के बीच टकराव की स्थिति में आचरण को नियंत्रित करने हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित करना शामिल हो सकता है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 93 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

स्वदेशी सुरक्षा कवच

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आइएडीडब्ल्यूएस) के पहले उड़ान परीक्षण को ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टेस्ट के दौरान इस स्वदेशी प्रणाली ने तीन अलग-अलग लक्ष्यों को विभिन्न ऊंचाइयों और दूरी पर एक साथ नष्ट कर अपनी ताकत दिखाई. इसका सबसे खास हिस्सा इसका लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है. लेजर हथियार प्रकाश की गति से हमला करते हैं, ये एकीकृत होते हैं तथा इनका इस्तेमाल बार-बार किया जा सकता है. इसका सफल परीक्षण, जाहिर है, देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम है और इससे विदेशी डिफेंस सिस्टम पर भारत की निर्भरता भी कम हो जायेगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, इस उपलब्धि ने देश की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है और यह प्रणाली दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूती देगी. गौरतलब है कि विगत अप्रैल में डीआरडीओ ने इसके जमीनी संस्करण की सफलता दिखाई थी, जिसमें उसने ड्रोन को नष्ट कर उनकी निगरानी प्रणालियों को अक्षम कर दिया था. यह एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीकों से निर्मित है. तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली छोटी दूरी की इस मिसाइल प्रणाली का मुख्य काम सैन्य टुकड़ियों को दुश्मनों के हवाई हमलों से बचाना है और इसे सेना, नौसेना तथा वायुसेना की जरूरतें पूरी करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह तीन से 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट कर सकती है और चलते-फिरते भी हमला कर सकती है. इसमें दो रडार शामिल हैं, जो 360 डिग्री निगरानी और ट्रैकिंग कर सकते हैं. इस पूरे वेपन सिस्टम को बेहद आधुनिक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया है. यह प्रणाली बेशक छोटी दूरी के खतरों को रोकती है, लेकिन भविष्य में इसे लंबी दूरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए बनायी गयी इस प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित 'सुदर्शन चक्र' रक्षा कवच का हिस्सा माना जा रहा है, जो कि एक व्यापक सुरक्षा कवच होगा. इसका उद्देश्य 2035 तक एक मजबूत, स्वदेशी रक्षा कवच विकसित करना है, जो निगरानी, भौतिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को एकीकृत करेगा. इस प्रणाली के साथ भारत अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और इस्राइल जैसे चुनींदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी तकनीक है.

स्वदेशी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के पहले उड़ान परीक्षण की सफलता मिशन सुदर्शन चक्र की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस उपलब्धि ने देश की हवाई सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है.

उपराष्ट्रपति चुनाव का दिलचस्प मुकाबला

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

एनडीए ने संघ के स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्ण को इस पद के लिए चुना है, जो तमिलनाडु से हैं. जबकि इंडिया गठबंधन ने न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया है. गणतंत्र के शुरुआती दशक में उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ करता था, और समान विचारधारा की बजाय योग्यता पर जोर दिया जाता था. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक-ये सभी सर्वसम्मति से चुने गये थे. लेकिन इंदिरा गांधी के समय से दबाव बनाने की शुरुआत हुई.

उपराष्ट्रपति के जिस पद को कभी गणतंत्र की खामोश अंतरात्मा माना जाता था, वह आज इसका वाचाल परिचालन केंद्र है. जो कुर्सी कभी दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और संविधान के रक्षक की कुर्सी मानी जाती थी, वह अब परम सत्ता संरक्षक, चुनावी प्रतिनिधि और सत्ता की विचारधारा के आक्रामक समर्थक की कुर्सी बन गयी है. इस साल का विवाद, पहले की तरह, दो भारत के बारे में बताता है. एनडीए ने संघ के स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना है, जो तमिलनाडु से हैं. इसके विपरीत, इंडिया गठबंधन ने न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को चुना है, जो न्यायशास्त्र की अंतरात्मा के प्रतिनिधि हैं. ऊंची जाति के होने के बावजूद वह उदारवादी हैं तथा नागरिक आजादी, संवैधानिक नैतिकता और न्यायिक शुद्धता के आग्रही हैं.

गणतंत्र के शुरुआती दशक में उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ करता था, और समान विचारधारा की बजाय योग्यता पर जोर दिया जाता था. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक-ये सभी सर्वसम्मति से चुने गये थे. लेकिन इंदिरा गांधी ने दबाव बनाने के युग की शुरुआत की. उन्होंने परंपरा पर निष्ठा को तरजीह दी. इस तरह जाति, पंथ तथा क्षेत्र चुनाव के आधार बनने लगे. यह प्रवृत्ति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने लगी, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग ने संसद को संवाद के मंच की बजाय विधेयकों को पारित करने की जगह मान लिया. चूंकि उत्तरोत्तर आने वाली सरकारों ने अपने बहुमत के बूते लोकसभा में विधेयकों को पारित कराना शुरू कर दिया, ऐसे में राज्यसभा लोकतंत्र की खासियत की आखिरी सीमा बनी. ऐसे में, उच्च सदन में उपराष्ट्रपति का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण हो गया. और यहीं पर भाजपा की सक्रियता का मतलब है : उपराष्ट्रपति अगर तटस्थ होता है, तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं, समान विचारधारा का होने पर फायदा है. अब तक के उपराष्ट्रपतियों का रोस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस की तरह लगता है : ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, लिंगायत, जाट, कायस्थ, कम्मा. हर चुनाव ने एक सांस्कृतिक गणना दिखायी, तो हर हार में गहरे मतभेद सामने आये. जैसे, शिंदे बनाम शेखावत (दलित बनाम राजपूत), हेप्तुल्ला बनाम अंसारी (मुस्लिम विविधता बनाम मुस्लिम कूटनीति), अल्वा बनाम धनखड़ (ईसाई अल्पसंख्यक बनाम हिंदू बहुसंख्यक). वर्ष 2025 में भी यह सिलसिला कायम है : भगवा तमिल बनाम तेलुगू न्यायिक सेवा, स्टालिन का संघवाद बनाम आरएसएस का केंद्रवाद, नेहरूयुगीन अंतरात्मा की पुकार बनाम राष्ट्रवादी वर्चस्व. यही नहीं, हर उपराष्ट्रपति चुनाव की अपनी कहानी है. वर्ष 2002 में यूपीए ने महाराष्ट्र से चर्चित दलित चेहरे सुशील कुमार शिंदे को भाजपा दिग्गज और राजस्थान के प्रमुख राजपूत नेता भैरों सिंह शेखावत के मुकाबले मैदान में उतारा. वह शुद्ध रूप से जाति आधारित मुकाबला बन गया. वर्ष 2007 में एनडीए ने विमर्श बदल दिया : उसने उपकुलपति रहे दिग्गज कूटनीतिज्ञ और शैक्षणिक तथा भारतीय विदेश सेवा से जुड़े संस्थानों से जुड़े मुस्लिम प्रत्याशी हामिद अंसारी के मुकाबले मुस्लिम महिला नजमा हेपतुल्ला को उतार दिया. यूपीए के सांस्थानिक उदारवाद के मुकाबले एनडीए ने विविधता का पक्षधर होने की सुविचारित कोशिश की.

यह सिलसिला 2022 में भी जारी रहा, जब यूपीए ने कर्नाटक से एक वरिष्ठ ईसाई नेत्री मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया. महिला और अल्पसंख्यक होने के साथ दक्षिणी राज्य कर्नाटक का होने के कारण यूपीए की प्रतीकवाद राजनीति सुस्पष्ट थी. मार्गरेट अल्वा का मुकाबला राजस्थान के जाट नेता और नरेंद्र मोदी के प्रति घोषित निष्ठावान जगदीप धनखड़ से हुआ. नतीजा जोरदार रहा : धनखड़ 346 मतों से विजयी हुए. एक बार फिर भाजपा का राज्यसभा में नियंत्रण हो गया. कभी प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए जिस जातिगत समीकरण का प्रयोग किया जाता था, अब उसका इस्तेमाल विपक्षी एकता को विभाजित और बाधित करने के लिए किया जाने लगा. वर्ष 2025 में भी यह सिलसिला जारी है. उपराष्ट्रपति पद के दोनों प्रत्याशियों ने दक्षिण भारत को मुश्किल में डाल दिया है : तमिल गौरव भाजपा के प्रत्याशी को स्वीकार करेगा या आंध्र की निष्ठा केंद्र के फरमान के आगे सिर झुकायेगी? संसद में संख्याबल भाजपा के साथ है, और उसके गठबंधन सहयोगी अनिच्छुक होते हुए भी उसके निर्देश का पालन कर सकते हैं. लेकिन इस चुनाव की प्रतीकात्मकता की- जो नेहरूवाद बनाम आरएसएस, तमिल बनाम तेलुगू, स्टालिन बनाम संघवाद है-अनदेखी करना कठिन है. इंडिया गठबंधन उम्मीद कर रहा है कि सुदर्शन रेड्डी की क्षेत्रीय पहचान एनडीए में फूट पैदा कर सकती है. इसके विपरीत, एनडीए को विश्वास है कि संघ का एक परंपरावादी आदमी धर्मनिरपेक्ष शिविर में सेंध लगा देगा. ये दोनों प्रत्याशी नहीं, शतरंज के दांव हैं, और खेल का उद्देश्य संघवाद को विखंडित करना है.

यह चुनाव राजनीतिक संस्कृति पर भी एक फैसला होगा. हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ जैसे पक्षपाती उपराष्ट्रपतियों का दौर, जिनका विपक्षी सदस्यों से विवाद लगातार होता रहता था, शायद अब स्वाभाविक हो चला है. उपराष्ट्रपति की कुर्सी तटस्थ नहीं रह गयी है. राज्यसभा विमर्श और विवेचना का सदन है, ऐसे में, इसके सभापति अगर सिद्धांत के बजाय सत्ता को तरजीह दें, तो उच्च सदन की कार्यवाही सर्वाधिक प्रभावित होगी. दलगत राजनीति से विध्वस्त भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा उपराष्ट्रपति चाहता है, जो जाति और पंथ के दायरे से ऊपर उठे. उपराष्ट्रपति का यह चुनाव संविधान की अंतरात्मा और बहुसंख्यक की ताकत के बीच का चुनाव है. इस बार वोट डालते हुए हमारे सांसदगण सिर्फ अगले उपराष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे, बल्कि अखंड बहुसंख्यकवाद और बहुलतावादी संभावना के बीच आधिकारिक निर्णय भी करेंगे. ध्यान रहे, जब उपराष्ट्रपति ताबेदार बन जाते हैं, तब गणतंत्र अतीत का अवशेष मात्र रह जाता है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सुदर्शन रेड्डी तक, दर्शनशास्त्र से विखंडन तक, उपराष्ट्रपति का कार्यालय क्रमशः अधःपतन को प्राप्त हुआ है. इसका कारण यह नहीं है कि प्रत्याशी कम योग्य हैं, बल्कि यह है कि चुनाव का आधार श्रेष्ठता की जगह मुनाफे तक सीमित रह गया है. जो देश कभी विचारों के लिए उपराष्ट्रपति की ओर देखता था, वह देश इस चुनाव के जरिये अब जाति समूहों, क्षेत्रों तथा बेचैन गठबंधनों को संदेश देता है. देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक कार्यालय दूसरा सबसे प्रतीकात्मक कार्यालय है, जो अब सम्माननीय कम और खोखला ज्यादा है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए गांवों का विकास जरूरी

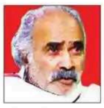

पद्मश्री अशोक भगत
सचिव, विकास भारती झारखंड
vikasbharti1983@gmail.com

दुनिया का कोई भी देश अपने नौजवानों की कार्य क्षमता और कौशल की बदौलत ही मजबूत बनता है. हमें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ीकरण की योजना बनानी चाहिए. साथ ही, अपनी युवा ताकत को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना चाहिए.

स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं. भारत की संस्कृति ऋषि, कृषि और पशुपालन के साथ ही हस्तशिल्प पर आधारित रही है. निःसंदेह भारत की संस्कृति के मूल तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता ही है. भारत के महान अर्थशास्त्री 'चाणक्य' ने बताया है कि जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होता है, उसका जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता और वह चलती-फिरती लाश के समान होता है. इसलिए परंपरा में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और इसके माध्यम से समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार व गांव की व्यवस्था प्रशासित और शासित होती रही है. आधुनिक भारत में स्वावलंबन, ग्राम विकास और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक जोर महात्मा गांधी ने दिया. उनके बाद इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य विनोबा भावे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ राम मनोहर लोहिया, दत्तोपंत ठेंगड़ी और धर्मपाल जैसे चिंतकों ने भारतीय समाज को प्रबोधित किया. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दे रही है.

गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देशभर में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. संस्कृति की प्रकृति वहां के वातावरण पर आधारित होती है. भारत की जलवायु समशीतोष्ण है. इसलिए यहां की संस्कृति पर उसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है. आज हम जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं, वैसी खेती के लिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति विकसित की. उन्होंने मिट्टी, पानी, जीवों, वृक्षों की सुरक्षा, यहां तक कि कीट-पतंगों की सुरक्षा पर भी संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया. यदि इस प्रकार की सुरक्षित खेती को आत्मसात कर उसमें नवीन प्रयोग सम्मिलित किये जायें, तो विकास की बेहतर अवधारणा प्रकट होगी. व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया और ब्रह्मांड, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. व्यक्ति समष्टि का एक छोटा रूप है. इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया ब्रह्मांड तक को प्रभावित करती है. इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसक कार्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया. वे बड़े-बड़े हिंसक कारखानों के विरोधी थे. उन्होंने कुटीर उद्योग को अहिंसक उद्योग बताया. उन्होंने मानव के विकास की परिभाषा को ही बदल कर प्रस्तुत किया. आज दुनिया जहां खड़ी है, वहां कई समस्याएं उसको घेरे हुए है. हालांकि उत्तर आधुनिक और भौतिकवादी चिंतक इस बात से सहमत नहीं हैं.

स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब व्यक्ति अपने कौशल का विकास कर अपने कौशल के माध्यम से आवश्यकता की सभी चीजों को प्राप्त करे. ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'जो व्यक्ति त्याग के बिना भोग करता है, वह मानव के आदर्श मूल्य के खिलाफ है. इसलिए भोग त्याग की कसौटी पर ही होना चाहिए.' भारत में त्याग के साथ भोग करने की परंपरा अनादि काल से रही है. इस कारण भारत की ग्रामीण व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित थी कि उस पर बाहरी किसी शक्ति का प्रभाव ही नहीं पड़ता था. भारत में यह व्यवस्था लंबे समय तक रही, पर बाहरी आक्रांताओं के कारण व्यवस्थाएं टूटीं और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्री गांव को कम करके आंकते हैं. उन्हें बड़े-बड़े कल-कारखानों एवं उद्योगों पर भरोसा होता है. उनका मानना है कि इन कल-कारखानों से ही विकास संभव है और देश की प्रगति होती है, पर कोरोना ने इस चिंतन को झूठा साबित कर दिया. जब बड़े-बड़े उद्योग बंद हो गये, तब भारत को भारत के गांवों ने ही बचाया. करोड़ों की संख्या में कामगार जब गांव आये, तब गांव ने ही उनका संपोषण और संवर्धन किया. यह साबित करता है कि देश के गांव यदि स्वावलंबी और मजबूत हैं, तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहेगी.

यदि ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर, स्वावलंबी नहीं हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो देश की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती. अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ रघुराम राजन ने कहा कि 'भारत को चीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अब विनिर्माण का क्षेत्र धीरे-धीरे सिकुड़ने वाला है और सेवा के क्षेत्र का विस्तार होने वाला है, इसलिए भारत को सेवा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए.' यह बयान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर इशारा करता है, साथ ही, एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की भी वकालत करता है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि कौशल और तकनीक वह ताकत है, जो व्यक्ति, समाज और देश की दिशा बदल सकता है. दुनिया का कोई भी देश अपने नौजवानों की कार्य क्षमता और कौशल की बदौलत ही मजबूत बनता है. हमें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ीकरण की योजना बनानी चाहिए. अपनी युवा ताकत को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना चाहिए.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

संकटों के कारण आंतरिक विभाजन से जूझ रहा यूरोपीय संघ

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हाल ही में, यूक्रेन संकट पर यूरोपीय संघ (ईयू) की हिचकिचाहट भरी प्रतिक्रिया ने चर्चाओं को जन्म दिया है. दरअसल, यूक्रेन संकट से पहले भी यूरोजोन ऋण संकट, शरणार्थी संकट और ब्रेक्जिट संकट आदि से निपटने में ईयू की कमजोर क्षमता उजागर हो गयी थी. अतीत में, संकट अक्सर ईयू की सामूहिक कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक का काम करते थे, परंतु, आज वे आंतरिक विभाजन को बढ़ावा देने वाले बन गये हैं. हाल के वर्षों में, यूरोपीय संघ ने संकटों के प्रति लापरवाही भरी प्रतिक्रिया का मॉडल अपना लिया है. नीति-निर्माता अपने विकल्पों को केवल यह कहकर सही ठहराते हैं कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था. टोंगजी विश्वविद्यालय में जर्मन अध्ययन केंद्र के निदेशक झेंग चुनरोंग की मानें, तो यह रणनीति यूरोप की सोच में बढ़ती जड़ता को दर्शाती है. निर्णयकर्ता ऐसी नीतियां अपनाते हैं जो वर्तमान जनमत के साथ अधिक मेल खाती हों, और विकल्पों पर व्यापक रूप से विचार करने से बचते हैं. प्रचलित धारणा यह है कि यूरोप में अब सच्चे राजनेताओं की तुलना में राजनेताओं की संख्या अधिक है- रणनीतिकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए. बेशक, समय बदल गया है, और यदि ऐसे रणनीतिकार मौजूद भी हों, तब भी यह संदिग्ध है कि वे कोई प्रभाव डाल पायेंगे. संक्षेप में कहें, तो ईयू एक हद तक नेतृत्व शून्यता का अनुभव कर रहा है. साथ ही, नीतिगत मुद्दों पर उसकी आंतरिक सहमति बिखर रही है. इसका एक उदाहरण राजनीतिक मध्यमार्गियों का सिकुड़ना और दक्षिणपंथी लोकलुभावन और अति दक्षिणपंथी ताकतों का उदय है. इस कारण ईयू के भीतर ज्वलंत समस्याओं के समाधान पर आम सहमति बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. इससे भी बुरा यह है कि ईयू अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने में हिचकिचा रहा है. चुनौतियों के सामने आने पर, कई यूरोपीय राजनेता अपनी जड़ जमायी सोच के अनुसार ही काम करना पसंद करते हैं.

GLOBAL TIMES

विशेष

संवेदनाओं में भीगी फिल्म 'पथेर पांचाली' के 70 वर्ष

जयनारायण प्रसाद
टिप्पणीकार
delhi@prabhatkhabar.in

मूवी कैमरे के जरिये भी एक अच्छी कहानी कही जा सकती है. यह बात ऑस्कर विजेता फिल्मकार सत्यजीत रे ने हमें सिखायी थी. उनकी बनायी पहली बांग्ला फिल्म 'पथेर पांचाली' (पथ का गीत, द सांग ऑफ द रोड) ने देखते ही देखते राय मोशाय को 'ग्लोबल' बना दिया. 'पथेर पांचाली' 1955 में बनी थी और वह भी सिर्फ सत्तर हजार रुपये में. इस क्लासिक फिल्म को भले ही बहुत सराहना मिली, पर जब इसका निर्माण शुरू हुआ, तब परिस्थितियां बहुत मुश्किल थीं. वर्ष 1952 में फिल्म बननी शुरू हुई और 1955 में बनकर तैयार हुई. यह फिल्म पहली बार कलकत्ता के बसुश्री सिनेमा हॉल में 26 अगस्त, 1955 को रिलीज हुई थी. क्लासिक फिल्म 'पथेर पांचाली' को बनाना सत्यजीत रे के लिए एक सपने को साकार करने की लड़ाई थी.

दो मई, 1921 को कलकत्ता के गड़पार रोड मोहल्ले में जन्मे सत्यजीत रे की मृत्यु 23 अप्रैल, 1992 को कलकत्ता के ही बेल व्यू नर्सिंग होम में हुई. तब सत्यजीत रे सत्तर साल के थे और बहुत बीमार थे. राय मोशाय ने कोई 36 फिल्में बनायीं. इनमें ज्यादातर फीचर, कुछ लघु और कुछ डॉक्यूमेंट्री हैं. पर उनकी बनायी पहली क्लासिक फिल्म 'पथेर पांचाली' का कोई तोड़ नहीं है. दुनियाभर की 'वर्ल्ड क्लासिक फिल्मों' की फेहरिस्त में यह बांग्ला मूवी भी शामिल है. इस फिल्म में वैश्विक अनुभूति से लेकर संवेदनाएं आपको जगह-जगह दिखाई दे जाती हैं, जो सरहद पार बैठे दर्शकों को भी सहज भाव से आकर्षित करती हैं. इस फिल्म को पूरा करने के लिए सत्यजीत रे ने कोई जतन उठा नहीं रखा. पत्नी विजया राय के गहने बेचे, उनकी पॉलिसियां बेचीं. अपने दुर्लभ गानों के रिकार्ड्स बेचे, इसके बावजूद जब 'पथेर पांचाली' पूरी नहीं हुई, तब पश्चिम बंगाल सरकार आगे आयी. राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय ने फिल्म की कहानी सुनी और उसके कुछ अंश देखे. सब कुछ देखने-सुनने के बाद उन्होंने सत्यजीत रे से इसका अंत बदलने को कहा, पर वे अड़े रहे. कहते हैं कि 'पथेर पांचाली' का अंत बदलने को लेकर सत्यजीत रे कुर्सी से उठ खड़े हुए थे. मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन राय को अपने चैंबर में फिर बुलाया और कहा, 'बैठो! उस दिन मैं तुम्हारी भावना को परख रहा था. घर जाओ, खाओ और सो जाओ. हमारी सरकार तुम्हारी फिल्म को फाइनेंस करेगी.' बाद में फिल्म को पश्चिम बंगाल सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से आर्थिक मदद दी गयी. उसके बाद 'पथेर पांचाली' ने वैश्विक स्तर पर जो धूम मचायी, वह फिल्म इतिहास का अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. मशहूर ब्रिटिश पत्रिका 'साइट एंड साउंड' ने सत्यजीत रे को एशिया के टॉप 10 निर्देशकों में शुमार किया. इस फिल्म को ढेर सारे पुरस्कार मिले. विदेशी फिल्म महोत्सवों में गोल्डन लायन, गोल्डन बियर तथा दो सिल्वर बियर मिले. इसके साथ ही रे को 1978 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मानद उपाधि तथा 1992 में 'ऑनरेरी एकेडमी' पुरस्कार मिला. उसी वर्ष उन्हें 'भारत रत्न' से भी नवाजा गया.

मोटे तौर पर देखें, तो मानवीय जटिलताएं, सामाजिक विरूपण और आम आदमी का संघर्ष सत्यजीत रे की फिल्मों का सार व कथ्य रहा है. उन्होंने फिल्म बनाने के अतिरिक्त, बांग्ला में बच्चों के लिए कहानियां और जासूसी उपन्यास भी लिखे हैं. उनकी फिल्म 'सोनार केल्ला' और 'फेलुदा सीरीज' बंगाल के घर-घर में आज भी काफी लोकप्रिय हैं. बंगाल में बच्चे इसे चाव से देखते और पढ़ते हैं. उन्होंने अपनी मातृभाषा में ढेर सारी फिल्में तो बनायीं ही, हिंदी में भी दो फिल्में बनायीं. एक 'शतरंज के खिलाड़ी' (1977) और दूसरी दूरदर्शन के लिए 'सद्गति' (1981). दोनों फिल्में प्रेमचंद की रचनाओं पर आधारित थीं. फिल्म 'शतरंज के खिलाड़ी' में हिंदी संवाद सत्यजीत रे, शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी ने लिखे थे. जबकि 'सद्गति' में संवाद सत्यजीत रे और प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय का था. 'शतरंज के खिलाड़ी' तो विदेशों में भी काफी सराही गयी. एक सौ तेरह मिनट की इस फिल्म का नृत्य निर्देशन बिरजू महाराज ने किया था. साउंड डिजाइन नरिंदर सिंह ने किया था और बंसीचंद्र गुप्त ने आर्ट डायरेक्शन. वहीं इसमें म्यूजिक सत्यजीत रे ने दिया था. संजीव कुमार (मिर्जा सज्जाद अली), सईद जाफरी (मीर रौशन अली), अमजद खान (वाजिद अली शाह), रिचर्ड एटनबरो (जनरल आउट्रम), शबाना आजमी (खुर्शीद), फरीदा जलाल (नफीसा), विक्टर बनर्जी (अली नकवी खान, प्रधानमंत्री), फारुख शेख (अकील), टॉम अल्टर (कैप्टन वेस्टर्न) और लीला मिश्रा (सिरिया) के किरदार में थीं. अब इनमें से ज्यादातर कलाकार जीवित नहीं हैं. स्वयं इस फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे भी.

'सद्गति' एक टेलीफिल्म थी. इस फिल्म में ओमपुरी (दुखी चमार), स्मिता पाटिल (झुरिया, दुखी की पत्नी), ऋचा मिश्रा (धनिया, दुखी की बेटी), मोहन अगाशे (घासी राम), गीता सिद्धार्थ (लक्ष्मी, घासी राम की पत्नी) और भैयालाल हेदाव (गोंड) ने खास भूमिका निभायी थी. राय मोशाय की इस टेलीफिल्म में सोमेंदु राय की फोटोग्राफी और अशोक बोस का कला निर्देशन देखने लायक है. बावन मिनट की इस फिल्म का म्यूजिक सत्यजीत रे ने दिया था.

आपके पत्र

नशे की गिरफ्त में फंस रहे युवक

युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने की खबर आये दिन आती रहती है. इससे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है. युवाओं की बदलती आदतों से आस-पड़ोस के लोग परेशान रहते हैं. धीरे-धीरे किशोरों में नशे की लत लगती जा रही है. इसके कारण वे अपराध करने लगते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है. इसके लिए प्रशासन को भी परिजनों के साथ मिल कर नशे की गिरफ्त में आये युवक-युवतियों की काउंसेलिंग कर सही राह पर लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए.

बंधु मुन्ना, सुपौल

चीन और भारत के बीच घटी दूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से त्रस्त चीन व भारत की दूरी कम हो रही है. चीन भारत के साथ भरोसा कायम रखता है, तो अमेरिका की बोलती बंद हो जायेगी. भारत को इसका ध्यान हमेशा रखना होगा कि चीन सिर्फ अपने फायदे की सोचता है. भारत आये चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार व व्यवहार में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए. चीन को समझ आ गया है कि भारत के साथ टकराव से दोनों देशों का नुकसान है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीति भारत व चीन के लिए चुनौती है.

युगल किशोर राही, छपरा

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

कागजी साबित हो रही बाघों की निगरानी

बाघों के संरक्षण को लेकर भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद इन्हें बचाने व जंगलों में निगरानी का काम कागजी ही साबित हो रहा है। यह सच है कि पिछले एक दशक में देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। इसके बावजूद बाघों के लापता होने, या फिर अज्ञात कारणों से मौत की आए दिन सामने आने वाली खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। राजस्थान में ही 13 बाघ लापता बताए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में 8 माह में 40 बाघ शावकों की मौत के मामलों की जांच जारी है। इसी तरह से महाराष्ट्र में 30, असम में 12 व समूचे देश की बात करें तो अब तक 115 बाघों की मौत हो चुकी है। इसी सप्ताह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तवा के बैक वाटर में एक बाघ का शव मिला। उसके पंजा काटे जाने की पुष्टि हुई। इसी महीने भोपाल के पास केरवा और कोलार के जंगलों से निकला बाघ शहर के करीब सड़कों के पास देखा गया।

बाघों के लापता होने का कारण वन विभाग की तरफ से इनका क्षेत्र बदलना रहा है। इसकी वजह शिकारियों का भय भी है। शिकारियों से बचने के लिए बाघ आबादी की ओर रुख करने लगते हैं। बालाघाट में बाघ के शिकार के मामले में दो वनकर्मियों पर इनाम घोषित होना बताता है कि बाघ संरक्षण के नाम पर घोर लापरवाही हुई है। कैमरे, कॉलर आईडी और न जाने किन-किन संसाधनों पर लाखों रुपए खर्च के बावजूद वन विभाग का लंबा-चौड़ा अमला बाघों की निगरानी में असफल साबित हो रहा हो तो इसे क्या कहेंगे? मध्यप्रदेश में तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अपने मातहतों को चेतावनी पत्र जारी कर कहना पड़ा है कि रिजर्व और जंगलों में बाघों की मौत का कारण पता नहीं चलना गंभीर चूक है। सच्चाई ये है कि चाहे राजस्थान हो, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या कर्नाटक सभी जगह रिजर्व और जंगलों में मानव गतिविधियां बढ़ रही हैं। कोई इसे कितना भी छिपाए, लेकिन अभयारण्यों और जंगलों में मानवीय दखल बढ़ रहा है। ऐसी घटनाओं को छिपाने में राजनीतिक दखल भी जानवरों की मौतों के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। एक तरह से मिलीभगत का खेल नजर आता है जिसमें बाघों की मौत व लापता होने के मामलों को कोई संज्ञान में नहीं ले रहा।

एक संकट और है, जंगल की सीमा से सटे गांवों में मवेशियों को बचाने के लिए ग्रामीण बाड़बंदी में करंट तक प्रवाहित कर रहे हैं। शिकारियों की मौजूदगी से घबराकर जब जानवर जंगलों से आबादी का रुख करते हैं तो कभी-कभी वह करंट लगे तारों की जद में भी आ रहे हैं। बाघों की मौत के पीछे एक ही कारण है वो है मानव। आज तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कि हर एक बाघ की मौत पर उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। हम जंगल कम करते जा रहे हैं और इसका नुकसान जंगली जानवरों को हो रहा है। हम जंगलों और जंगली जानवरों दोनों को ही नहीं गंवा सकते। बाघों के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

भू-राजनीति : पूरे हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है उससे भारत को रहना होगा सतर्क

चीन की सक्रियता : सहयोग या छिपा विस्तारवाद

डॉ. रहीस सिंह
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

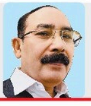

यदि चीनी गतिविधियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव में तेज हो रही हैं तो उन्हें केवल एक बंदरगाह अथवा आर्थिक गलियारे तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि वे व्यापक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती हैं जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि इंडो-पैसिफिक को प्रभावित कर सकती हैं।

इस समय बीजिंग-इस्लामाबाद बॉण्डिंग में कुछ और आयाम जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जिनके सिरे एक तरफ काबुल और दूसरी तरफ ढाका तक पहुंच रहे हैं। यह बीजिंग के सामरिक और आर्थिक 'गेम प्लान' का हिस्सा है अथवा कुछ और, अभी कहना जल्दबाजी होगी लेकिन उससे बेहतर की उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती। यह भी संभव है कि बीजिंग-इस्लामाबाद-ढाका त्रिकोण क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को प्रभावित करे। इस्लामाबाद तो बीजिंग को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहता ही रहा है। इसके बदले में चीन ने उसका भरपूर वित्त पोषण किया तथा इंफ्रा व रक्षा सहयोग किया है लेकिन ढाका की इस दिशा में बढ़ती निकटता कुछ और कह रही है। सच तो यह है कि ढाका इस समय बीजिंग और इस्लामाबाद से एक रणनीतिक 'हेजिंग' करता हुआ देखा जा सकता है जिसके अपने मायने हैं।

यदि चीनी गतिविधियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव में तेज हो रही हैं तो उन्हें केवल एक बंदरगाह अथवा आर्थिक गलियारे तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि वे एक व्यापक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती हैं जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि इंडो-पैसिफिक को प्रभावित कर सकती हैं। पूरे हिंद महासागर में चीन एक आक्रामक रणनीति, कैलकुलेटेड इकोनॉमिक्स और सधी हुई जियो-पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ रहा है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। ध्यान रहे कि चीन 'सीपेक' (चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर) से पहले ही 'स्ट्रिंग आफ पर्ल्स' की नींव डाल चुका था जो एक तरफ ग्वादर (पाकिस्तान) से लेकर मारओ (मालदीव), हम्बनटोटा (श्रीलंका) होते हुए सिंहनाक्विलै (कम्बोडिया) तक और दूसरी तरफ मलक्का से जिबूती तक रणनीतिक समुद्री केंद्रों की एक सामरिक शृंखला निर्मित कर रहा, जो हिंद महासागर में उसके लिए पावर बैलेंसिंग का काम कर सकती है। सीपेक को ही लें तो इसके माध्यम से चीन ग्वादर बंदरगाह को मुख्य स्ट्रैटेजिक नोड के रूप में विकसित कर रहा है, जिससे उसकी पहुंच मध्य पूर्व की ओर के समुद्री मार्गों तक होगी, फलतः मलक्का जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ मलक्का) पर निर्भरता कम होगी। अब चीन इसे पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान तक विस्तार देना चाहता है ताकि व्यापार और संपर्क मार्ग को मध्य एशिया तक बढ़ाया जा सके।

अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक का समस्त क्षेत्र चीन के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। इससे उसे न केवल आर्थिक लाभांश हासिल होंगे, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक लाभांश भी हासिल होंगे। इसका इस्तेमाल वह दक्षिण एशिया में पावर बैलेंसिंग के लिए कर सकता है। भारत को इसे गंभीरता से लेना होगा। बीजिंग, इस्लामाबाद और ढाका के बीच हालिया त्रिपक्षीय संवाद और समझौता एक संभावित 'रणनीतिक त्रिकोण' का संकेत देता है। हालांकि बांग्लादेश सरकार अभी किसी भी 'सैन्य गठबंधन' अथवा 'ब्लॉक आधारित व्यवस्था' में शामिल होने से इनकार कर रही है। वह चीन से तकनीकी और आर्थिक मदद तो चाहता है, जो उसकी 'अनुबंधात्मक' और 'संतुलित' विदेश नीति का हिस्सा है। लेकिन क्या ऐसा ही है?

ध्यान रहे कि पिछले दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस चीन यात्रा पर गए थे। उनकी इस यात्रा के बाद से ही चीन की ओर से 'चिकन नेक' (सिलिगुड़ी कॉरिडोर) के करीब बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में एक एयरफील्ड बनाने की योजना की चर्चा चल पड़ी है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश की वायुसेना के कुछ अधिकारियों की पाकिस्तान में जेएफ-17 विमानों के प्रशिक्षण संबंधी खबरें भी आ रही हैं। ये विमान चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किए हैं। जानकारों की मानें तो इन फाइटर विमानों को लालमोनिरहाट में तैनात किया जाना है। देखना यह है कि चीन 'सीपेक 2.0' के जरिए पाकिस्तान के किस-किस क्षेत्र तक विस्तार करता है। यह विस्तार खनन, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तक सीमित रहेगा अथवा उसकी संपूर्ण सप्लाई चेन पर कब्जे तक जाएगा? चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस्लामाबाद यात्रा और काबुल में उनके पाकिस्तानी व अफगान समकक्षों के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक की, जिसमें तीनों देशों ने सीपेक को काबुल तक विस्तार देने पर सहमति जताई। ध्यान रहे कि 'आसियान प्लस थ्री' विदेश मंत्रियों की बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पहले ही कह दिया था कि बीजिंग, पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन जारी रखेगा। उनके इन शब्दों के कुछ मायने हैं, जो चीनी विदेश नीति के आयामों में गहरे छिपे हुए हैं। नई दिल्ली इनसे भलीभांति परिचित है और समय-समय पर विरोध भी दर्ज कराती है।

चीन लंबे समय से भारत के साथ 'लव-हेट गेम' खेल रहा है। गौर से देखें तो पाकिस्तान में असल सत्ताधारी जनरल मुनीर हैं, जिनका लोकतंत्र से कोई नाता नहीं हैं। बांग्लादेश में भी चुनी हुई लोकप्रिय सरकार नहीं है, बल्कि वह जनता की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके सत्ता पर काबिज हुई है। वहां एक्टिव सरकार के मुख्य सलाहकार दिखते हैं उनके पीछे असल कौन है, यह अदृश्य है। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में हैं जो सरकार को पदच्युत और लोकतंत्र को पैरों तले रौंदकर सत्ता में आए हैं। ये चीजें बीजिंग के अनुकूल हैं। चीनी गतिविधियां संदिग्ध हैं, भारत को इस पर नजर ही नहीं रखनी होगी, बल्कि काउंटर रणनीति भी तैयार करनी होगी।

प्रसंगवश

सड़क हादसे रोकने के लिए बड़े शहरों में भी जरूरी हैं लेन सिस्टम

जयपुर समेत प्रमुख बड़े शहरों में बेतरतीब यातायात बड़ी समस्या है

सड़क हादसे कम हों इसकी चिंता सबको है। सरकारी स्तर पर इस मकसद को पूरा करने के लिए अभियान भी चलते हैं लेकिन ठोस काम कभी नजर नहीं आता। राजस्थान में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस प्रशासन की ओर से लागू की जा रही लेन व्यवस्था ऐसे ही अभियानों का हिस्सा कही जा सकती है। हाईवे पर लेन व्यवस्था समुचित पेट्रोलिंग से ही लागू हो पाएगी इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। दरअसल लेन सिस्टम में चलने का प्रशिक्षण शहरी इलाकों से देना ज्यादा कारगर हो सकता है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के बड़े शहरों में सड़क हादसों की एक बड़ी वजह वाहनों का बेतरतीब तरीके से सड़क पर उतरना भी रहता है। हाईवे के साथ इन शहरों में भी ट्रैफिक के नियमों को लेकर जागरूकता नहीं होने से एकाएक वाहनों के लेन बदलने, अचानक यू-टर्न लेने की गलतियां हादसों को न्योता देती हैं।

प्रदेश के प्रमुख शहरों के ट्रैफिक के हाल को देखें तो वाहनों का दबाव नजर आता है। लेन सिस्टम के अभाव में ट्रैफिक की व्यवस्था अस्त-व्यस्त होती रहती है। जयपुर में तो कुछ वर्ष पहले जेएलएन मार्ग पर यातायात पुलिस ने प्रायोगिक तौर पर लेन सिस्टम शुरू करने की कवायद की थी लेकिन कुछ समय बाद ही फुस्स हो गई। तब वाहनों की निगरानी के लिए रोड पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। लेन सिस्टम के साथ वाहनों की गति सीमा यातायात नियमों में पहले से ही निर्धारित है। लेकिन पर्याप्त पुलिस जाप्ता नहीं होने और दूसरे दबावों के चलते जयपुर का यह लेन सिस्टम परीक्षण के दौर में ही विफल हो गया। वर्तमान में लेन सिस्टम तो दूर जयपुर शहर की हर सड़क पर यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लेन सिस्टम की व्यवस्था हाईवे के साथ-साथ प्रमुख शहरों में भी लागू करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक कंट्रोल की बैठक के दौरान इस पर भी विशेष रूप से चर्चा कर प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता है।

- शरद शर्मा
sharad.sharma@in.patrika.com

मानवीय मूल्य

सोच व संवेदनशीलता ही विकास का पैमाना

चेतन प्रकाश मण्डावरिया

भारत एक ऐसा देश है जहां सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां की परंपराएं और रीति-रिवाज जीवन के हर पहलू में शामिल हैं, लेकिन केवल आर्थिक व तकनीकी प्रगति असली विकास का उद्देश्य नहीं हो सकता। देश की असली तरक्की नागरिकों की विचारशीलता, नैतिकता, आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी में दिखाई देती है।

धार्मिक मान्यताएं जीवन के हर पड़ाव में मार्गदर्शक की तरह होती हैं। यहां पूजा-पाठ, संस्कार व परंपराएं आत्मिक विकास का जरिया बन सकती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य सद्गुणों और सद्व्यवहार को अपनाना है। धर्म का वास्तविक सार करुणा, सहिष्णुता, सेवा और सत्य में निहित है। जब व्यक्ति अपनी सोच और कर्म में इन मूल्यों को अपनाता है, तभी वह समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। नागरिकों की जिम्मेदारी देश के विकास में सबसे अहम है। विकसित समाज की ताकत सामूहिक जिम्मेदारी और अनुशासन में होती है।

यह जरूरी है कि हर नागरिक सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, ट्रैफिक नियमों का पालन और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। जिम्मेदार नागरिक अपने फायदे से ऊपर समाज और देशहित को रखता है। अगर हम हर कार्य में 'हमारा दायित्व' सोच अपनाएं, तो सामाजिक बदलाव तेजी से आएगा। भारत में शिक्षा को आमतौर पर नौकरी के साधन के रूप में देखा जाता है। इससे बच्चे रटने तक सीमित रह जाते हैं, सोचने-समझने, भावनात्मक संवेदनशीलता या सामाजिक जिम्मेदारी जैसी बातें पीछे छूट जाती हैं। ऐसे नागरिक समाज के लिए अमूल्य संपत्ति हैं, जो अपनी क्षमता से दूसरों का भी कल्याण करने में सक्षम हैं।

मार्गदर्शन व ज्ञान साझा करना समाज निर्माण में अहम है। अगर हर सक्षम नागरिक मेंटरशिप या सहायता करना शुरू कर दे, तो सामाजिक स्तर पर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। नैतिकता और व्यावसायिक ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। निजी जीवन में नैतिकता का पालन जितना जरूरी है, उतना ही व्यावसायिक जीवन में भी। सेवा भावना केवल आपदा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गरीब बच्चों की मदद, बुजुर्गों या महिलाओं के लिए कोई योगदान, समाज के प्रति नियमित स्वैच्छिक सेवाएं बदलाव का मार्ग बन सकती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत के विकास की असली पहचान उसकी प्रगति, जीडीपी, तकनीक या इमारतों में नहीं, बल्कि नागरिकों के चरित्र, सोच, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी में झलकती है। जब व्यक्ति स्वयं को बदलता है, तो पूरा देश स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है।

(लेखक आयोजना विभाग राजस्थान में संयुक्त शासन सचिव हैं)

टाइगर एंड टर्टल : यह कोई रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि पैदल पथ है

जर्मनी *के डुइसबर्ग में स्थित 'टाइगर एंड टर्टल-मैजिक माउंटेन' एक अनोखा पब्लिक आर्ट स्ट्रक्चर है, जो दूर से देखने पर किसी रोमांचक रोलर कोस्टर की तरह दिखाई देता है। परंतु असलियत में यह किसी झूले की सवारी नहीं, बल्कि पैदल पथ है, जिस पर लोग चलकर रोमांच का अनुभव करते हैं। इस स्ट्रक्चर को कलाकारों हाइके मुथे और उलरिख गेयर ने 2011 में तैयार किया था। इसका निर्माण डम्प साइट पर किया गया है।*

टाइगर एंड टर्टल का डिजाइन गति और ठहराव, आधुनिकता और परंपरा के बीच का अद्भुत विरोधाभास दर्शाता है। दिन में इसकी चमकदार धातु संरचना ध्यान खींचती है, जबकि रात में एलईडी लाइटिंग इसे किसी स्वप्निल दृश्य जैसा बना देती है। यहां आने वाले लोग न केवल तस्वीरें खींचते हैं, बल्कि इसकी घुमावदार पगडंडियों पर चलते हुए कला और इंजीनियरिंग के अनूठे संगम का अनुभव भी करते हैं। यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे डम्प साइट को रचनात्मक दृष्टिकोण और कला के माध्यम से एक जीवंत सांस्कृतिक लैंडमार्क में बदला जा सकता है।

सरोकार एकीकृत योजना ही समाधान, प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की सोच अपनाएं

जैव विविधता का संरक्षण ही सतत विकास की कुंजी

डॉ. रिपुन्जय सिंह
सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
@patrika.com

आज के दौर में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। मानव समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता का क्षरण बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में एकीकृत योजना ही एकमात्र रास्ता है, जो जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास दोनों को साथ लेकर चल सकती है।

जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव-जंतुओं, पौधों, सूक्ष्मजीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है। यह न केवल पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, बल्कि मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी, औषधियां, ईंधन और वस्त्रों का स्रोत भी है। यदि जैव विविधता नष्ट हो जाती है, तो मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सतत विकास का अर्थ एक ऐसा विकास है, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और अधिकारों से समझौता न करे। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन आवश्यक है। जैव विविधता और सतत विकास को जोड़ने के लिए एकीकृत योजना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि विकास के बीच संतुलन होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही संरक्षण प्रयास सफल हो सकते हैं।

एकीकृत योजना के मुख्य आयामों में विकास योजनाओं के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य करना है। हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता देना है। जैविक खेती, फसल विविधीकरण और जल-संरक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है। वनों की कटाई रोकना, वनीकरण को बढ़ावा देना, जलस्रोतों की रक्षा करना है। एकीकृत योजना ही वह मार्ग है, जो जैव विविधता और सतत विकास के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती है। यदि विकास योजनाओं में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाए, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित पृथ्वी सौंप सकते हैं। आज समय की मांग है कि सरकारें, वैज्ञानिक, समाज और आम नागरिक मिलकर 'प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व' की सोच अपनाएं। यही सच्चे अर्थों में सतत विकास का मार्ग है।

इसलिए आज ऐसी नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता है जो विकास और संरक्षण को एक साथ लेकर चलें। भारत में 47,000 पौधों और 89,000 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई विलुप्ति के कगार पर हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव है।

एकीकृत योजना के मुख्य घटक के तहत विकास परियोजनाओं में पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य करना है। शहरी और ग्रामीण नियोजन के तहत हरित क्षेत्र और जैव विविधता पार्कों का निर्माण करने के साथ वर्षा जल संचयन और नदियों का पुनर्जीवन करना है और सतत परिवहन को लागू करना है। तकनीकी नवाचार के तहत रिमोट सेंसिंग के जरिए भूमि उपयोग की निगरानी करना, भू-स्थानिक तकनीक से जैव विविधता मानचित्रण आदि पर कार्य करना है।

जैव विविधता और सतत विकास के लिए एकीकृत योजना केवल नीति नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। यदि विकास योजनाओं में पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए, तो न केवल प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित होंगे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास भी स्थायी रूप से संभव होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

बुक इनसाइट

कास्टिंग ऑफ

एलिजाबेथ जेन हावर्ड की लिखी पुस्तक 'कास्टिंग ऑफ' द कैजलेट क्रॉनिकल्स शृंखला का एक रोचक और भावनात्मक हिस्सा है। यह एक सार्थक और प्रभावशाली उपन्यास है। यह उपन्यास 20वीं सदी के मध्यकालीन ब्रिटेन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो कैजलेट परिवार की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को बयां करता है। इस किताब में पारिवारिक रिश्तों, प्रेम, और जीवन की चुनौतियों को संवेदनशील और सच्चाई से पेश किया गया है। इस पुस्तक में समय के बदलाव का प्रभाव बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। युद्ध के बाद के समाज में आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों को लेखिका ने इतनी बारीकी से पिरोया है कि पाठक उस दौर की सच्चाई को महसूस कर सकता है। युद्ध के बाद का समय और सामाजिक बदलाव इस परिवार पर गहरा असर डालते हैं। हर किरदार की अपनी कहानी है, जो पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। चाहे वह युवा पीढ़ी के सपने हों या बुजुर्गों की चिंताएं लेखिका ने हर पहलू को बारीकी से उकेरा है। भाषा प्रवाहमयी है, जो इसे आम पाठकों के लिए आकर्षक बनाती है।

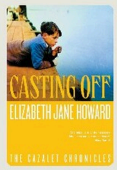

आपकी बात

कानून की कड़ाई से पालना जरूरी

दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों की कड़ाई से पालना जरूरी है। दहेज की मांग करने वालों की सूचना जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रशासन को देनी चाहिए। समस्त राजकीय कर्मचारियों को दहेज प्रकरणों को उजागर करने के लिए पाबंद करना चाहिए। समाज में बिना दहेज के शादी करने वाले लोगों को सामाजिक मंचों पर सम्मानित किया जाना चाहिए। **- सुरेंद्र सारस्वत,** हनुमानगढ़

समाज में जागरूकता लाई जाए

दहेज हमारे समाज की एक गहरी कुरीति है। शादी एक पवित्र संस्कार है। इस दौरान दहेज की मांग करना अनुचित कृत्य है। इस कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता लाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि इसे समूल नष्ट किया जा सके। साथ ही लड़की के माता-पिता को भी दृढ़ता से निर्णय लेना होगा कि वे अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करेंगे जहां दहेज की मांग हो। **- रंजू अजमेरा,** सूरत

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/1C05E

आज का सवाल

स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?
ईमेल करें: edit@epatrika.com

दृष्टिकोण आज आवश्यकता है तकनीक के साथ विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखने की

तकनीक का ट्रिगर : बढ़ रहा किशोर मन का असंतुलन

डॉ. सुरभि गोयल
चिकित्सा विशेषज्ञ
@patrika.com

एक समय था जब गुस्सा भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र माना जाता था, लेकिन आज यह सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संकट बनता जा रहा है- विशेष रूप से किशोरों व युवाओं के बीच। तेजी से बढ़ रही इंटरनेट की आदत और स्मार्टफोन की लत ने जहां एक ओर सूचनाओं और जुड़ाव के नए रास्ते खोले हैं, वहीं दूसरी ओर यह गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता जैसे लक्षणों का भी कारण बन रहा है।

अमरीका की ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, जो बच्चे 12 वर्ष से पहले स्मार्टफोन के सम्पर्क में आए। उनमें 38% में अचानक गुस्से या आक्रामकता, 49% में सामाजिक अलगाव व अकेलापन और 17% में भ्रम जैसे लक्षण पाए गए। बेंगलूरु स्थित निम्हांस की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि कई किशोरों को इंटरनेट स्लो होने पर अत्यधिक गुस्सा आता है- कुछ माता-पिता पर चिल्लाते हैं, सामान फेंकते हैं, दोस्तों से लड़ते हैं या स्वयं को नुकसान पहुंचाने तक का व्यवहार करते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे 'डिजिटल विड्रॉल सिंड्रोम' कहते हैं, जिसमें दिमाग डोपामिन (खुशी देने वाला केमिकल) की आदत डाल लेता है। जब आप कुछ आनंददायक करते हैं, तो मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है, जिससे अच्छा महसूस होता है और आप उस गतिविधि को दोहराना चाहते हैं। उसमें थोड़ी रुकावट से ही असहजता व क्रोध उत्पन्न होता है।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं में तुलनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। हर किसी की जिंदगी 'परफेक्ट' लगती है, सिवाय अपनी। ऐसे में खुद को कमतर महसूस करना, डिप्रेशन और अंततः गुस्से में प्रतिक्रिया देना आम हो जाता है।

यह गुस्सा केवल ऑनलाइन नहीं रुकता- यह घरों में, स्कूलों में और सड़कों पर उतर आता है। गुस्सा स्वाभाविक भाव है, लेकिन जब यह बेकाबू और ट्रिगर बेस्ड हो जाए तो खतरनाक बन जाता है। आज का युवा हर सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है, गहराई से सोचने की आदत कम हो गई है। साथ ही, ऑनलाइन 'इको चैम्बर्स' केवल उन्हीं विचारों को दोहराते हैं, जो व्यक्ति पहले से मानता है, जिससे असहमत विचारों के प्रति असहिष्णुता और गुस्सा पैदा होता है।

38% बच्चों में अचानक गुस्से या आक्रामकता, 49% में सामाजिक अलगाव और अकेलेपन के लक्षण पाए गए। (ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के अनुसार)

सोशल मीडिया और गेमिंग बच्चों को ऐसा मंच देते हैं जहां वे खुद को 'महसूस' कर सकते हैं- भले ही वह अनुभव हिंसात्मक या नकली ही क्यों न हो। उनको 'वेलिडेशन' की तलाश रहती है, जो सिर्फ अपने दोस्तों या सोशल मीडिया के 'लाइक्स' में मिलता है। विशेषकर 6-12 वर्ष की उम्र में अगर बच्चों को नियमित रूप से माता-पिता से बातचीत, निर्देश और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो व्यावहारिक परेशानियां पनपने लगती हैं। आज के युवा का गुस्सा केवल इंटरनेट का प्रभाव नहीं है, बल्कि बचपन में हुए छोटे-छोटे सम्पर्कविहीन क्षणों का जमा हुआ दबाव भी है। जब घर एक भावनात्मक ढांचा बनने के बजाय वाई-फाई जोन बन जाए तो उस घर में पल रहे बच्चे अपने गुस्से की भाषा स्क्रीन से सीखने लगते हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमें केवल तकनीकी उपायों की नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा की जरूरत है। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और इमोशनल इंटेलिजेंस पर कार्यक्रम होने चाहिए। माता-पिता को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें। स्क्रीन टाइम तो सीमित होना ही चाहिए साथ ही बच्चों को आउटडोर गेम्स में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

यदि हमें अपने किशोरों व युवाओं को बेहतर मानसिक भविष्य देना है, तो हमें आज ही उनके डिजिटल व्यवहार पर ध्यान देना होगा। इंटरनेट उन्हें जोड़ सकता है, लेकिन वही उन्हें तोड़ भी सकता है। आज की आवश्यकता है तकनीक के साथ विवेकपूर्ण संतुलन की- जहां जुड़ाव हो, लेकिन नियंत्रण के साथ।

प्रेरणा

मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे, तो दूसरा गढ़े। - अटल बिहारी वाजपेयी

संपादकीय

हमें ब्राजील की तरह कृषि को ताकत बनाना होगा

भारत और ब्राजील ट्रम्प के अकारण आक्रोश के दो सबसे बड़े शिकार हैं, जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। ब्राजील पर तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी कृषि का कुल निर्यात में हिस्सा लगभग 50% है और उसके कृषि उत्पाद मुख्यतः चीन और ईयू जाते हैं। दरअसल ब्राजील ने कृषि को अपनी ताकत बना लिया है। कृषि क्षेत्र में मात्र 8% लोग हैं और जीडीपी में योगदान भी 8-9% है। इसका सीधा मतलब हुआ कि कृषि और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण संगठित और मैकेनाइज्ड है। यह देश दुनिया में कृषि निर्यातक देशों में सबसे आगे है। यह सच है कि भारत से लगभग तीन गुना भूभाग वाले इस क्षेत्र में बड़ा इलाका जंगलों का है, लेकिन समुन्नत कृषि के कारण इसकी प्रति-व्यक्ति आय भी भारत से चार गुना अधिक है। ट्रम्प के टैरिफ आक्रोश को जिन दो देशों ने सबसे ज्यादा हिकारत से खारिज किया है- वे हैं चीन और ब्राजील। चीन इसलिए कि उसके रेयर अर्थ की सप्लाई रोकने से अमेरिकी उद्योग ठप हो जाएगा, जबकि ब्राजील इसलिए कि उसके कृषि उत्पाद न लेने से उसे नहीं स्वयं अमेरिका को नुकसान होगा। यह सच है कि टेक-सेवा निर्यात में भारत ब्राजील से आगे है, लेकिन कृषि में भारत के 65% लोगों का लगना उनकी प्रति व्यक्ति आय को सीमित कर रहा है। जहां ब्राजील के 2.50 करोड़ लोग कृषि व संबंधित उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाकर जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, वहीं भारत के किसान वैल्यू-एडिशन (गेहूं की जगह आटा, मैदा और सूजी बेचना) नहीं कर पाते हैं।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

प्रशंसा करते व सुनते समय विवेक का प्रयोग करिए

कभी-कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर हमारे पास ही होता है, लेकिन हम पूछते दूसरों से हैं, क्योंकि विवेक की कमी है। गणेश चतुर्थी के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम विवेक को जगाए रखेंगे। सरस्वती जी बुद्धि की देवता हैं और गणेश जी विवेक के। यदि विवेक का सहारा न मिला तो बुद्धि का पतन हो जाएगा। और इसीलिए आज बड़े से बड़े बुद्धिमान गलत काम करते हुए दिखते हैं। जैसे प्रशंसा करते समय और प्रशंसा सुनते समय विवेक का प्रयोग करिए। किसी की प्रशंसा करें तो उसमें सत्य पूरी तरह से बना रहे। उनकी सादगी का उदाहरण दें। केवल परिणाम पर ना टिकें, उस तरीके पर अधिक बोलें, जो उन्होंने अपनाया है। उन्होंने जिस संघर्ष और सम्बल से काम किया हो, हमारे प्रशंसा के शब्द उसको स्पर्श करें। और जब प्रशंसा ले रहे हों, तब भी अत्यधिक सावधानी रखें। इसे संस्कार मान ग्रहण करिए। हो सकता है सामने वाला चापलूसी कर रहा हो या कोई षड्यंत्र अपना रहा हो तो आप उसके सकारात्मक पहलू को निकाल लें। क्योंकि प्रशंसा यदि ठीक से पचाई नहीं गई तो सद्‌पुरुष का भी पतन हो जाता है।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

युवाओं को मूल्यों का महत्व सिखाएं

टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इनके अति प्रयोग से युवाओं में धैर्य, संवेदनशीलता और आपसी सम्मान जैसे मूल्य धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। नैतिक मूल्य सफलता और संतुलित जीवन की नींव हैं। ऐसे में जरूरत है कि परिवार और शिक्षा प्रणाली मिलकर युवाओं को संतुलित डिजिटल उपयोग और संस्कारों का महत्व सिखाएं। तभी तकनीक साधन बन सकेगी।
-श्वेता जैन, अलवर, राजस्थान

अंधविश्वास कब तक?

आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि पांढुर्ना के गोटमार मेले को सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं कर पा रहा है? इस मेले में हर साल सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। कई लोग असमय काल-कवलित हो जाते हैं। आज हम विकसित चेतना के जिस युग में जी रहे हैं, उसके समक्ष ऐसे जानलेवा अंधविश्वासों का अस्तित्व बेहद शर्मनाक है। -शरद कुमार श्रीवास्तव, गोटेगांव, मध्यप्रदेश

युद्धस्तर पर हो सड़कों में सुधार

दुर्घटना की खबरें आए दिन अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। अधिकांश मामलों में घायलों या मृतकों की कोई गलती नहीं होती। अंतरिक्ष तक की सवारी सुरक्षित हो गई है, लेकिन हमारी सड़कें भगवान भरोसे हैं। सड़कों की मरम्मत, वाहनों के अनुरूप सड़कों के चौड़ीकरण, खराब वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है। अन्यथा ऐसा लगता रहेगा, मानो सड़क पर यमराज का भैंसा दौड़ते हुए आ रहा है।
-मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

बैंक नोट नहीं बदल रहे हैं

पिछले दिनों दैनिक भास्कर ने खुलासा किया कि नोटों में भारी संक्रमण पाया गया। इन पुराने नोटों को चलन से बाहर करके नए नोटों में बदलना चाहिए। रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों में फटे-पुराने नोट लाओ और नए ले जाओ। लेकिन निमाड़ क्षेत्र के बैंकों ने रिजर्व बैंक नियमों को ताक पर रख दिया है। बैंक वाले नोट बदलने से मना करते हैं। क्योंकि निमाड़ के आदिवासी, ग्रामीण रिजर्व बैंक के नियमों से अनजान हैं। -विक्रम चौधरी, ईमेल पर प्राप्त

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

ब्रह्मांड के परमाणुओं से भी ज्यादा चालें सम्भव हैं चेस में

शतरंज यों तो चंद मोहरों के साथ खेला जाने वाला खेल है। लेकिन इन मोहरों से चेस बोर्ड पर संभावित वैध-अवैध चालों और स्थितियों की अनुमानित संख्या 10 की घात 120 के बराबर हो सकती है, यानी दस के बाद 120 शून्य लगाने पर आने वाली संख्या। यह ब्रह्मांड में परमाणुओं की अनुमानित संख्या 10 की घात 80 से अधिक है। प्रसिद्ध गणितज्ञ क्लॉड शैनन ने इसका अनुमान लगाया था, इसलिए इसे शैनन संख्या भी कहते हैं।

269 चालें अब तक के सबसे लंबे शतरंज के खेल में चली गई थीं। यह मैच 1989 में विश्व जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में हुआ था।

बामुलाहिज़ा • ट्रम्प ने जो अफरा-तफरी मचाई है, वह व्यवहार-कुशलता से ही दूर की जा सकेगी

यूरोप से जरूरी सबक सीख सकते हैं हम

कूटनीति

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X @ShekharGupta

एक पल के लिए उस तस्वीर पर गौर कीजिए, जिसे कई पीढ़ियों तक याद किया जाता रहेगा : जेलेंस्की समेत यूरोपीय संघ के बड़े नेता 'शाही हेडमास्टर' ट्रम्प के सामने माफी मांगते हुए स्कूली बच्चों की तरह बैठे हैं! उसे देखकर सबसे पहले आपके अंदर कौन-सी भावना उभरती है? सहानुभूति की या मनोरंजन की या दया की या नई उभरती विश्व-व्यवस्था के एहसास की? वैसे, पूरी संभावना यह है कि सहानुभूति को छोड़ इस सबका मिला-जुला एहसास ही मन में उभरेगा और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ट्रम्प के सताए हुए हैं।

हम देख सकते हैं कि कम-से-कम एक नेता तो ऐसा है, जिसके मन में इस तरह का कोई भावनात्मक घालमेल नहीं है। पुतिन इस सबको खालिस हिकारत की नजर से देखते हैं। जबकि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश; सबसे बड़ी तीसरी और छठी अर्थव्यवस्थाएं, दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक खेमा (ईयू); परमाणु हथियारों से लैस दो पी5 देश, सबके सब घुटने टेके नजर आए। वे सब ट्रम्प के दरबारी बने नजर आए, जबकि पुतिन इस खेमे को कमजोर करने में लगे हैं। पुतिन इसे इस बात की स्वीकृति के रूप में देखते हैं कि युद्ध उन्होंने जीता है। जीत को परिभाषित करना उन पर निर्भर है। यूरोपीय लोग इसे उलटे रूप में देखते हैं, जिन्हें अब इसे एक बुरी हार के रूप में देखने की जरूरत नहीं।

पुतिन को अब पता चल गया है कि उन्होंने 2022 में जो आक्रमण शुरू किया था, सिर्फ उसमें कब्जाए गए इलाके ही नहीं, बल्कि क्रीमिया और डोनबास भी उनके अपने हैं। यह यूक्रेन के विशाल भूभाग के करीब 20 फीसदी के बराबर है। इसके अलावा, पूरब की ओर 'नाटो' का विस्तार अब इतिहास की बात हो गई है। ट्रम्प यह अकसर कह चुके हैं। हमें यह तो मालूम है कि वे अपना दिमाग बदलते रहते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि वे अचानक यूक्रेन और यूरोप की सपनीली मांगों का समर्थन करने लगेंगे, जिनमें पुतिन की हार शामिल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे क्या रियायत कर सकते हैं। पुतिन उसे कबूल करके और ज्यादा के लिए वार्ता कर सकते हैं।

रूस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उसने हमला जारी रखा है, चाहे प्रगति कितनी ही धीमी और खर्चीली क्यों न हो। अगर इस मुकाम पर शांति कायम होती है तो पुतिन अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। वे अपनी विजय घोषणा क्रीमिया या मारीउपोल से कर सकते हैं। शांति बहाल होने के बाद आर्थिक प्रतिबंध भी हट जाएंगे। तब वे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने में लग जाएंगे। उनका वजन इस बात से बढ़ा है कि उन्होंने ट्रम्प को यह विश्वास दिला दिया है कि वे लड़ना जारी रख सकते हैं, चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े।

यूक्रेन को अर्ध-सम्प्रभु देश में बदलने की पुतिन की बड़ी मांग- जिसमें सरकार उनकी पसंद की हो- अगर खारिज कर दी गई है तो इसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने अविश्वसनीय बहादुरी और चुस्ती से लड़ाई लड़ी। पश्चिमी मित्र देशों और अमेरिका ने संसाधनों से बेशक उसकी मदद की, लेकिन यूक्रेनियों ने एक सम्प्रभु देश के रूप में अपना वजूद इतनी लंबी लड़ाई लड़ कर और पुतिन के रूस जैसे कठोर देश से उतनी कीमत वसूल करके बचाया है, जिसे वही बर्दाश्त कर सकता था।

उन्होंने दुनिया को ड्रोन के बूते दूर जाकर ऐसे पैमाने पर युद्ध लड़ना भी सिखाया है, जिससे मोसाद को भी ईर्ष्या हो सकती है। मात्र 3.5 करोड़ की छोटी-सी आबादी के (जिसका करीब 20 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह रहा है) अनुपात से हताहतों की भारी संख्या को उसने बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किया है। उन्होंने रूसियों को कहीं बड़ी संख्या में अपने सैनिक गंवाने पर मजबूर किया है और उनकी अर्थव्यवस्था तथा सैन्य तंत्र को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन को दो वजहों से बेहतर नतीजे नहीं हासिल हुए। पहली यह कि उसके यूरोपीय सहयोगी सैन्य या आर्थिक मोर्चे पर कोई नुकसान सहने को राजी नहीं हुए और दूसरी यह कि ट्रम्प सत्ता में वापस आ गए।

खेमेबाजी से बचें, पश्चिम-विरोध का भविष्य नहीं है...

यूरोप भावना में बहकर नहीं बल्कि हकीकत के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत के लिए सबक ये हैं कि सेना को मजबूत बनाइए। रूस से रिश्ता मजबूत कीजिए, लेकिन किसी खेमेबंदी में पड़ने से बचिए। लोकतांत्रिक भारत का भविष्य पश्चिम-विरोध में नहीं है।

इतना स्पष्ट करने के बाद हम ट्रम्प के ओवल ऑफिस की उस ऐतिहासिक तस्वीर की ओर लौटते हैं। यूरोप ने खुद को एक विशाल गुलाम-क्षेत्र में कैसे तब्दील कर लिया, इस पर कई किताबें लिखी जाएंगी। यूरोप अपनी राजी-खुशी से ट्रम्प के नव-साम्राज्यवाद का पहला शिकार बना, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोप भावना में बहकर नहीं बल्कि हकीकत के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा है। इसलिए भारत के लिए सबक ये हैं कि अपनी सेना को मजबूत बनाइए और इसके लिए उपयुक्त उपमा यही होगी कि यह युद्धस्तर पर कीजिए। अभी से शुरुआत की जानी चाहिए। रूस के साथ रिश्ता और मजबूत कीजिए, लेकिन किसी खेमेबंदी में पड़ने से बचिए। लोकतांत्रिक भारत का भविष्य पश्चिम-विरोध में नहीं है। चीन के मामले में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है उसमें स्थिरता बनाए रखिए और दोनों पक्षों को उस दिशा में बढ़ने दीजिए जिससे उनके साझा हित पूरे होते हों। याद रहे, चीन को अभी हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपना ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित कीजिए।

अपने पड़ोस को शांत रखिए। भारत को सभी मोर्चों पर दुश्मनी में नहीं उलझना चाहिए। पाकिस्तान का मामला अलग है, लेकिन हर एक पड़ोसी के साथ रिश्ते में घरेलू राजनीति की घालमेल करने से बचिए। इससे आपके विकल्प सीमित होते हैं। अपना वक्त चुनिए और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते में कुछ समझदारी लाने की कोशिश कीजिए। भरोसा पैदा करना मुश्किल हो सकता है। याद रहे, शीतयुद्ध वापस नहीं आने वाला और अमेरिका/पश्चिम विरोधी खेमा उभरने वाला नहीं है। यूक्रेन में अमन कायम होते ही पुतिन और ट्रम्प फिर दोस्त बन जाएंगे। अमेरिका और चीन तो सौदे करने में व्यस्त हो ही गए हैं। यूरोप से सीखिए। ट्रम्प के कारण जो अफरा-तफरी मची है वह व्यवहार-कुशलता के बूते ही दूर की जा सकेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • अमेरिका से स्थायी जुड़ाव पर जोर देना होगा

रातोंरात बनती या बिगड़ती नहीं हैं रणनीतिक साझेदारियां

देश-दुनिया

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन
कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

हाल ही में अपने एक लेख में निक्की हेली ने रिपब्लिकन खेमे के भीतर भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर स्पष्ट आकलन पेश किया। भारत को एक 'मूल्यवान साझेदार' बताते हुए उन्होंने चेताया कि उसे अपने से दूर करना अमेरिका के लिए 'रणनीतिक हादसा' होगा। चीन के प्रति अमेरिका के नरम रवैए से तुलना करते हुए हेली ने भारत पर लगाए टैरिफ की आलोचना की है। उनका दखल महज इसीलिए मायने नहीं रखता कि वे भारतवंशी हैं, बल्कि यह संकेत देता है कि अमेरिका के नीति निर्माता प्रतिष्ठानों में अब भी भारतीय मूल्यों के प्रति यथार्थवादी समझ बची है।

हाल के महीनों में जिस तेजी से भारत-अमेरिका संबंध बिगड़े हैं, वह चिंताजनक है। अमेरिकी नीति में एकाएक बदलाव, विरोधाभासी संकेतों और नौकरशाही की अधीरता के कारण दशकों से बना भरोसा टूटता दिख रहा है। लेकिन हमें इस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। क्योंकि रणनीतिक साझेदारियां रातोंरात नहीं बनतीं, और न ही रातोंरात इन्हें तोड़ा जाना चाहिए।

1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों के बावजूद 2000 के दशक की शुरुआत में भारत-अमेरिका संबंधों में बदलाव शुरू हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने पुरानी शंकाओं को दरकिनार कर भारत के साथ नए सिरे से काम करने का फैसला किया था। चीन की महत्वाकांक्षाएं तब दिखने लग गई थीं। एशिया में दबदबा बनाने की उसकी कोशिशों ने अमेरिका को परेशान करना शुरू कर दिया था। 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की लंबी लड़ाई को अमेरिकी सहानुभूति मिली। दोनों देशों में नया भावनात्मक जुड़ाव हुआ।

2005 में, भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रैंड कॉर्पोरेशन में एक भाषण के दौरान कहा था कि भारत अमेरिका के साथ गहरी साझेदारी के लिए तैयार है। लगभग इसी वक्त, अमेरिकी विद्वान स्टीफन ब्लैंक ने लिखा कि भारत अब 'स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षित साझेदार' बना गया है। तब बनी साझेदारी आपसी हितों पर आधारित थी। यही अगले दो दशक तक मार्गदर्शक-सिद्धांत बना रहा। परमाणु समझौता हुआ। रक्षा समझौते हुए। संयुक्त सैन्य अभ्यासों में तेजी आई। क्वाड बना। रक्षा जरूरतों पर समान दृष्टिकोण से यह सब संभव हुआ। जब तक चीन प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी बना रहा, भारत अमेरिका का अपरिहार्य साझेदार था।

लेकिन बाइडेन काल में शंकाएं पैदा हुईं। सितंबर, 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एफ-16 बेड़े के लिए 450 मिलियन डॉलर के रखरखाव पैकेज को मंजूरी देकर नए सुरक्षा गठजोड़ के संकेत दिए। बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में भी अमेरिकी भूमिका सभी ने देखी। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीद एक और विवादित मसला बन गई है, भले ही भारत महज अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के तहत ऐसा कर रहा था। अमेरिका ने शुरू में इसे सहन किया। भारत की एस-400 मिसाइलों की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाए, लेकिन अमेरिकी नौकरशाही चिढ़ने लगी थी। हालिया टैरिफ और प्रतिबंध भारत को यही याद दिलाने के लिए हैं कि उसकी स्वायत्तता सीमित है।

चीन के प्रति अमेरिकी नीति उसकी बढ़ती ताकत और रूस से उसके तालमेल को रोकने की रही है। तो भारत को क्यों ऐसे हाशिए पर धकेला जा रहा है, जिससे यह तालमेल मजबूत हो? क्यों फिर से पाकिस्तान को खुश किया जा रहा है?

चीन के प्रति अमेरिकी नीति उसकी बढ़ती ताकत और रूस से उसके तालमेल को रोकने की रही है। तो भारत को क्यों ऐसे हाशिए पर धकेला जा रहा है, जिससे यह तालमेल मजबूत हो? क्यों पाकिस्तान को खुश किया जा रहा है? ये विरोधाभास खतरनाक हैं। इससे आपसी भरोसा कमजोर हो रहा है। ऐसे में भारत को धैर्यपूर्वक पर मजबूती से जवाब देना चाहिए। तीखी प्रतिक्रिया के बजाय अमेरिका से स्थायी जुड़ाव पर जोर देना चाहिए। उसे साफ करना चाहिए कि रूस से उसका व्यापार चीन की व्यापक चुनौतियों पर अमेरिका से उसके तालमेल को कमजोर नहीं करता। साथ ही भारत को चीन से भी अपने रिश्तों को स्थिर करना चाहिए। विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे समांतर ट्रैक के तौर पर, जहां जरूरत पड़ने पर राह बदलने की गुंजाइश हो। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • कई तरह से सामने आता है वर्चस्ववाद

पूर्वग्रहों से मुक्त वैकल्पिक नक्शों की खोज जरूरी है

देशकाल

प्रियदर्शन
लेखक और पत्रकार
priyadarshan.parag@gmail.com

वर्चस्ववाद के रूप बड़े सूक्ष्म होते हैं। कई बार वे अवचेतन में इतने धंसे होते हैं कि लोगों को पता तक नहीं चलता वे किसी वर्चस्ववादी प्रवृत्ति के शिकार हैं। इसकी एक मिसाल दुनिया का बनाया वह नक्शा है, जिस पर अब अफ्रीका के मुल्कों को ऐतराज हो रहा है।

यह नक्शा 16वीं सदी में गेरार्डस मेर्काटर नाम के एक नक्शानवीस ने बनाया था। दुनिया का नक्शा बनाना आसान काम नहीं है- खासकर तब जब इस गोल धरती को आयताकार शक्ल देनी हो। लेकिन मेर्टाकर ने मेहनत से यह काम किया और मोटे तौर पर वही नक्शा इस सदी तक चला आया है। लेकिन अब पता चल रहा है कि इस नक्शे में अफ्रीका को छोटा और दबा हुआ दिखाया गया है, जबकि यूरोप को अपने आकार से बड़ा दिखाया है। मेकार्टर की अपनी मुश्किलें थीं, जिनको हल करने की कोशिश में उसने एक सपाट रास्ता खोजा। तब यूरोप का साम्राज्यवादी विस्तार शुरू नहीं हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे इस नक्शे को मिली मान्यता के पीछे अवचेतन में बसा यूरोप का बड़ा होता कद भी रहा हो तो हैरानी की बात नहीं।

लेकिन अब अफ्रीकी देश जाग रहे हैं। उनका कहना है इस नक्शे को बदलना होगा। 'अफ्रीका नो फिल्टर' और 'स्पीक-अप अफ्रीका' जैसे संगठनों ने एक मुहिम चलाई है- 'करेक्ट द मैप'- जिसे अफ्रीकी यूनियन भी समर्थन दे रही है। उनके लिए ये वास्तविक पहचान का मामला है। उनका कहना है नक्शे में हेरफेर की वजह अफ्रीका के प्रति पूर्वग्रह और यूरोप की श्रेष्ठता ग्रंथि है। नक्शे में जितना अफ्रीका दिखता है, उसके मुकाबले वास्तविक अफ्रीका तीन गुना बड़ा है, जबकि जो यूरोप दिखता है, वह असल में तीन गुना छोटा है। उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड भी अनुपात से बड़े हैं।

इसके पीछे यह मानसिकता है कि अफ्रीका हाशिए पर पड़ा महादेश है, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें 54 देश हैं और दुनिया की एक अरब से ज्यादा आबादी बसती है। नक्शे में संशोधन की इस मुहिम ने इसलिए भी जोर पकड़ा है कि अब दुनिया के सामने एक वैकल्पिक नक्शा सुलभ है, जिसमें देशों और महादेशों को उचित अनुपात के साथ प्रतिनिधित्व मिला है। यह 2018 में तैयार किया गया इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन है, जिसे हर जगह इस्तेमाल करने की मांग हो रही है।

लेकिन यह टिप्पणी नक्शों के बारे में नहीं, उन पूर्वग्रहों के बारे में है, जो हम सरलीकृत धारणाओं के आधार पर बना लेते हैं। इनमें लैंगिक पूर्वग्रह भी होते हैं- जैसे मर्द मजबूत होते हैं, औरतें कमजोर। नागरिक पूर्वग्रह भी होते हैं- जैसे शहर सभ्य होते हैं, गांव गंवार। कुछ शैक्षणिक पूर्वग्रह भी होते हैं- जैसे पढ़े-लिखे लोग योग्य होते हैं, अनपढ़ अयोग्य। कुछ पूर्वग्रह देशों और महादेशों को लेकर भी होते हैं, जिसका प्रमाण इस नक्शा प्रकरण से मिलता है। पर ये पूर्वग्रह बनते कैसे हैं? जाहिर है, इन्हें वर्चस्वशाली तबके ही बनाते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भारतीय समाज भी ऐसे पूर्वग्रहों से पटा पड़ा है- हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारी बोली श्रेष्ठ, हमारी जाति श्रेष्ठ- जैसे पूर्वग्रह आक्रामक ढंग से सामने आ रहे हैं- उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है- बल्कि उन्हीं के दम पर राजनीति की जा रही है।

अब दुनिया के सामने एक वैकल्पिक नक्शा सुलभ है, जिसमें देशों और महादेशों को उचित अनुपात के साथ प्रतिनिधित्व मिला है। यह इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन है, जिसे हर जगह इस्तेमाल करने की मांग हो रही है।

ध्यान से देखें तो दुनिया में देश और महादेश जितने वास्तविक और स्थायी दिखते हैं, उतने वे हैं नहीं। सारी रेखाएं काल्पनिक हैं और मनुष्यों द्वारा खींची हैं। कुंवर नारायण की एक कहानी है, जिसमें दो देशों के बीच की सीमारेखा गायब हो जाती है। अब सब परेशान हैं कि रेखा कहां गई। उनके लिए सारी दुनिया उलट-पुलट गई है। नेता-अफसर-सिपाही सब सीमा रेखा की तलाश में लगे हैं। कहानी के अंत में बस बच्चे सीमारेखाओं के गुम होने से बेखबर और खुश खेल रहे हैं।

नक्शे हों, सीमारेखाएं हों, धारणाएं हों- उनमें हमारे पूर्वग्रह झांकते हैं, वर्चस्ववाद चला आता है। कोशिश करें हम इनसे मुक्त हों, इन्हें अटल और अंतिम सत्य न मानें, समझें कि उन्हें बदला जा सकता है, बदला जाना चाहिए। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

सरोकार • 2003 से 2023 के बीच भारत में 24,651 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन-क्षेत्र का नाश हुआ है

विकास की बढ़ती गति से संघर्ष में जंगल लगातार हारते जा रहे हैं

वन-जीवन

मोहन चंद्र परगाई
पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी
mcpargaien@gmail.com

आज भारत जलवायु परिवर्तन सहित बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों से ग्रस्त है। इसके फलस्वरूप यहां पर्यावरणीय जागरूकता भी बढ़ रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रैमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और बॉन चुनौती के तहत अपना फॉरेस्ट-कवर बढ़ाने और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, भारत के कुल वन और फॉरेस्ट-कवर 2021 की तुलना में 1,445 वर्ग किमी बढ़ा है। इसमें वन-आवरण (फॉरेस्ट-कवर) की 156 वर्ग किमी की वृद्धि में से 149 वर्ग किमी की वृद्धि अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर हुई है। दूसरी ओर वृक्ष आवरण (ट्री-कवर) में 1,289 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, जो कुल वृद्धि का 89% है। वन बाह्य वृक्ष (टीओएफ) अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर के पेड़ हैं, जिनमें छोटे वन, मानव द्वारा वृक्षारोपण, सड़कों, पार्कों, घरों और कृषि भूमि पर स्थित पेड़ शामिल हैं। ये निजी, सामुदायिक या सरकारी भूमि पर हो सकते हैं। वृक्ष आवरण, वन बाह्य वृक्ष का हिस्सा होने के नाते वन आवरण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मौजूदा रिपोर्ट जहां एक ओर वन बाह्य वृक्षों की बढ़त का शुभ संकेत देती है, वहीं दूसरी ओर वन आवरण और मुख्यतः अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर मात्र 7 वर्ग किमी की अल्प वृद्धि को ही दर्शाती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) की रिपोर्ट ने भारत में 2019-20 से 2023-24 के बीच 1,78,261 हेक्टेयर पूर्तिकर वनीकरण (कर्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन) की पुष्टि की है। इन आंकड़ों को अगर हम 50% सर्वाइवल (उत्तरजीविता) लेकर भी वन क्षेत्र की बढ़ोतरी से जोड़ें तो इनके द्वारा कम से कम 800 वर्ग किमी के वन आवरण की वृद्धि होनी चाहिए, जो कि नहीं है और यही बड़ी चिंता का विषय है।

विगत दो वर्षों में निर्मित इस परिस्थिति के पीछे की दशा और अवस्थाओं का अध्ययन करने पर बहुआयामी चुनौतियां और समस्याएं मुंह बाए खड़ी दिखती हैं और मौजूदा वनों पर अनवरत पड़ने वाले दबाव और जमीनी समस्याएं वनीकरण के सारे प्रयासों पर पानी फेर रही हैं। इसके साथ-साथ बढ़ती गरीबी, जनसंख्या का दबाव, राजनीतिक समझौतों और वैज्ञानिक प्रबंधन की कमी इन चुनौतियों को और भी जटिल बना रही है, जिनके कारण वन क्षेत्रों का वांछनीय विकास और वृद्धि प्रभावित हुई है।

भारत के वनों की चुनौतियां गंभीर और बहुआयामी हैं। विकास की योजनाओं और कृषि विस्तार के लिए वनों की कटाई और अतिक्रमण से वन क्षेत्र निरंतर घट रहे हैं। वर्ष 2003-2023 के बीच 24,651 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र के नाश में 17,500 वर्ग किमी वन क्षेत्र का नाश तो 2013-2023 के दशक में हुआ। इसमें अतिक्रमण और कटाई की बड़ी भूमिका रही। वहीं पिछले डेढ़ दशक में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का उपयोग गैर-वन कार्यों के लिए किया गया है। लगभग 25 करोड़ लोगों की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर आजीविका के लिए निर्भरता से और 75% वनों पर चराई का प्रभाव पड़ा है। इससे उनका पुनर्स्थापन भी मुश्किल होता जा रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और लंबे शुष्क मौसम ने 2023-24 में लगभग 34,562 वर्ग किमी वन क्षेत्र को आगजनी से नुकसान पहुंचा है। वन-रोपण के लिए धन की कमी सभी राज्यों में एक बड़ी समस्या रही है, और जिन राज्यों के पास पैसा है भी, वह उसके कम उपयोग या दुरुपयोग जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी निगरानी भी प्रभावशाली नहीं पाई गई है। अतिक्रमण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की गतिविधियां वन्य जीवों- विशेषकर हाथी एवं बाघ के कॉरिडोर- को संकुचित करते हुए उनकी संख्या को प्रभावित कर रही है और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को बढ़ा रही है। जंगलों के संरक्षण और विकास में आदिवासी और ग्राम समुदायों की भूमिका को वन अधिकार अधिनियम 2006 और संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से बढ़ावा तो मिला है, परंतु प्रशासनिक चुनौतियों और अधिकारों की अनदेखी के कारण स्थानीय सहभागिता सीमित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 27 अगस्त 2025

फिर एक दहेज हत्या

पितृसत्ता की जीत, मानवता की हार

यह राष्ट्रीय मुद्दा भले ही न हो, लेकिन होना चाहिए। हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भले ही बुलंदियों को छू रहे हों, लेकिन जब बात महिलाओं के सम्मान और उनके प्रति संवेदनशीलता की आती है, तो हम पितृसत्तात्मक मानसिकता और रूढ़िवादी सोच में ही उलझे रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में 26 वर्षीय निक्की की जघन्य हत्या इसका एक उदाहरण है। 36 लाख रुपये के दहेज और अपनी आजादी का दावा करने की हिम्मत दिखाने पर पति और ससुराल वालों द्वारा ज़िंदा जला दी गई निक्की की मौत सिर्फ. एक और अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज के सामने एक आईना है। यह एक कड़वी सच्चाई को दशार्ता है–कि 2025 में भी, वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत में, महिलाओं को घरों में मोलभाव करने के लिए मजबूर किया जाता है।

निक्की की कहानी दर्दनाक लेकिन दुखद रूप से जानी-पहचानी है। एक ऐसे परिवार में विवाहित जहां न तो उसका पति और न ही देवर काम करता था, उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जाता था। स्वतंत्रता का यही कार्य–अपना व्यवसाय चलाना और पितृसत्तात्मक हुक्मों से बंधे रहने से इनकार करना–उसकी क्रूर मौत का एक कारण बन गया।

सबसे बुरी बात यह है कि समाज में पितृसत्ता इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए पति ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। एक समाज के तौर पर हमें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। सिर्फ.

इसलिए नहीं कि एक युवती की ज़िंदगी इतने बर्बर तरीके से खत्म कर दी गई, बल्कि इसलिए भी कि निक्की कोई अकेला मामला नहीं है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल हजारों दहेज हत्याओं की रिपोर्ट करता है, और कलंक, डर या सामाजिक दबाव के कारण उत्पीड़न के अनगिनत मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। हो सकता है कि इसे वह सुर्खियां और कवरेज न मिल रही हो जिसके यह हकदार है, लेकिन दहेज हत्याएं अभी भी बड़े पैमाने पर हो रही हैं और दुर्भाग्य से, इनके प्रति हमारी संवेदनशीलता का अभाव है। हम अभी भी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां परंपराओं और रीति-रिवाजों की आड़ में जबरन वसूली और घरेलू हिंसा को सामान्य माना जाता है। विवाह, आपसी सहयोग की साझेदारी होने के बजाय, अक्सर एक लेन-देन के रूप में देखा जाता है। पितृसत्ता तब फलती-फूलती है जब महिलाओं की स्वायत्तता को–चाहे वह ब्यूटी पार्लर खोलने में हो या अपनी शर्तों पर जीने में–एक खतरे के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा लैंगिक समानता का है।

दहेज के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ, महिलाओं के संपत्ति और वित्तीय अधिकारों के लिए–कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन कमजोर है, और सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिगामी बना हुआ है। समानता केवल कानून द्वारा नहीं बनाई जा सकती; इसे एक सामाजिक नैतिकता के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, परिवारों में सुदृढ़ किया जाना चाहिए, और कार्यस्थलों पर इसकी मांग की जानी चाहिए। और नागरिकों के रूप में, हमें अपनी आत्मसंतुष्टि त्यागनी होगी–ऐसे अपराधों को घरेलू मामले कहकर नजरअंदाज करना बंद करना होगा और इसके बजाय उन्हें उनके वास्तविक रूप में पहचानना होगाः व्यवस्थागत स्त्री-द्वेष में निहित हत्या के कृत्य।

आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता

अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करना भारत के इस रुख को पुष्ट करता है कि शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं रह सकते। साथ ही यह आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त वैश्विक मोर्चा बनाने में अमेरिका-भारत के बढ़ते सहयोग को भी रेखांकित करता है।

सुधीर हिन्दवान
लेखक, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक प्रतिनिधि, रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करने और इसे विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में नामित करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया फैसले ने न केवल आतंकवाद पर भारत की शून्य-सहिष्णुता की नीति को सही ठहराया है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी साझा लड़ाई में भारत और अमेरिका को और करीब भी लाया है।

भारत लंबे समय से आतंकवाद का मुकाबला करने में वैश्विक प्रयासों का समन्वय करने की मांग करता रहा है, और हाल ही में 2025 के शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में इसके साहसिक रुख ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ इसके अडिग रुख की पुष्टि की है।

भारत का दृढ़ विश्वास स्पष्ट हैः एक ऐसी दुनिया में जो आपस में जुड़ी हुई है और आतंकवाद, हिंसा और उग्रवाद जैसी आम चुनौतियों का सामना कर रही है, सच्चे सहयोग के लिए साझा सिद्धांतों, आपसी सम्मान और अटूट मूल्यों की आवश्यकता होती है।

ऐसे समय में जब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय संघर्ष और युद्ध छिड़े हुए हैं, पड़ोसी क्षेत्रों के आतंकवादी समूह कश्मीर में अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता में बेचैनी बढ़ रही है और आतंकवादी गुर्गों के गिरते मनोबल की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित हो रहा है।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए और कई अन्य घायल हुए, हाल की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक है। हाल के वर्षों में घाटी में नागरिकों और सैन्य कर्मियों की निर्मम हत्या आतंकवाद से लड़ने में जारी चुनौतियों को रेखांकित करती है। यह वास्तविकता इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है।

घरेलू स्तर पर, भारत ने एक बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र विकसित किया है जो उन्नत तकनीक और मजबूत खुफि या अभियानों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर आतंकवाद, सीमा पर घुसपैठ और समुद्री खतरों को लक्षित करता है। फिर भी, आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति विकसित करते रहते हैं, जिससे संभावित खतरों का अनुमान लगाने वाली संचार प्रणालियों को विकसित करने और सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने के लिए वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसके लिए विवेक, दूरदर्शिता और दुनिया भर के देशों के सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग के लिए त्वरित तंत्र की आवश्यकता है।

जैविक या रासायनिक हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने की संभावना सहित, सबसे खराब परिस्थितियों के लिए तैयारी हेतु एक साझा रणनीति आवश्यक है। ऐसे हथियारों के कब्जे और उपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून बनाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य है। आतंकवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करने और गुणवत्तापूर्ण सूचना सुनिश्चित करने में सरकारों और मीडिया की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

दुनिया भर में आत्मघाती दस्तों की अचानक बढ़ती संख्या सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनी हुई है, जिसके लिए अत्यधिक सतर्क खुफिया प्रणालियों की आवश्यकता है। जैसे-जैसे धार्मिक रूप से प्रेरित हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए इस पुरानी धारणा को अब त्यागना ही होगा कि एक व्यक्ति के लिए आतंकवादी दूसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानी है।

आधुनिक आतंकवादी समूह अक्सर अपने गुप्त अभियानों के लिए जन समर्थन जुटाने हेतु धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बैटरी चालित विस्फोटक उपकरणों का बढ़ता उपयोग उनकी रणनीति का एक और महत्वपूर्ण घटक बन गया है। इसलिए, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता हैः पूर्व खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवादी नेटवर्क के गुप्त अभियानों का पदार्फाश करना, सटीक जानकारी के साथ दुष्प्रचार का मुकाबला करना, और सुरक्षा, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दैनिक आधार पर घनिष्ठ समन्वय को बढ़ावा देना।

इस उद्देश्य के लिए, चरमपंथी दुष्प्रचार के सामने उनकी प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए सशस्त्र बलों और पुलिस दोनों का समर्थन करने वाले समन्वित कार्यक्रम आवश्यक हैं।

हालाँकि कई देशों ने वित्तीय प्रतिबंधों जैसे उपायों के माध्यम से राज्य प्रायोजित आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने का प्रयास किया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर आम सहमति अभी भी अप्राप्य बनी हुई है। पिछले दो दशकों में, मादक पदार्थों के तस्करों और आतंकवादी समूहों के बीच अपवित्र गठजोड़ ने राज्य सुरक्षा प्रणालियों को और कमजोर कर दिया है, जिससे देशों को इस गठबंधन के खिलाफ निरंतर युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

हालांकि, केवल कड़े कानून ही पर्याप्त नहीं हैं। शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रणालियों में सुधार आवश्यक है। आतंकवादियों की बदलती रणनीति ने राष्ट्रों को लगातार वैकल्पिक रणनीतियाँ तलाशने के लिए मजबूर किया है।

कुछ वर्ष पहले नाटो देशों और जापान द्वारा आयोजित लंदन वित्तीय शिखर सम्मेलन, आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने के तरीकों पर चर्चा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। फिर भी, केवल आतंकवाद के विरुद्ध एक साझा वैश्विक मंच का निर्माण ही स्थायी परिणाम दे सकता है।

दुनिया भर में आत्मघाती दस्तों की अचानक बढ़ती संख्या सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनी हुई है, जिसके लिए अत्यधिक सतर्क खुफिया प्रणालियों की आवश्यकता है। जैसे-जैसे धार्मिक रूप से प्रेरित हमले बढ़ रहे हैं, इस पुरानी धारणा को त्यागना होगा कि एक व्यक्ति का आतंकवादी दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी है।

स्थानीय आबादी को, व्यक्तिगत कीमत पर भी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए, जबकि राष्ट्रों को आतंकवादी नेटवर्क को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने के लिए दृढ़ और तत्काल उपाय अपनाने चाहिए। स्थानीय खुफिया जानकारी को संदर्भ-संवेदनशील सुरक्षा प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए। अंततः, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। राष्ट्रों को इस व्यापक खतरे का सामना करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए, रणनीतियों को संरेखित करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

निरंतर बदलते परिवेश में, सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विशेषज्ञता और दशकों के अनुभव को एकीकृत करके अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र और उन्नत क्षमताओं का निर्माण है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

शिक्षकों पर थकान व अदृश्य तनाव का प्रभाव

जब शिक्षकों को नुकसान होता है, तो छात्रों को अनिवार्य रूप से कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा कि कहावत है, जब माली थक जाता है, तो फूल भी पीड़ित होते हैं। इसका समाधान व्यवस्था को दुरुस्त करने में है, शिक्षकों को सख्त बनाने में नहीं।

साक्षी सेठी
लेखिका, शिक्षाविद हैं।

प्र जब लोग शिक्षक के बर्नआउट के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर मन में एक परेशान शिक्षक की छवि उभरती है जो शोरगुल वाली कक्षाओं और बेचैन छात्रों से जूझ रहा है। लेकिन किसी भी शिक्षक से पूछिए, और वे एक ही बात कहेंगेः छात्र समस्या नहीं हैं। वास्तव में, वे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा हैं। यह किसी बच्चे की आंखों में चमक है जब कोई अवधारणा समझ में आती है, अतिरिक्त मदद के बाद शांत धन्यवाद, या वह हंसी जो सुबह को रोशन करती है और शिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

ये क्षण शायद ही कभी बर्नआउट का कारण बनते हैं। शिक्षकों को जो थका देता है वह बाकी सब है, युवा मस्तिष्कों को पोषित करने से कोसों दूर की ज़िम्मेदारियां। अंतहीन कागजी कार्रवाई, बदलती नीतियाँ और अवास्तविक अपेक्षाएं उन घंटों को खा जाती हैं जिन्हें जिज्ञासा जगाने में बिताया जाना चाहिए। आज शिक्षक स्क्रीन पर उतना ही समय बिताते हैं जितना वे छात्रों के साथ, पाठ अपलोड करने, अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने और निरीक्षण नोट्स पूरा करने में। 2023 के एक यूनेस्को सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में 60 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने गैर-शिक्षण कर्तव्यों को अपना सबसे बड़ा तनाव बताया है।

इसके अलावा, विशाल पाठ्यक्रम, बोर्ड परीक्षा का दबाव और कार्यस्थल की राजनीति, पक्षपात, सूक्ष्म प्रबंधन और अनुचित मूल्यांकन भी हैं। यह नौकरी अक्सर बहुत कम इनाम वाली एक पतली रस्सी पर चलने जैसी लगती है। तकनीक, हालांकि आवश्यक है, एक दोधारी तलवार बन गई है। स्मार्ट क्लासरूम और एआई-संचालित मूल्यांकन नवाचार का वादा करते हैं, लेकिन अक्सर भारी पड़ जाते हैं।

कम प्रशिक्षण के साथ, शिक्षक जटिल प्रणालियों को समझने में संघर्ष करते हैं, जिससे कार्यभार कम होने के बजाय बढ़ जाता है। जैसा कि एक ने कहा, ₹हमसे विमान बनाते समय उसे उड़ाने की उम्मीद की जाती है।₹ शिक्षक कई भूमिकाएँ भी निभाते हैंः परामर्शदाता, मध्यस्थ, यहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्ता भी। वे देखते हैं कि बच्चे भावनात्मक रूप से संघर्ष करते हैं, लेकिन उनसे न्यूनतम संसाधनों के साथ इसे संभालने की उम्मीद की जाती है। महामारी ने इस बोझ को और बढ़ा दिया। रातोंरात, शिक्षक तकनीकी विशेषज्ञ बन गए, अपने परिवारों का प्रबंधन करते हुए पाठ रिकॉर्ड करने और आभासी कक्षाओं के अनुकूल होने लगे। उनका लचीलापन अपार था, फिर भी डॉक्टरों या नर्सों के विपरीत, उनके संघर्षों ने शायद ही कभी सुर्खियां बटोरीं। नीतिगत सुधार, हालाँकि नेक इरादे से किए जाते हैं, अक्सर बिना किसी समर्थन के आते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और नई मूल्यांकन रणनीतियां, जब जल्दबाजी में लागू की जाती हैं, तो दबाव और बढ़ जाता है। मानकीकृत परीक्षणों का जुनून समस्या को और बढ़ा देता है, शिक्षकों को आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के बजाय परीक्षा के लिए पढ़ाने₹ पर मजबूर करता है। प्रबंधन और अभिभावकों से अवास्तविक अपेक्षाएं स्वायत्तता को और कम करती हैं, शिक्षकों को मार्गदर्शक के बजाय डेटा प्रबंधक बना देती हैं। शायद सबसे निराशाजनक बात मान्यता का अभाव है। शिक्षक लंबे समय तक काम करते हैं, कागजों की जांच, पाठ तैयार करना, छात्रों को मार्गदर्शन देना–फिर भी उनका वेतन शायद ही कभी उनके प्रयासों के अनुरूप होता है। व्यावसायिक विकास सीमित है, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता लगभग न के बराबर है।

जैसा कि एक अनुभवी ने संक्षेप में कहाः मैं चालीस छात्रों को संभाल सकता हूँ, लेकिन जो चीज मुझे तोड़ देती है, वह है संसाधनों के लिए संघर्ष, निरंतर जाँच, और कभी भी मूल्यवान महसूस न करना। बर्नआउट की कीमत बहुत अधिक है। प्रतिभाशाली शिक्षक छोड़ देते हैं, या इससे भी बदतर, असंलग्न रहते हैं।

और जब शिक्षकों को नुकसान होता है, तो छात्रों को अनिवार्य रूप से कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा कि कहावत है, जब माली थक जाता है, तो फूल भी पीड़ित होते हैं। इसका समाधान व्यवस्था को दुरुस्त करने में है, शिक्षकों को सख्त बनाने में नहीं। स्कूलों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम करनी चाहिए, यूपीडीआईएसई जैसे प्लेटफॉर्म को सुव्यवस्थित करना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए और तकनीक के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। सीपीडी सार्थक होना चाहिए, दिखावटी नहीं। सबसे बढ़कर, वास्तविक सराहना की आवश्यकता हैः बेहतर वेतन, कम कार्यभार, अधिक स्वायत्तता और सार्वजनिक सम्मान।

शिक्षण एक आह्वान है, लेकिन केवल जुनून इसे बनाए नहीं रख सकता। यदि हम इन बोझों को कम करते हैं, तो हम शिक्षण के आनंद को जीवित रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को प्रेरित, समर्थित शिक्षकों से लाभ मिले।

आप की बात

प्रधानमंत्री की डिग्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर लंबे समय से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री संबंधी याचिका को रद्द कर दिया है कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, यह निजता का मामला है। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मामले में भी फैसला दिया है। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थित है। यह मामला यहीं थमने वाला नहीं है। अगर वास्तव में डिग्री हासिल की है तो उसे सार्वजनिक करने में कैसी निजता हनन होती है। समझ से परे हैं। अगर आपने वास्तव में कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर डिग्री हासिल नहीं की है तो उस सत्य को स्वीकार करने से कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। लेकिन इस प्रकार निजता का हवाला देकर डिग्री नहीं दिखाना तो संदेह को पुख्ता करने वाला है कि दाल में काला ही नहीं, दाल ही काली है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डिग्रियां तो सार्वजनिक ही है। उनकी निजता तो प्रभावित नहीं हुई है? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर कई लोग तरह-तरह के पोस्ट कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर मजाक ही उड़ने वाले हैं, जो अच्छी बात नहीं है। डिग्री तो एक ऐसा प्रमाण होता है, जिससे कोई निजता का हनन नहीं होता है। वह एक तरह से सार्वजनिक ही होती है। किसी भी सरकारी नौकरी व काम में उसका हर जगह उपयोग होता है, तो वहां निजात कहां आड़े आती है।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, अक्षत खाचरोद, उज्जैन

स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भरता

भारत ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है ।रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित इस स्वदेशी प्रणाली ने तीन अलग-अलग लक्ष्यों को विभिन्न ऊंचाइयों और दूरी पर एक साथ नष्ट कर अपनी क्षमता साबित की। इसका सबसे खास हिस्सा लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो प्रकाश की गति से हमला कर बार-बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है और छोटी दूरी की मिसाइल क्षमता के साथ सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतें पूरी करेगी। इसकी मारक क्षमता तीन से 30 किलोमीटर तक है और यह चलते-फिरते भी लक्ष्य भेद सकती है। इसमें दो रडार हैं जो 360 डिग्री निगरानी और ट्रैकिंग करने में सक्षम हैं। आधुनिक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित यह सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों से सैन्य टुकड़ियों और रणनीतिक ठिकानों की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित ह्यसुदर्शन चक्रह्व रक्षा कवच का यह हिस्सा 2035 तक एकीकृत निगरानी, भौतिक एवं साइबर सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत इस अत्याधुनिक सफलता के साथ उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीक है।

– **अमृतलाल मारू 'रवि'**, इन्दौर मप्र

संस्कारविहीन शिक्षा प्रणाली

आज समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का प्रायः अभाव देखने को मिलता है। इसके लिए हम निःसंकोच आज की शिक्षा नीति और परिवार को दोषी ठहराते हैं। यह कुछ सीमा तक सही भी है। किन्तु एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि जब कभी विद्यालयों में भूले से भी कोई छात्र किसी सेवा कार्य में लगा दिख गया तो मीडिया उस समाचार को ब्रेकिंग न्यूज बना कर अपनी स्क्रीन पर ऐसे प्रदर्शित करता है जैसे कोई भूकम्प का समाचार हो। निःसंदेह आज बिखरते परिवारों में संस्कार मिलना असम्भव ही नहीं बल्कि संस्कार देना या लेना हीन समझा जाने लगा है। जब शिक्षाविद् या शिक्षानीति निर्धारक बच्चों में संस्कारों या महापुरुषों के चरित्र के पठन- पाठन की बात करते हैं तो वे ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी भी महापुरुष का जीवन बिना गुरुसेवा , बिना समाजसेवा, बिना प्रताड़ना और बिना त्याग और संघर्ष के अधूरा है। गुरु के लिये भिक्षा तक महापुरुष मांगकर लाते थे। भगवान राम से लेकर स्वामी विवेकानन्द तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने गुरचरणों में रहकर कठोर शारीरिक श्रम न किया होऔर प्रताड़ना न सही हो। किन्तु आज यदि किसी छात्र के हाथ में झाड़ू, फावड़ा यहां तक कि शिक्षक को पानी पिलाते हुए या हैंडपंप भी चलाते हुए देख लिया तो उसे घोर अपराध की श्रेणी में मानकर तुरन्त वायरल करने में मीडिया देर नहीं लगाता ।शिक्षक की छड़ी को तो सरकारी कानून ने छीन लिया।

– **डॉ नरेंद्र टोंक**, मेरठ

लहराएंगे विश्व शांति का परचम

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के चलते पाक पर दरियादिली दिखाते हुए व मानवीय दृष्टि कोण अपनाते हुए वहां स्थित भारतीय राजदूत के जरिये पाक को "बाढ़" के खतरे से सतर्क किया है. पाकिस्तान की सरकार ने भी आपातकालीन सतर्कता जारी की है. हाल ही में पाक से युद्ध व सिंधु नदी समझौता स्थगित करने से उत्पन्न तनाव के बावजूद भारत ने सहिष्णुता का परिचय दिया है. दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प बारम्बार "विश्वशांति"."विश्वशांति" का राग अलापते हुए भी टेरिफ टेरर के जरिये दुनिया में असामान्य/असमंजस्य की स्थिति पैदा करते जा रहे हैं. उनके द्वारा कभी किसी से युद्ध-विराम हेतु समझौते की बात की जाती है तो दूसरे ही पल उससे पलटने का पैगाम सूना दिया जाता है जिससे शान्ति की बात दूर-दूर तक उड़नछू होकर गायब ही हो जाती है. अब बताइये ऐसे में कैसे शान्ति या विश्वशांति के प्रयास अमरीका कर सकता है ? जबकि हम तो दुश्मन को भी मानवीय आधार पर खुले मन से कूटनीति मदद कर रहे हैं. ऐसे ही संस्कार-संस्कृति रूपी कदम पर चलने से ही "विश्वशांति" की ओर बढ़ा जा सकता है. "आत्मनिर्भरता" व पूर्ण आत्मविश्वास के संकल्प के निरंतर क्रियान्वन से आशा है भारत माता के आशीर्वाद से एक दिन अवश्य भारत "विश्वशांति" का परचम फहराने में सफल होगा।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 163

उचित अनुरोध

देश के बैंकिंग क्षेत्र के नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्रों में बैंकों की भागीदारी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कई कठोर नियम बनाए हैं। ये नियम उचित कारणों से लागू किए गए और उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा किया है। 1992 के प्रतिभूति घोटाले में जब बैंकों के फंड का इस्तेमाल शेयर बाजार में सटोरिया गतिविधियों के लिए किया गया तब इस व्यवस्था को और मजबूत किया गया। उस समय यह स्पष्ट हो गया था कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र कुछ खास तरह की गतिविधियों को वित्तपोषित करने की क्षमता या विशेषज्ञता नहीं रखता था। हालांकि, तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। बैंकिंग क्षेत्र परिपक्व हो गया है और नियामक क्षमता भी इसके साथ-साथ बढ़ी है। इसलिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का आरबीआई से बैंक वित्तपोषण पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का अनुरोध करना उचित ही है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा है कि आईबीए यह अनुरोध करेगा कि बैंकों को घरेलू कॉरपोरेट क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण यानी ऋण देने की अनुमति दी जाए और इसकी शुरुआत सूचीबद्ध कंपनियों से की जाए। यह स्वागतयोग्य होगा और नियामक को इस अनुरोध पर सकारात्मक ढंग से विचार करना चाहिए।

विलय एवं अधिग्रहण के मामलों में बैंक वित्तपोषण पर लगाए गए प्रतिबंधों के कुछ विपरीत और अनपेक्षित नतीजे सामने आए हैं। एक शिकायत यह है कि यह प्रतिबंध भारतीय कंपनियों को विलय एवं अधिग्रहण के क्षेत्र में नुकसान में डालते हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धी अपने देश में उपलब्ध बैंक वित्त का लाभ उठाकर अधिग्रहण की दौड़ में स्थानीय कंपनियों से अधिक बोली लगा सकते हैं। खासकर तब जबकि भारत और अन्य देशों के बीच ब्याज दरों में अधिक अंतर हो। भारत बैंक वित्त पर आधारित बाजार है, लेकिन अधिग्रहण की तलाश में लगी कंपनियों के लिए यह वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं होता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में वित्तीय संरचना बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों ने अपने कर्ज को कम किया है और अब वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए पूंजी बाजार की ओर रुख कर रही हैं। जैसे-जैसे वित्तीय बाजार विकसित होंगे, अधिक कंपनियां इस मार्ग को अपनाएंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि बदलते बाजार परिवेश को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों की समीक्षा की जाए।

जब रिजर्व बैंक आईबीए के प्रस्ताव की परीक्षा करेगा तो उसे सावधानीपूर्वक यह आकलन करना चाहिए कि विलय एवं अधिग्रहण के धन हासिल करने के तरीके किस प्रकार अलग हैं। खासकर जोखिम प्रबंधन की आवश्यकताओं के मामले में यह बैंकों द्वारा मुहैया कराए जाने वाले वर्तमान कॉरपोरेट ऋण से कैसे अलग हैं। अगर एक सूचीबद्ध कंपनी दूसरी को खरीदने का निर्णय लेती है और अगर दोनों की जोखिम प्रोफाइल पर्याप्त रूप से समान हैं, तो फिर बैंकों से वित्तीय सहायता नए प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध होती है, लेकिन अधिग्रहण के लिए नहीं। ऐसा क्यों होता है? दोनों ही मामलों में जोखिम का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की स्थिरता और भविष्य की आय धाराओं का विश्लेषण शामिल होता है। इसलिए यह उचित होगा कि रिजर्व बैंक यह भी विचार करे कि क्या इस क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जैसे विनियमित संस्थानों की भागीदारी से अधिक व्यापक वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, या फिर यह क्षेत्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विदेशी फंड्स के अधीन ही बना रहना चाहिए।

विदेश में निजी ऋण में तेजी ने यह भी दिखाया है कि जब बैंक पीछे हटते हैं तो क्या होता है। ऐसे संस्थानों द्वारा किए गए लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी नहीं होते, और वे प्रणाली में जोखिम के संचय को छिपा सकते हैं। पिछले दशक में नियामक की प्राथमिकता यह रही है कि इस प्रकार की गतिविधियां बड़े, पारदर्शी और विनियमित संस्थानों द्वारा संचालित की जाएं, न कि निजी या मुखौटा संस्थाओं द्वारा।

इस संदर्भ में, अब समय आ गया है कि रिजर्व बैंक यह स्वीकार करे कि भारतीय बैंक कॉरपोरेट को ऋण देने की अपनी कार्यप्रणाली का विस्तार करने के लिए तैयार हैं।

(डिस्क्लेमरः कोटक परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है।)

विनय सिन्हा

विनम्रता, महत्त्वाकांक्षा और विकास की इच्छा

जापान से सबक लेकर हम ट्रंप के साथ आर्थिक जंग जीतने के प्रयास कर सकते हैं। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं नौशाद फोर्ब्स

डॉनल्ड ट्रंप की शुल्क संबंधी धमकियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की राह उपयुक्त होती। परंतु दुनिया ने ऐसा नहीं किया और यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों ने उसके साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो अमेरिका के लिए अधिक फायदेमंद थीं, उनके लिए कम। हमारे देश की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। अमेरिका ने जिन देशों पर सर्वाधिक शुल्क लगाया है उनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने शुल्क वृद्धि के साथ-साथ हमें अपमानित करने वाली बातें भी कहीं हैं। मसलन भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करने की बात या भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मृत अर्थव्यवस्था बताना। ऐसे में प्रश्न यह है कि हम कहां हैं और हमारे समक्ष क्या विकल्प हैं?

इसी समाचार पत्र में प्रकाशित टीएन नाइनन के बेहतरीन आलेख से मुझे दो बातों की याद आई। पहली बात तो यह कि मैं सप्ताहांत पर प्रकाशित होते रहे (अब बंद) उनके स्तंभ को कितनी शिद्दत से याद करता हूं और दूसरा हम जापान से कितना कुछ सीख सकते हैं जिसने 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकी दबंगई के जवाब में खुद को चमत्कारिक रूप से बदला और एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गया। मेरे प्रमुख स्रोत हैं समाजशास्त्री रोनाल्ड डोर जिन्होंने जापानी संस्कृति और आर्थिक सफलता पर काफी कुछ लिखा है।

विनम्रता और महत्त्वाकांक्षाः नाइनन हमें याद दिलाते हैं कि हमें आर्थिक जंग जीतनी है न कि ट्रंप से कोई बहस जीतनी है। यानी हमें अपमान को विनम्रतापूर्वक नजरअंदाज करते हुए अंतिम परिणाम पर नजर रखनी है। 'पेरी घटनाक्रम' (वर्ष1853 में) से अमेरिका ने जापान पर दबाव बनाकर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने पर विवश किया और उससे कुछ रियायतें हासिल की थीं। इन असमान समझौतों में अपनी ही शुल्क दरें तय करने का अधिकार गंवाना और विदेशियों के निवास वाले इलाकों में पश्चिमी कानूनों को लागू होने देना शामिल था। जापानियों ने इसका उत्तर कुछ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ दियाः

1870 का दशक- जापान औपनिवेशीकरण से मुक्त।

1890-1911- पश्चिम द्वारा आरोपित असमान संधियों की समीक्षा।

1890 का दशक- चीन को कोरिया पर नियंत्रण करने से रोकना।

1900 का दशक- रूस को कोरिया पर नियंत्रण करने से रोकना।

1930 का दशक- महाशक्तियों के साथ बराबरी हासिल करना।

डोर बताते हैं कि इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को सभी जापानियों के साझा लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इन्हें हासिल करने में राष्ट्रवाद की भावना का जमकर इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रवाद अक्सर खराब ढंग से समाप्त होता है। न केवल किसी देश के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों के लिए भी। यहां खराब से तात्पर्य युद्ध और पेशेगत पराजय से है। चीन के लिए 1895 में, कोरिया के लिए 1905 में और जापान के लिए ऐसा 1945 में दो परमाणु बम विस्फोटों के बाद हुआ।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई सकारात्मक चीजें हुईं। आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय आकांक्षा बन गई। जापान के दैनिक अखबारों ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि की सारणी प्रकाशित करनी शुरू की। हर बार जब जापान प्रति व्यक्ति आय में किसी देश को पीछे छोड़ता तो यह सुर्खियों में आ जाता। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय गौरव था न कि महज आर्थिक वृद्धि। 1950 और 1960 के दशक में जापान रिकॉर्ड गति से (दो दशकों में 9 से 10 फीसदी की तेज वृद्धि) विकसित हुआ। इसमें तकनीकी क्षमताओं की अहम भूमिका थी। 1950 से 1978 के बीच जापान दुनिया में तकनीक का सबसे बड़ा आयातक था। डोर के मुताबिक उसने 9 अरब डॉलर की राशि तकनीक आयात करने में व्यय की। हालांकि, 1978 में अमेरिका ने शोध एवं विकास पर 60 अरब डॉलर खर्च किए थे। जापानी कंपनियों ने आंतरिक शोध पर भी खूब व्यय किया। जापानी कंपनियों ने विदेश में विस्तार किया। होंडा, सोनी, पैनासोनिक और टोयोटा दुनिया भर में पहचानी जाने लगीं। सर्वश्रेष्ठ से सीख लेने के लिए विनम्रता जरूरी है। नई तकनीक और विश्वस्तरीय कंपनियां बनाने के लिए महत्त्वाकांक्षा जरूरी है। इन दोनों का मेल बेजोड़ साबित हुआ।

विकास की आकांक्षाः डोर जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर में 'विकसित होने की इच्छा' की बात करते हैं। यह इच्छा पिछड़ेपन की भावना से आई जिसे दूर करने की आकांक्षा थी। अपने इतिहास में 30 वर्ष की उच्चतम वृद्धि के बाद हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से सबसे गरीब पांचवे देश से सबसे गरीब तीसरे देश बने। यह अच्छा सुधार है लेकिन पर्याप्त नहीं। चीन आज भारत से पांच गुना अमीर है और शोध एवं विकास में हमसे 25 गुना निवेश करता है। हमें अपनी इच्छाशक्ति और मजबूत करने की जरूरत है।

डोर कहते हैं कि पिछड़ेपन की यह भावना पूरे समाज में साझा होनी चाहिए। हम नोबेल पुरस्कार विजेताओं और वैश्विक कंपनियों का नेतृत्व करने वाले भारतीयों के नाम पर गर्व करते हैं लेकिन अगर हम इसके साथ ही यह प्रश्न करना शुरू करें कि अमर्त्य सेन, वेंकटरमन रामाकृष्णन और अभिजित बनर्जी जैसे हमारे नोबेल विजेता विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में काम क्यों करते हैं तथा सत्य नाडेला और सुंदर पिचाई जैसे लोग अमेरिकी कंपनियों का ही नेतृत्व क्यों करते हैं तब आग्रह पूर्णतः सकारात्मक होगा। लेकिन अगर हमारे महान बुद्धिजीवियों और कारोबारियों पर गर्व, खेत में काम करने वाले किसानों को अपने साथ जोड़ने की हमारी इच्छा को कम कर देता है, तो हम विकास की साझा इच्छाशक्ति को कमजोर कर देते हैं। तेज आर्थिक विकास के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने से हमारी विकास की इच्छाशक्ति को बढ़ावा मिल सकता है।राजनीतिक नेताओं और उद्योगपतियों के रूप में हमें इस पिछड़ेपन की भावना को साझा करना होगा भले ही हम इसे स्वयं में महसूस नहीं कर सकें। इससे आगे बढ़ने की साझा ललक तैयार होगी।

ऐसे में हम जहां ट्रंप के अपमान की अनदेखी कर रहे हैं वहीं हमें क्या महत्त्वाकांक्षाएं पालनी चाहिए? वर्ष 2047 तक विकसित होने का हमारा लक्ष्य एक अच्छा आर्थिक लक्ष्य है। इसके लिए हमें जापान की तरह दो दशक से अधिक समय तक 9 फीसदी से अधिक की वृद्धि हासिल करनी होगी। यानी मौजूदा दर से 3 फीसदी अधिक। हमारे समाचार पत्र भी ऐसी सारणी प्रकाशित कर सकते हैं कि इस दौरान हम प्रति व्यक्ति जीडीपी में किन देशों को पछाड़ते हैं। फिलहाल हम इस मामले में 136वें स्थान पर हैं।

टीएन नाइनन और साजिद चिनॉय ने इस अखबार में कई बड़े सुधारों की बात कहीः नई शिक्षा नीति को लागू करना, विनिर्माण में देश के लिए अच्छी जगह बनाना, कृषि उत्पादकता की समस्याओं को हल करना, अपने शहरों में बदलाव, औद्योगिक शक्ति का कुछ घरानों तक सीमित होने पर अंकुश, कारोबारी सुगमता की लागत कम करना, वस्तु एवं सेवा कर की एकल दर, निजीकरण पर जोर और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए शुल्क कम करना। यह एक अच्छी सूची है। कई लोग संदेह करेंगे कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं। हम चरणबद्ध सुधार जारी रख सकते हैं। यानी दो कदम आगे तो एक कदम पीछे। हम ट्रंप की धमकियों और अपमान के बदले या तो प्रतिक्रिया दें और अंतर्मुखी हो जाएं या फिर उसकी अनदेखी करें और चुनौती को अवसर में बदल लें। इसके लिए हमें पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चलना होगा और इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। हम क्या करेंगे इसका चुनाव हमें करना है।

(लेखक फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरमैन और सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष हैं)

देसी संस्थागत निवेशक फिर जमा रहे हैं धाक

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

वर्ष 1992 में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। यह भारतीय पूंजी बाजार विदेशी निवेश के लिए खोलने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था। एफआईआई ने 1992-93 में 13 करोड़ रुपये के मामूली निवेश के साथ भारतीय शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत की थी। उस समय घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) में पूर्ववर्ती यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई), छह बैंक-प्रायोजित म्युचुअल फंड और चार वित्तीय संस्थान-प्रायोजित म्युचुअल फंड शामिल थे। ये सभी तब तक पूरी तरह स्थापित हो चुकी थीं। 1993 में निजी क्षेत्र की म्युचुअल फंड कंपनियों को भी बाजार में कदम रखने की अनुमति मिल गई। इसके पीछे सोच यह थी कि ये म्युचुअल फंड कंपनियां बाजार में एफआईआई के विकल्प के रूप में काम करेंगी। मार्च 1993 के अंत में डीआईआई का शेयरों में संयुक्त निवेश लगभग 45,000 करोड़ रुपये था। हालांकि, अगले कुछ वर्ष डीआईआई के लिए उथल-पुथल वाले रहे जिससे एफआईआई की तुलना में उनका महत्त्व स्पष्ट रूप से कम हो गया।

यूटीआई उस समय एक बड़ी म्युचुअल फंड कंपनी हुआ करती थी मगर वर्ष 1998 में उसकी सुनिश्चित रिटर्न देने वाली योजनाएं समस्याओं से घिर गईं। इससे म्युचुअल फंडों पर निवेशकों का विश्वास हिल गया जिसका नतीजा यह हुआ कि आने वाले वर्षों में उन्हें निवेश जुटाने में मुश्किल पेश आने लगी। डीआईआई का बचा हुआ इक्विटी निवेश मार्च 1998 के अंत में दर्ज 65,300 करोड़ रुपये से मामूली बढ़कर मार्च 2000 के अंत तक 65,800 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान एफआईआई निवेश दोगुना से अधिक होकर 70,300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे यह पहली बार डीआईआई से आगे निकल गया। डीआईआई का इक्विटी निवेश मार्च 2005 के अंत तक घटकर 59,000 करोड़ रुपये रह गया जिसका आंशिक कारण 2003 में पूर्ववर्ती यूटीआई का दो घटकों में विभाजन था।

जनक राज

अगले 14 वर्षों (2000-01 से 2013-14) के दौरान एफआईआई का इक्विटी निवेश कुछ हद तक धीमा पड़ गया। यह मात्र 18 फीसदी की दर से बढ़ा जबकि पहले छह वर्षों (1994-95 से 1999-00) में यह 58 फीसदी की दर से बढ़ा था। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, डीआईआई के निवेश में 2 फीसदी की गिरावट आई। नतीजा यह हुआ कि मार्च 2014 के अंत में डीआईआई का बचा निवेश 42,000 करोड़ रुपये रहा जबकि इसके मुकाबले एफआईआई के निवेश का यह आंकड़ा लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

वर्ष 2014-15 निवेश के लिहाज से डीआईआई के लिए एक महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस वर्ष शेयरों में उनका निवेश 98 फीसदी बढ़ गया और उसके बाद यह सिलसिला मजबूत बना रहा और तब से 42 फीसदी की वार्षिक औसत दर से बढ़ता रहा। डीआईआई के निवेश में 2014-15 से 2019-20 तक 55.4 फीसदी की दर से इजाफा हुआ, जबकि कोविड के बाद की अवधि (2021-22 से 2024-25) में यह दर 37 फीसदी रही थी। इस प्रकार, सामान्य धारणा के विपरीत खुदरा निवेशक कोविड महामारी से पहले ही शेयर बाजार की ओर आकर्षित होने लगे थे। इसकी पुष्टि पारिवारिक क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत में पूंजी बाजार साधनों की हिस्सेदारी से साबित होती है, जो 6 फीसदी से अधिक रही। यह मोटे तौर पर कोविड से पूर्व की अवधि (2014-15 से 2019-20) के बराबर थी। कुल मिलाकर, डीआईआई द्वारा किया गया निवेश मार्च 2025 के अंत में 14 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

पिछले एक दशक में डीआईआई निवेश तेज गति से बढ़ने के बीच एफआईआई निवेश में केवल 4.9 फीसदी की वृद्धि हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि मार्च 2025 के अंत में 10 लाख करोड़ रुपये के साथ उनका निवेश डीआईआई की तुलना में लगभग 29 फीसदी कम था। इस तरह, डीआईआई ने 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शेयर बाजार में अपना पुराना रसूख फिर से हासिल कर लिया है।

यह स्थिति उत्साहजनक मानी जा सकती है क्योंकि डीआईआई के पास अब एफआईआई का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त क्षमता है जिससे भारत का शेयर बाजार और मजबूत हो गया है। पिछले एक दशक में डीआईआई का बाजार पर दबदबा रहा है। एफआईआई निवेश और शेयर बाजार (बीएसई सेंसेक्स) के बीच सह-संबंध (जो जनवरी 2000 से मार्च 2014 तक 0.37 था) वह अप्रैल 2014 से जून 2025 तक लगभग नगण्य (-) 0.03 हो गया। इसका मतलब यह है कि पिछले एक दशक में एफआईआई का शेयर बाजार पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं रहा है। इसके विपरीत, डीआईआई निवेश और शेयर बाजार के बीच सह-संबंध, जो जनवरी 2000 से मार्च 2014 तक (-) 0.20 था, अप्रैल 2014 से जून 2025 के दौरान तेजी से बढ़कर 0.59 हो गया। इससे पता चलता है कि पिछले एक दशक में डीआईआई ने मुख्य रूप से शेयर बाजार को प्रभावित किया है।

देश में विशेष रूप से मझोले और छोटे शहरों में शेयर बाजार की पहुंच बढ़ाने में डीआईआई ने अहम किरदार निभाया है मगर अब भी उन्हें एक लंबा सफर तय करना है। हालांकि, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पिछले 10 वर्षों में एफआईआई द्वारा निवेश कम क्यों हो गया है? इसका प्रश्न का कोई सीधा जवाब नहीं है लेकिन गौर करने वाली बात है कि भारतीय शेयर बाजार का औसत मूल्यांकन (मूल्य-आय गुणक), जो जनवरी 2000 से मार्च 2014 तक 18.5 (दायरा 11-28) था, अप्रैल 2015 और मार्च 2025 के बीच बढ़कर 23.7 (दायरा 18.5-41.1) हो गया।

ऐसा लगता है कि उच्च मूल्यांकन ने एफआईआई (जिनके पास विभिन्न देशों में निवेश करने की गुंजाइश रहती है) को पिछले एक दशक में भारतीय शेयर बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने से रोक रखा है। क्या एफआईआई उसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे जैसा उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखने के पहले 20 वर्षों में किया था? यह तो समय ही बताएगा।

(लेखक सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस, नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं।)

आपका पक्ष

ट्रंप के टैरिफ पर भारत की सख्त प्रतिक्रिया

भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है और इस पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि भारत की नीतियां केवल और केवल राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगी। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही अमेरिका से व्यापार समझौता न हो पाए। जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया ने ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा, जिसने विदेश नीति को इतने सार्वजनिक रूप से संचालित किया हो। इस स्पष्टवादिता का एक कारण यह भी है कि ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी भारत के खिलाफ चेतावनी भरे शब्दों का उपयोग कर रहे थे, खासकर रूस से तेल

ट्रंप टैरिफ के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत की नीतियां केवल राष्ट्रीय हित पर आधारित होंगी

आयात और चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर। विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर अनुचित रूप से निशाना साधा जा रहा है। 27 अगस्त से लागू होने वाले 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद, भारत ने वार्ता के दरवाजे खुले रखे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

जीएसटी में सुधार की घोषणा बेहद अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में सबसे अहम तोहफा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अगले चरण के सुधारों को लेकर घोषणा की है। इस हेतु दो स्लैब बनाना एक तार्किक कदम है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा भी काफी अहम है। अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता पर केवल बातों से कुछ भी हासिल नही होने वाला है इसके लिए सरकार के साथ जनता को भी ईमानदारी से कदम उठाना होगा। यही बात भ्रष्टाचार का है जब तक सरकारी तंत्र में दंडित होने का भय और जनता में शॉर्टकट वाली प्रवृत्ति समाप्त नही होती तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात बेमानी है।

विमलेश पगारिया, बदनावर

स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य करीब

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देश हित के कई संकल्पों का उल्लेख किया जिनमें से प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और 2030 की समय-सीमा से पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50 फीसदी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह आत्मनिर्भर तथा सतत भविष्य की ओर बढ़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

धरातल पर उतरे वादे

प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर हर वर्ग के अच्छे दिन लाने के वादे किए हैं। साथ ही उन्होंने महंगाई से कुछ राहत दिलाने के लिए दीपावली पर कुछ सरप्राइज देश को देने का वादा किया है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जीएसटी में कुछ बदलाव कर सकती है। रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली सभी जरूरी चीजों पर जीएसटी कम होना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विशाखापत्तनम में दो बहुउद्देशीय युद्धपोतों आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि का जलावतरण किया। दोनों युद्धपोत नौसेना के नवीनतम अत्याधुनिक 'प्रोजेक्ट 17ए' के तहत बने हैं।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 27-08-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP8 User: kamlesh.mestry Time: 08-26-2025 22:30 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । बुधवार, 27 अगस्त 2025

'कमर्शल' अभिव्यक्ति

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, उसे बहुत सावधानी से लेने की जरूरत है। समय रैना समेत पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की टिप्पणियों को दिव्यांगों की गरिमा के खिलाफ पाया गया है।

हास्य की सीमा । इंटरनेट सेंसेशन के इस दौर में जब अपने कंटेंट को वायरल बनाने की इच्छा सब पर हावी होती दिख रही है, इस केस ने यह ध्यान दिलाया है कि हर दूसरे अधिकार की तरह अभिव्यक्ति की आजादी भी अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ठीक ही बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि किसी को भी दूसरों पर, खासकर दिव्यांगों, बीमारों, जैसे कमजोर तबकों पर हंसने की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत का यह मानक भी तर्कसंगत कहा जाएगा कि प्रायश्चित के तौर पर की जाने वाली क्षतिपूर्ति होने वाले नुकसान के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए।

AI Image

इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी

गाइडलाइन की जरूरत । इसमें दो राय नहीं कि ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े मामलों के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन होनी चाहिए। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। लेकिन कोर्ट ने भी माना कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइन किसी खास केस की प्रतिक्रिया में आनन-फानन तैयार नहीं की जा सकती और न ही ऐसा किया जाना चाहिए। यह कार्य न केवल मौजूदा परिस्थिति और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का बल्कि आने वाले दौर की चुनौतियों का भी ध्यान रखते हुए करना होगा।

कमर्शल अभिव्यक्ति । सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह सवाल भी सामने आया कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी को कमर्शल और नॉन कमर्शल जैसी दो श्रेणियों में बांटकर देखा जा सकता है। ध्यान रहे, संविधान की ओर से सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति का एक जैसा अधिकार दिया गया है। इसके साथ जुड़ी पाबंदियां भी सबके लिए समान हैं। यहां तक कि मीडिया या मीडियाकर्मियों को भी अलग से कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे में इस पर विचार करना होगा कि क्या किसी की अभिव्यक्ति को इस आधार पर अलग तरह से देखा जाना चाहिए कि वह कमर्शल कंटेंट की श्रेणी में आता है या नहीं।

अधिकारों का टकराव । पिछली सुनवाई की रोशनी में देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में अनुच्छेद 19 के तहत मिले अभिव्यक्ति के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार दोनों पर विचार करना है। जाहिर है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शीर्ष अदालत कैसे दोनों के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ती है।

कभी-कभी

असली-नकली चेहरे

ललित वर्मा

कुछ दिन पहले दिल्ली की एक वरिष्ठ पत्रकारा ने अपने फेसबुक पर लिखा - अपने एक निजी अनुभव से आप सबको एक सलाह देती हूं, काम आएगी। किसी भी नए रिश्ते/दोस्ती में अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी-बड़ी बातें करे, तो समझ जाइए कि कुछ वक्त बाद वह उतनी ही छोटी/ओछी हरकतें करेगा। जो व्यक्ति किसी का भी इस्तेमाल न करने की बात जितनी जोर शोर से करे, वही मतलब पड़ने पर सबसे पहले आपके/दूसरों के पद/पहचान का उपयोग करेगा। ये सलाह दे पाने के लिए कई बुरे अनुभव झेले हैं।

आपमें से कई चौंके होंगे, कई नहीं। जो चौंके होंगे, उन्हें मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की बात समझनी होगी। कुछ थिअरीज आपका 'जायका' बिगाड़ सकती हैं। इनमें एक है जॉर्ज सी. होमेंस की सोशल एक्सचेंज थिअरी (1961)। यह कहती है कि इंसानी फितरत ही है कि वह सब रिश्तों को लागत और फायदे के तराजू पर तौलता है। बाबा सिग्मंड फ्रायड समझाते हैं, इंसान को अपनी कमजोरियों का पता होता है, लेकिन वह उन्हें उजागर नहीं होने देना चाहता, इसलिए उन्हें छिपाने के लिए उनके उलट दावे करने लगता है। फ्रायड ने इसे प्रोजेक्शन मेकेनिजम का नाम दिया और कहा कि जिस दिन वह दावे के उलट व्यवहार कर बैठता है, उसका असल चेहरा उजागर हो जाता है।

पर, हम एर्विंग गॉफमैन के इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात थोड़ा विस्तार से करेंगे। उनका एक फेमस कोट है, 'हम सब जीवन के रंगमंच के एक्टर्स हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से अपने रोल निभा रहे हैं।' क्या गजब कह रहे हैं गॉफमैन साब। यानी हम अपने हिसाब से नहीं, दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। 1959 में उनकी बुक 'द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ' ने इसे 'सामाजिक नाट्यशास्त्रीय नजरिये' के रूप में समझाया था। हमारा जीवन ड्रामा के स्टेज की तरह है। हम एक रोल स्टेज पर निभाते हैं, एक बैक स्टेज, जहां रिहर्सल भी करते हैं, कमजोरियों को दूर करने की प्रैक्टिस भी। और तीसरा, स्टेज और बैक स्टेज, दोनों के परे। जहां हमें कोई जानता नहीं, उनके बीच। इन तीनों जगह खुद को रखिए, समझ जाएंगे।

साहिर लुधियानवी ने 50 साल पहले लिखा था, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। साहिर साब, ऐसा कहेंगे तो किस-किस से नहीं मिलेंगे आप?

एकदा

एक वीर का आत्मसमर्पण

नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आदिवासी समाज के एक जमींदार परिवार में हुआ था। सन 1856 की बात है। उनके इलाके में भयानक सूखा पड़ा था। हर तरफ भूख, बीमारी का आलम था। लेकिन व्यापारी माखन का गोदाम अन्न से भरा हुआ था। जब गरीबों की गुहार को माखन ने नजरअंदाज कर दिया तो नारायण ने उसके गोदाम के ताले तुड़वा कर अनाज गरीबों में बंटवा दिया। 24 अक्टूबर, 1856 को उन्हें संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सन 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तेज हुई, तब सैनिकों, समर्थकों और सामान्य लोगों की मदद से वह जेल से भाग कर अपने गांव सोनाखान पहुंच गए। वहां उन्होंने 500 बंदूकधारियों की सेना बनाई और अंग्रेजी सेना से लोहा लेने लगे। उन्हें पकड़ने में असमर्थ अंग्रेजों ने उनके इलाके के आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। ऐसे में अपनी मौत की परवाह किए बिना नारायण ने आत्मसमर्पण कर दिया। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के 'जय स्तंभ चौक' पर तोप से उड़ा दिया गया। आज भी छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह बिंझवार का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

Subrata Dhar

संकलन : **रेनू सैनी**

रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाने से पूतिन पर दबाव नहीं बना पाएंगे ट्रंप

इसमें US का घाटा, भारत का कुछ ही जाता

प्रणब ढल सामंता

अगर अमेरिका रूस की कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) से होने वाली आमदनी को रोकना चाहता है तो उसने रूसी तेल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? ईरान और वेनेजुएला क्रूड पर उसने ऐसा ही किया था। फिर रूस के मामले में उसने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर 'अप्रत्यक्ष दबाव' बनाने का रास्ता क्यों चुना?

ग्लोबल प्लेयर । कच्चे तेल के उत्पादन में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वह करीब 10% ग्लोबल डिमांड पूरी करता है। इसलिए मार्च 2022 में जब कच्चे तेल का भाव $137 प्रति बैरल तक जा पहुंचा तो डर बना कि रूसी तेल पर पाबंदी लगाई गई तो भाव $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा।

यूरोपीय संघ का रास्ता । इसलिए G7 के समर्थन से यूरोपीय संघ ने 'कीमतों पर नियंत्रण (प्राइस कैपिंग)' वाला रास्ता चुना। इसमें तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में रूसी तेल को काफी कम भाव पर खरीदा जा रहा था। सोच यह थी कि इससे हर बैरल पर उसे कम पैसा मिलेगा। साथ ही, रूस से माल ढुलाई करने वाले जहाजों के लिए इंश्योरेंस-रीइंश्योरेंस पर भी पाबंदी लगाई गई। मकसद रूस से माल की ढुलाई की लागत बढ़ाना था।

भारत नियम से चला । भारत ने यूरोपीय संघ की ओर से तय कीमत पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। रूस ने भी भारतीय बंदरगाहों पर उस कीमत पर तेल की डिलिवरी जारी रखी, जिसकी मांग भारत की ओर से की गई। इसी वजह से 2021-22 में भारत के कुल तेल आयात में जहां रूस का योगदान 1% से भी कम था, वहीं 2023-24 में यह करीब 36% हो गया।

चीन-तुर्किये बड़े खरीदार । पिछले तीन वर्षों में रूस ने जितना तेल बेचा है, उसमें चीन ने 47% की खरीदारी की है। इस दौरान भारत ने 38% और यूरोपीय संघ-तुर्किये ने 6% की खरीदारी की। दिलचस्प बात यह है कि तुर्किये जो नैटो का सदस्य देश है, वह रूस से रिफाइंड पेट्रो-प्रॉडक्ट्स का सबसे बड़ा आयातक है। रूस से रिफाइंड पेट्रो-प्रॉडक्ट्स के निर्यात में उसका योगदान 26% और चीन का 13% है।

नकली चेहरा । ट्रंप सरकार इन बातों पर खामोश है। उसकी वजह यह है कि यह समस्या उससे अधिक जटिल है, जैसा अमेरिका इसे दिखा रहा है। यूरोपीय संघ ने पिछली जुलाई में रूस से मंगाए गए कच्चे तेल से रिफाइंड प्रॉडक्ट्स के आयात पर प्रतिबंध लगाया तो उससे सहयोगी देशों अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड को छूट दी गई। वहीं, 6 महीने बाद अगर कोई भारत से रिफाइंड पेट्रो प्रॉडक्ट्स खरीदता है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी।

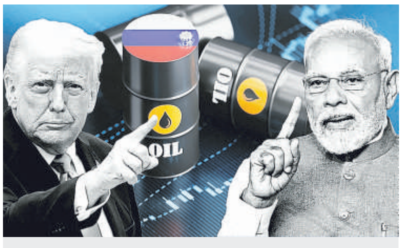

तेल का असली खेल

- चीन, तुर्किये, यूरोपीय संघ भी रूस से तेल-गैस के बड़े खरीदार
- अमेरिका ने रूस से खरीदा हजारों करोड़ रुपये का यूरेनियम
- भारत अब शायद ही अमेरिका को भरोसेमंद सहयोगी माने

गैस का हाल । ये तो हुई कच्चे तेल की बात, आइए अब जरा रूसी नैचरल गैस की चर्चा कर लें। पिछले तीन वर्षों से यूरोपीय संघ रूसी LNG का सबसे बड़ा आयातक रहा है। रूस के कुल LNG निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 51% रही है। इसके बाद 21% के साथ चीन और 18% के साथ जापान का नंबर आता है। पाइपलाइन गैस में भी यूरोपीय संघ 37% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद 30% के साथ चीन और 27% के साथ तुर्किये का नंबर आता है।

यूरेनियम की खरीद । यूरेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो पिछले साल अमेरिका को रूसी यूरेनियम की बिक्री पर रोक लगाई गई, लेकिन लगे हाथ कुछ रियायतें भी दी गईं। इससे अमेरिका ने रूसी यूरेनियम की खरीद जारी रखी। सिर्फ इस साल के पहले पांच महीनों में अमेरिका ने रूस से 5000 करोड़ रुपये से अधिक का यूरेनियम आयात किया है।

टारगेट है भारत । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप ने भारत को खासतौर से टारगेट किया है क्योंकि यूरोपीय संघ, चीन, तुर्किये और एक हद तक खुद अमेरिका, रूस से तेल-गैस, रिफाइंड पेट्रो-प्रॉडक्ट्स व यूरेनियम खरीदते रहे हैं। यूरोपीय संघ ने हंगरी-स्लोवाकिया जैसे देशों को भी अपनी पाबंदियों से छूट दी। इस साल जून तक जापान को रूसी ऑयल फील्ड सखालिन-2 से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिली हुई थी। दूसरी तरफ, भारत को कोई रियायत नहीं मिली और उसने यूरोपीय संघ की ओर से तय कीमत पर रूस से तेल खरीदा। इसके बावजूद अमेरिका ने सिर्फ भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है।

रिश्ते पर आंच । सच यह है कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने से रूस के तेल मार्केट पर असर नहीं होगा बल्कि अमेरिका के साथ उसका कारोबार प्रभावित होगा। इससे दोनों देशों के रिश्ते पर आंच भी आएगी। भारत को आर्थिक चोट भी पहुंचेगी, लेकिन अमेरिका को लंबी अवधि में इसके राजनीतिक दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। उसके लिए न सिर्फ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति दांव पर होगी बल्कि निवेश प्रभावित होगा और मार्केट्स पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उसकी छवि भी प्रभावित होगी। भारत आगे शायद ही अमेरिका को भरोसेमंद सहयोगी मानेगा।

क्या भारत को युद्ध नीति बदलनी चाहिए?

पूनम पाण्डे

ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी सफलता की चर्चा हर फोरम पर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस ऑपरेशन में एयर पावर की बात हो रही है और एयरफोर्स चीफ से लेकर एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी एयर एसेट्स की क्विक मोबिलिटी (कहीं भी तुरंत तैनात होने की क्षमता) की बात कर रहे हैं उससे यह सवाल उठने लगा कि है क्या थिएटर कमांड के ब्लूप्रिंट पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

बेहतर तालमेल । अभी इंडियन आर्मी की 7, एयरफोर्स की 7 और नेवी की 3 कमांड हैं। इन्हें मिलाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने पर काम हो रहा है। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए थिएटर कमांड की जरूरत काफी वक्त से बताई जा रही है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन में भी थिएटर कमांड हैं। भारत में अलग-अलग कमांड स्ट्रक्चर हैं, जो अलग-अलग अधिकारी के तहत आते हैं।

तीन कमांड का प्रस्ताव । थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया जनवरी 2020 में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति के साथ शुरू हुई थी। इस पर कुछ प्रगति भी हुई। फिर 30 सितंबर 2022 को जनरल अनिल चौहान ने CDS का पद संभाला तो थिएटर कमांड के नए प्रस्ताव पर बात होने लगी। मौजूदा प्रस्ताव, जिस पर काम हो रहा है, उसके मुताबिक कुल तीन थिएटर कमांड बनाई जानी है। एक पाकिस्तान बॉर्डर के अपोजिट, एक चीन बॉर्डर के अपोजिट और एक मेरीटाइम कमांड।

बदलाव की जरूरत । इंडियन एयरफोर्स शुरू से ही कहती रही है कि एयर असेट्स को बांटना सही नहीं होगा। अब एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी कहने लगे हैं कि मौजूदा ब्लूप्रिंट ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभव को ठीक तरह से शामिल नहीं करता। अब फिर इस पर जोर दिया जा रहा है कि हवाई संसाधन (एयर असेट्स) भू-भाग की सीमाओं में बंधे नहीं होते। वे लंबी दूरी की क्षमता वाले क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में एयरफोर्स के सीमित संसाधनों को अलग-अलग थिएटर कमांड में बांटने से ऑपरेशनल क्षमता घट सकती है।

कॉमन रूम

अवॉर्ड्स के संकेत । स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गैलेंट्री अवॉर्ड्स और विशिष्ट सेवा मेडल का ऐलान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी कई अवॉर्ड घोषित हुए। भारत में वीर चक्र युद्ध काल का तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एयरफोर्स को 9 वीर चक्र मिले और आर्मी को चार। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल (SYSM), विशिष्ट अवॉर्ड में युद्ध सीरीज का सबसे बड़ा अवॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एयरफोर्स को 4 तो आर्मी को 2 SYSM मिले। इसी तरह एयरफोर्स को 5 उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिले, जबकि आर्मी को 3 मिले। युद्ध सेवा मेडल भी एयरफोर्स को 13 तो आर्मी को 9 मिले।

सपोर्ट आर्म नहीं । ध्यान रहे, जुलाई 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एयरफोर्स को ग्राउंड फोर्स के लिए सपोर्ट आर्म करार दिया था, जिस पर विवाद भी हुआ था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह पहली बार सार्वजनिक रूप से बोले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हुई इस झड़प ने साबित कर दिया है कि हम एयर पावर के बिना कुछ नहीं कर सकते।

एयरफोर्स का रुख । एयर चीफ के इस बयान को अगर थिएटर कमांड बनाने की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो साफ संकेत है कि एयरफोर्स अपने उस स्टैंड पर न सिर्फ कायम है बल्कि उसे और पुख्ता तरीके से सामने रख रही है कि थिएटर कमांड में एयर असेट्स को नहीं बांटना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaper/Paid1

कुत्ते की नज़र में हम सब बच्चन साब हैं!

वीर दास

यह अजीब वक्त है। इतना अजीब कि कमीडियन अखबारों में लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह देश के हाल के बारे में क्या कहता है। हां, कुछ लोग इस पर कह सकते हैं कि 'हालात और बदतर हो रहे हैं।'

मुझसे ज्यादा समझदार लोग आपको बताएंगे कि जानवरों में 'बर्थ कंट्रोल' को लेकर कितनी संवेदनशीलता बरती जाती है? शेल्टर होम में छोड़े गए कुत्तों के साथ कैसा बर्ताव होता है? या फिर इनकी नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास के लिए कितना श्रम, पैसा और समय चाहिए। दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया (जिसे बाद में बदल दिया गया), तब एक्सपर्ट्स में यह सब बताने की होड़ लग गई, लेकिन मैं नादान क्या कहूं! मैं न तो इस विषय का जानकार हूं और न ही मुझमें इसकी काबिलियत है।

लेकिन मैं एक इंसान भी हूं। ऐसा इंसान, जिसने सड़क पर रहने वाले देसी कुत्तों को अपनाया है। इसलिए बहुत कुछ न सही, कुछ बातें तो मैं भी बता ही सकता हूं:

कुत्ता मेरे जैसे बेवकूफ और आपके जैसे जीनियस, दोनों को एक ही नजर से देखता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपमें कितनी अक्ल है। सच पूछिए तो क्या प्यार यही नहीं है। मुझे लगता है कि बिना शर्त किसी की बेवकूफी को नजरअंदाज करना ही तो प्यार है।

कुत्तों को चिल्लाना पसंद नहीं। इस लिहाज से से वे अच्छी पत्रकारिता को उन लोगों से अधिक महत्व देते हैं, जो हर रोज न्यूज चैनलों पर चलने वाली प्राइम टाइम डिबेट्स देखते हैं।

मैं यह भी कह सकता हूं कि कोई कुत्ता बेतुके टैरिफ से विचलित नहीं होता। उनके लिए ब्लॉन्ड बालों वाला, शोर मचाने वाला व्यक्ति किसी खिलौने जैसा है, जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है।

अगर किसी इंसान की हाइट कुत्ते से अधिक हो तो वह उसे किस नजर से देखता है, क्या आप जानते हैं? भले ही भारतीयों की औसत हाइट 5 फुट 8 इंच हो, किसी कुत्ते की नजर में हम सब बच्चन साहब हैं।

एक कुत्ता दिन में 1 से 3 बार शौच करता है। इसलिए इंटरनेट पर shit content का जो दरिया है, उसे देखते हुए कुत्ते को भी 'content creator' मानना होगा, वह भी असली वाला।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी कुत्ते को आपका धर्म नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी वे पूजा कर सकते हैं क्योंकि आपमें वे रोज अपने भगवान को देखते हैं।

मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी कुत्ते को पता नहीं होगा कि आपको विरासत में कितनी संपत्ति मिली है। वह यह भी नहीं जानता होगा कि आपने अपनी शादी में कितना पैसा लुटाया है। वे तो भेदभाव देखकर अपने प्रति बर्ताव का पता लगाते हैं।

कुत्ता आसानी से पता लगा लेता है कि आप दयालु हैं या नहीं। ऐसे में वह इसका पैमाना हो सकता है कि आपकी जिंदगी में किस शख्स को होना चाहिए और किसे नहीं।

मुझे लगता है कि जो पीढ़ी कुत्तों को खत्म करने की राह पर आगे बढ़ेगी, वह आगे चलकर उस तरह के प्यार के लिए तरसेगी।

मैं बेझिझक यह भी कह सकता हूं कि आपके कानों में कुत्ते की हांफने की आवाज किसी पॉडकास्ट से कहीं अधिक इन्फॉर्मेशन देकर जाती है। पता है, कुत्ते की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती। अगर आप उसके सामने किसी bird को रखें तो वह 'left wing' को उतनी ही जल्दी चट कर जाएगा, जितनी जल्दी 'right wing' को।

जब कुत्ता किसी को अपना लीडर मान लेता है तो वह आदरभाव से उसका अनुसरण करता है, न कि डर या लालच की वजह से।

यह बात भी साइंस के हिसाब से सही है कि जब कुत्ता आपकी बगल में लेटता है तो उससे आपका बॉडी टेंपरेचर बढ़ जाता है, जबकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो 3 'extra degree' लेने में 9 साल लग जाते हैं।

कुत्ते गुस्सा करते हैं, नफरत नहीं। इसलिए कोई कुत्ता कितना भी गुस्सैल हो, ट्रेनिंग से ठीक हो जाता है। ट्रेनिंग देकर आप उसे इंसानों के साथ पेश आने का तरीका सिखा सकते हैं। आप उसे यह भी बता सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। असल में, गुस्सा कुछ ही समय तक रहता है, लेकिन नफरत हमेशा आपके साथ होती है।

जो कुछ आप कुत्ते में पसंद करते हैं, वह हमारी भारतीय देसी ब्रीड 'indies' में किसी अन्य ब्रीड की तुलना में तीन गुना ज्यादा मिलता है। वे हमारे घर, हमारी गोद, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जगह deserve करते हैं।

मुझे यह भी पता है कि आप भले ही कुत्ते को भूल जाएं, कुत्ता आपको नहीं भूलता। मेरी मानिए तो किसी 'ideology' की तुलना में किसी 'indie' को अपनाना ज्यादा आसान है।

अगर कुत्ता किसी कोने में बैठा है तो वह सुरक्षा देता है। अगर हम कुत्तों के साथ खड़े होंगे, तो हम भी उन्हें सुरक्षा देंगे। हो सकता है कि किसी कुत्ते की वजह से आप किसी रात सो न पाएं हों, लेकिन अगर उन्हें त्याग देंगे तो हमें नींद कैसे आएगी।

असल में, किसी कुत्ते का आपके घर होना जरूरी नहीं, फिर भी आप उसके लिए 'घर' बन सकते हैं। अगर आप उसे अपने घर में जगह देंगे तो पाएंगे कि कैसे वह उसके लिए पूरी दुनिया बन गया है।

(लेखक emmy अवॉर्ड विजेता कमीडियन हैं)

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

सोच बदलना जरूरी

26 अगस्त का संपादकीय 'बेटी बचाओ' पढ़ा। ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी हत्याकांड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि दहेज हत्या जैसे अपराध कानून बनने और लागू होने के दशकों बाद भी थम क्यों नहीं रहे। आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों बेटियां इस लालच की भेंट चढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि समाज की चुप्पी और न्याय व्यवस्था की सुस्ती अपराधियों को मनमानी करने की हिम्मत लगातार दे रही है। समाज को यह समझना होगा कि बेटियों की इज्जत ससुराल में सहनशीलता से नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान से बनी रहती है। अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है, तो जल्द और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन यह काफी नहीं। सही मायनों में हालात बदलने के लिए समाज की सोच में बदलाव लाना होगा।

प्रीति जायसवाल, ईमेल से

पुजारा की पारियां

यह पत्र 25 अगस्त के लेख 'अपने समय का अलबेला क्रिकेटर' से संबंधित है। चेतेश्वर पुजारा भारतीय क्रिकेट के उन विरल खिलाड़ियों में रहे, जिन्होंने चमक-दमक से दूर रहकर टेस्ट क्रिकेट का असली अर्थ समझाया। जब टी-20 ने क्रिकेट को पैसों और मनोरंजन की मशीन बना दिया, तब भी पुजारा ने धैर्य, संयम और एकाग्रता को सबसे ऊपर रखा। आलोचना के बीच भी उनका क्रीज पर टिके रहना टीम को जीत की राह दिखाता रहा। द्रविड़ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह साबित किया कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, इस खेल की जान है।

कार्तिक सैनी, ईमेल से

readersmail.nbt@gmali.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ट्रंप और मस्क : ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर
राजनीति में कब कौन दोस्त या दुश्मन बने, कहा नहीं जा सकता

-ओम प्रकाश हुंडिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

गणेशजी के हाथ की रस्सी सिखाती है अनुशासन

ब्रह्माकुमारी शिवानी

आज जब मनुष्य दिखावा और भौतिक उपलब्धियों के अहंकार में उलझा हुआ है, तब गणेशोत्सव याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना और दिव्य ज्ञान में है। जब हम स्वयं को परमात्मा की रूहानी संतान और विश्व परिवार का सदस्य मानकर देखते हैं, तब अहंकार और भेदभाव के बीज स्वयं समाप्त हो जाते हैं। श्रीगणेश का आशीर्वाद यही है कि हम अपने अंतर में बसे सत्य को पहचानें और जीवन में शांति, संतुलन और सद्‌भाव को स्थापित करें।

श्रीगणेश हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाने का संदेश देते हैं। उनका एकदंत यही संदेश देता है कि हम सबको एकता और विश्व-बंधुत्व में जीना चाहिए। उनका स्वरूप बताता है कि शरीर की बनावट को लेकर कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। हाथी की सूंड पेड़ को उखाड़ भी सकती है और बच्चे को प्यार से उठा भी सकती है। आध्यात्मिक सोच इंसान को कोमल, दयालु और मजबूत भी बनाती है।

गणेशजी का बड़ा पेट हमें दो बातें सिखाता है- पहला, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति हर बात को अपने भीतर रख सकता है, वह बातें फैलाता नहीं है। दूसरा, बड़ा पेट यह भी बताता है कि हमें दूसरों के अलग-अलग स्वभाव और संस्कारों को स्वीकार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। गणेशजी की चार भुजाएं भी गहरा संदेश देती हैं। एक हाथ की कुल्हाड़ी बुराई और नकारात्मक आदतों को काटने का प्रतीक है। रस्सी यह बताती है कि जीवन में अनुशासन जरूरी है।

वरदानी मुद्रा कहती है कि हमें लेने के बजाय देने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों को शुभकामनाएं, प्रेम और सहयोग देते हैं तो हमें और अधिक खुशी और आशीर्वाद लौटकर मिलते हैं। चौथे हाथ का मोदक यह बताता है कि आध्यात्मिक अभ्यास थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा और सुखदायी होता है।

गणेशजी का पूरा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और गुणों से भरा जीवन ही सुख, सफलता और शांति लाता है। लेकिन साथ ही हमें इस पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। जैसे गणेशजी मोदक अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि सबको देने के लिए पकड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी सफलताएं और विशेषताएं परमात्मा को अर्पित करनी चाहिए और उनका उपयोग सबके भले में करना चाहिए।

राजयोग ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास से मनुष्य अपने भीतर ऐसी दिव्य चेतना को जागृत कर सकता है, जो विघ्नहर्ता श्रीगणेश के गुणों को जीवन में उतारने में सहायक बनती है। गणेशजी का बड़ा सिर बड़ी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, उनके विशाल कान सुनने की क्षमता और धैर्य के, वहीं उनका छोटा मुख संयम और मितभाषिता का संदेश देता है।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स: (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 27 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है
-पंचतंत्र

जनहित का मामला नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री दिखाने की मांग करने वालों के मंसूबों पर ठंडा पानी डाल दिया है। अदालत ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को ही रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। इसे निहायत व्यक्तिगत जानकारी मानते हुए अदालत ने साफ कर दिया कि यह कोई जनहित का मामला नहीं है, जो डिग्री को सार्वजनिक किया जाए। सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह फैसला सुनाया। विद्वान न्यायाधीश ने फैसले में स्पष्ट किया कि 'कुछ ऐसा जो जनता की जिज्ञासा का विषय हो' और 'कुछ ऐसा जो जनता के हित में हो' बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सूचना का अधिकार के तहत नीरज नामक एक व्यक्ति के आवेदन के बाद, सीआईसी ने 1978 में बीए (कला स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे दी थी। प्रधानमंत्री ने भी यह परीक्षा वर्ष 1978 में ही उत्तीर्ण की थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस मामले में सवाल उठाने पर उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश पर 23 जनवरी, 2017 को रोक लगा दी थी। सोमवार को आए फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी में जनहित निहित नहीं है। यह भी साफ कर दिया गया कि शैक्षिक योग्यता कोई ऐसी वैधानिक आवश्यकता नहीं है जो किसी सार्वजनिक पद को संभालने या सरकारी जिम्मेदारियां निभाने को जरूरी हो। सच है कि हमारे देश में सांसद, विधायक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता कभी बाधक नहीं रही है। वर्तमान लोक सभा में भी तमाम सांसद 12वीं, दसवीं या उससे कम पढ़े लिखे हैं। आरटीआई अधिनियम को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, न कि सनसनी फैलाने के लिए। इस फैसले से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी राहत मिलेगी। अदालत के फैसले ने सीईसी में बैठे अधिकारियों के ज्ञान के स्तर को भी एक तरह से कठघरे में खड़ा कर दिया है। यदि उन्होंने समझदारी से काम लिया होता तो विवाद ही खड़ा नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को इतना गोपनीय क्यों बनाया जा रहा है। क्या इसीलिए आरटीई में छह साल पहले संशोधन किए गए थे।

महंगी हुई मेट्रो सवारी

दिल्ली में मेट्रो रेल से सफर करना सिर्फ रोमांच नहीं है बल्कि यह महंगा होने के बावजूद यात्रियों की आवाजाही का बेहतरीन परिवहन बन चुका है। दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन ने काफी समय बाद यात्री किराए में एक से चार रुपये की बढ़ोत्तरी की है। दिल्ली की सड़कों पर यातायात व भीड़-भाड़ से त्रस्त दैनिक यात्रियों के लिए मेट्रो सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन के तौर पर प्रचलित हुई। दिसम्बर 2002 में चालू हुई मेट्रो सेवा सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली-एनसीआर में लंबाई/चौड़ाई में फैलती गई, क्योंकि लाखों यात्रियों के लिए सबसे आम साधन के रूप में प्रचलित है। केंद्र सरकार द्वारा ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश से तैयार मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहरी परिवहन बन चुका है। बसों व अन्य स्थानीय साधनों के बनिस्पत यात्रियों को मेट्रो किराए हमेशा ही अधिक लगता रहा है। बस सेवा सुधारने के साथ ही नई तथा इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल कर दैनिक यात्रियों की सुविधाएं भी इस दरम्यान मुहैया कराई गईं। बावजूद इसके मेट्रो यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा है। आबादी का बढ़ता भार सहने वाली दिल्ली को यातायात साधनों का समाधान करना बड़ी चुनौती है। पीक ऑवर में यात्रियों की भारी को संभालना कई दफा मुश्किल हो जाता है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि जगह की कमी से जूझने के लिए स्टैंडिंग बोगियों को प्रचलन में लाने की जरूरत है। मगर उनमें बुजुर्गों, गर्भवती, विकलांगों या बीमारों के लिए लंबा सफर करना मुश्किल हो सकता है। कहने को दो/चार रुपये की बढ़ोत्तरी मामूली है मगर आम दैनिक यात्रियों के लिए एक रुपया भी जेब पर भारी पड़ता है। देश में अभी भी लोगों की मासिक न्यूनतम आमदनी गुजारे लायक नहीं कही जा सकती है। दूर-दराज के इलाकों में रोजगार या शिक्षा के लिए आवाजाही करने वालों की संख्या दिल्ली/एनसीआर में सालों-साल बढ़ती ही जा रही है। उस अनुपात में सड़कों का जाल फैलाने की न तो जगह है, न ही सार्वजनिक परिवहन को लेकर योजनाएं हैं। सड़क क्षमताओं का उपयोग केवल 20% यात्रियों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में पार्किंग खर्च भी भारी पड़ता है। महानगर की बाधाहीन गतिशीलता और अवरोधहीन सुगम आवाजाही के लिए आम दैनिक यात्रियों की जेब पर बगैर अतिरिक्त बोझ डाले सार्वजनिक परिवहन के सुधारात्मक कदम निश्चित रूप से उठाने के प्रति सरकारों को अपना दृष्टिकोण व्यापक करना होगा।

गणेशोत्सव/महेन्द्र तिवारी

संस्कृति और जीवन संदेश

भारतीय संस्कृति में पर्व-त्योहारों का अत्यंत महत्त्व है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक भी होते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख पर्व है गणेशोत्सव, जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणेशजी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता माना जाता है। यही कारण है कि हर शुभ कार्य का प्रारंभ उनके पूजन से किया जाता है।

भाद्रपद मास की चतुर्थी से शुरू होकर दस दिनों तक गणेशोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। महीनों पहले से कारीगर प्रतिमाएं बनाना आरंभ कर देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन घरों व पंडालों में प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती है। दस दिनों तक भक्ति, आरती, भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गणेशजी को लड्डू और मोदक प्रिय हैं, इसलिए भोग में इन्हीं का विशेष स्थान रहता है। इतिहास गवाह है कि मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज गणेशजी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस उत्सव को सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक जागरण का साधन बनाया। उनके बाद पेशवाओं ने भी इस परंपरा को और अधिक भव्य बनाया। ब्रिटिश शासन में सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगी हुई थी। ऐसे समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक स्वरूप देकर इसे राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया। पंडालों में एकत्र होकर लोग राष्ट्रभक्ति के गीत गाते और स्वतंत्रता संग्राम का संदेश फैलाते। इस प्रकार धार्मिक पर्व ने राजनीतिक आंदोलन को नई दिशा दी।

आज गणेशोत्सव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उत्तर भारत, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा विदेशों में भी भारतीय समुदाय इसे धूमधाम से मनाता है। यह पर्व सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुका है। गणेशोत्सव केवल पूजा और अनुष्ठान का पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन-दर्शन का संगम है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, त्याग और एकता के बिना जीवन अधूरा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक समाज तक इस पर्व ने लोगों को जोड़ने का कार्य किया है।

अहम मसलों पर होगा विमर्श

संघ शताब्दी वर्ष

अवधेश कुमार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष इस बार विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रहा है। पूरे 1 वर्ष तक संघ ने अपने विस्तार और सामाजिक आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत सघन कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इन्हीं में से एक कार्यक्रम सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का देश के चार प्रमुख शहरों राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में सक्रिय नागरिकों के साथ संवाद है। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति भवन में 26, 27 और 28 अगस्त को होगा।

कोई संगठन अपने शीर्ष नेता का कुछ घंटे का एक दिन का संबोधन या प्रश्नोत्तर या फिर पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम रखना है। आम सोच यही होगी कि डॉ. भागवत संघ पर लगने वाले आरोपों पर विस्तार से बात रखेंगे तथा अपनी उपलब्धियां का बखान करेंगे। अभी तक संघ की कार्यप्रणाली में ऐसा कभी नजर नहीं आया कि संघ का चरित्र अन्य संगठनों की तरह लगने वाले आरोपों का त्वरित या किसी स्तर पर पत्रकार वार्ता आदि बुलाकर खंडन करना और आत्म प्रचार का हो। जब यह अभी तक संघ की कार्यप्रणाली में रहा ही नहीं तो शताब्दी वर्ष पर सरसंघचालक का राजधानी दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उपयोग वे इसमें करेंगे ऐसी कल्पना निरर्थक है। तो फिर? स्वाभाविक ही तीन दिनों तक लगातार लोगों के सामने संघ की 100 वर्ष की यात्रा, वर्तमान भारत एवं विश्व की स्थिति, उत्पन्न प्रश्न एवं चुनौतियां, उन पर संघ का मत एवं उपस्थित समूह के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि शामिल होंगे।

हां उपस्थित श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में शेष बातें आएंगी। राजधानी दिल्ली के इस कार्यक्रम की ओर निश्चित रूप से संघ के स्वयंसेवकों व समर्थकों के अलावा देश भर के विरोधियों की भी दृष्टि होगी। शताब्दी वर्ष की दृष्टि से संघ का संगठन के बाहर देश के समक्ष शीर्षतम नेतृत्व द्वारा अपनी बात रखने का यह पहला कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से इसकी तैयारी भी उसी अनुसार दिखाई दी है। संघ के विरोधी भी यह मानते हैं कि उनका कार्यक्रम सुव्यवस्थित सुलक्षित होता है। निष्पक्ष दृष्टि रखने वाले मानेंगे कि डॉ. भागवत का यह कार्यक्रम ऐसा होगा कि दूसरे संगठन भी इससे अपने महत्त्वपूर्ण अवसरों का उपयोग करने का तौर-तरीका सीखकर आगे अपनाते हुए दिख सकते है। सच कहा जाए तो यह देश के समक्ष केवल संघ को अपनी बात रखने का एक महत्त्वपूर्ण और बड़ा अवसर नहीं है, देश के लिए भी संघ को जानने समझने का अब तक का सबसे प्रामाणिक आयोजन है। हालांकि 2018 में भी मोहन भागवत ने इसी भवन में संवाद किया था और उसका भी असर हुआ। शताब्दी वर्ष की तैयारी को देखते हुए यह अभी तक का संघ की

दृष्टि से सबसे अलग होगा। पिछले 23 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित प्रतिनिधि सभा के समापन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के सर सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव नहीं मनाएगा बल्कि इसकी जगह हमने इस वर्ष के लिए तीन बिंदु सुनिश्चित किए हैं। एक, आत्मचिंतन करना, दो, संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए समर्थन के लिए आभार प्रकट करना तथा तीन, राष्ट्र के लिए तथा समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करना है। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष में हम अधिक सावधानी, गुणवत्ता तथा व्यापकता से कार्य करने का संकल्प लेते हैं।

स्वाभाविक ही जीवंत सक्रिय संगठन 100 वर्ष की अपनी यात्रा पर आत्चिंतन करेगा। आत्चिंतन व्यापक आयाम वाला विषय है। आत्मचिंतन यानी हम जिन उद्देश्यों के लिए जिन परिस्थितियों में जिस तरह उत्पन्न हुए अभी तक अपने लक्ष्यों की दृष्टि से जो कुछ किया क्या वह संतोषजनक है, कुछ कमियां हैं तो उन्हें कैसे दूर करेंगे, वर्तमान काल और परिस्थिति में हमें और क्या करना है आदि। पिछले दिनों एक साक्षात्कार में मोहन भागवत ने कहा था कि 'डॉक्टर साहब, श्री गुरुजी या बाबा साहब के विचार सनातन परम्परा या संस्कृति से अलग नहीं हैं। प्रगाढ़ चिंतन व कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष प्रयोगों के अनुभव से संघ की पद्धति पक्की हुई और चल रही है। पहले से ही उसमें पोथी निष्ठा, व्यक्ति निष्ठा व अंधानुकरण की कोई जगह नहीं है। हम तत्वप्रधान हैं। महापुरुषों के गुणों का, उनकी बताई दिशा का अनुसरण करना है, परंतु हर देश-काल-परिस्थिति में अपना मार्ग स्वयं बनाकर चलना है। इसलिए नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। संघ में नित्य क्या है? एक बार बाबा साहब ने कहा था कि 'हिन्दुस्थान हिन्दू राष्ट्र है', इस बात को छोड़कर बाकी सब कुछ संघ में बदल सकता है।' सरसंघचालक का वक्तव्य संघ के लिए दिशाबोधक है। अगर वे पूर्व सरसंघचालक को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि मूल विचार को छोड़कर सब कुछ बदला जा सकता है तो इसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

संघ के साहित्य बताते हैं यह स्वयं को समाज परिवर्तन का आंदोलन मानकर सारे कार्य करता है। संघ एक संगठन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का बड़ा आंदोलन है। स्वभाविक है कि शताब्दी वर्ष में इसी को केंद्र में रखकर कार्यक्रम तय किए गए होंगे। जैसा पिछले काफी समय से पत्रकार वार्ताओं में संघ की ओर से बताया जा रहा है कि आगामी समय में सामाजिक परिवर्तन के पांच आयामों पर अपने कार्य को अधिक केंद्रित करेगा। इन पांच आयामों में सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, नागरिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। पिछले सात जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित प्रांत प्रचारक बैठक में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के वक्तव्य की कुछ पंक्तियां इन्हें ज्यादा स्पष्ट करती हैं' शताब्दी वर्ष के सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यापक आउटरीच है, भौगोलिक, सामाजिक दृष्टि से समाज के सभी लोगों तक जाना और सभी कार्यों में उनकी सहभागिता हो। यह अभियान एक तरह से सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी होगा। इन सारी बातों के अवलोकन करने के बाद यह मानने में किसी को हिचक नहीं होगी कि सरसंचालक मोहन भागवत का राजधानी में शताब्दी वर्ष का यह पहला कार्यक्रम अब तक के किसी भी संगठन के कार्यक्रमों से अलग ऐसे विषय, सोच और दिशा लिए हुए होगा जो लंबे समय तक चर्चा में तो रहेगा ही भविष्य में संघ पर बात करने की दृष्टि से उद्धरण की भी भूमिका निभाएगा। साथ ही यह पूरे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की वैचारिक और क्रियात्मक आधारभूमि का पूर्वावलोकन भी होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

सरसंघचालक मोहन भागवत का राजधानी में शताब्दी वर्ष का यह पहला कार्यक्रम अब तक के किसी भी संगठन के कार्यक्रमों से अलग ऐसे विषय, सोच और दिशा लिए हुए होगा जो लंबे समय तक चर्चा में तो रहेगा ही भविष्य में संघ पर बात करने की दृष्टि से उद्धरण की भी भूमिका निभाएगा। साथ ही यह पूरे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की वैचारिक और क्रियात्मक आधारभूमि का पूर्वावलोकन भी होगा

हरसिंगार के पत्तों से मिलती है साइटिका में राहत

- भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हजारों सालों से जड़ी-बूटियों और पेड़-पौधों की ताकत को पहचानती आई है। कई पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम रोज अपने घरों या बगीचों में देखते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपे औषधीय गुणों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है। ऐसा ही एक पौधा है 'हरसिंगार', जिसे अंग्रेजी में 'नाइट जैस्मीन' कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम निक्टेन्थिस आर्बर-ट्रिस्टिस है
- हरसिंगार में छोटे-छोटे सफेद फूल होते हैं, जिनके बीच में हल्का नारंगी रंग होता है। ये फूल बरसात के मौसम में खूब दिखाई देते हैं। हरसिंगार कई गंभीर बीमारियों के इलाज में बेहद उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक शोध में भी पुष्टि हो चुकी है कि हरसिंगार साइटिका जैसी बीमारियों के लिए भी असरदार हो सकता है

(मीडिया इनपुट्स)

संस्कृत के अक्षर बोल सकना ही पहुंचे हुए चमत्कारी साधु होने का प्रमाण है क्या? यह तो अक्षरशः बड़ा अटपटा पैमाना ठहरता है, काहे कि देवनागरी लिपि ने भी अपने सारे अक्षर संस्कृत से ही लिये हैं।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

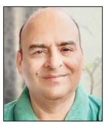

गणपति पूजन और प्रकृति का सम्मान

मुद्दा

पंकज चतुर्वेदी

कुछ ही दिनों में बारिश के बादल अपने घरों को लौटने वाले हैं। सुबह सूरज कुछ देर से दिखेगा और जल्दी अंधेरा छाने लगेगा। असल में मौसम का यह बदलता मिजाज उमंगों-खुशहाली के स्वागत की तैयारी है। सनातन मान्यताओं की तरह प्रत्येक शुभ कार्य के पहले गजानन गणपति की आराधना अनिवार्य है और इसीलिए उत्सवों का प्रारंभ गणेश चतुर्थी से ही होता है, जो इस बार 27 अगस्त को है। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री 'मन की बात' में अपील कर चुके हैं कि देव प्रतिमाएं प्लास्टर आफ पेरिस (पीओपी) की नहीं बनाएं, मिट्टी की ही बनाएं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान की सरकारें भी ऐसे आदेश जारी कर चुकी हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर धड़ल्ले से पीओपी की प्रतिमाएं बन रही हैं और बिक भी रही हैं। ऐसा ही दृश्य देश के हर बड़े-छोटे कस्बों में देखा जा सकता है।

यह तो प्रारंभ है, इसके बाद दुर्गा पूजा या नवरात्रि, विश्वकर्मा पूजा, दीपावली से ले कर होली तक एक के बाद एक के आने वाले त्योहार असल में किसी जाति-पंथ के नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की मजबूत कड़ियां हैं। विडंबना है कि जिन पर्व-त्योहारों के रीति रिवाज, खानपान कभी समाज और प्रकृति के अनुरूप हुआ करते थे, आज पर्व के मायने हैं पर्यावरण, समाज और संस्कृति सभी का क्षरण। निर्देश, आदेश ,अदालतों के फरमान के बावजूद गणपति-पर्व का मिजाज बदलता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र, उससे सटे गोवा, आंध्र प्रदेश व तेलंगांना, छत्तीसगढ़, गुजरात व मप्र के मालवा-निमाड़ अंचल में पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला गणेशोत्सव अब देश में हर गांव-कस्बे तक फैल गया है। दिल्ली में ही हजार से ज्यादा छोटी-बड़ी मूर्तियां स्थापित हो रही है। यही नहीं मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा की ही तरह विशाल प्रतिमा, उसी नाम से यहां देखी जा सकती है। पारंपरिक तौर पर मूर्ति मिट्टी की बनती थी, जिसे प्राकृतिक रंगों, कपड़ों आदि से सजाया जाता था। आज प्रतिमाएं प्लास्टर आफ पेरिस से बन रही हैं, जिन्हें रासायनिक रंगों से पोता जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियों को जब्त करने की चेतावनी भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पूरा बाजार घटिया रासायनिक रंगों से पुती पीओपी की प्रतिमाओं से पटा हुआ है। गणेशात्सव का समापन होते ही नवरात्रि में दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। यह भी लगभग पूरे

भारत में मनाया जाने लगा है। हर गांव-कस्बे में एक से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक पूजा पंडाल बन रहे हैं। बीच में विश्वकर्मा पूजा भी आ गई और अब इसी की प्रतिमाएं बनाने की रिवाज शुरू हो गई है। कहना ना होगा कि प्रतिमा स्थापना कई हजार करोड़ की चंदा वसूली का जरिया है। एक अनुमान है कि हर साल देश में इन तीन महीनों के दौरान 10 लाख से ज्यादा प्रतिमाएं बनती हैं और इनमें से 90 फीसद पीओपी की होती है। इस तरह देश के ताल-तलैया, नदियों-समुद्र में नब्बे दिनों में कई सौ टन प्लास्टर आफ पेरिस, रासायनिक रंग, पूजा सामग्री मिल जाती है। पीओपी ऐसा पदार्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता है। इससे वातावरण में प्रदूषण का मात्रा के बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। प्लास्टर आफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है जो कि जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट) से बनता है चूंकि ज्यादातर मूर्तियां पानी में न घुलने वाले पीओपी से बनी होती है, उन्हें विषैले एवं पानी में न घुलने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबेल रंगों में रंगा जाता है, इसलिए हर साल इन मूर्तियों के विसर्जन के बाद पानी की बॉयोलॉजिकल आक्सीजन डिमांड तेजी से घट जाती है जो जलजन्य जीवों के लिए कहर बनता है। वैसे बहुत से राज्य ऐसी प्रतिमाओं को नदी-तालाब के स्थान पर कृत्रिम बनाए गए तालाबों में विसर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस तरह विसर्जित प्रतिमाओं का जहर भी अंततः प्रकृति में ही घुलता है। परंपरा तो ही थी कि कुम्हार नदी-सरिताओं के तट से यह चिकनी महीन मिट्टी ले कर आता था और उससे प्रतिमा गढ़ता था। पूजा होती थी और-'तेरा तुझको अर्पण' की सनातन परंपरा के अनुसार उस मिट्टी को फिर से जल में ही प्रवाहित कर दिया जाता था, लेकिन आज तो हम नदी में जहर बहा रहे हैं जो जलचरों का काल बना है।

सवाल खड़ा होता है कि तो क्या पर्व-त्योहारों का विस्तार गलत है? इन्हें मनाना बंद कर देना चाहिए? एक तो हमें प्रत्येक त्योहर की मूल आत्मा को समझना होगा, जरूरी तो नहीं कि बड़ी प्रतिमा बनाने से ही भगवान ज्यादा खुश होंगे! क्या छोटी प्रतिमा बना कर उसका विसर्जन जल-निधियों की जगह अन्य किसी तरीके से करके, प्रतिमाओं को बनाने में पर्यावरण मित्र सामग्री का इस्तेमाल करने जैसे प्रयोग तो किए जा सकते हैं। भारतीय पर्व असल में प्रकृति को उसकी देन-आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए होते हैं, लेकिन इस पर बाजारवाद जो रंग चढ़ा है, उससे वे प्रकृति-हंता बन कर उभरे हैं। प्रशासन के लिए भी प्रधानमंत्री की अपील काफी है कि वह बलात पीओपी की प्रतिमाओं के निर्माण पर पाबंदी लगाए। समाज को भी गणपति या देवी प्रतिमाओं को पानी में विसर्जित करने के बजाए जमींदोज करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए।

परिधि

श्रीराम शर्मा आचार्य

मानवीय विकास का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना हो, तो यह मानकर नहीं चला जा सकता कि मनुष्य शरीर पाने तक ही उसकी अंतिम परिधि है। उसे विकासोन्मुख होने के लिए शरीरगत जीवन-यापन को भी सब कुछ न मानकर अपनी सत्ता चेतना के साथ जोड़नी पड़ेगी, जो इस ब्रह्माण्ड पर अनुशासन करती और अंतराल को सुविकसित, स्वच्छ बना लेने वालों पर अपनी उच्च स्तरीय अनुकंपा बरसाती है। साथ ही मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि उसके अंतराल में अति महत्त्वपूर्ण क्षमताओं का भी भंडार भरा पड़ा है, जिसे थोड़ा विकसित कर लेने पर वह काया की दृष्टि से यथावत रहते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से महानतम बन सकता है। इस अध्यात्म विकास के तत्वज्ञान के अनुरूप चेतना को विकसित, परिष्कृत, समर्थ, विलक्षण बनाने का द्वार मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत खुलता है। इससे पूर्व तो वह मात्र जीवधारी ही बनकर रहता है। साथ ही प्रकृति का अनुशासन मानने के लिए बाधित रहता है। उसे प्रकृति पर अनुशासन करने, उसे अपने अनुकूल बनाने की विद्या का ज्ञान तक नहीं होता। प्रकृति पर परमात्मा का स्वामित्व है। दूसरा हस्तांतरण उसके युवराज मनुष्य को उसकी परिपता विकसित होते ही उपलब्ध होने लगता है। यह दूसरी बात है कि वह उस अनुदान का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ प्रयुक्त करता है। विकास की मानवीय परत में उभरते ही उसे आत्मबोध की एक नई उपलब्धि हस्तगत होती है वह अनुभव करता है कि काय-कलेवर उसका समग्र स्वरूप नहीं वरन एक वाहन उपकरण आच्छादन मात्र है। उसके भीतर रहने वाली चेतना ही मनुष्य को ऊंचा उठाती, नीचे गिराती है। मनःस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदाता है। मनुष्य अपने भाग्य निर्माता आप है। वरन व्यक्तित्व का स्तर उठाकर जीवन सज्जा को, अनेक उपलब्धियों-विभूतियों से अलंकृत करना भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तक यह विचारणा नहीं उठती, तब तक वस्तुतः मनुष्य नर-पशु ही रहता है और इंद्रिय लिप्साओं तथा मानसिक तृष्णाओं तक ही उसकी गतिविधियां सीमित रहती हैं, न वह जीवन का महत्त्व समझ पाता है और न उसे चेतना की पृथकता, विशिष्टता संबंधी कुछ ज्ञान होता है।

रीडर्स मेल

समय की मांग

सरकार द्वारा प्रस्तुत लोक सभा में 130वां संविधान संशोधन हालांकि वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है, लेकिन इस विधेयक के पेश किए जाने का मुख्य उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने एवं नैतिकता स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास तो लग ही रहा है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 30 दिन तक जेल में रह जाते हैं तो फिर उन्हें तत्काल अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष की यह दलील कि नैतिकता के प्रतिमान स्थापित होंगे, वहीं विपक्ष की आशंका संस्थाओं की मनमानेपन इस्तेमाल को लेकर है कि गंभीर आपराधिक आरोप के तहत तत्काल जेल में तो डाल दिया जाता है, लेकिन आपराधिक वारदात की पृष्ठभूमि सत्यापित न होने की स्थिति में जो पद चले जाते हैं वे तो लौटकर नहीं आते हैं, जो गरिमा चली जाती है वह तो लौटकर नहीं आती है। पक्ष और विपक्ष के तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता। इन सबों के साथ स्वघोषित रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने नेताओं से नैतिकता की अपेक्षा करें कि वह उसे पर स्वयं खरे उतरे यह समय की मांग है। कानून के क्रियान्वयन के पूर्व उच्च नैतिक मापदंड व्यावहारिक धरातल पर अपनाएं यह भी जरूरी है।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

चुप रहना पीड़ा देता है

दहेज हत्या की घटनाएं केवल अदालतों के केस फाइलों तक सीमित नहीं बल्कि समाज के माथे पर काला धब्बा हैं। कानून किताबों में है, लेकिन बेटियों की चिताएं आज भी जल रही हैं। आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि 6450 केस दर्ज हुए और सजा दर महज 2 फीसद ही है। त्वरित और उचित सजा के अभाव में अदालतों में तारीखों के बढ़ते रहने गुनहगार निर्भिक हो जाते हैं और समाज बेटी को ससुराल की 'मालिकाना संपत्ति' मानकर चुप रह जाता है? मान-सम्मान की लाज में परिवार बेटियों को नरक में सौंप देता है। ऐसे में उनके साथ जो वीभत्स घटनाएं होती है वह पीड़ा देती है। इस बारे में सभी को सोचना होगा।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

'रॉक' हैं चेतेश्वर पुजारा

यह पत्र 'जबर्दस्त विरासत छोड़ गए पुजारा' से संबंधित है। लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 'बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी' जीतने के पीछे सबसे बड़ा श्रेय पुजारा को जाता है। 19 जनवरी 2021 को जिस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को ढाल बनाकर 56 रन की पारी में 11 बार शरीर पर गेंद से आघात झेला और भारत को जीत दिलाने में योगदान दिया वह वर्षों तक याद रहेगा। विकेट पर टिककर तेज और स्पिन दोनों ही गेंदबाजों को थका देने की कला में पुजारा माहिर थे। धैर्य और दृढ़ निश्चय की पराकाष्ठा थे पुजारा। द्रविड़ जिनको 'वॉल' के नाम से जाना जाता था तो पुजारा को भी 'रॉक' यानि चट्टान के नाम से जानना चाहिए। भारत की ओर से सिर्फ 14 खिलाडियों ने 100 या अधिक टेस्ट मैच खेले हैं और पुजारा उनमें से एक हैं। वह भारत की ओर से आठवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके कॅरियर में उनके पिता अरविंद पुजारा का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही चेतेश्वर को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बल्लेबाज बनाने की लिए रात दिन एक कर दिया था।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 13

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

बिहार के युवा मतदाता

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से इसके नागरिकों को अधिकार देता है कि वे 18 वर्ष की उम्र से ऊपर होने पर लोकतन्त्र के महापर्व चुनाव में शामिल हों और अपनी मनपसन्द की सरकारें बनवाने में मदद करें। विधानसभा व लोकसभा चुनावों के लिए 80 के दशक में यह महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाये। यह परिवर्तन स्व. राजीव गांधी की केन्द्र सरकार ने किया था। आश्चर्यजनक यह था कि मतदाता आयु घटाने की मांग मुख्य रूप से उस समय भारतीय जनसंघ (भाजपा) द्वारा की जाती थी। इसके बाद भारत में एक दर्जन से ज्यादा बार केन्द्र व राज्यों के चुनाव हुए और युवा मतदाताओं ने इनमें शिरकत की। वोट का अधिकार भारत के लोगों को सौगात में नहीं मिला, बल्कि स्वतन्त्र भारत की पुख्ता लोकतान्त्रिक नींव के रूप में मिला जिसके लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने साफ घोषणा कर दी थी और 1934 में ही भारत के लोगों से वादा किया था कि स्वतन्त्रता मिलने पर प्रत्येक वर्ग व समुदाय के स्त्री-पुरुष वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक वोट का अधिकार दिया जायेगा और यह ऐसा अधिकार होगा जिसके जरिये भारत के लोग अपनी लोकप्रिय सरकारों का गठन चुनावों में मिले बहुमत के आधार पर कर सकेंगे।

दरअसल यह एक मूक क्रान्ति थी जिसे गांधी बाबा लेकर आये थे क्योंकि एक हजार साल की गुलामी में रहने वाले लोगों में दासता भाव अंग्रेजों ने अपने दो सौ वर्ष के शासन के दौरान कूट-कूट कर भर दिया था। गांधी बाबा ने इसी दासता भाव को एक वोट के अधिकार से तोड़ा और ऐलान किया कि भारत का मतदाता अब स्वयंभू होगा। उसके दरवाजे पर हर पांच साल बाद बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को भी जाना होगा और उनसे वोट की याचना करनी पड़ेगी। पूरी चुनाव प्रणाली को शुचिता व पवित्रता प्रदान करने के लिए एक स्वतन्त्र चुनाव आयोग होगा जो सरकार का अंग नहीं होगा और उसकी सीधी जवाबदेही भारत के मतदाता के प्रति होगी। मगर क्या कयामत है कि यही चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची की सघन जांच करते समय राज्य के युवा समझे जाने वाले मतदाताओं के नाम ही मतदाता सूची से उड़ा रहा है। मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूं कि चुनाव आयोग किस प्रकार काम करता है, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं होता। उसकी निगाह में चुनाव में भाग लेने वाली हर राजनीतिक पार्टी एक समान होती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ है और कौन सी विपक्ष में बैठी हुई है।

> **चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को भारत के लोकतन्त्र का सबसे बड़ा भागीदार मानता है क्योंकि उन्हीं की मार्फत मतदाता चुनाव में अपनी वरीयता दर्शाते हैं और बहुमत की सरकार का गठन होते हुए देखते हैं। मगर क्या कयामत है कि बिहार में मतदाता सूची की जांच करते समय चुनाव आयोग खुद ही 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर रख रहा है और तर्क दे रहा है कि 22 लाख से अधिक मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख अपना घर-बार छोड़ कर दूसरी जगहों को पलायन कर चुके हैं और सात लाख कई-कई स्थानों पर मतदाता बने हुए हैं।**

चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को भारत के लोकतन्त्र का सबसे बड़ा भागीदार मानता है क्योंकि उन्हीं की मार्फत मतदाता चुनाव में अपनी वरीयता दर्शाते हैं और बहुमत की सरकार का गठन होते हुए देखते हैं। मगर क्या कयामत है कि बिहार में मतदाता सूची की जांच करते समय चुनाव आयोग खुद ही 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर रख रहा है और तर्क दे रहा है कि 22 लाख से अधिक मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख अपना घर-बार छोड़ कर दूसरी जगहों को पलायन कर चुके हैं और सात लाख कई-कई स्थानों पर मतदाता बने हुए हैं। मैं चुनाव आयोग के आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा हूं बल्कि यह कह रहा हूं कि इन 65 लाख मतदाताओं की सघन जांच होनी चाहिए क्योंकि 2024 की मतदाता सूची के मुताबिक ये सभी बिहार में विद्यमान थे। इन 65 लाख मतदाताओं की जांच अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सघन रूप से की और पाया कि बिहार के तीन जिलों मधुबनी, पटना और पूर्वी चम्पारण में ही दस लाख 63 हजार मतदाताओं के नाम सूची से काट दिये गये। इनमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लगभग 38 प्रतिशत मतदाता भी शामिल हैं। पहले चुनाव आयोग इन कुल 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने से भी इन्कार कर रहा था मगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उसे सभी के नाम सार्वजनिक करने पड़े। बिहार के ये तीन जिले सर्वाधिक आबादी वाले माने जाते हैं। इन तीनों जिलों के मतदान केन्द्रों के सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है। इन तीन जिलों में विधानसभा की 36 सीटें हैं।

सब जानते हैं कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 36 सीटों पर ही कुल काटे गये 65 लाख मतदाताओ में से 16 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम आ गये। यह तो केवल एक बानगी है जो जांच में सामने आयी है। अगर दस लाख से अधिक मतदाताओं में से 37.8 प्रतिशत मतदाता 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के हैं तो आसानी से समझा जा सकता है कि युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के अभियान को कितना धक्का लगेगा। चुनाव आयोग की यह पहली जिम्मेदारी बनती है कि वह इसका सन्तोषजनक उत्तर दे क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके इकबाल से भारत का लोकतन्त्र बंधा हुआ है। सितम भारत में यह हो रहा है कि चुनाव आयोग आम जनता के बीच सन्देहास्पद बनता जा रहा है जबकि जनता अभी तक मान कर चलती आ रही है कि आयोग का फैसला किसी भी प्रकार से राजनीतिक समीकरणों से नहीं बंधा होता है और वह चुनाव के दौरान एक निष्पक्ष न्यायकर्ता के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग अपना इकबाल बुलन्द रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाये और भारत की जनता को विश्वास दिलाये कि उसकी बनाई गई मतदाता सूची पूरी तरह से त्रुटिविहान होगी। अगर बिहार के कुल 38 जिलों में से तीन की हालत यह है तो शेष 35 जिलों की मतदाता सूचियों के बारे में अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अन्य 35 जिलों के युवा मतदाताओं को अभी से सचेत हो जाना चाहिए और अपने हक के लिए अपना आधार कार्ड या अन्य कोई जरूरी कागज चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड को भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही जरूरी प्रपत्र माना गया है। अभी 1 सितम्बर तक का समय है। तब तक जायज मतदाता अपना दावा पेश कर सकते हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव का दिलचस्प मुकाबला

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
newindianexpress.com

उपराष्ट्रपति के जिस पद को कभी गणतंत्र की खामोश अंतरात्मा माना जाता था, वह आज इसका वाचाल परिचालन केंद्र है, जो कुर्सी कभी दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और संविधान के रक्षक की कुर्सी मानी जाती थी, वह अब परम सत्ता संरक्षक, चुनावी प्रतिनिधि और सत्ता की विचारधारा के आक्रामक समर्थक की कुर्सी बन गयी है। इस साल का विवाद, पहले की तरह भारत के बारे में बताता है। एनडीए ने संघ के स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना है, जो तमिलनाडु से हैं। इसके विपरीत, इंडिया गठबंधन ने न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को चुना है, जो न्यायशास्त्र की अंतरात्मा के प्रतिनिधि हैं। ऊंची जाति के होने के बावजूद वह उदारवादी हैं तथा नागरिक आजादी, संवैधानिक नैतिकता और न्यायिक शुद्धता के आग्रही हैं।

गणतंत्र के शुरुआती दशक में उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ करता था और समान विचारधारा की बजाय योग्यता पर जोर दिया जाता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक-ये सभी सर्वसम्मति से चुने गये थे लेकिन इंदिरा गांधी ने दबाव बनाने के युग की शुरुआत की, उन्होंने परंपरा पर निष्ठा को तरजीह दी। इस तरह जाति, पंथ तथा क्षेत्र चुनाव के आधार बनने लगे। यह प्रवृत्ति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने लगी, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग ने संसद को संवाद के मंच की बजाय विधेयकों को पारित करने की जगह मान लिया। चूंकि उत्तरोत्तर आने वाली सरकारों ने अपने बहुमत के बूते लोकसभा में विधेयकों को पारित कराना शुरू कर दिया, ऐसे में राज्यसभा लोकतंत्र की खासियत की आखिरी सीमा बनी।

ऐसे में, उच्च सदन में उपराष्ट्रपति का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण हो गया और यहीं पर भाजपा की सक्रियता का मतलब है, उपराष्ट्रपति अगर तटस्थ होता है तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं, समान विचारधारा का होने पर फायदा है। अब तक के उपराष्ट्रपतियों का रोस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस की तरह लगता है। ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, लिंगायत, जाट, कायस्थ, कम्मा, हर चुनाव ने एक सांस्कृतिक गणना दिखायी, तो हर हार में गहरे मतभेद सामने आये। जैसे, शिंदे बनाम शेखावत (दलित बनाम राजपूत), हेपतुल्ला बनाम अंसारी (मुस्लिम विविधता बनाम मुस्लिम कूटनीति), अल्वा बनाम धनखड़ (ईसाई अल्पसंख्यक बनाम हिंदू बहुसंख्यक) वर्ष 2025 में भी यह सिलसिला कायम है। भगवा तमिल बनाम तेलुगू न्यायिक सेवा, स्टालिन का संघवाद बनाम आरएसएस का केंद्रवाद, नेहरूयुगीन अंतरात्मा की पुकार बनाम राष्ट्रवादी वर्चस्व। यही नहीं, हर उपराष्ट्रपति चुनाव की अपनी कहानी है, वर्ष 2002 में यूपीए ने महाराष्ट्र से चर्चित दलित चेहरे सुशील कुमार शिंदे को भाजपा दिग्गज और राजस्थान के प्रमुख राजपूत नेता भैरों सिंह शेखावत के मुकाबले मैदान में उतारा। वह शुद्ध रूप से जाति आधारित मुकाबला बन गया। वर्ष 2007 में एनडीए ने विमर्श बदल दिया, उसने उपकुलपति रहे दिग्गज कूटनीतिज्ञ और शैक्षणिक तथा भारतीय विदेश सेवा से जुड़े संस्थानों से जुड़े मुस्लिम प्रत्याशी हामिद अंसारी के मुकाबले मुस्लिम महिला नजमा हेपतुल्ला को उतार दिया। यूपीए के सांस्थानिक उदारवाद के मुकाबले एनडीए ने विविधता का पक्षधर होने की सुविचारित कोशिश की।

> **राज्यसभा विमर्श और विवेचना का सदन है, ऐसे में इसके सभापति अगर सिद्धांत के बजाय सत्ता को तरजीह दें तो उच्च सदन की कार्यवाही सर्वाधिक प्रभावित होगी। दलगत राजनीति से विध्वस्त भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा उपराष्ट्रपति चाहता है जो जाति और पंथ के दायरे से ऊपर उठे। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव संविधान की अंतरात्मा और बहुसंख्यक की ताकत के बीच का चुनाव है।**

यह सिलसिला 2022 में भी जारी रहा, जब यूपीए ने कर्नाटक से एक वरिष्ठ ईसाई नेत्री मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। महिला और अल्पसंख्यक होने के साथ दक्षिणी राज्य कर्नाटक का होने के कारण यूपीए की प्रतीकवाद राजनीति सुस्पष्ट थी। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला राजस्थान के जाट नेता और नरेंद्र मोदी के प्रति घोषित निष्ठावान जगदीप धनखड़ से हुआ। नतीजा जोरदार रहा, धनखड़ 346 मतों से विजयी हुए। एक बार फिर भाजपा का राज्यसभा में नियंत्रण हो गया। कभी प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए जिस जातिगत समीकरण का प्रयोग किया जाता था, अब उसका इस्तेमाल विपक्षी एकता को विभाजित और बाधित करने के लिए किया जाने लगा। वर्ष 2025 में भी यह सिलसिला जारी है। उपराष्ट्रपति पद के दोनों प्रत्याशियों ने दक्षिण भारत को मुश्किल में डाल दिया है, तमिल गौरव भाजपा के प्रत्याशी को स्वीकार करेगा या आंध्र की निष्ठा केंद्र के फरमान के आगे सिर झुकायेगी? संसद में संख्या बल भाजपा के साथ है और उसके गठबंधन सहयोगी अनिच्छुक होते हुए भी उसके निर्देश का पालन कर सकते हैं लेकिन इस चुनाव की प्रतीकात्मकता की (जो नेहरूवाद बनाम आरएसएस, तमिल बनाम तेलुगू, स्टालिन बनाम संघवाद है) अनदेखी करना कठिन है। इंडिया गठबंधन उम्मीद कर रहा है कि सुदर्शन रेड्डी की क्षेत्रीय पहचान एनडीए में फूट पैदा कर सकती है। इसके विपरीत, एनडीए को विश्वास है कि संघ का एक परंपरावादी आदमी धर्मनिरपेक्ष शिविर में सेंध लगा देगा, ये दोनों प्रत्याशी नहीं, शतरंज के दांव हैं और खेल का उद्देश्य संघवाद को विखंडित करना है।

यह चुनाव राजनीतिक संस्कृति पर भी एक फैसला होगा। हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ जैसे पक्षपाती उपराष्ट्रपतियों का दौर, जिनका विपक्षी सदस्यों से विवाद लगातार होता रहता था, शायद अब स्वाभाविक हो चला है, उपराष्ट्रपति की कुर्सी तटस्थ नहीं रह गयी है। राज्यसभा विमर्श और विवेचना का सदन है, ऐसे में इसके सभापति अगर सिद्धांत के बजाय सत्ता को तरजीह दें तो उच्च सदन की कार्यवाही सर्वाधिक प्रभावित होगी। दलगत राजनीति से विध्वस्त भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा उपराष्ट्रपति चाहता है जो जाति और पंथ के दायरे से ऊपर उठे। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव संविधान की अंतरात्मा और बहुसंख्यक की ताकत के बीच का चुनाव है। इस बार वोट डालते हुए हमारे सांसदगण सिर्फ अगले उपराष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे, बल्कि अखंड बहुसंख्यकवाद और बहुलतावादी संभावना के बीच आधिकारिक निर्णय भी करेंगे। ध्यान रहे, जब उपराष्ट्रपति ताबेदार बन जाते हैं, तब गणतंत्र अतीत का अवशेष मात्र रह जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सुदर्शन रेड्डी तक, दर्शनशास्त्र से विखंडन तक, उपराष्ट्रपति का कार्यालय क्रमश: अध:पतन को प्राप्त हुआ है। इसका कारण यह नहीं है कि प्रत्याशी कम योग्य हैं, बल्कि यह है कि चुनाव का आधार श्रेष्ठता की जगह मुनाफे तक सीमित रह गया है जो देश कभी विचारों के लिए उपराष्ट्रपति की ओर देखता था, वह देश इस चुनाव के जरिये अब जाति समूहों, क्षेत्रों तथा बेचैन गठबंधनों को संदेश देता है। देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक कार्यालय दूसरा सबसे प्रतीकात्मक कार्यालय है, जो अब सम्माननीय कम और खोखला ज्यादा है।

भारत की आन, बान, जान, शान और पहचान है, उर्दू !

फिरोज बख्त अहमद

उर्दू एक भाषा होने के साथ-साथ एक तहज़ीब, परंपरा और प्यार की भाषा भी है, जो भारत की कोख से जन्मी है और हर भारतीय भाषा, क्षेत्र, समाज, धर्म और संस्कृति की सुगंध शामिल है इस में। यह भारत की आत्मा से जुड़ी भाषा है। यह विकसित भारत की भाषा है। इसी संदर्भ में पटना के बापू धाम में एक विशाल संगोष्ठी इस बात को लेकर हुई कि उर्दू तो अपने जन्म से ही भारत के विकास से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उर्दू से जुड़ी सभी संस्थाओं और संस्थानों को अपने राष्ट्र विकास मंत्र, 'सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास' से जोड़ा है, जिसका जीता- जगता उदाहरण हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद विकास (नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज) का पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्रि-दिवसीय समागम, 'उर्दू भाषा का भविष्य, विकसित भारत @ 2047', था, जिसमें उर्दू से जुड़े लेखकों, शायरों, नाटककारों आदि ने उर्दू के भूत, वर्तमान और भविष्य को विकसित भारत के विषय से बख़ूबी जोड़ा।

विकसित भारत और उर्दू के संदर्भ में बिहार के राज्यपाल, आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि पटना में इस प्रकार की संगोष्ठी इस बात का प्रमाण है कि सरकार उर्दू की सर्व धर्म समभाव वाली सद्भावना के साथ है और इस भाषा से जुड़ी सभी सरकारी संस्थाओं का साथ दिया है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष, डॉ. शम्स इकबाल के अनुसार उर्दू में देश हित के अतिरिक्त होली, दीपावाली, दशहरा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री कृष्ण आदि के इकबाल में भी बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जा रहा है। उर्दू भारत के कण-कण में रची बसी है। उनका कहना-उर्दू है खालिदा खानम तो हिंदी राजकुमारी है, पूरी महफ़िल लूट ले गया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भारतीय भाषाएं और विशेष रूप से उर्दू भले ही बाज़ार में, विज्ञापनों में और रोजगार में भले है जगह बनाएं या न बनाएं, हां देशवासियों और भारत के अंतर्मन में सटीक रूप से जगह बनने में सक्षम हैं। उर्दू के साथ सब से बड़ी नाइंसाफी यह हुई कि इसे मुसलमानों की भाषा समझ लिया गया और इसके विरुद्ध द्वेष बढ़ता गया। इतनी नफरत बढ़ी कि इसे विभाजन और पाकिस्तान बनाने का ज़िम्मेदार तक समझ लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि मुस्लिमों की कोई भाषा है तो वह है, अरबी, न कि उर्दू। उर्दू के लेखकों और शायरों की कमी नहीं, जैसे, बृजनारायण चकबस्त, देश शंकर नसीम, मुंशी हरगोपाल तुफ्तका, फ़िराक़ गोरखपुरी, कृष्ण चंद्र, राम लाल, बशेशर प्रदीप, मोहिंदर सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, तिलोक चंद महरूम, जगन्नाथ आज़ाद, कृष्ण बिहारी नूर, रत्न नाथ सरशार, मुंशी नवल किशोर गोपी चंद नारंग, चरण सिंह बशर, मुंशी नवल किशोर आदि।

भारत के चीफ इमाम डॉ. उमैर अहमद इलियासी का मानना है कि किसी भी भाषा का कोई धर्म नहीं होता और भाषा उसकी हो जाती है, जो उसे दिल से चाहता है। उर्दू तो शुरू से ही भारत के विकास की द्योतक रही है। उनके अनुसार उर्दू पर प्राय: इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं कि इसने पाकिस्तान बनवाया, सरासर बेबुनियाद और झूठे हैं क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना जिन्ना की धार्मिक सांप्रदायिकतावादी मानसिकता ने कराई थी। "उर्दू तो प्यार-मुहब्बत और दिल की रूहानी भाषा है! विकसित भारत की आन, बान, शान और पहचान है, उर्दू !" कहते हैं इलियासी।

उर्दू साझा विरासत और आपसी भाईचारे की भाषा है। जिस समय अंग्रेज भारत पर पंजे गड़ा कर बैठे थे, उस समय देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी उर्दू अखबार, जैसे, 'अवध अखबार', 'उर्दू अखबार', 'पैसा अखबार' 'जाम-ए- जहांनुमा', 'अकमल-उल-अखबार', 'अल-मशरिक', 'अल-हिलाल', 'अल-बालाग' आदि। देशभक्ति की कितनी कविताएं हिंदी या अन्य भाषाओं में हैं, उतनी ही उर्दू में भी हैं, जैसे, 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा', 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है', 'मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहां' आदि।

इसी प्रकार से उर्दू भाषा में राजकुमार उपाध्याय का नाटक, 'गांधी तुम कहां हो' भी इस बात को प्रमाणित करता है कि हर दौर में उर्दू के भारत की संप्रभुता और भारत सर्वोपरि को सर्वोपरि रखा है। ईमानदारी की बात तो यह है कि जहां-जहां कोई उर्दू बोलता है, वहां वहां हिंदुस्तान बोलता है। राजा राम मोहन रॉय, डा. राजेंद्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा, मुरली मनोहर जोशी आदि सभी मदरसों के छात्र रहे हैं।

आज से ही नहीं शुरू से ही उर्दू ने विकसित और सुरक्षित भारत के संदर्भ में भारत के लिए, 'चमन', 'गुलज़ार', 'गुलशन', 'बाग-ओ-बहार', 'गुल-ए-बहार' आदि शब्दों से सुसज्जित किया है। आज के दौर में भी उर्दू में भारत की प्रगति को ले कर खूब लिखा जा रहा है। भारतीय उर्दू विकास परिषद की ओर से प्रकाशित होने वाली, बच्चों की मासिक उर्दू पत्रिका, 'बच्चों की दुनिया' में चंद्रयान विक्रम, ब्रह्मोस मिसाईल, कोविड वैक्सीन, सूर्य पर खोज आदि के बारे में लिखा जाता रहा है। पहले अंतरिक्ष में गए राकेश शर्मा के बारे में ख़ूब लिखा गया और अब सुधांशु शुक्ल के ऊपर भी नज़्में लिखने वालों की कमी नहीं।

बकौल, डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, (अध्यक्ष इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया), उर्दू विकसित भारत की आन, बान, शान, जान और पहचान है। उन्होंने ने बताया कि विकसित भारत और उर्दू के मेल-जोल और सद्भावना का ही परिणाम है कि उर्दू के पत्र-पत्रिकाओं में श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, होली, दीपावली, दशहरा आदि पर खूब लिखा गया है। एक लंबे अर्से तक चले मुशायरे, 'जश्न-ए-बहार' की संयोजिका, कामना प्रसाद का मानना है बरसों बाहरी ताकतों ने लूटा, मगर बावजूद इसके कारण, यह ऊपर वाले की कृपा से रचा-बसा रहा। एक और सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके देश वासियों ने न तो रूहानियत का दामन न छोड़ा और न ही नवीनता का। देश आत्मिकता के साथ आधुनिकता का अनुसरण करता रहा, जिसके कारण यह आज विश्व गुरु बनने की कगार पर है।

सीमाओं पर साजिश के तहत हो रहा डेमोग्राफी बदलाव : शाह

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक "सोची समझी साजिश " के तहत हो रहा है और वे देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। शाह ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों से अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सीमाओं से कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए।

उन्होंने समुद्री और स्थलीय सीमाओं पर कई अतिक्रमण को हटाने में सराहनीय कार्य करने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की। यहां दो दिवसीय 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वीवीपी तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है -- सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि सीमावर्ती गांवों के प्रत्येक नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ मिले और वीवीपी के तहत गांवों को सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए मजबूत उपकरण के रूप में विकसित करना। शाह ने जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद नागरिक अपने गांवों को न छोड़ें, पलायन को रोका जाए और गांव की आबादी भी बढ़े। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन चिंता का विषय है।

मंत्री ने कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल जिलों के कलेक्टरों को इस मुद्दे को गंभीरता से और बारीकी से ध्यान देकर समाधान करने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। यह नहीं माना जाना चाहिए कि ऐसा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है, बल्कि, यह एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मुख्य सचिवों और सीएपीएफ से भी इस मुद्दे पर ध्यान देने को कहा।

हर नागरिक को मिले योजनाओं का लाभ

शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वीवीपी की अवधारणा प्रस्तुत की तो यह निर्णय लिया गया कि इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। न केवल हर सीमांत गांव को सभी सुविधाओं से युक्त किया जाए, बल्कि सीमांत गांवों में रहने वाले हर नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लैस करके उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया जाए। इन गांवों को देश और सीमा की सुरक्षा के मजबूत उपकरण के तौर पर विकसित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के अंतिम गांव को देश के पहले गांव के रूप में नामित कर सीमावर्ती गांवों को देखने का लोगों का नजरिया बदल दिया।

नैनी झील की बदहाल स्थिति

दैनिक पंजाब केसरी दिल्ली उन समस्याओं को उठाने तथा प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है जो जन-जन की आवाज है तथा जिन्हें अफसरशाही नजरंदाज कर देती है। ऐसी समस्याएं हमें इस पते पर प्रेषित करें- संपादक, आवाज-ए-खबरदार, 2 प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली-35 या ई-मेल करें pnjkesri@gmail.com

मैं आपके माध्यम से संबंधित एमसीडी अधिकारियों का ध्यान मॉडल टाउन स्थित नैनी झील और आसपास के क्षेत्रों की बदहाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। यहां की सड़कें जगह-जगह टूटी हुई हैं और बड़े गड्ढों में बरसात के दौरान जलभराव हो जाता है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आए दिन दुर्घटनाओं का डर बना रहता है।

इसके अतिरिक्त झील के आसपास कचरा फैला रहता है और सफ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से चूहों की समस्या बढ़ती जा रही है, जो निवासियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। स्थानीय निवासियों ने कई बार एमसीडी के अधिकारियों (स्वच्छता निरीक्षक) एवं एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत की परंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह नगर निगम की गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। संबंधित विभाग तुरंत कार्यवाही करें और नैनी झील क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण मिल सके।

श्रीमती बीनू चौहान (वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब)
ब्रांच हेड, मॉडल टाउन शाखा

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

जो देशसेवा करना चाहता है, उसके पास सोचने के साथ ही काम करने की इच्छाशक्ति का होना जरूरी है। -प्लूटो

भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लागू कर अपनी अहंमन्यता और दोहरे आचरण का सच पूरी तरह उजागर करने वाले अमेरिका की ही रेटिंग एजेंसियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताना एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, यह सतर्क नीति-निर्माण की मांग भी करता है।

भरोसा और चुनौतियां

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के आज लागू होने के पहले अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों-पहले एस एंड पी और अब फिच का यह संकेत कि अमेरिकी टैरिफ का हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिहाज से आश्वस्त करता है। दुनिया को दूसरे शीतयुद्ध काल में ले जाने पर तुले अमेरिका को बेशक लगता हो, कि इन हथकंडों से वह भारत को दबाव में ले आएगा, लेकिन वस्तु-स्थितियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अमेरिका को भारत से होने वाला निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज दो फीसदी है। इसके अलावा, भारत बहुत तेजी से विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रहा है, जो यकीनन नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देंगे। दरअसल, रूस से तेल खरीदने का मामला बताकर भारत पर अतिरेक टैरिफ लागू कर अमेरिका ने अपनी अहंमन्यता और दोहरे आचरण का सच पूरी तरह उजागर कर दिया है, तो दूसरी तरफ अगर अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही हैं, तो यह अकारण नहीं है। रूस-यूक्रेन और इस्राइल-हमास/ ईरान युद्धों की शुरुआत के बाद से ही वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर मंडरा रहे संकट के बावजूद हम देख चुके हैं कि वैश्विक रेटिंग एजेंसियां लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताती रहीं। एस एंड पी रेटिंग एजेंसी ने करीब दो हफ्ते पहले अठारह वर्ष में पहली बार भारत की साख में इजाफा किया है, तो इसका कुछ अर्थ है। फिच रेटिंग ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जो 'बीबीबी' श्रेणी के अन्य देशों के औसत से कहीं अधिक है। यह मजबूत आर्थिक वृद्धि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च, निजी उपभोग और अनुकूल जनसांख्यिकी से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 695 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो करीब 11 महीनों के आयात को कवर करने में सक्षम

है। ये आंकड़े देश की आर्थिक स्थिरता को रेखांकित करते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनकी ओर फिच भी इशारा करती है। फिच का अनुमान है कि 2026 तक भारत का सरकारी कर्ज जीडीपी के 56.1 फीसदी तक पहुंच सकता है, जो भले ही कई विकसित देशों से कम हो, लेकिन भारत जैसे उभरते बाजार के लिए चिंता का विषय है। वजह यह है कि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश की जरूरत है, जिससे राजकोषीय संसाधनों पर दबाव पड़ना तय है। ऐसे में जरूरी है कि नीति-नियंता कर्ज प्रबंधन का एक स्पष्ट रोडमैप बनाएं। फिच की स्थिर रेटिंग से स्पष्ट है कि भारत हर तरह की चुनौती झेलने में सक्षम है, लेकिन यह सतर्क नीति-निर्माण की मांग भी करती है।

भू-राजनीति में मनमानी नहीं चलती

आज अमेरिका जो भी कर रहा है, वह उसकी कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि ट्रंप दो कदम आगे, तो तीन कदम पीछे और कुछ कदम दाएं-बाएं चलते दिखाई दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर राष्ट्राध्यक्ष मनमानी करने लगें, तो इससे दुश्मन डरे न डरे, दोस्त जरूर दूर होने लगते हैं।

यह कयास लगाया जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, तो इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन, जो हुआ वह अमेरिका और यूरोप के कुछ नेताओं को काफी निराशा दे गया और पुतिन के कद को और ऊंचा बना गया। यूरोपीय नेताओं की निराशा जायज हो सकती है, लेकिन उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि ट्रंप की विदेश नीति उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से चलती है, जिसमें दुनिया में घट रही घटनाओं और वैश्विक उथल-पुथल के लिए कोई खास जगह नहीं है।

इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। 14 फरवरी, 1972 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने चीन की यात्रा कर निक्सन को सलाह दी थी कि रूसियों की तुलना में चीनी उतने ही खतरनाक हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि, '20 साल बाद आपका उत्तराधिकारी, यदि वह आपकी तरह बुद्धिमान हुआ, तो चीनियों के विरुद्ध रूसियों की ओर झुक जाएगा।' ट्रंप 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी शुरुआत में रूस की तरफ झुकते दिखे थे, लेकिन बाद में बदल गए। अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी कुछ वैसा ही दिख रहा है।

रहीस सिंह

वैदेशिक मामलों के जानकार

1950 के दशक में आइजनहावर प्रशासन ने चीन के नेता माओ त्से तुंग और सोवियत संघ के निकिता खुश्चेव के बीच दरार डालने की कोशिश में रूसियों से बेहतर संबंध रखे। अक्तूबर 1959 में, जब ख्रुश्चेव आइजनहावर से कैंप डेविड में मुलाकात कर लौटे, तो वे बीजिंग पहुंचे और यह संदेश दिया कि चूंकि अमेरिका के साथ सोवियत संबंध सुधरे हैं, इसलिए मास्को चीन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का समझौता तोड़ देगा। इसके दस साल बाद निक्सन ने आइजनहावर की नीति पलट दी और अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बीजिंग को शामिल कर लिया। कुछ साल बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इस नीति को और आगे बढ़ाया।

सोवियत प्रभाव को दक्षिण-पूर्व एशिया में फैलने से रोकने के लिए कार्टर प्रशासन ने चीन के वियतनाम पर आक्रमण को मौन स्वीकृति दे दी। इसके बाद की अमेरिकी सरकारों-चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, ने अंगोला, अफगानिस्तान और कंबोडिया में सोवियत संघ के खिलाफ चीन के साथ मिलकर प्रॉक्सी युद्ध लड़े, जिसने सोवियत शक्ति को बुरी तरह कमजोर किया। यानी आज अमेरिका जो भी कर रहा है, वह उसकी कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन ट्रंप दो कदम आगे तो तीन कदम पीछे और कुछ कदम दाएं-बाएं चलते दिखाई देते हैं। यह दिख रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की विदेश नीति गहन जानकारी और विशेषज्ञता के बजाय उनकी गट फीलिंग पर आधारित है।

इस समय ट्रंप ने जो माहौल निर्मित किया है, उससे ऐसा लगता है कि सभी को अमेरिकी बाजारों तक पहुंच चाहिए। वैसे यह सच भी है, तभी तो ट्रंप ने अपनी विदेश नीति को टैरिफ हथियार के जरिये चलाना शुरू किया। लेकिन, यह हथियार व्यक्तिगत तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हित में भले ही हो, अमेरिका के हित में नहीं है। ट्रंप अगर 'माइट-मेक्स-राइट' के सार्वभौमिक सिद्धांत पर चलने का निर्णय ले चुके हैं, तो उनके लिए यह नुकसानदेह है, क्योंकि यह दोस्तों को दूर कर देगा और दुश्मनों को डरा नहीं पाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रपति की मनमानी नहीं, बल्कि सुसंगत सिद्धांत होने चाहिए। मनमानी जियो पॉलिटिक्स में प्रायः अप्रत्याशित व खतरनाक परिणाम देती है।

वैसे भी ट्रंप न तो विश्ववादी (ग्लोबलिस्ट) हैं, न एकांतवादी (आइसोलेसनिस्ट) हैं और न ही क्षेत्रीय प्रभाव वाले क्षेत्रों (रीजनल स्फेयर्स) के समर्थकों पर विश्वास रखने वाले हैं, वह सिर्फ ट्रंपवादी हैं। उनकी विदेश नीति को तीन श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में चीन और रूस जैसी शक्तियां आती हैं। दूसरी में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को रखा जा सकता है और तीसरी श्रेणी में वे गरीब देश आते हैं, जिन्हें बड़ी शक्तियां 'ग्रेट गेम' का हिस्सा बनाए रखना चाहती हैं। रूस व चीन से अमेरिकी संबंध जटिल और टकरावपूर्ण रहे हैं। आज के समय में यदि इनके साथ यूक्रेन, इस्राइल, ईरान, सीरिया, तुर्किये, उत्तर कोरिया और ताइवान जैसे देशों को भी जोड़ दें, क्योंकि इनके 'हेड या टेल' वहां तक हैं, तो मामला और जटिल हो जाता है। ऐसे में ट्रंप की जिम्मेदारी यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने और इस्राइल पर नियंत्रण स्थापित कर फलस्तीन में शांति लाने की हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया मान लेगी कि ट्रंपिज्म सफल है। हो सकता है कि यह उन्हें नोबेल पुरस्कार तक भी पहुंचा दे। लेकिन, निष्कर्ष तक पहुंचते हुए यह ध्यान रखना होगा कि पुतिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक भूमिका निभाना चाहते हैं और चीन हिंद-महासागर में अपना जाल बिछाते हुए इसे क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए इस्तेमाल करने का हुनर सीख चुका है। यानी ट्रंपिज्म की राह में दीवार ही नहीं सीधे पर्वत खड़ा है। वैसे भी ट्रंप चीन से डरे हुए लग रहे हैं। तभी तो पहले चीन को टैरिफ से डराने की कोशिश की, लेकिन जब चीन ने पलटवार कर दिया, तो इतना डर गए कि एक बार फिर समयसीमा बढ़ा दी। यही नहीं उन्होंने एनवीडिया चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध हटाकर अपनी ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को कमजोर कर दिया।

ट्रंप भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका को एक संदिग्ध की तरह देख रहे हैं और भारत के साथ बना हुआ तालमेल कमजोर पड़ता दिख रहा है। संभव है कि ब्रिक्स इस तालमेल को और मजबूत करे। हां, गरीब या छोटे देशों जैसे अजरबेजान और आर्मीनिया तथा कांगो और रवांडा में ट्रंप कामयाब रहें। अजरबेजान-आर्मीनिया में शांति समझौता और कांगो-रवांडा के बीच संघर्ष विराम ट्रंप की उपलब्धियों के रूप में देखा जा सकता है।

कुल मिलाकर ट्रंप की विदेश नीति एक तरफ मास्को और बीजिंग की मनुहार, पाकिस्तान से क्रिप्टो डील के बदले नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन में सहयोग और कतर के साथ गिफ्ट डिप्लोमैसी (विमान) तक सिमटी दिख रही है। इससे ट्रंप के हित भले ही सध जाएं, लेकिन अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगेगा, बल्कि दुनिया इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी कि अमेरिकी शक्ति अब न तो बेजोड़ है और न ही निर्विवाद।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

फ्रेडरिक नीत्शे

जीवन का आनंद दूसरों के साथ आता है। प्रेम, दोस्ती और रिश्ते, ये वे रंग हैं, जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं। सच्चा प्रेम वह है, जो हमें मजबूत बनाए और हमारे असली स्वरुप को खोजने में मदद करे।

अपनी कहानी के कैनवास पर खुद ही रंग भरना है

__जीवन__ एक अनोखा सफर और एक ऐसा रंगमंच है, जहां हर इन्सान अपनी कहानी खुद लिखता है। जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। धर्म, समाज, और परंपराएं हमें अक्सर बताती हैं कि जीवन का मकसद क्या है, लेकिन उनके नियमों पर आंखें मूंदकर भरोसा न करें। जीवन एक खाली कैनवास, तो हम ही वह चित्रकार हैं, जो इसे रंगों से भर सकते हैं। यह एक मौका है, जब अपने लिए एक नया अर्थ, एक नया रास्ता बनाने के लिए अपने जीवन की कहानी के कैनवास में रंग भर सकते हैं। क्या हम अपने सपनों को सच करने की हिम्मत कर सकते हैं? अपने डर को गले लगाकर उसे ताकत में बदलने की?

जो समाज के बनाए बेबुनियादी नियमों से ऊपर उठता है, जो अपनी कमजोरियों को चुनौती देता है, और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोजता है। वही अपने सपनों तक पहुंच पाता है। हम सबके भीतर वह शक्ति है कि हम सामान्य से असाधारण बन सकें, लेकिन इसके लिए हमें अपने डर, अपने शक और समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ना होगा, जो हमें जकड़ती हैं। अपने आप को बार-बार नया बनाएं, हर दिन एक बेहतर इन्सान बनने की कोशिश करें। हर दिन खुद से पूछें कि क्या मैं आज वह इन्सान हूं जो कल था? अगर जवाब नहीं है, तो हम सही रास्ते पर हैं। जीवन में दुख और पीड़ा से कोई नहीं बच सकता। लेकिन इनसे भागने की जरूरत नहीं है। पीड़ा हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि गुरु है। हर दुख, हर असफलता, हमें कुछ सिखाती है। जब जीवन नीचे गिराए, तो उठें, और मुस्कराकर आगे बढ़ें। दुख को गले लगाएं, क्योंकि यह हमें वह ताकत देता है, जो सुख कभी नहीं दे सकता। जीवन एक नृत्य है, एक संगीत है, जिसे हमें अपने तरीके से जीना है। समाज हमें नियमों में बांधना चाहता है, यह करो, वह मत करो, लेकिन अपने दिल की सुननी चाहिए।

जीवन का आनंद उसकी आजादी में है, उसकी रचनात्मकता में है। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो अपने दिल की आवाज को सुनने की? जीवन का आनंद अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ है। प्रेम, दोस्ती और रिश्ते, ये वे रंग हैं, जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं। प्रेम वह नहीं, जो हमें कमजोर बनाए। सच्चा प्रेम वह है, जो हमें और मजबूत बनाए, जो हमें हमारे असली स्वरूप को खोजने में मदद करे। अपने रिश्तों में ईमानदार रहें और उन लोगों को चुनें, जो हमें ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। क्या तुम ऐसे लोगों के साथ हो, जो सपनों को पंख देते हैं? अपने कर्मों को इतना बड़ा करें कि वे समय की सीमाओं को पार करें। हमारा हर कदम, हर मेहनत, हर सपना हमें अमर बना सकता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी कहानी दुनिया को प्रेरणा दे। जीवन एक चुनौती है, एक अवसर है, और सबसे बढ़कर, एक उपहार है। इसे बेकार न गंवाएं। अपने भीतर की आग को जलाए रखें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

सपनों का पीछा करें

जीवन के अवसर अनंत हैं और हम अपने कर्मों, विचारों और अनुभवों से अपने जीवन की तस्वीर बनाते हैं, इसे मूल्यवान और सुंदर बनाते हैं।

सूत्र

हर पल अपने आप को पहले से बेहतर करें। सपनों का पीछा करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस राह में बाधाएं भी बहुत आती हैं।

दूसरा पहलू

हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ तो कुछ और ही कहते हैं।

दूध से कितनी मजबूत होती हैं हमारी हड्डियां

बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। स्कूली पोषण कार्यक्रमों और विज्ञापनों में भी बताया जाता है कि दूध स्वस्थ आहार का एक आवश्यक हिस्सा है। एक कप दूध में 300 मिलीग्राम पोषक होते हैं। इसलिए करीब तीन कप दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। इस संबंध में एमिडिमियोलॉजी और न्यूट्रीशन विशेषज्ञ डॉ. वाल्टर विलेट का कहना है कि यह नैरेटिव सीमित अध्ययनों और डेयरी उद्योगों के आधार पर गढ़ा गया है। पोषण वैज्ञानिक डॉ. क्रिस्टोफर गार्डनर कहते हैं, 'अमेरिका के एक तिहाई से ज्यादा लोगों को लैक्टोज (दुग्धशर्करा) पचाने में परेशानी होती है, इसलिए किसी को भी गाय का दूध पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन, कई उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बेहतर स्रोत भी हो सकते हैं।'

सिमर बजाज

विशेषज्ञ कहते हैं कि दूध पीने से फ्रैक्चर नहीं होता, यह नैरेटिव सीमित अध्ययनों और डेयरी उद्योगों के हितों के आधार पर गढ़ा गया है।

कैल्शियम तंत्रिका, मांसपेशियों, हृदय के कार्य के साथ-साथ हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अमेरिका में एक वयस्क के लिए 1,000 से 1,200 मिलीग्राम व ब्रिटेन में 700 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन जरूरी बताते हैं। डॉ. विलेट कहते हैं कि 1999 से 2023 के बीच दूध पर 79 पेपर प्रकाशित हुए, जिनमें एक तिहाई से अधिक डेयरी उद्योग से संबंधित थे। 2020 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, जो दूध नहीं पीते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रेने रिजोली कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने का दूध से शायद ही कोई संबंध है? इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं हैं कि दूध का सेवन फ्रैक्चर रोकता है। डॉ. रिजोली के अनुसार, व्यायाम व आहार स्वस्थ हड्डियों के लिए जरूरी है। न्यूट्रीशनल एमिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. जेरी नीव्स कहती हैं कि दूध, प्रोटीन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे अन्य पोषक तत्वों के साथ, कैल्शियम के सबसे सुविधाजनक स्रोतों में से एक हो सकता है। आपको दूध अच्छा लगता है, तो इसे पिएं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है या इसके लैक्टोज को पचाने में दिक्कत है, तो टोफू, बोनी फिश, पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड संतरे का जूस या पौधों पर आधारित दूध भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।

2020 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, जो दूध नहीं पीते हैं, उनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रेने रिजोली कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने का दूध से शायद ही कोई संबंध है?

विशेषज्ञ कहते हैं कि दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। हालांकि, दूध पीने या न पीने से हड्डियों के फ्रैक्चर का कहीं कोई संबंध नहीं है। हड्डियों को मजबूत रखना है, तो व्यायाम करें व संतुलित आहार लें तथा दूध पीते हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है।

©The New York Times 2025

आंकड़े

ऊर्जा आपूर्ति

ऊर्जा की वैश्विक स्तर पर की जाने वाली आपूर्ति में दुनिया के कई देशों की हिस्सेदारी है, लेकिन इस मामले में चीन सबसे ऊपर है।

देश	हिस्सेदारी
चीन	26.8%
अमेरिका	15.5%
भारत	6.5%
रूस	5.4%
जापान	2.8%

आंकड़े वर्ष 2024 में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति हिस्सेदारी के, प्रतिशत में | स्रोत : Energy Institute

गणेश जी कुबेर के यहां बना पूरा भोजन खा गए, फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। धन के स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शंकर से मदद मांगी।

गणेश जी ने तोड़ा कुबेर का घमंड

आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश से संबंधित अनेक कथाएं हैं, उन्हीं में से एक कथा के अनुसार, उन्होंने धन के स्वामी कुबेर के घमंड को नष्ट किया था। अत्यधिक धन और संपदा होने के कारण कुबेर को खुद के ऊपर पर बहुत अभिमान था। एक दिन कुबेर ने सभी देवी-देवताओं समेत भगवान शंकर और माता पार्वती को भी भोजन पर बुलाया। भगवान शंकर कुबेर का मंतव्य समझ गए थे। भगवान देवों और भक्तों का घमंड चूर करने में देर नहीं लगाते हैं।

इसलिए भगवान महादेव और माता पार्वती ने अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को कुबेर के यहां भेज दिया। गणपति को कुबेर का घमंडी व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुबेर का घमंड तोड़ने का निर्णय ले लिया। गणेश जी ने कुबेर के महल में उपलब्ध सारा भोजन खा लिया और बाकी देवों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बावजूद गणेश जी की भूख नहीं मिटी। उन्होंने कुबेर से और भोजन की मांग की। यह देखकर धन के स्वामी कुबेर चिंतित हो गए और भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। गणपति की भूख अब तक शांत न हुई थी, तब भगवान शिव ने गणपति को एक कटोरे में अनाज खाने के लिए दिया और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई। इसके बाद कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी संपन्नता को अन्य प्राणियों में बांटने का निर्णय किया।

अंतर्यात्रा

संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 27 अगस्त, 1953

जनसंघ बख्शी सरकार का समर्थन करेगा

जनसंघ बख्शीसरकार का समर्थन करेगा

४० लाख हिन्दू पूर्वी बंगाल में पुनः बसाये जायें

भारतीय जनसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष मौलिचंद्र शर्मा ने कहा कि बख्शी सरकार दिल्ली और भारत में जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्मिलन पर दृढ़ रहती है, तो जनसंघ उसका पूरा समर्थन करेगा।

क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं

राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष में भारत से संबंध सुधारने के लिए चीन का आगे बढ़ना और सीमा विवाद सुलझाने हेतु गंभीर होना शुभ संकेत है।

सुजान चिनॉय | अंतरराष्ट्रीय

चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हाल की दिल्ली यात्रा भविष्य की संभावनाओं का एक संकेत है। पिछले वर्ष के अंत में, वाशिंगटन में राजनीतिक बदलाव से ऐन पहले स्थितियां बदलनी शुरू हो गई थीं। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम इस प्रक्रिया को और आगे ले जाते दिखते हैं। बीते अक्तूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बनी सहमति ने जून 2020 में हुए तनाव के बाद संबंधों को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया को गति दी है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने और चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा देने के फैसले से आपसी समझ बेहतर हुई है। सीधी उड़ानें शुरू करने और पर्यटकों, व्यवसायों, मीडिया एवं अन्य आगंतुकों को वीजा की सुविधा प्रदान करने पर सहमति एक सकारात्मक संकेत है। साझा नदियों के संबंध में, चीन आपातकालीन स्थितियों के दौरान जल विज्ञान संबंधी जानकारियां साझा करने पर भी सहमत हुआ है। व्यापार और निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के प्रति एक नई प्रतिबद्धता है, जो भारत को इन कठिन समय में निर्यात को वैकल्पिक

बाजार की ओर मोड़ने में मदद कर सकती है। लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रे के रास्ते होने वाले सीमा व्यापार को फिर से खोलना एक ऐसा कदम है, जिससे दोनों तरफ के सीमावर्ती निवासियों को लाभ होगा।

चीनी पक्ष ने तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति का स्वागत किया है। एससीओ की सफलता ब्रिक्स जैसे मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत अगले वर्ष और चीन 2027 में करेगा। भले ही द्विपक्षीय संबंधों में सुधार आ रहा है, फिर भी दोनों पक्षों को इस बात का एहसास है कि सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। उल्लेखनीय रूप से, दोनों पक्ष भारत-चीन सीमा मामलों से संबंधित मौजूदा परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) के तहत एक विशेषज्ञ समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं, ताकि 'भारत और चीन के बीच के सीमावर्ती इलाकों में सीमा निर्धारण के मामले में शीघ्र हल' तलाशे जा सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता पश्चिमी क्षेत्र में व्यवस्थित कोर कमांडर-स्तरीय बैठकों की तर्ज पर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में 'जनरल स्तर के तंत्र' की स्थापना से संबंधित है।

लिहाजा, मौजूदा मॉडल के आधार पर, मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड से सटे) और पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से सटे) के संबंध में उच्चस्तरीय सैन्य वार्ता के लिए एक अलग तंत्र की स्थापना अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। डब्ल्यूएमसीसी के तहत एक विशेषज्ञ समूह का गठन दोनों पक्षों द्वारा सीमा निर्धारण के मामले में प्रगति हासिल करने को दिए गए महत्व को रेखांकित करता है। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार, सीमा निर्धारण एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें सीमा को एक बड़े पैमाने के स्थलाकृतिक मानचित्र पर रेखांकन किया जाता है और लिखित विवरणों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसके बाद मानचित्र पर रेखांकन और मिलान विवरण अंततः जमीनी स्तर पर सीमांकन की दिशा में एक अभिन्न कदम बन जाते हैं।

संबंध सुधारने के लिए चीन की आगे बढ़ने की इच्छा एक शुभ संकेत है। एक कार्य समूह के जरिये कारगर सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाना भी एक स्वागत योग्य कदम है। कुछ विश्वास बहाली के उपायों (सीबीएम) में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी अन्य उपायों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत हो सकती है। एजेंडे में संचार संपर्कों में सुधार एवं वृद्धि, अग्रिम चौकियों के बीच हॉटलाइन की संख्या बढ़ाना, सीमा कर्मियों की बैठकों (बीपीएम) के लिए अतिरिक्त बैठक बिंदु निर्धारित करना और गश्ती दल के बीच टकराव की स्थिति में आचरण को नियंत्रित करने हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित करना शामिल हो सकता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में पारदर्शिता और विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने के लिए एकतरफा कार्रवाई से बचने की दृढ़ प्रतिबद्धता भी इच्छा सूची में शामिल होनी चाहिए। भड़काऊ स्थिति से बचने के लिए गश्त से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करना एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। पूर्व सूचना के साथ गश्त करना, समवर्ती गश्त से बचना या कुछ हिस्सों में संयुक्त गश्त करना कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।

तनाव कम करने के लिए, हाल के वर्षों में अग्रिम मोर्चों पर पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे को नष्ट करना पड़ सकता है। लेकिन, यह एक कठिन काम साबित हो सकता है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2020 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर कुछ अड़चनें आई थीं, लेकिन इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्थितियां बदल रही हैं।

(लेखक पूर्व राजदूत हैं और वर्तमान में मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक हैं।)

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

भारत की दृढ़ता

आज के समय में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। इसी दिशा में नया चौंकाने वाला खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। अगर इस अखबार का दावा सही है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए चार फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया है। जर्मनी के इस अखबार *फ्रैंकफर्टर अलगेमाइन जितुंग* ने अपने विश्लेषण में दोटूक इशारा किया है कि व्यापार संबंधी विवादों में ट्रंप की चेतावनियां या धमकियां जिस तरह से दूसरे देशों पर असर कर रही हैं, वैसा भारत पर नहीं कर पा रही हैं। भारत पर दबाव बनाने की ट्रंप की नीति नाकाम हो रही है और यह भारत व भारतीय प्रधानमंत्री की मजबूती का प्रमाण है। बीते दिनों में दबाव के बावजूद हमने भारत सरकार की दृढ़ता को देखा है और स्वयं प्रधानमंत्री अनेक बार यह दोहरा चुके हैं कि वह भारत के किसानों, मजदूरों के हित के विरुद्ध नहीं जाएंगे। भारत न केवल ज्यादा अमेरिकी टैरिफ के लिए तैयार है, वह जुर्माने का सामना करने को भी दृढ़ दिख रहा है। भारत अभी भी अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए रूस से तेल लेने के पक्ष में है। ऐसे में, भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो यह अपने आप में बड़ी वैश्विक घटना है।

आज से भारत पर पूरी तरह से टैरिफ लगने जा रहा है। ऐसे में, भारतीय प्रधानमंत्री यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो यह एक बड़ी वैश्विक घटना है।

जर्मनी के इस अखबार ने यह बताया है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वियतनाम के मामले में उन्होंने समझौते से पहले ही व्यापार सौदे की घोषणा कर दी, ठीक ऐसी ही कोशिश ट्रंप भारत के संदर्भ में भी कर चुके हैं, पर भारत ऐसी अनुचित अमेरिकी कोशिशों को जरा भी भाव नहीं दे रहा है। भारत के सामने ट्रंप के मीडिया स्टंट फेल हो जा रहे हैं। दुनिया गवाह है कि ट्रंप भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष-विराम कराने का श्रेय लूटने की भी कोशिश करते रहे हैं, पर भारतीय प्रधानमंत्री भी ऐसी कोशिशों पर पानी फेर चुके हैं। ऐसे में, ट्रंप के फोन कॉल्स का अगर भारत की ओर से कोई जवाब न गया हो, तो यह कोई विचित्र बात नहीं। ट्रंप की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वह भारत से अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सहलाने में जुटे हैं। अतः भारतीय प्रधानमंत्री की दृढ़ता ऐतिहासिक है।

आंतरिक रूप से भी भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिशों पर हमें गौर करना चाहिए। अहमदाबाद में हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के अधिकतम उपयोग का जो आह्वान किया है, उससे पता चलता है कि वह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, ताकि खरीदारों को आसानी हो। यह कोई रस्मन दिया गया बयान नहीं है, आज से लागू हो रहे 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ के आलोक में इसकी अहमियत स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी सीमा शुल्क लादे जाने से वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं, आभूषणों और कुछ खाने-पीने की चीजों के जुड़े उद्यमों के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इस असर को न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि घरेलू बाजार में इनकी मांग बढ़े और भारत अपने लिए नए विदेशी बाजारों की तलाश करे। बेशक, ऐसी कोशिशें हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 27 अगस्त, 1950

काश्मीर मिशन की असफलता

संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ सर ओवन डिक्सन अपने माथे पर असफलता का टीका लगवाकर लेक सक्सेस लौट गये हैं और नेहरूजी के शब्दों में 'हम आज वहीं हैं, जहां से हमने प्रारम्भ किया था।'

इस असफलता का दायित्व किस पर है? यह जानने के लिए हमें सर ओवन के प्रयत्नों पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यतः यह सुझाव दिया था कि राज्य के जिन क्षेत्रों में जनता का मत स्पष्टतः ज्ञात है, उन्हें संबंधित देशों को सौंप दिया जाये और केवल काश्मीर की घाटी में ही जनमत लिया जाये। उसके लिए भी यह शर्त थी कि शेख अब्दुल्ला की वैध और नियमित सरकार को हटाकर वहां छह मास तक संयुक्त राष्ट्रीय शासन-प्रबन्ध स्थापित किया जाये।

इससे स्पष्ट है कि सर ओवन आक्रान्ता के हाथों में खेल गये और उन्होंने हर प्रकार से उसे संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। भारत, जिसके जवानों ने अपना खून देकर काश्मीर की मनोरम घाटी को आक्रान्ताओं से बचाया है और उसकी हरियाली को बहाल रखा है, इस असम्भव शर्त को किस प्रकार स्वीकार कर लेता? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खां ने अपने वक्तव्य में सर ओवन की असफलता का सारा दोष भारत के सिर मढ़ने का प्रयत्न किया है और वस्तु-स्थिति पर पर्दा डालना चाहा है। लेकिन भारतीय नेता इतने भोले नहीं। वे अपनी स्थिति को अच्छी प्रकार समझते हैं। नेहरूजी ने पत्रकारों के सामने अपना वक्तव्य देते हुए इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया कि काश्मीर-वार्ता की असफलता का शत-प्रतिशत दायित्व पाकिस्तान के कंधों पर है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने भी नेहरूजी के मत का पूर्ण प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि नेहरूजी के विचार समस्त काश्मीरी जनता के विचार हैं और जनमत-संग्रह तब तक संभव नहीं है, जब तक पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य से निकाल नहीं दिया जाता, 'आजाद' सेनाओं को भंग नहीं कर दिया जाता और समस्त जम्मू तथा काश्मीर राज्य जनता की इच्छा से निर्वाचित वहां की लोकप्रिय सरकार को नहीं सौंप दिया जाता। डिक्सन-मिशन की असफलता के बाद अब यह निश्चित है कि काश्मीर के प्रश्न को पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया जायेगा और सुरक्षा परिषद को उसके हल के लिए नये सिरे से प्रयत्न करना पड़ेगा।

वक्त की नजाकत समझें भारत और चीन

इन दोनों पड़ोसी देशों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक-दूजे को यह मौका देना ही चाहिए कि वे अपनी भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा कर सकें।

यहां स्कैन करें

जोरावर दौलत सिंह | इतिहासकार और रणनीतिकार

बीजिंग और नई दिल्ली से मिल रहे संकेत स्पष्ट हैं। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, उसे भुलाकर अब दोनों देश नए सिरे से आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। बेशक, अमेरिका की इस पर पैनी नजर है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्तूबर में कजान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करके इसका रास्ता काफी हद तक तैयार कर दिया था।

संबंधों में गिरावट दरअसल कई ऐतिहासिक कारकों का नतीजा थी। मसलन, अमेरिका-केंद्रित एकध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ती वैश्विक सत्ता-संरचना, शक्ति के इस बदलते संतुलन को आकार देने के लिए अमेरिका व यूरेशियाई ताकतों के बीच तेज संघर्ष, और इस भू-राजनीतिक व्यवस्था का भारत-चीन संबंधों पर पड़ने वाला परोक्ष प्रभाव।

भारत की बात करें, तो वैश्विक बदलाव के उस दौर में चीन-नीति को लेकर उसकी दुविधा यही रही कि वह अपने इस पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए या फिर सहनशीलता का परिचय दे। आम तौर पर ऐसी स्थिति में ठीकरा विंस्टन चर्चिल पर फोड़ते हुए कहा जाता है कि कोई राष्ट्र एक ही समय में इन दोनों विकल्पों का एक साथ चयन नहीं कर सकता, बल्कि किसी एक को चुनना उसकी मजबूरी है। लिहाजा, भारत की नीति भी आक्रामकता और सहनशीलता के बीच झूलती रही, जिसका नतीजा यह रहा कि पिछले एक दशक में भू-राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई।

अब हमारे क्षेत्रीय रिश्ते पहले से अधिक जटिल हो गए हैं। उत्तरी सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ गया है, जबकि चीन और पाकिस्तान का सैन्य रिश्ता ऐसा आकार ले चुका है कि वह भू-सामरिक संतुलन को पलटने का माद्दा रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी भारत को इस उप-महाद्वीप में कमजोर करने और भू-राजनीतिक उठा-पटक के दौर में नई दिल्ली को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

यदि यह एक अस्थायी तूफान था, जिसकी नियति गुजर जाने की थी, तो अब इस दौर का लाभ उठाना हमारे लिए रणनीतिक रूप से मुफीद है। हालांकि, भारत द्वारा अभूतपूर्व आर्थिक, तकनीकी और सैन्य बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन इससे पुरानी विश्व-व्यवस्था खुद-ब-खुद साकार नहीं हो सकती। वास्तव में, यह वक्त धीमे पड़ गए प्रयासों को नई गति देने और भू-राजनीतिक खतरों से पार पाने का है, ताकि भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया देख सके।

क्या हम चीन-नीति को इस तरह गढ़ सकते हैं कि हमारे लिए कहीं अधिक अनुकूल रणनीतिक माहौल का निर्माण हो सके?

इस संबंध में हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। एक-दूसरे से होड़ ले रहे देशों ने तमाम संघर्षों के बाद आखिरकार दोस्ती पर ही जोर दिया। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, 1970 के दशक में अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई नरमी या 1980 के दशक में चीन और सोवियत संघ का तालमेल। दोनों ही मामलों में, आक्रामक रुख के कारण आपसी विश्वास को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था।

क्या आज भारत-चीन रिश्ते को लेकर भी यही कहा जा सकता है? निस्संदेह, कोई भी ऐसा प्रभावी बाहरी कारक या बल नहीं है, जो इन दोनों को तनाव खत्म करने के लिए प्रेरित कर सके। यह समझना अनिवार्य है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में दोनों का व्यावहारिक फायदा है, पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अब भी दोनों देशों की सोच इतनी परिपक्व नहीं है कि ऐसी व्यवस्था को लेकर वे साझा संवाद कर सकें। फिर, महत्वपूर्ण यह भी है कि बाह्य संतुलन को लेकर भारत के सीमित विकल्पों के बावजूद भौतिक विषमता दोनों देशों के बीच किसी बड़े सौदे को साकार नहीं कर सकती।

बेशक, न तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जैसी राजनीतिक मुश्किलें आज सामने हैं और न ही देंग शियाओपिंग जैसा क्रांतिकारी नेता हमारे पास हैं, जो नए वैश्विक परिदृश्य में भारतीय व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित कर सकें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देंग ने आक्रामकता की जगह संयम को अहमियत दी थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी इस नीति को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा। जाहिर है, आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक वृहद नजरिये के बिना। ऐसे में, चीन-नीति से जुड़े तीन मसले नजर आते हैं।

पहला, एशिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनने का भारत का अघोषित लक्ष्य व्यावहारिक नहीं है। इसके कारण हैं- अमेरिका का अब वैसा दबदबा नहीं रहा, उप-महाद्वीप से बाहर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ताकत का हमारे पास अभाव है और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों में शामिल होने से संप्रभुता और भू-राजनीतिक नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर, पश्चिम के देश भारत के इस विचार से भी इत्तफाक नहीं रखते कि आजाद भारत को शामिल करने के लिए उनके गठबंधनों को नया रूप देना चाहिए।

दूसरा, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए अब नव-उदारवाद के बाद के नियम गढ़े जा रहे हैं। बेशक, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसे बनाएंगी, पर भारत के पास तरकश में अब भी कई तीर हैं। बाजार क्षमता, मानव पूंजी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसी परिसंपत्तियां भारत के पास हैं और वह चाहे, तो चीन के साथ पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक संबंधों के आधार पर बातचीत कर सकता है। यहां दरवाजे को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है, व्यापकता के साथ। यदि यह ठीक से किया जाए, तो ब्रिक्स जैसी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को अधिक ठोस रूप दिया जा सकता है, जो भारत और क्षेत्र, दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

तीसरा, आपसी मतभेदों के बावजूद, भारत और चीन, दोनों के हित भू-राजनीतिक स्थिरता में छिपे हुए हैं। बेशक, दोनों के बीच कोई बड़ी सौदेबाजी नहीं हो सकती, लेकिन क्षेत्र में अपनी अलग-अलग नीतिगत प्राथमिकताओं और भू-राजनीतिक भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए दोनों देश कुछ हद तक आम राय बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो उनको एक-दूसरे को यह मौका देना चाहिए कि वे अपनी भू-राजनीतिक व सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को पूरा कर सकें।

आशा है कि रविवार को जब शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, तो मोदी व जिनपिंग में बातचीत का यह शुरुआती बिंदु बनेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

युवाओं के हित में ऑनलाइन गेम्स की जरूरी निगरानी

यहां स्कैन करें

शहजाद पूनावाला | राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

पिछले 11 वर्षों में भारत की डिजिटल क्रांति ने देश को बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान देश के करोड़ों लोगों को सशक्त बना रहा है। इसमें यूपीआई भुगतान प्रणाली, 5जी कनेक्टिविटी और सेमीकंडक्टर सिस्टम जैसे एप की अहम भूमिका है। मगर डिजिटल क्षेत्र में प्रगति के साथ नई-नई तरह की समस्याएं भी आई हैं। बेतरतीब ढंग से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को जुए की लत लगने लगी, पैसे गए, यहां तक कि मौतें भी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार 'ऑनलाइन गेमिंग बिल-2025' लेकर आई, जो अब कानून बन चुका है।

कर चोरों की पनाहगाह बने देशों (टैक्स हेवन) में जालसाजी करके बनाए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग एप ने भारत के कुछ कमजोर तबकों, कम जागरूक लोगों, खासकर युवाओं से झूठे वादे किए और तुरंत अमीर बनाने का लालच देकर उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया। ऑनलाइन जुए की लत के कारण बांदीपोरा में एक व्यक्ति ने डेढ़ करोड़ रुपये गंवाए, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर गया। मैसूर में एक पिता और उसके दो बेटों ने गेमिंग में हार के बाद आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में 31 महीनों में 32 गेमर्स ने आत्महत्या कर ली। यह इंतिहा थी, जिसको सार्वजनिक मानसिक आपातकाल की तरह लिया गया। ये वेबसाइट्स सिर्फ लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचातीं, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

'ऑनलाइन गेमिंग कानून- 2025' सट्टेबाजी, जुआ, फंतासी स्पोर्ट्स और लॉटरी जैसे मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाता है।

'ऑनलाइन गेमिंग कानून- 2025' में इन खतरों से निपटने के पुख्ता प्रावधान किए गए हैं। यह सट्टेबाजी, जुआ, फंतासी स्पोर्ट्स और लॉटरी जैसे ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। इन खेलों में लिप्त पाए जाने वाले ऑपरेटरों, उनके विज्ञापनदाताओं और उनकी वित्तीय मदद करने वालों को तीन से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा होगी और एक से दो करोड़ रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- 2000 के तहत काम करने वाली ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी को गेमिंग साइट्स पर रोक लगाने का अधिकार होगा। अगर कोई ऑनलाइन जुआ खेलता है, तो उससे संबंधित वित्तीय लेन-देन पर बैंक प्रतिबंध लगा देंगे। इस कानून में ट्रेनिंग अकादमी, रिसर्च सेंटर और तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के प्रावधान हैं। ई-स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए दिशा-निर्देश बनाने का काम खेल मंत्रालय को दिया गया है। मंत्रालय ऑनलाइन सामाजिक खेलों को मान्यता देगा, सुरक्षित और उम्र के हिसाब से सही सामाजिक व शैक्षिक खेलों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जागरूकता फैलाएगा और सांस्कृतिक-शैक्षिक खेल सामग्री मुहैया कराएगा। यह कानून देश के 65 प्रतिशत युवाओं के हित में है। उम्र सत्यापन, खर्च की सीमा और शिकायत निवारण प्रणाली की मदद से यह जुए के लती बन चुके लोगों के परिवारों को मानसिक और आर्थिक बोझ से उबारने में मदद करेगा। डाटा के स्थानीय होने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ तालमेल कर निगरानी करने से गैर-कानूनी जुआ गतिविधि रुकेगी और यह कानून भारतीय न्याय संहिता जैसे कानूनी संहिताओं के साथ तालमेल कर काम करेगा। सबसे अहम है कि यह कानून गेमिंग के खिलाफ नहीं है। यह ई-स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में बढ़ावा देता है और सामाजिक व शैक्षिक खेलों को भी प्रोत्साहित करता हैं। भारत का सकारात्मक गेमिंग उद्योग 2028 तक 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और दो लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकता है। इस कानून के सारे नियम पारदर्शी हैं, जिससे यह नैतिकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, खासकर छोटे शहरों में, जहां के बल पर भारत दुनिया में गेमिंग निर्यात का अग्रदूत बन सकता है।

यह कानून सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत को दर्शाता है। 'ऑनलाइन गेमिंग कानून' सिर्फ नीति नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और देश का भविष्य तय करने वाला है। यह शोषण रोकते हुए रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, ताकि इस तरह के खेल ताकत बनें, न कि जुए के लती बनाने वाले जाल।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

गजानन का सुंदर संदेश

भगवान गणेश की प्रतिमा देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि एक चेतना और सर्वोच्च सत्ता को हाथी के रूप में ही क्यों दर्शाया गया है? वास्तव में, हाथी में कुछ अद्भुत गुण होते हैं, जैसे निर्भयता तथा उसकी राजसी चाल। वह अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ता जाता है।

हाथी अधिकार, धैर्य, शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। दैवीय गुणों के प्रतीक के रूप में भगवान गणेश को एक हाथी के रूप में चित्रित किया गया है और जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो इन सभी गुणों को अपनी चेतना में आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। उनकी लंबी सूंड दर्शाती है कि सच्चा ब्रह्मज्ञान वह है, जिसमें ज्ञान व कर्म, दोनों रूपों का क्रियान्वयन हो, दोनों में समरसता हो।

जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं, तो हमारे भीतर भी हाथी जैसे गुण जागृत होने लगते हैं और हम उनको अपनाने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आप जिस किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके गुणों को ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए यदि आप गणेश जी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनके गुण आपको प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे गुण आप में विकसित होने लगते हैं। आप सभी बाधाओं को पार करने लगते हैं।

हाथी में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इनका सिर बहुत बड़ा होता है, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। इनके कान भी बड़े-बड़े होते हैं, जो पंखे के समान हिलते हैं और आंखें छोटी होती हैं, जो इस बात की सूचक हैं कि जो कुछ भी आप सुनते-समझते हैं, उसका अनुसरण करना केवल रूप-रंग पर ध्यान देने और उसे महत्व देने की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए जो कुछ भी हम देखते और सुनते हैं, उनको आपस में जोड़कर हमें देखना चाहिए।

हाथी अपनी सूंड का उपयोग दो कार्यों के लिए करता है। सूंड से वह सूंघता भी है और फिर उसी के अनुसार उस पर कार्य करता है। इसी प्रकार, हम ज्ञान में भी पहले सूंघते हैं और तत्पश्चात उस पर कार्य करते हैं। सूंड ज्ञान शक्ति तथा कर्म शक्ति के बीच आदर्श संतुलन को दर्शाती है। सूंघने का अपना महत्व है। एक लोकप्रिय

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

भगवान गणेश को एक हाथी के रूप में चित्रित किया गया है और जब हम गजानन की पूजा करते हैं, तो हाथी के सभी गुणों को अपनी चेतना में आत्मसात करने में सक्षम होते हैं।

लोकोक्ति है- दाल में कुछ काला है, अगर ऐसा कुछ आभास बुद्धिमान व्यक्ति को होता है, तो वह समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करता है।

हाथी के एक वह दांत होता है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जबकि उनके पास भोजन चबाने के लिए अलग से भी दांत होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वे उनके मुंह के अंदर होते हैं। ऐसे ही, गणेश जी का भी एक बाह्य दांत होता है, जिसका भाव है कि हमें एक ही लक्ष्य पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए।

श्री श्री रविशंकर

एलन मस्क | उद्यमी

हॉलैंड में पहले ही दो बार गिरफ्तार किए जा चुके एक हिंसक बलात्कारी को जेल भेजने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों को गंभीर सजा दी जानी चाहिए। उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए।

अनुलोम-विलोम

विज्ञान बनाम धर्म

धर्म और विज्ञान को अलग-अलग रखिए

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक स्कूल में छात्रों से बातचीत के दौरान जो कहा, उससे एक बार फिर विज्ञान बनाम धर्म की बहस तेज हो गई है। उनका कहना था कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने यह बयान तब दिया, जब बच्चों ने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में नील आर्मस्ट्रांग का नाम लिया। हालांकि, बच्चों का जवाब भी गलत था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इसका सही जवाब है, यूरी गागरीन, जो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। मगर इस सवाल-जवाब का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वीडियो में भाजपा नेता ने यह भी कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति में कई ऐसे प्रसंग हैं, जो प्रेरणा दे सकते हैं। लगे हाथ उन्होंने छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों से बाहर निकलकर वेदों, परंपराओं और प्राचीन ज्ञान को समझने की भी सलाह दी। बेशक, हमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि बच्चों को हर तर्कों को विज्ञान की कसौटी पर कसने की शिक्षा दी जाए। उनको समझाया जाए कि आधुनिक युग विज्ञान का है और वैज्ञानिक सोच ही उन्हें देश-दुनिया में तरक्की दिला सकती है। एक अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि धर्म को विज्ञान के नजरिये से देखना चाहिए, लेकिन बच्चों को विज्ञान को ही धर्म की दृष्टि से देखने की सलाह दी गई। यह कहां तक उचित है? क्या आज के वैज्ञानिक युग में इसकी कल्पना उचित है? वैसे, मेरी जिज्ञासा यह भी है कि कोई छात्र परीक्षा में यदि पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में हनुमान जी का नाम लिखेगा, तो क्या उसे अंक मिलेंगे या काट लिए जाएंगे?

नरेश पाराशर, बीमा अधिकारी

आज से कुछ वर्ष पूर्व त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके बिप्लव देब ने दावा किया था कि महाभारत काल में भी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान से दूर बैठे संजय भला कैसे अपनी आंखों से युद्ध देख सकते थे, जिसका मतलब है कि उस समय इंटरनेट व सैटेलाइट कम्युनिकेशन मौजूद था। अनुराग ठाकुर का नया वीडिया बिप्लव देब के बयान की ही अगली कड़ी है। ऐसे बयान के बाद उचित ही लोग मौजूदा सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या शिक्षा प्रणाली में मिथकों को वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में थोपने की कोई कोशिश हो रही है? अगर हां, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

परंपराएं और दर्शन भारत की प्राचीन पहचान

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को संदर्भ से काटकर जिस तरह से प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है, वह दुखद है। यह घटनाक्रम कई पहलुओं को सामने लाता है। पहला, भाजपा नेता का मंतव्य छात्रों को विज्ञान से विमुख करना नहीं था। वह तो भारतीय दर्शन और परंपरा से बच्चों का परिचय करा रहे थे। दरअसल, मैकाले की शिक्षा पद्धति का यह नुकसान हुआ है कि हम आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। जबकि, कोई समाज यदि अपनी जड़ों से कट जाता है, तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचता। भारत पर भी यह खतरा बना हुआ है, जिससे भाजपा नेता गाफिल नहीं हैं। उन्होंने यही सीख बच्चों में पिरोने की बात कही। उनका कहना भी था कि अंग्रेजों द्वारा दी गई पाठ्य-पुस्तकों से आगे हमें ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए और बच्चों को वेदों व भारतीय दर्शन से परिचय कराना चाहिए।

हमें यह समझना ही चाहिए कि पहले भारत विश्वगुरु की हैसियत में क्यों था और गुलामी के दिनों में उससे यह दर्जा कैसे छिन गया? देखा जाए, तो आज हमारे पास फिर से मौका है कि हम दुनिया भर में अपनी विद्वता का लोहा मनवा सकते हैं, जिसके लिए हमें फिर से अपनी परंपराओं को जीना होगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि विज्ञान और धर्म साथ-साथ आगे बढ़ें, ताकि बच्चों को वैज्ञानिक तर्कों का भी ज्ञान हो और भारतीय संस्कृति का भी। वास्तव में, भारत अपनी विविध व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन परंपराओं, रीति-रिवाजों, कला-संगीत व नृत्य के लिए ही दुनिया भर में जाना जाता है। इसे एक अनूठा देश इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के लोग परंपराओं पर भरोसा करते रहे हैं, जो विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के मिलन से तैयार हुई है। इसे आगे बढ़ाने ही बात अगर कोई इंसान करता है, तो इसमें क्या गलत है?

इस पूरे प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि जिस तरह संदर्भ से काटकर किसी एक बयान को दुष्प्रचारित करने की मानिसकता पनपने लगी है, उससे हमें गहरे नुकसान हो सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। किसी भी नेता के एक वाक्य को संदर्भ से काटकर प्रचारित किया जाता है, उसके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति के खिलाफ कोई मजबूत कानून बनना चाहिए, ताकि जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, उनको सबक मिल सके। जरूरी संदर्भ को काटकर गलत नीयत से बयानों को तोड़ना-मरोड़ना भी गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। हमें अनुराग ठाकुर के बयान को समग्रता में देखना चाहिए और उनकी नीयत को ध्यान में रखकर ही उनके बयान की समीक्षा करनी चाहिए।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

सही समय की प्रतीक्षा में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है

ट्रंप की चुनौती का सामना

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल करके ही माने। उन्होंने यह मनमाना अतिरिक्त टैरिफ इस आरोप में जुर्माने के रूप में थोपा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तरह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में उसकी मदद कर रहा है। यह है तो नितांत निराधार निष्कर्ष, लेकिन ट्रंप ऐसे ही बेतुके आरोप लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा है कि भारत पहले दिन से ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति का मुकाबला करने की दृढ़ता दिखा रहा है। अब इस दृढ़ता के अनुरूप हरसंभव कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ पहले ही इसलिए लगा दिया था, क्योंकि तय समयसीमा में द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हो पाया। यह इसीलिए नहीं हो पाया, क्योंकि भारत उनकी मनमर्जी वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था। इसी से चिढ़े ट्रंप ने एक तो यह राग अलापना शुरू किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया और दूसरे, इस हास्यास्पद आरोप के साथ सामने आ गए कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। ट्रंप ने उस चीन को बख्श दिया है, जिसके खिलाफ वह गर्जन-तर्जन करते रहते हैं और जो भारत के मुकाबले रूस से कहीं अधिक तेल खरीदता है। चूंकि ट्रंप में इतना साहस नहीं कि वे चीन पर भारत जितना टैरिफ लगा सकें, इसलिए उनके सहयोगी तरह-तरह के कुतर्क देने में लगे हुए हैं। इसके कारण उनकी जगहंसाई ही हो रही है, पर शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं। जो भी हो, भारत को जहां आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों को गति देनी होगी, वहीं स्वदेशी के मंत्र को भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ उनकी निरंतर समीक्षा भी करनी होगी। इसलिए करनी होगी, क्योंकि स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की बातें कोविड महामारी के बाद से ही हो रही हैं और सब जानते हैं कि उनके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। कम से कम अब तो वांछित नतीजे हासिल करने के लिए ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए। ये उपाय तब सफल होंगे, जब हमारे कारोबारी ट्रंप की ओर से पेश की गई टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। वे सरकार से सहायता की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लड़ाई केवल कारोबार की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। सरकार, कारोबार जगत के साथ देश की आम जनता को इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि ट्रंप का भारत विरोधी रवैया लंबे समय तक कायम रह सकता है।

जांच पर सवाल

भागलपुर में रह रही पाकिस्तानी महिला इमराना खानम या इमराना खातून को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सालों से बिना नागरिकता वह भारत में रह रहीं, वोट तक कर रहीं। बड़ा सवाल यह कि सालों तक पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले को पकड़ा क्यों नहीं और जब मामला पकड़ में आया तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सालों तक तलाश के बाद पुलिस की जांच में 2022 में यह स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तानी नागरिक इमराना शिक्षक की नौकरी कर रहीं। गृह विभाग को यह रिपोर्ट भी भेजी गई, लेकिन तबसे कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। अब जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ तो इनका नाम मतदाता सूची में पाकर दस्तावेज खंगालते हुए बीएलओ ने आपत्ति की और हंगामा मचा। सवाल यह उठ रहा है कि पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अभी हंगामे के बाद भी जब पुलिस से इस बाबत पूछा गया तो वह यही कहती रही कि इमराना जहां पढ़ाती हैं वहां पुलिस की टीम गई थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक तरह से उन्हें लापता बताया गया, जबकि वह अपने घर पर ही थीं। इतने गंभीर मामले में ऐसी लापरवाही उचित नहीं। शासन को इसपर संज्ञान लेते हुए तत्काल मामले को निष्पादित करवाना चाहिए। इसी तरह से और भी पाकिस्तानियों के राज्य में होने के मामले की गहराई से जांच कर एक्शन लिया जाना चाहिए।

राज्य में पाकिस्तानियों के छिपे होने के मामले पर तत्काल एक्शन जरूरी है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सुप्रीम कोर्ट के संशोधित फैसले के बाद आवारा कुत्तों की समस्या दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है?

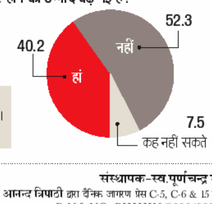

आज का सवाल

क्या भारत ट्रंप टैरिफ की काट तलाशने में सक्षम दिख रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अमेरिका नहीं चाहता भारत का उभार

दिव्य कुमार सोती

अब अमेरिकी सोच यह है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से उसे कोई लाभ नहीं। यही ट्रंप के मनमाने टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है

भारत द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव न होते देख और चीन एवं इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर एशिया की भूराजनीति चलाना संभव नहीं है। हालांकि उस दौर में दोनों देशों के संबंधों में इतनी कटुता आ चुकी थी कि एकदम से सब कुछ सामान्य हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भारत और अमेरिका कैसे एशिया की अगली सदी को मिलकर गढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टालबोट और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच 11 दौर की गुप्त वार्ता विश्व में अलग-अलग स्थानों पर हुई। इन वार्ताओं से अमेरिका में यह सहमति बनी कि भारत के सामरिक उदय को सुनिश्चित किया जाना पूरे एशिया और समूचे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह कुछ-कुछ वैसा ही था, जैसा निक्सन और किसिंजर द्वारा 1970 के दशक में यह तय करना कि अमेरिका सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन का उदय सुनिश्चित करेगा। टालबोट-जसवंत वार्ता की परिणति ही भारत के ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत की ओर झुकाव के रूप में दिखाई दी। भारत के उदय को सुनिश्चित करने की इस नीति के पक्षधर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही बने। क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार की और उसे मूर्त रूप भी दिया गया। इससे जरिये भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना भी एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया।

द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही। दोनों देशों के बीच 2005 में बनी रणनीतिक साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में समग्र वैश्विक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया। भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी किए। यह सिलसिला एक बड़ी हद तक ट्रंप के पहले कार्यकाल और बाइडन के दौर तक चलता रहा, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल विशेषकर आपरेशन सिंदूर के बाद के परिदृश्य में अमेरिकी रवैया बदल गया। कुछ लोग इसे भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा बार-बार खारिज करने से भी जोड़कर देख रहे हैं। यह पूरी तरह सही नहीं।

अवधेश राजपूत

अमेरिका में एक तबका भारत से कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता आया है। ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान से जुड़ी है। वहां एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत उसके मुकाबले में सहायक बने, मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भाड़े पर लड़ने वाला देश नहीं बन सकता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही। यह उसकी समझ से बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौतों के बाद भी कोई देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है? भारत के मामले में ऐसा होते देख अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी पड़ी है।

भारतीय मामलों पर वाशिंगटन में एक बड़ी आवाज माने जाने वाले एश्ले टैलिस ने 2023 में ही एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को ही दर्शा रहे थे। यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था, इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में लेने का फैसला लिया गया। तब से ही यही नीति जारी है। बस बाइडन और ट्रंप के तरीके अलग हैं। बाइडन प्रशासन भारत को दबाव में लेने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलता रहा। कनाडा की ट्रूडो सरकार के जरिये भारतीय नेतृत्व पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप लगाए गए। इतने से बात नहीं बनी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप भी मढ़े गए।

जब ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी प्रारंभ कर दी थीं। जब पहलगाम हमला हुआ, तब उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टोकरेंसी डील पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में यह सोचना एक भूल है कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर का श्रेय न मिलने से क्रुद्ध ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। वाशिंगटन में अब यह सोच बन चुका है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय का समर्थन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। अमेरिका को लगता है कि जब चीन से निपटना ही उसे भारी पड़ रहा है तो सामरिक रूप से स्वायत्त महाशक्ति के रूप में भारत का उदय तो भविष्य में उसके वैश्विक प्रभुत्व के लिए चुनौती बढ़ाने का ही काम करेगा। अमेरिका भारत को अगला चीन बनते नहीं देखना चाहेगा।

अमेरिकी अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स कहते हैं कि भारत को सफल होते देख अमेरिका उसका विरोध करेगा, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। इसी कारण पहले अमेरिका रूस का विरोध कम्युनिज्म के नाम पर करता था। अब कम्युनिज्म के पतन के बाद भी उसका विरोध जारी है, क्योंकि अभी भी रूस एक बड़ी भूराजनीतिक शक्ति है और वह कभी अमेरिकी कठपुतली नहीं बनेगा। भारत के चमत्कारिक आर्थिक विकास के चलते यही अमेरिकी रवैया अब भारत के प्रति दिखने लगा है। ऐसे में यदि भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा जारी रखनी है तो हमारे उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों और छात्रों को चौगुनी शक्ति से काम करना होगा।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अटका हो तो

राजीव सचान

यदि राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर तय समय में फैसला लेना जरूरी है तो हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं?

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राष्ट्रपति की ओर से संदर्भित ऐसे प्रश्नों पर विचार कर रही है कि जब संविधान में विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है तो क्या अदालत समयसीमा तय कर सकती है? राष्ट्रपति ने इस और इस जैसे कुल 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को इसलिए संदर्भित किए थे, क्योंकि इसी वर्ष अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्यपाल की ओर से दस विधेयकों को लंबे समय तक रोक कर रखना और उन पर कोई निर्णय न लेना अवैध और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके रखने की कोई वीटो पावर नहीं। इसे ऐतिहासिक बताए जाने वाले फैसले ने इसलिए हैरान किया, क्योंकि एक तो ऐसा आदेश देते हुए राज्यपाल के पास लंबित सभी दस विधेयकों को स्वीकृत करार दिया गया और दूसरे, यह आदेश दो सदस्यीय पीठ ने दिया। इसमें यह भी व्यवस्था दी कि राज्यपालों के लिए विधेयकों पर एक माह में फैसला लेना होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आदेश में यह भी कहा गया कि विधेयकों पर फैसला लेने के मामले में राज्यपालों की तरह राष्ट्रपति के समक्ष भी समयसीमा है। इसने और हैरान किया। वास्तव में इसी कारण राष्ट्रपति की ओर से इस फैसले के खिलाफ 14 प्रश्न संदर्भित किए गए।

इस संवैधानिक मामले में राजनीतिक दलों और विधि विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। एक पक्ष विधेयकों पर फैसले लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उचित मान रहा है और दूसरा पक्ष उसे शीर्ष अदालत की ओर से न्यायिक सीमा एवं स्वतंत्रता का अतिक्रमण बता रहा। फिलहाल दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के वकील कह रहे हैं कि संविधान ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है और जिसकी जरूरत संविधान ने नहीं महसूस की, उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? इसी पहलू पर जोर देने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कुछ समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से भी होता है। यहां यह स्मरण करना आवश्यक है कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब यह प्रचलित था कि वे ऐसा मानते थे कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। पता नहीं आज कितने लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि विधेयकों पर निर्णय लेने के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है?

सुप्रीम कोर्ट को भी देने होंगे कुछ सवालों के जवाब ● फाइल

पिछले दिनों इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल किए कि यदि संवैधानिक पदाधिकारी यानी राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों पर कोई फैसला नहीं करते तो क्या अदालत के हाथ बंधे हैं? क्या अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती? क्या वह शक्तिहीन है? मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई का प्रश्न था, यदि राज्यपाल बिना किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संविधान पीठ की ओर से ऐसे उचित प्रश्न भी उठाए गए कि यदि कोई पीड़ित राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या राज्यपाल की निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है और अगर किसी विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए लंबित रखे तो क्या होगा?

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

उक्त प्रश्नों को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता और यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ राज्यपाल किस तरह विधेयकों को दबाए बैठे रहते हैं। गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब-तब इसकी शिकायत भी करते रहते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था तो ऐसी ही शिकायत भाजपा शासित राज्य करते थे। स्पष्ट है कि इन सवालों का अपना महत्व है, लेकिन क्या किसी और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सवालों का जवाब है कि यदि उसके समक्ष कोई मामला लंबित है और उस पर फैसला होने में देर हो रही हो यानी एक तरह की निष्क्रियता सी व्याप्त हो तो क्या कोई यह प्रश्न करने की भी स्थिति में है कि फैसले में देरी से पीड़ित लोग क्या करें? क्या पीड़ितों की ओर से संसद या सरकार या फिर अन्य कोई यह पूछ सकता है कि क्या लंबित मामले लंबे समय तक अनसुने रह सकते हैं? क्या कोई किसी का दरवाजा खटखटा सकता है? यह तो सुप्रीम कोर्ट को ज्ञात ही होगा कि हाई कोर्ट के साथ उसके समक्ष भी लाखों मामले लंबित हैं। एक आंकड़े के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 80 हजार से अधिक है। इनमें से सात हजार से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जो एक दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मुस्कान का माधुर्य

हमारे चेहरे की भाव-भंगिमाएं हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। कई बार हम चेहरा देखकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। व्यक्ति की सरलता, सहजता या कुटिलता अथवा उसका भोलापन सब कुछ उसके चेहरे पर अंकित रहता है। प्रायः मधुर मुस्कान से आप्लावित मुखमंडल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। चेहरे की मुस्कान ऊर्जा देती है। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए बात करता है तो संवाद का आकर्षण बढ़ जाता है। उसके प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इससे संवाद सार्थकता प्राप्त करता है। संवाद के उद्देश्य की पूर्ति होती हुई प्रतीत होने लगती है।

वहीं निराश, हताश एवं मुस्कान रहित मुखमंडल वाले व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता। संवाद से पहले ही एक तरह की नकारात्मकता छाने लगती है। संवाद उद्देश्य रहित लगने लगता है। ऐसे लोगों से स्वतः दूरी बनाने का मन करने लगता है। कठोर मुखमंडल एवं नीरस व्यक्ति यदि किसी बड़े पद पर बैठा हो तो भी लोग अथवा फरियादी उसके पास जाने से कतराते हैं। उसका व्यक्तित्व लोगों को नकारात्मक लगने लगता है। भले वह बड़े पद वाला व्यक्ति हृदय से सरल हो, पर मुस्कान का अभाव उसके व्यक्तित्व को नीरस बना देता है।

हमें सबसे अधिक ऊर्जा मंदिरों में मिलती है। वहां रखी भगवान की प्रतिमा प्रायः मुस्कुराती हुई बनाई जाती है, क्योंकि वह प्रतिमा सकारात्मकता एवं ऊर्जा का अप्रतिम स्रोत है। वह हमारे अंतस को अथाह सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रतिमा को देखते ही मन शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार मधुर मुस्कान का धनी व्यक्ति जीवन में ऊर्जा एवं सकारात्मकता बिखेरता है। उसके व्यक्तित्व की सुगंध से सभी आनंद की अनुभूति करते हैं। हम सभी अपने व्यक्तित्व में मुस्कान का गुण समाहित करें। मुस्कान का माधुर्य जीवन के लालित्य को प्रभावी बना देता है।

ललित शौर्य

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता

'एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियां' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में बलबीर पुंज ने यह रेखांकित करने का प्रयास किया कि विदेशी फंडिंग से संचालित कई संगठन देश की विकास योजनाओं को बाधित करते हैं। यह पहलू सही है, किंतु आलेख में उन संवैधानिक प्रविधानों का उल्लेख नहीं किया गया जो ऐसी संस्थाओं के अधिकार और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(अ) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(स) संघ बनाने का अधिकार देता है। इसलिए केवल दमन या पाबंदी पर्याप्त नहीं, बल्कि कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है। आलेख में यह पहलू भी अनदेखा रहा कि देश में अनेक एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। उन्हें विकास विरोधी कह देना ऐसा ही है, जैसे पूरे जंगल को काटकर केवल कुछ सूखी टहनियों को दोष देना। यह रचनात्मक पक्ष नजरअंदाज होने से आलेख का संतुलन कमजोर पड़ गया। साथ ही, चुनाव आयोग की भूमिका का अभाव भी खटकता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों पर सख्त नजर रखने का अधिकार है। यदि किसी एनजीओ का प्रभाव मतदाताओं तक पहुंचता है तो यह लोकतंत्र की नींव को सीधी चुनौती है। अंततः कहा जा सकता है कि आलेख ने ज्यादातर नकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला। यदि इसमें संवैधानिक संतुलन, चुनावी पारदर्शिता और सकारात्मक योगदानों की चर्चा शामिल होती तो यह अधिक तर्कसंगत बन पाता। लोकतंत्र का आधार आलोचना नहीं, बल्कि तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण का सह-अस्तित्व है। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना ही श्रेयस्कर है।

awanishg30@gmail.com

विकास विरोधी शक्तियां

'एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियां' शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा। जिसमें उल्लेखित है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू ने रखी थी। मगर इसका उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वजह थी, पर्यावरण के नाम पर इस परियोजना का मेधा पाटकर द्वारा विरोध किया जा रहा था, जबकि आज इसके लाभान्वित राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान हैं। इस राज्य के लोगों के खेतों की सिंचाई इस परियोजना के पानी से हो रहा है एवं गुजरात के कई इलाकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है। ऐसी अन्य परियोजना का विरोध पर्यावरण के नाम पर करने की परिपाटी को मौजूदा केंद्र सरकार ने खत्म किया। जिसका लाभ देश को मिल रहा है। बाकायदा सरदार सरोवर की तुलना चीन के यांगत्जी नदी पर बनने वाले बांध से की है। जिससे प्रभावित लोगों की संख्या सरदार सरोवर से कई गुना अधिक थी। बावजूद चीन की यह परियोजना 10 साल में पूरी हो गई।

मुकेश कुमार मनन, पटना

बेवजह का विरोध

अपने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कटु सच्चाई है, लेकिन जब भी उस पर लगाम लगाने की कोई पहल होती है, किसी न किसी बहाने उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसका ही ताजा उदाहरण है 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध। आम तौर पर जब विपक्ष सदन में किसी विधेयक का विरोध करता है तो उसे संसदीय समिति भेजने की भी मांग करता है। अब जब किसी मामले में फंसकर जेल गए सत्ताधारी नेता को हटाने के प्रविधान वाले विधेयक को ऐसी ही समिति में भेजने का फैसला कर लिया गया है, तब कई विपक्षी दल उसका बहिष्कार करना आवश्यक समझ रहे हैं। समझना कठिन है कि विपक्षी दल उक्त विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? उक्त विधेयक मुख्यतः भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लाया जा रहा है। प्रस्तावित कानून पूर्ण राज्य का दर्जा वाले प्रांतों के लिए नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में कई माह जेल में रहे तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी किस तरह जमानत पाते ही मंत्री बना दिए गए थे। क्या विपक्षी दल यह चाहते हैं कि नेताओं को जेल से सरकार चलाने या जमानत पर होते हुए भी मंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए? यदि वे अपने लिए विशिष्ट नियम-कानून चाहते हैं तो यह विशेषाधिकारों की पराकाष्ठा है।

राजेश कुमार, दानापुर, पटना

पोस्ट

अमेरिका ने भारत पर 27 अगस्त से अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का नोटिस जारी किया। इसके कुछ ही घंटे पहले अहमदाबाद में पीएम मोदी ट्रंप टैरिफ पर भाषण दे रहे थे, 'भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों न हो।'

मधुरेंद्र कुमार@Madhurendra13

एक जर्मन अखबार के अनुसार बीते दिनों ट्रंप ने चार बार मोदी से फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी ने बात नहीं की। भारत ने आधिकारिक रूप से ऐसे किसी संपर्क का खंडन किया है। ट्रंप की नीतियों की काट तलाशने के लिए मोदी ने रूस एवं चीन की ओर अपना रुख किया है। अस्थिर एवं अनिश्चित दुनिया में नई दिल्ली संतुलन की राह पर चलने को प्राथमिकता देती दिख रही है। वेलिना@vtchakarova

देश के पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के चलते आपदा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण अनियोजित एवं अतिशय कंस्ट्रक्शन से बड़े पैमाने पर इमारतों को खड़ा करना भी है। वैशाली माथुर@mathur_vaishali

जनपथ

गणपति बप्पा आइए बनकर कृपानिधान,
आकर बहुविधि कीजिए भारत का कल्याण।
भारत का कल्याण रहे ना कोई बाधा,
करे बुद्धि को शुद्ध देश का 'दुश्मन आधा'!
रखें न घर के लोग बैरियों जैसी निज मति,
ऐसा ठोस जुगाड़ कीजिए कुछ तो गणपति!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 136

****

कल्पमेधा

अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम भीतर ही भीतर प्रसन्न होना, क्योंकि तुम्हारी निंदा करके वह तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले रहा है।

– ब्रह्मानंद सरस्वती

संवाद की संवेदना

हास-परिहास हमारे जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ है- हंसी, मजाक, जिससे लोगों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो हंसी-मजाक से उसके भीतर उदासी के भाव को कम किया जा सकता है। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। मगर जब हंसने और हंसाने के लिए परिहास के बजाय किसी का उपहास किया जाए, तो उसे मानवीय, नैतिक और कानूनी पहलू से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत इसे अपने अहंकार की तुष्टि, असभ्य व्यवहार और असंवेदनशीलता ही कहा जाएगा। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सोशल मीडिया पर खासा असर रखने वाले पांच लोगों को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश देना उन लोगों के लिए भी सबक है, जो सार्वजनिक रूप से किसी का उपहास करने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि व्यावसायिक फायदे के लिए टिप्पणी करना और प्रतिबंधित भाषण मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आजकल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर कई तरह के हास्य कार्यक्रम एवं सामग्रियां परोसी जा रही हैं और इस दौरान हास्य के नाम पर आपत्तिजनक टीका-टिप्पणियों के मामले भी सामने आते रहते हैं। लोगों का मनोरंजन एक तरफ है, लेकिन किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज की भावनाओं को आहत करना या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों और प्रस्तोताओं की यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई भी टिप्पणी करते समय सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए। खासकर, जब ऐसे लोग उपहास से पीड़ित हों, जो समाज में हाशिये पर रहने वाले वर्ग से संबंधित हों, तो मामले की गंभीरता और भी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले जिन पांच लोगों का मामला सामने आया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया तथा कहा कि आरोपियों पर जुर्माना लगाने पर भी विचार किया जाएगा और इस राशि का इस्तेमाल उन दिव्यांगों के उपचार में किया जा सकता है, जिन्हें उपहास का पात्र बनाया गया।

यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या हास्य के नाम पर इस तरह के व्यावसायिक कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी सामग्री परोसी जा सकती है! क्या इस बात का खयाल नहीं रखा जाना चाहिए कि मनोरंजन के लिए किसी के सम्मान और संवेदना को ताक पर न रखा जाए? शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह की गतिविधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से कारोबार है। यही नहीं, न्यायालय ने सरकार को सोशल मीडिया पर सामग्री के विनियमन को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने को भी कहा है। दरअसल, इसे लेकर काफी पहले से मांग उठती रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसमें दोराय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपत्तिजनक और संवेदनहीन सामग्री परोसने का चलन बढ़ रहा है, उस लिहाज से जवाबदेही तय करने का पहलू भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सही है कि हास्य मनोरंजन का एक जरिया है। मगर, दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसी को बेचने की कोशिश किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

दावे के बरक्स

बिहार में पिछले कुछ समय से जघन्य अपराधों के आंकड़ों और निरंतरता में जैसी तेज बढ़ोतरी हुई है, वह बताती है कि राज्य सरकार ने जितने बड़े पैमाने पर कथित सुशासन का प्रचार किया था, वह हकीकत से काफी दूर है। हाल के दिनों में राज्य में हत्या की कई घटनाएं सुर्खियों में रहीं। यह तब है, जब राज्य सरकार हर कुछ दिन बाद यह दावा करती दिखती है कि वहां जंगलराज के बाद उसने सुशासन कायम किया। सवाल है कि पिछले करीब दो दशक से सत्ता में रहने के बावजूद अगर अपराधों की बढ़ती संख्या, उसकी प्रकृति और निरंतरता पर रोक नहीं लग सकी, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालत यह है कि अब अपराधियों के निशाने पर बच्चे भी आने लगे हैं। इसी महीने की शुरुआत में पटना के जानीपुर इलाके में दो बच्चों को जला कर मार डाला गया था। अब बीते पंद्रह अगस्त को भी पटना के इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चे घर से खेलते-कूदते ट्यूशन के लिए निकले और बाद में सड़क किनारे खड़ी कार में दोनों के शव मिले।

सवाल है कि यह किस तरह का सुशासन है कि न तो अपराधों पर लगाम लग पा रही है, न ही अपराध हो जाने के बाद पुलिस कुछ कर पा रही है। इंद्रपुरी में दो बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस को जहां सक्रिय होकर जल्द से जल्द मामले को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहीं वह अब तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। नतीजतन, वहां सोमवार को सरकार और पुलिस के रुख से भड़के लोगों की भीड़ अराजक हो गई और उसने पुलिस के वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। निश्चित रूप से लोगों का इस तरह हिंसक हो जाना समस्या के समाधान के रास्ते को बाधित करता है, मगर सवाल है कि आखिर पुलिस और प्रशासन की नींद तभी क्यों खुलती है, जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है। अफसोसनाक यह है कि अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं राज्य की सरकार और पुलिस मानो लाचार खड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है। सवाल है कि सरकार क्या अपराधों की ऐसी ही तस्वीर के साथ जनता से समर्थन की उम्मीद कर रही है!

जीव विज्ञान के समांतर कृत्रिम मेधा

कृत्रिम मेधा आज न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि यह मानव सभ्यता के सोचने, समझने, सीखने और कार्य करने के तरीकों को भी जड़ से बदल रही है। मगर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच जीव विज्ञान जैसे परंपरागत विषय की प्रासंगिकता बनी रहेगी?

सलोनी यादव

इक्कीसवीं सदी की सबसे तीव्र और परिवर्तनशील क्रांति अगर कोई मानी जा रही है, तो वह है कृत्रिम मेधा, यानी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (एआइ)। आज यह न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव सभ्यता के सोचने, समझने, सीखने और कार्य करने के तरीकों को भी जड़ से बदल रही है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इसके उपयोग से नए-नए अनुसंधान कर रहे हैं। मगर इन सबके बीच एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कृत्रिम मेधा के बढ़ते प्रभाव के बीच जीव विज्ञान जैसे परंपरागत विषय की प्रासंगिकता बनी रहेगी? क्या जीव विज्ञान के विषय को एक 'कूट भाषा' से पूरी तरह संभाला जा सकता है? सवाल है कि कृत्रिम मेधा के इस युग में जीव विज्ञान की क्या भूमिका है। उसकी उपयोगिता और सीमाएं क्या हैं तथा मानवीय हस्तक्षेप और जिम्मेदारी का क्या स्थान है।

आज कृत्रिम मेधा का विस्तार जंगल की आग की तरह हो रहा है। मशीन और इसके जटिल निर्माण तथा अन्य प्रणालियों से लैस तकनीकों ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना दिया है। एआइ का उपयोग मशीनीकरण, ध्वनि या स्वर सहयोग, यातायात नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और संगीत रचना में भी किया जा रहा है। शिक्षा जगत में एआइ ने शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक नया संवाद स्थापित किया है। 'स्मार्ट' कक्षा, आभासी सहयोग और निजी स्तर पर सीखने के लिए समाधान की तलाश में विद्यार्थी अब अपनी रुचियों और जरूरतों के अनुसार पढ़ाई कर पा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा जांच और इलाज में मदद कर रही है, रोगों की पहचान कर रही है और शल्य चिकित्सा के लिए रोबोटिक सहयोग प्रदान कर रही है।

इन सबके बीच जीव विज्ञान का क्षेत्र, जो मूलतः जीवन के अध्ययन से जुड़ा है, पर थोड़ा पीछे छूटता हुआ प्रतीत होता है। जीव विज्ञान की जटिलता और इसकी नैतिक सीमाएं इसे बाकी तकनीकी क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। जीव विज्ञान केवल जीवों का अध्ययन नहीं, यह उन प्रक्रियाओं, घटनाओं, संबंधों और संरचनाओं की पड़ताल करता है, जो जीवन को संभव बनाती हैं। कोशिकाओं की बनावट, जीन की क्रियाएं, 'मेटाबोलिज्म', रोगों की उत्पत्ति और पर्यावरणीय प्रभाव- इन सभी को समझे बिना न तो हम स्वयं को, न अपने समाज और न ही अपने ग्रह को सही ढंग से समझ सकते हैं। यह समझ हमें सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम मेधा जीव विज्ञान में सहायक बन सकती है? इसका उत्तर है- हां। कुछ क्षेत्रों में यह पहले से मदद का जरिया बन चुकी है। आज वैज्ञानिक कृत्रिम मेधा की मदद से 'जीनोमिक्स' में व्यापक स्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। एक इंसान के डीएनए में लगभग तीन अरब 'बेस पेयर्स' होते हैं। इनका विश्लेषण करना अत्यंत जटिल कार्य है, लेकिन एआइ एल्गोरिदम के उपयोग से हम कोशिकाओं के लक्षणों को पहचान सकते हैं। उनके बहुरूपण का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि व्यक्तिगत 'जीन प्रोफाइल' के अनुसार दवाएं विकसित की जा सकती हैं। दरअसल, दवा की खोज में भी कृत्रिम मेधा

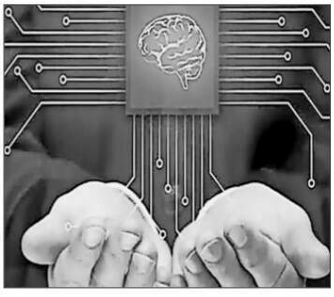

की मदद ली जा रही है। मशीनें अब यह अनुमान लगा सकती हैं कि कोई रासायनिक अणु किस बीमारी पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा।

भले ही कृत्रिम मेधा कई मायनों में उपयोगी है, पर इसके कुछ मूलभूत दोष और सीमाएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन,

> **जीव विज्ञान में मानवीय भागीदारी केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि वह नैतिक, भावनात्मक और व्याख्यात्मक भी होती है। जब कोई वैज्ञानिक किसी नई दवा की खोज करता है, तो वह न केवल इसके परिणामों को देखता है, बल्कि यह भी सोचता है कि यह समाज पर क्या प्रभाव डालेगी। मनुष्य की जिज्ञासा, संवेदना और नैतिक जिम्मेदारी ही उसे मशीनों से अलग बनाती हैं। ऐसे में कृत्रिम मेधा और मनुष्य के बीच संबंध प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहकारी होने चाहिए। इस आधुनिक तकनीक को एक सहायक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए, न कि किसी अंतिम निर्णयकर्ता की तरह।**

प्रयोगशाला से दूरी। एआइ पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन वह परीक्षण नहीं कर सकता। कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तभी मान्य होता है, जब वह प्रयोगशाला में दोहराया जा सके। आज भी कई एआइ प्रतिरूप प्रयोगशाला स्तर पर प्रमाणित नहीं हो पाते। दूसरा, नैतिकता की कमी। एआइ संवेदनाओं से रहित होता है। वह 'क्या करना चाहिए' और 'क्या नहीं करना चाहिए', इसका निर्णय नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए अगर एआइ एक दवा की सलाह देता है, जो किसी रोगी पर प्रभावी नहीं है, तो इसका दोष किस पर होगा? तीसरा, आंकड़ों का पूर्वाग्रह। एआइ वही सीखता और करता है, जो आंकड़ों में होता है। अगर आंकड़े असंतुलित या पक्षपाती हैं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। चिकित्सा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह स्थिति घातक हो सकती है।

वहीं, जीव विज्ञान में मानवीय भागीदारी केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि वह नैतिक, भावनात्मक और व्याख्यात्मक भी होती है। उदाहरण के लिए- जब कोई वैज्ञानिक किसी नई दवा की खोज करता है, तो वह न केवल इसके परिणामों को देखता है, बल्कि यह भी सोचता है कि यह समाज पर क्या प्रभाव डालेगी। मनुष्य की जिज्ञासा, संवेदना और नैतिक जिम्मेदारी ही उसे मशीनों से अलग बनाती हैं। हम प्रकृति के प्रति 'लगाव' और 'संरक्षण' की भावना से कार्य करते हैं, जबकि मशीन केवल निष्कर्ष और निष्पादन तक सीमित होती है। ऐसे में एआइ और मनुष्य के बीच संबंध प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहकारी होने चाहिए। कृत्रिम मेधा को एक सहायक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए, न कि किसी अंतिम निर्णयकर्ता की तरह। कृत्रिम मेधा द्वारा प्रदान की गई सटीकता और गति अगर मनुष्य की समझ, अनुभव और नैतिकता से जुड़ जाए, तो हम विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन निर्णय, जिम्मेदारी और नेतृत्व की भूमिका हमेशा मनुष्य के पास होनी चाहिए।

कृत्रिम मेधा और जीव विज्ञान के इस बढ़ते संवाद से शिक्षा प्रणाली का रूप भी बदल रहा है। पारंपरिक कक्षाएं अब साइबर प्रयोगशाला और संवादात्मक जैविक प्रतिरूप के माध्यम से बदल रही हैं। इसके उपयोग से अब विद्यार्थियों को जटिल जैविक प्रक्रियाओं जैसे प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, जीन अभिव्यक्ति आदि को त्रिआयामी और एनीमेशन के जरिए देखने और समझने का अवसर मिल रहा है। इससे न केवल गहराई से समझ विकसित हो रही है, बल्कि सीखने की रुचि और रचनात्मकता भी बढ़ रही है। अब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचि और सीखने की शैली के अनुसार पाठ तैयार होते हैं। साथ ही शिक्षक अब डेटा-विश्लेषण की मदद से यह पहचान सकते हैं कि किस विद्यार्थी को किस विषय में अधिक सहायता की आवश्यकता है और उसी के अनुसार शिक्षण की नीतियां अपनाई जा सकती हैं।

शिक्षा में यह तकनीकी एकीकरण अगर सही दिशा और संतुलन के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में नई पीढ़ी को और अधिक आत्मनिर्भर, जिज्ञासु और व्यावहारिक बना सकता है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है कि कृत्रिम मेधा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। इस साधन को मानवीय समझ, संवेदना और मार्गदर्शन के साथ जोड़ना ही शिक्षण की सफलता की कुंजी होगी। कृत्रिम मेधा एक शानदार तकनीक है, जिसने विज्ञान को नई दिशा दी है, लेकिन जब बात जीव विज्ञान की आती है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह विषय केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन की समझ, भावनाओं और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। इसलिए कृत्रिम मेधा जीव विज्ञान को अधिक तेज, सटीक और गहन बना सकती है, लेकिन वह कभी भी मानवीय अंतर्दृष्टि की जगह नहीं ले सकती।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

खुशी की चाह

गौरव बिस्सा

हममें से ज्यादातर लोगों ने अक्सर यह महसूस किया होगा कि सब कुछ होने के बावजूद मन बड़ा अशांत है। मन के भीतर खुशी नहीं है। चित्त प्रसन्न नहीं है। आखिर क्या है प्रसन्नता के अभाव का कारण? इस पर गहनता से विचार किया जाए, तो सामने आएगा रेखा विज्ञान। रेखा विज्ञान ही सब क्लेशों का मूल है। रेखा विज्ञान यानी एक खुशी मिलते ही नई रेखा खींचना और खुद से यह कहना कि यह खुशी तो मिल चुकी, लेकिन मैं तब खुश होऊंगा जब इससे इतर दूसरी खुशी मिल जाए। बस यही रेखा खींचने का रेखा शास्त्र है। इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। छोटा बच्चा, कक्षा चार। उसके मन में भाव है कि एक बार परीक्षा खत्म हो जाए और छुट्टियां शुरू हो जाएं, तो खुशी ही खुशी है। वही बच्चा, कक्षा दस। उसकी सोच कि बोर्ड में अच्छे अंक आ जाएं तो सब आनंद। कुछ साल बाद उसकी सोच यह कि पढ़ाई पूरी हो और एक नौकरी मिल जाए तो खुशी। नौकरी लगते ही विवाह, संतान और उसके बाद संतान पढ़ ले तो खुशी। फिर मकान, प्रोन्नति, संपत्ति, वित्त प्रबंध, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो खुशी मिलेगी का भाव। इन सबके बीच समझना यह है कि खुशी मिली नहीं, बस तलाशी जा रही है। हर व्यक्ति इसी अंतहीन चक्र में अपना जीवन जी रहा है। एक उपलब्धि मिलते ही उस उपलब्धि पर खुश होने के बजाय दूसरी उपलब्धि मिलने पर खुश होने का लक्ष्य बना रहा है, रेखा खींचे जा रहा है। बस, खुशी न मिलने का यही कारण है।

हरेक व्यक्ति वह हासिल करने में व्यस्त है जो उसके पास नहीं है। साथ ही, हर व्यक्ति वह बनने में व्यस्त है जो वह आंतरिक रूप से है ही नहीं। इसी कारण दुख है। जो मिला है, उसके लिए व्यक्ति में किसी तरह की कृतज्ञता का भाव नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही मनुष्य में अगली इच्छा जन्म ले लेती है। इन इच्छाओं का अंतहीन चक्र व्यक्ति को कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं होने देता। यही दुखों और कष्टों का कारण है। 'जो नहीं है', उसकी इच्छा करके 'जो है' उसे खराब करने में व्यक्ति मानो आमादा है।

व्यक्ति कृत्रिम सुख या बाहरी खुशी की प्राप्ति के स्वप्न को जी रहा है। कृत्रिम खुशी क्षणिक है। कृत्रिम खुशी बाहरी संसाधनों, जैसे टीवी या सिनेमा देखने, मोबाइल की दुनिया से सोशल मीडिया पर पसंदगी का चटका, पर्यटन यात्राओं आदि से प्राप्त होती हैं। ये कुछ क्षणों तक सुख देती हैं, लेकिन उसके बाद व्यक्ति वापस दुखी हो जाता है। वास्तविक खुशी आंतरिक है जो दूसरों को सुख देकर मिलती है। हमने देखा होगा कि इंद्रधनुष बड़े ही सीमित समय के लिए दिखता है, यानी उसकी आयु बहुत छोटी होती है। अपनी सीमित आयु में भी इंद्रधनुष लोगों को खुशी देता है। मनुष्य को भी इंद्रधनुष की ही तरह अपनी सीमित आयु में अनेक व्यक्तियों को प्रसन्न करने का, उनके जीवन की मुस्कुराहट बनने का कार्य करना चाहिए। इसी में वास्तविक खुशी है।

भगवद्गीता के अनुसार, जो व्यक्ति बाह्य भोग-विलास में आसक्त नहीं होता और जिसका चित्त स्थिर रहता है, वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट है कि चिर स्थायी खुशी अनासक्त रहने में, बाहरी भोग विलास के कुचक्र को त्यागने में और अपने मन को स्थिर रखने में है। अच्छी या बुरी- जो भी परिस्थिति हो, उसे स्वीकारते हुए अपना कार्य करते रहना व्यक्ति में खुशी का संचार करता है। कठोपनिषद् कहता है कि त्याग से शांति प्राप्त होती है और यही सच्चा सुख है। इससे स्पष्ट है कि बाहरी संसाधनों, संपत्ति आदि से बंधन ही दुख का मूल है। इसलिए अनासक्त भाव उचित है। 'मेरा कुछ नहीं है' का भाव रखना ही खुशी प्राप्ति का पहला सूत्र है।

डेनमार्क में खुश रहने की 'ह्यूगे शैली' अपनाई जाती है। ह्यूगे का अर्थ है छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूंढ़ना। बड़ी घटनाओं और खुशियों के बजाय इस पल की खुशी का आनंद लेना ही ह्यूगे है। भारत तो इस तकनीक को सहस्रों वर्षों से जी रहा है। हमने मंदिरों में उद्घोष सुना होगा- 'आज के आनंद की जय'। ये ह्यूगे शैली ही है। इस शैली में परिवारजन सुखपूर्वक साथ में अध्ययन करते हैं, चाय-काफी पीते हैं या संगीत सुनते हैं। वे खुश होने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतजार नहीं करते। इसी तरह जापान में इकिगाई संस्कृति है। इकिगाई का अर्थ है जीने के कारण की खोज। ये जीने की प्रेरणा देता है। इकिगाई के चार सूत्र हैं- आपको किससे प्रेम है? आप किस चीज में कुशल हैं? आपकी क्या आवश्यकता है? आप किस चीज से आजीविका कमा सकते हैं? इन चार प्रश्नों का उत्तर शांति से देने पर जीवन का उद्देश्य मिलता है।

खुशी लेने में नहीं, देने में है। भारतीय शास्त्रों में यही बात वर्णित है। यही तत्त्व बोध है। मनुष्य को तत्त्व बोध तब होता है जब वह दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उन्हें प्रसन्न करने का भाव रखे। जीवन में तत्त्व बोध बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। जिन संसाधनों में व्यक्ति खुशी खोजता है, वे मृत्यु के बाद यहीं रह जाते हैं। व्यक्ति के साथ चलते हैं उसके सत्कर्म और अन्यों की दी गई खुशी। दूसरों को खुशी देना ही जीवन का उद्देश्य है। एक शोध के अनुसार, जो लोग खुशी बांटने में समय खर्च करते हैं और दूसरों के लिए कुछ करने की सोच रखते हैं, उनका जीवन काल अन्यों के मुकाबले लंबा और रोग विहीन होता है। अन्यों के जीवन की खुशी बनना ही जीवन है। करुणामय बनकर जीना ही जीवन है। वास्तविक आयु वही समय है जो व्यक्ति अन्य की खुशी और कुछ नया सीखने में देता है। बाहरी के बजाय अंतर्मन में खुशी तलाशना ही जीवन जीने का तरीका है।

दुनिया मेरे आगे

> **जिन संसाधनों में व्यक्ति खुशी खोजता है, वे मृत्यु के बाद यहीं रह जाते हैं। व्यक्ति के साथ चलते हैं उसके सत्कर्म और अन्यों की दी गई खुशी। एक शोध के अनुसार, जो लोग खुशी बांटने में समय खर्च करते हैं और दूसरों के लिए कुछ करने की सोच रखते हैं, उनका जीवन काल अन्यों के मुकाबले लंबा और रोग विहीन होता है।**

राजनीति में शुचिता

एक दौर था जब जैन हवाला डायरी में सिर्फ नाम आने पर कई दिग्गज नेताओं ने नैतिकता के आधार पर अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। एक आज का दौर है, जब नेता जेल में रहते हुए भी सरकार चलना चाहते हैं। नैतिकता का ह्रास होने पर ही सरकार को भ्रष्टाचार में शामिल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को तीस दिन तक जेल या हिरासत में रहने पर हटाने वाला विधेयक लाना पड़ा। राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात सब करते हैं, लेकिन ईमानदार कोशिश कोई नहीं करता। विपक्ष राजनीति में शुचिता लाने के इस प्रयास का विरोध दुरुपयोग के डर से कर रहा है। हर कानून के दुरुपयोग की संभावना होती है। मगर इस कारण कानून बनाने और व्यवस्था को सुधारने का काम रुक नहीं सकता। इस विधेयक पर विचार के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति से सपा और तृणमूल कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस भी दूरी बना सकती है। विचार-विमर्श और अपने दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से रखने के लिए जरूरी है कि विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हो। विरोध करने के बजाय सरकार के साथ सहयोग करे, ताकि ऐसा कानून बन सके जिसका दुरुपयोग बिल्कुल न हो।

– बृजेश माथुर, गाजियाबाद

भरोसे का संकट

पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में विशेष महत्त्व रखती है। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को दूर करने और संवाद की राह खोलने का यह प्रयास है। सीमा पर तनाव घटने के बावजूद अभी स्थायी समाधान की दरकार है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह यात्रा अहम है, क्योंकि अमेरिका की शुल्क नीतियों ने भारत और चीन दोनों को नए साझेदारों की तलाश के लिए मजबूर किया है। हालांकि चीन के साथ भारत का कड़वा अनुभव रहा है। सीमा विवाद और व्यापारिक असंतुलन दोनों जारी रहते हैं। चीन तकनीकी सहयोग और निर्यात में अड़चनें डालता है, जिससे भारत का घाटा और बढ़ा है। ऐसे में वांग यी की यात्रा संवाद को गति तो दे सकती है, पर भरोसे की खाई पाटना आसान नहीं होगा। कोई दोराय नहीं कि प्रधानमंत्री की आगामी चीन यात्रा से पहले यह कूटनीतिक पहल भविष्य की दिशा तय करने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

धैर्य का महत्त्व

संकट का क्षण मनुष्य के लिए सबसे कठिन परीक्षा होता है। ऐसे समय में घबराहट और अधीरता व्यक्ति की शक्ति को क्षीण कर देती है जबकि धैर्य भीतर से ऊर्जा का स्रोत बन कर मार्ग प्रशस्त करता है। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। शास्त्रों में कहा गया है 'क्षमा धैर्य दया शांति धर्मस्य मूलं'। अर्थात धर्म का आधार धैर्य और शांति में निहित है। जीवन में हर कठिनाई धैर्य की कसौटी होती है। किसान महीनों तक फसल पकने की प्रतीक्षा करता है। साधक वर्षों की तपस्या के बाद ही ज्ञान प्राप्त करता है। नदी धैर्यपूर्वक पत्थरों को काटती है और अंततः अपना मार्ग बना लेती है। यही धैर्य साधारण को असाधारण में बदल देता है। आज समाज और व्यक्ति दोनों को धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। अधीरता से लिए गए निर्णय संघर्ष बढ़ाते हैं। जबकि धैर्य हमें दूरगामी समाधान की ओर ले जाता है। अगर हम कठिन परिस्थितियों में ठहरना सीख जाएं, तो संकट अवसर में बदल सकता है।

– अमन सिंह गौर, वाराणसी

सूखती जड़ें

शहरी क्षेत्रों में आए दिन आंधी-तूफान में पेड़ों का गिरना आम बात हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि सड़कों और फुटपाथों के निर्माण के समय पेड़ों के चारों ओर सीमेंट-कंक्रीट पूरी तरह भर दिया जाता है। इससे पेड़ की जड़ों तक पानी पहुंच नहीं पाता। धीरे-धीरे जड़ें कमजोर हो जाती हैं और तेज हवा में पेड़ धराशायी हो जाते हैं। सड़क निर्माण के समय पेड़ों के चारों ओर कुछ खुली जगह छोड़ी जाए, तो पानी जमीन में जा सकेगा। इससे न केवल पेड़ स्वस्थ रहेंगे, बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ेगा। पानी के अभाव में कमजोर जड़ें ही इन हादसों का मुख्य कारण हैं। कायदे से पेड़ों के चारों ओर लोहे की मजबूत जाली लगाई जानी चाहिए। इससे होकर पानी जमीन में चला जाता है। इससे भू-जल स्तर बढ़ता है। बारिश का जल जमीन सोख लेती है। इससे पेड़ हरे-भरे बने रहते हैं और आंधी में गिरने की संभावना भी नहीं रहती।

– अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 27 अगस्त 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

उपराष्ट्रपति पद के विवाद, सरकार जिम्मेदार

देश में उपराष्ट्रपति का पद अमूमन सियासी दलदल से दूर ही रहता था। राष्ट्रपति चुनाव में फिर भी राजनैतिक दांव-पेंच देखने मिल जाते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति या उपराष्ट्रपति चुनाव से विवादों का नाता नहीं होता था, अब 11 सालों की मोदी सरकार में यह बड़ा परिवर्तन भी देखने मिल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य अब भी बना हुआ है। रोजाना उनके लिए विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि धनखड़ साहब कहां हैं, कैसे हैं, वे सामने क्यों नहीं आते। लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिलता। मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन 21 जुलाई यानी सत्र के पहले दिन श्री धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उनकी कोई चर्चा उस राज्यसभा में नहीं हुई, जहां वो आसंदी पर बैठते थे। मोदी सरकार कम से कम उनके लिए एक विदाई समारोह आयोजित कर ही सकती थी, लेकिन इतनी शालीनता और शिष्टता भी नहीं दिखाई गई। इस बारे में गृहमंत्री अमित शाह से न्यूज एजेंसी एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। धनखड़ साहब को भी न जाने किस बात का डर है जो अब तक उन्होंने न किसी से फोन पर बात की, न आम जनता के लिए एक संदेश ही भेजा कि वे ठीक हैं या स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े रहस्य अभी बरकरार हैं और इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी भी शुरु हो गई है। मैदान में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के बी श्रीनिवास रेड्डी हैं। श्री रेड्डी को आम आदमी पार्टी ने भी साथ देने का वादा किया है, जबकि वह इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। लेकिन चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए इसे विचारधारा की लड़ाई बताया था, इसलिए संविधान की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। इधर अखिलेश यादव ने भी अपील कर दी है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के सामने क्रॉस वोटिंग का खतरा खड़ा हो गया है। भाजपा तो संघ से जुड़े रहे सी पी राधाकृष्णन को वोट देगी ही, लेकिन जेडीयू, टीडीपी या शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, इनमें से किसी ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन ली, तो फिर एनडीए प्रत्याशी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब अमित शाह खुद मैदान में उतरते दिख रहे हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव में शालीनता की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा इसे मलिन कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह जस्टिस रेड्डी को घेरने के लिए छत्तीसगढ़ के सलवा जुडूम अभियान पर 2011 के उनके फैसले को फाइलों से निकाला है। इस फैसले के आधार पर श्री शाह जस्टिस रेड्डी को नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं, उनके मुताबिक अगर सलवा जुडूम को खत्म करने का फैसला न आया होता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो गया होता। यहां अमित शाह ने न केवल न्यायपालिका पर उंगली उठाई है, बल्कि सुरक्षा बलों का अपमान भी किया है, जो जान की बाजी लगाकर नक्सली इलाकों में तैनात हैं।

इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस रेड्डी ने साफ कहा है कि गृहमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के 40 पन्नों के फैसले को पढ़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि इस देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री, 14 साल बाद यह मुद्दा उठा रहे हैं। जब वे इस समस्या से जूझ रहे थे, तब उन्हें कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि यह फैसला इसकी जड़ है या उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है और उनके हाथ बांध रहा है। जस्टिस रेड्डी ने सलवा जुडूम के अपने फैसले पर कहा कि हिंसा से लड़ने के नाम पर आप एक और हिंसक समूह नहीं बना सकते और दोनों एक-दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। हथियार चलाने का एकाधिकार हमेशा से राज्य का रहा है। राज्य को हिंसा के ऐसे खतरे से लड़ने का पूरा अधिकार है। फैसले में बस इतना कहा गया था, 'इसे आउटसोर्स न करें।' हिंसा से निपटना संप्रभु राज्य का संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व और ज़िम्मेदारी है।

बता दें कि 2011 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस.एस. निज्जर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया। कोर्ट ने इसे मानवाधिकारों के हनन के साथ संविधान के खिलाफ भी बताया था। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को इसे तुरंत खत्म करने का आदेश दिया था। अब अमित शाह उसी मुद्दे को अकारण जिंदा कर रहे हैं, ताकि विपक्ष के उम्मीदवार की छवि बिगड़े और उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत उनकी हो जाए। अमित शाह के अलावा पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जस्टिस रेड्डी का झुकाव माओवाद की तरफ बताया है। हालांकि इस तरह के हमले और कटाक्ष न केवल उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी चिंता जगा रहे हैं। भाजपा के शासन में पहले से जांच एजेंसियों और न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। अब अमित शाह उसे सही साबित कर रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री की टिप्पणी बहुतों को नागवार गुजरी है।

18 पूर्व जजों ने गृहमंत्री के बयान को सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए ख़तरा बताया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. पटनायक, अभय ओका, गोपाला गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकुर और जे. चेलमेश्वर, जैसे नामों के अलावा तीन पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। इन पूर्व जजों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि शाह का सलवा जुडूम फैसले की गलत व्याख्या करना और उसका राजनीतिकरण करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। पूर्व जजों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि फैसले में कहीं भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया गया।

बी सुदर्शन रेड्डी के साथ सी पी राधाकृष्णन को मुकाबला करने देने की जगह अमित शाह खुद मुकाबला करने उतर गए हैं, यह सही रवैया नहीं है।

नैतिकता और सुशासन के भेष में शैतानियत भरा इरादा

सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की आठ तारीख (8 अगस्त) को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह एक 'धूर्त' की तरह काम करने के बजाय कानून के दायरे में रह कर काम करे। इससे पहले 21 जुलाई, 2025 को भी शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा था कि, 'राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं बल्कि जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए।' उससे भी पहले 6 मई, 2025 को शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा था कि ईडी ने बिना सबूत के आरोप लगाने का 'पैटर्न' अपना लिया है। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा था कि कई मामलों में ईडी बिना पर्याप्त सबूतों के आरोप लगाती है। इसी साल फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली को 'संवैधानिक प्रावधानों के प्रति असम्मान' करार देते हुए कहा था कि वह 'कानून के विपरीत दलीलें देने' को बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे कुछ ही दिनों पहले 21 जनवरी, 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ईडी की हिरासत प्रक्रिया को अवैध ठहराया था और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी।

पिछले सात-आठ महीने के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से की गई ये सभी टिप्पणियां इस आम धारणा को पुख्ता करती हैं कि ईडी की कार्रवाइयां राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होती हैं। केंद्र सरकार की ही एक अन्य एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से इसी तरह की सख्त टिप्पणियां अक्सर सुनती रहती हैं। इसके बावजूद अब केंद्र सरकार इन्हीं एजेंसियों को यह अधिकार देने वाला कानून बनाना चाहती है कि वे जब चाहे किसी भी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री का क्रियाकर्म कर दे। यह नए मिजाज का लोकतंत्र विकसित हो रहा है- पुलिसिया लोकतंत्र।

इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता और सुशासन का ढोल पीटते हुए संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में 20 अगस्त को आनन-फानन में तीन विधेयक संसद में पेश किए, जो अगर पारित हो गए तो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। हालांकि इस प्रस्तावित कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को रखने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रावधान एक हास्यास्पद पाखंड है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहां बैंक से ठगी करने वाले किसी रसूखदार कारोबारी या सत्तारूढ़ दल या उसके समर्थक किसी धार्मिक मठ से जुड़े किसी बलात्कारी के खिलाफ तक आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वहां किसकी हिम्मत होगी कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी मामले में एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दे? ऐसा होना संभव ही नहीं है।

आज अगर देश में यह धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से ठोस तथ्यों के आधार पर कदम उठाती है, तो प्रस्तावित नए कानून को एक स्वस्थ पहल माना जाता। दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां राजनेताओं के दल और उनकी

अनिल जैन

> **आज अगर देश में यह धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से ठोस तथ्यों के आधार पर कदम उठाती है, तो प्रस्तावित नए कानून को एक स्वस्थ पहल माना जाता। दुर्भाग्य से आज धारणाएं उसके उलट हैं। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है, वह यह कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां राजनेताओं के दल और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखकर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है।**

राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखकर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और आम लोगों में भी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है।

चूंकि इस प्रस्तावित कानून पर केंद्र ने विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया है और संसद का सत्र समाप्त होने से महज एक दिन पहले गृह मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर ये विधेयक पेश किए हैं, लिहाजा सरकार की नियत पर सवालों का उठना और प्रस्तावित कानून को नैतिकता और सुशासन के आवरण में सत्ता के केंद्रीयकरण की एक शैतानियत भरी खूंखार कोशिश के रूप में देखा जाना लाजिमी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और राजनीति के शुद्धिकरण के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका यह दावा सरासर हास्यास्पद है, क्योंकि मोदी को और उनकी सरकार को अगर भ्रष्टाचार से वाकई परहेज होता तो वे इस पहलकदमी के लिए 11 साल का इंतजार नहीं करते। वे तो यह गर्जना करते हुए ही सत्ता में आए थे कि, ''न खाऊंगा और न खाने दूंगा''। देश ने तो यही देखा है कि उनकी सरकार ने अरबों रुपये के घोटालों में फंसे हेमंत बिस्व सरमा, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, नारायण राणे, अशोक चह्वाण, एचडी कुमार स्वामी, सुवेंदु अधिकारी जैसे अनगिनत नेताओं के खिलाफ मामले सिर्फ इसलिए रफा-दफा कर दिए कि इन लोगों ने भाजपा में शामिल होना या सत्ता में उसका सहयोगी बनना कुबूल कर लिया। भाजपा के शिवराज सिंह और रमन सिंह जैसे कई नेताओं पर अरबों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, जांच तक नहीं हुई है।

नियमानुसार सदन में कोई भी विधेयक पेश होता है तो सदस्यों को उस विधेयक की प्रति 24 घंटे पहले उपलब्ध करानी होती है, ताकि वे विधेयक पर चर्चा के लिए तैयारी करके सदन में आएं, लेकिन ये विधेयक पेश हुए 20 अगस्त को सुबह और इन विधेयकों की प्रतियां सांसदों के पास भेजी गई 19 अगस्त की देर शाम को। लोकसभा सचिवालय को भी इन विधेयकों के बारे में 19 जनवरी की शाम को सूचित किया गया और इन विधेयकों को पेश करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई, जो कि मिलनी ही थी।

बहरहाल एक प्रस्ताव के जरिये इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है, जो इन विधेयकों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। हालांकि इसके बाद भी इन विधेयकों का पारित होना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा, जो कि मौजूदा स्थिति में बेहद मुश्किल है। मोदी सरकार अभी सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है और लगता नहीं कि सारे सहयोगी दल खास कर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) इन विधेयकों का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करेंगे, क्योंकि ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए तलवार बनेगा, बल्कि यह भाजपा के लिए अपने सहयोगी दलों को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बन जाएगा। फिर भी अगर किसी तरह सरकार संसद में इन विधेयकों को पारित करा लेती है तो उसके लिए अगली बड़ी चुनौती होगी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा में इन्हें पारित कराना, जो कि आसान नहीं लगता।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस समय चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने लंबे समय से यह नैरेटिव बना रखा था कि वह इस मुददे पर कोई समझौता नहीं करती है, लेकिन पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से उस नैरेटिव की कलई उतर चुकी है। पाकिस्तान पर बढ़त बना रही भारतीय सेना को उसने न सिर्फ अमेरिकी दबाव में सीजफायर करने के लिए मजबूर किया बल्कि इस सिलसिले में उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समर्थन नहीं मिला और उल्टे रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की ताकतवर देशों के साथ नजदीकियां बढ़ गईं, जो कि कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी नाकामी है।

इधर घरेलू राजनीति में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवाने वाले प्रकरण ने तो मोदी सरकार को कमजोर किया ही, साथ ही उजागर हुई गंभीर चुनावी गड़बड़ियों और बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण चुनाव आयोग के विवादों में घिर जाने की वजह से भी उसकी मुश्किलें बढ गई हैं। चुनावी गड़बड़ियों के उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे विवादास्पद अभियान ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है, जो अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में भी फैलने की संभावना है। इसलिए लगता है कि इन्हीं सब बातों से लोगों का और खास कर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के सरकार ने इन तीन नए कानूनों को लाने की नैतिकता में लिपटी अनैतिक पहल की है, जिसका हश्र तीन विवादास्पद कृषि कानूनों जैसा ही होने की संभावना है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भारी विरोध और लगभग 500 किसानों की दर्दनाक मौत के बाद यह कहते हुए वापस ले लिया था कि ''शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है।''

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ट्रम्प का अमेरिका भरोसेमंद नहीं, शी जिनपिंग का चीन हो सकता है और भी बुरा

■ **नन्तू बनर्जी**

अमेरिका के साथ भारत के मौजूदा व्यापार शुल्क विवाद के बावजूद, भारत को चीन से आयात को और बढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। भारत पहले से ही भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा है। चीन-भारत द्विपक्षीय व्यापार एक-दूसरे की मुद्राओं में सबसे स्वागत योग्य है, जैसा कि रूस-भारत व्यापार के मामले में किया जा रहा है, जिससे रूस से भारत के तेल आयात को काफी बढ़ावा मिल रहा है। रूस-भारत व्यापार का 90 प्रतिशत से अधिक अब रूबल और रुपये में होता है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होती है और दोनों देशों की वित्तीय संप्रभुता बढ़ती है।

साथ ही, भारत को उर्वरकों, दुर्लभ मृदा तत्वों और औषधि मध्यस्थों आदि का अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। भारत चीन से लगभग 2,000 वस्तुओं का आयात करता है। लगभग 600 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दो-तिहाई से अधिक आयात चीन से होता है। भारत के चीन के साथ कई असहज मुद्दे हैं, सीमा विवाद से लेकर भारत के दो कठिन पड़ोसियों - पाकिस्तान और बांग्लादेश - के साथ चीन के मजबूत सैन्य गठबंधन तक। चीन, अमेरिका और भारत के बीच ताज़ा व्यापारिक विवाद का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह अमेरिकी कार्रवाई के ख़िलाफ़ चेतावनी देकर, अमेरिका को 'धौंसिया' बताकर और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के ढांचे को बनाए रखने के लिए भारत के साथ खड़ा होकर, इसे और तूल दे रहा है। चीन एशिया में अमेरिकी प्रभाव का मुक़ाबला करने के लिए भारत-अमेरिका के मौजूदा कूटनीतिक तनाव का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसका लक्ष्य अमेरिका-भारत संबंधों को कमज़ोर करना, नई दिल्ली को बीजिंग के क़रीब आने के लिए मजबूर करना और क्षेत्र में चीन की अपनी रणनीतिक स्थिति को मज़बूत करना है, ख़ासकर वाशिंगटन की अप्रत्याशित विदेश नीति को लेकर साझा चिंताओं के संदर्भ में।

> **अगर भारत, अमेरिका के साथ मौजूदा तनातनी के बीच चीन की चालाकी और उसकी दोस्ती के हाथ पर भरोसा करता है, तो वह एक बड़ी भूल करेगा। अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक विश्वास के टूटने का चीन लाभ उठाना चाहता है। हाल ही में, नई दिल्ली की यात्रा के तुरंत बादचीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस्लामाबाद की यात्रा ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह बढ़ते चीन-पाकिस्तान संबंधों को कहीं अधिक महत्व देता है।**

अगर भारत, अमेरिका के साथ मौजूदा तनातनी के बीच चीन की चालाकी और उसकी दोस्ती के हाथ पर भरोसा करता है, तो वह एक बड़ी भूल करेगा। अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक विश्वास के टूटने का चीन लाभ उठाना चाहता है। हाल ही में, नई दिल्ली की यात्रा के तुरंत बादचीनी विदेश मंत्री वांग यी की इस्लामाबाद की यात्रा ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह बढ़ते चीन-पाकिस्तान संबंधों को कहीं अधिक महत्व देता है।

वांग यी की दिल्ली यात्रा के दौरान, चीन ने ताइवान मुद्दे को अपने 'एक-चीन' संकल्प के रूप में भारत के साथ छल करने की कोशिश की और भारत को अपने समर्थन में खींचने की कोशिश की। पिछले हफ्ते, चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के दौरान एक-चीन नीति से संबंधित कथित टिप्पणियों पर भारत द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर 'आश्चर्य' व्यक्त किया। भारत ने कहा है कि ताइवान पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और ताइवान के साथ नई दिल्ली के रिश्ते आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत को चीन के नवीनतम कदमों से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है।

भारत को 'प्रतिद्वंद्वी' के बजाय 'साझेदार' के रूप में दिखाने की कोशिश करके चीन अमेरिका-भारत व्यापार विवाद का बेतहाशा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे उर्वरक, दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक और औद्योगिक उपकरणों पर निर्यात प्रतिबंधों में तुरंत ढील दी। बदलाव के तौर परचीन ने अपने देश में भारतीय निवेश का स्वागत किया है और एक 'निष्पक्ष, न्यायसंगत और भेदभाव रहित व्यापार' की उम्मीद जताई है।

भारत में कार्यरत चीनी उद्यमों के लिए 'एक बेहतर माहौल' की आवश्यकता पर बल देते हुए, चीनी राजदूत जू ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को व्यापक संबंधों से अलग देखने की आवश्यकता पर भी बल दिया और सुझाव दिया कि सीमा मुद्दे के समाधान के साथ-साथ सहयोग भी आगे बढ़ सकता है। भारत को इन परिस्थितियों से सावधानीपूर्वक निपटना होगा और अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंधों को संभालना होगा, क्योंकि वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

हालांकि, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखते हुए चीन आज भारत के साथ राजनयिक संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शीजिनपिंग ने 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। सीमा मुद्दों को व्यापक रूप से सुलझाने और दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने हेतु महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों के लिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी यात्राएं की हैं।

फिर भी, भारत के साथ व्यवहार करने के दृष्टिकोण में चीन के सुविचारित बदलाव, विशेष रूप से अमेरिका-भारत व्यापार विवाद के बाद, के प्रतिभारत के लोगों को चीन के इरादों को लेकर कुछ हद तक संशय है, खासकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम पर एक विशाल बांध बनाने जैसी बीजिंग की कई गतिविधियों को लेकर, जो भारत में प्रवेश करने से पहले चीन से होकर आता है जिसके प्रवाह को चीन नियंत्रित करेगा। पाकिस्तान में मसूद अजहर जैसे आतंकवादी नेताओं को वहां इस्लामी नेटवर्क का समर्थन करने के लिए चीन संरक्षण देता रहा है। अब डर है कि बीजिंग चुपचाप बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे सकता है। ऐसी गतिविधियां भारत की आर्थिक जीवनरेखा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। भारत को व्यापारिक और कूटनीतिक विकल्पों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए।

आपके पत्र

क्यों पिछड़ रही है पशु चिकित्सा सेवाएं

भारत में पशुपालन केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं है बल्कि यह करोड़ों परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार भी है। दूध, मांस, अंडे, ऊन और अन्य पशु उत्पादों की आपूर्ति के साथ-साथ यह क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन का एक सशक्त साधन है। लेकिन विडंबना यह है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को संवारने वाले पशु चिकित्सकों की भारी कमी से आज देश जूझ रहा है। हाल ही में संसद में पूछे गए प्रश्न और सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से यह तथ्य सामने आया कि देशभर में पशु चिकित्सकों के कुल 38,916 स्वीकृत पदों में से 10,839 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह लगभग 28 प्रतिशत रिक्तता है, जो सीधे-सीधे पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक असर डालती है।

पशु चिकित्सक केवल पशुओं का इलाज ही नहीं करते, बल्कि वे पशुधन से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, प्रजनन संबंधी परामर्श और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उनके अभाव में न केवल पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बल्कि देश की दुग्ध और मांस उत्पादन क्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आँकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में पशु चिकित्सकों की कमी कितनी गंभीर है। महाराष्ट्र में 4685 स्वीकृत पदों में से 3072 पद खाली हैं। कर्नाटक में 3317 स्वीकृत पदों में से 1156 रिक्त हैं। बिहार में 2067 पदों में से 860 खाली पड़े हैं। राजस्थान में 3691 में से 1367 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में 1984 में से 506 पद खाली हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों जैसे मेघालय और लक्षद्वीप में कोई भी रिक्ति नहीं है। लेकिन देश के बड़े और कृषि प्रधान राज्यों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। कुल मिलाकर 38,916 स्वीकृत पदों के मुकाबले 10,839 रिक्तियां यह दर्शाती हैं कि लगभग हर तीसरा पद खाली है। यह आंकड़ा किसी भी देश के पशु स्वास्थ्य ढांचे के लिए खतरे की घंटी है।

इतनी बड़ी संख्या में पदों के रिक्त रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। खासकर छोटे और सीमांत किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिनकी आजीविका पूरी तरह से पशुपालन पर निर्भर है। आपात स्थिति में बीमार या घायल पशु के लिए समय पर डॉक्टर न मिल पाना पशुपालकों के लिए गंभीर संकट बन जाता है। मुंहपका-खुरपका, ब्रूसेलोसिस, बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटना मुश्किल हो जाता है। पर्याप्त पशु चिकित्सक न होने से बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है। पशुओं की समय पर देखभाल न होने से दूध और मांस उत्पादन घटता है, जिससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ता है। और ज़ूनोटिक बीमारियाँ जैसे रैबीज़ या एवियन फ्लू का खतरा भी बढ़ता है।

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पशु चिकित्सकों की नियुक्ति राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार केवल दिशानिर्देश और वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। इसी क्रम में लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स चलाए जाते हैं, जो गांव-गांव जाकर पशुपालकों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। अभी तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8191 मोबाइल इकाइयां कार्यरत हैं। किसानों के लिए 1962 नंबर की टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। ये प्रयास निश्चित रूप से उपयोगी हैं, लेकिन इनसे स्थायी समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि मोबाइल इकाइयां नियमित पशु चिकित्सक का विकल्प नहीं बन सकतीं।

इस समस्या की जड़ गहराई से समझने पर पता चलता है कि सबसे बड़ा कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी है। अधिकांश राज्यों में चयन आयोगों और भर्ती एजेंसियों की धीमी गति के कारण वर्षों तक पद खाली रह जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन की बढ़ती जरूरतों के बावजूद नए पदों का सृजन नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रति पशु चिकित्सकों की अनिच्छा और शैक्षणिक संस्थानों की सीमित संख्या भी समस्या को और जटिल बनाती है। कई बार वेतन और सुविधाओं का स्तर भी इस पेशे को युवाओं के लिए आकर्षक नहीं बनाता।

-डॉ. प्रियंका सौरभ

ललित सुरजन की कलम से

क्या तिलिस्म टूट रहा है?

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुखमंडल की उत्फल्लता अब मद्धिम पड़ गई प्रतीत होती है। उनकी सभाओं में अब पहले जैसी भीड़ नहीं उमड़ती। उन्हें जगह-जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में नवजीवन का संचार किया है। आए दिन भाजपा के नेता अपने पितृदल को छोड़कर कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। चार साल की अवधि में कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में चले आए वे अब परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की मध्यप्रदेश यात्रा की एक तस्वीर को लेकर काफी चर्चा हुई। शिवराज सिंह लंबी सी मुस्कान खींचकर नरेन्द्र मोदी को फूल भेंट कर रहे हैं और मोदीजी प्रत्युत्तर में श्री चौहान को आंखें तरेर कर देख रहे हैं। लगातार यात्राएं करते-करते प्रधानमंत्रीजी भी शायद थक जाते हैं। यह शायद ऐसा ही अवसर रहा हो!

(देशबन्धु में 27 सितम्बर 2018 को प्रकाशित)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://lalitsurjan.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html

गणेश चतुर्थी आज

बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक:श्री गणेश

बुद्धि , ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी दिखावे और अहंकार के वश में रहने वालों को ज्ञान का पाठ भी पढ़ाया करते हैं। हिंदू धर्म - ग्रंथों में प्रथम पूज्य गणेश जी से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हमें इस बात का ज्ञान कराती हैं कि गणेश जी अपने उन भक्तों पर कृपा बरसाते हैं जो भले ही गरीब हों किंतु विनम्रता और सदव्यवहार उनकी आत्मा में बसे हों।

भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर का एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग शास्त्रों में बताया गया है। धन के देवता भगवान कुबेर का हृदय भी अपार धन संपन्नता से मलिन हो चुका था। इसी बीच भगवान कुबेर से भगवान श्री गणेश की शिक्षाप्रद मुलाकात हुई। कुबेर का भव्य स्वर्ण महल और प्रचुर हीरे-मोती- जवाहरात वाला खजाना पौराणिक कथाओं में वर्णित है। कथा के अनुसार अपनी इसी वैभवशीलता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एक बार धन कुबेर ने अपने महल में भव्य भोज का आयोजन किया। अपने वैभव का प्रदर्शन करने उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती सहित अनेक देवताओं को निमंत्रित करने का मन बनाया। अपनी अपार धनसंपन्नता के अभिमान से अभिभूत कुबेर स्वयं भगवान शिव और देवी पार्वती के निवास कैलाश पर्वत पहुंच गए। जब कुबेर वहां पहुंचे तो भगवान शिव अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे भगवान शिव ने कुबेर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। भगवान शिव ने कुबेर को सुझाव देते हुए कहा कि उनकी तरफ से उनके युवा पुत्र गणेश भोज में शामिल हो सकते हैं। अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान श्री गणेश कुबेर के महल पहुंचे। ज्ञान और भोलेपन के साथ सादगी को पसंद करने वाले गणेश ने प्रवेश करते ही अनुभव किया कि कुबेर भव्य संपत्ति के वशीभूत अपने मेहमानों को प्रभावित करना चाहते हैं! कुबेर ने अपने महल की भव्यता, साज-सज्जा, विलासिता के साथ स्वर्ण पात्रों के माध्यम से अपनी अकूत संपत्ति का प्रदर्शन कर रखा था। कुबेर ने बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ गणेश जी के समक्ष 108 प्रकार के विविध भोज्य पदार्थ परोसे। भगवान गणेश की दिव्य दृष्टि में यह भोज नहीं बल्कि एक बड़ा तमाशा था। यह इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देने और अभिभूत कर देने वाला था। भोज शुरू हुआ और गणेश जी का पूरा ध्यान भोजन पर केंद्रित हो गया। गणेश जी की भूख केंद्र में आ बैठी जो तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुबेर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचते रहे कि आखिर इतनी भोज्य सामग्री ग्रहण करने के बाद भी गणेश की भूख शांत क्यों नहीं हो रही है? महल में उपलब्ध सारी भोजन सामग्री के अलावा गणेश जी ने कच्ची-पक्की सभी सामग्री को ग्रहण कर समाप्त कर दिया! उनकी नजरें निरंतर भोजन की नई थाली की ओर ताकती रही। भगवान गणेश की अतृप्त भूख से व्याकुल कुबेर चुपचाप महल से निकलकर कैलाश पर्वत पहुंचे! भगवान शिव ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। कुबेर निराशा से भरे हुए थे। उन्हें अपने अभिमान का एहसास हो चुका था और वे उसका समाधान ढूंढ रहे थे। सर्वज्ञ और दयालु भगवान भोलेनाथ ने कुबेर की निराशा का कारण जान लिया। भगवान गणेश की अतृप्त भूख का मूल कारण समृद्धि और फिजूल खर्ची का अहंकारी प्रदर्शन ही था,उन्होंने कुबेर को समझाया कि जिस अति अभिमान के साथ उन्होंने भोज का आयोजन किया था, वही समस्या का मूल कारण है। उन्होंने कुबेर को सुझाव दिया कि गणेश के पास विनम्रता और स्नेह के साथ जाएं तो उन्हें समस्या का समाधान मिल जाएगा। समस्या को सुलझाने के लिए भगवान शंकर ने कुबेर को माता पार्वती द्वारा प्रेमपूर्वक तैयार किए गए मुरमुरे से भरा एक कटोरा भेंट किया।

भगवान शिव से प्राप्त उक्त भेंट को लेकर कुबेर अपने महल लौटे और भगवान गणेश के सम्मुख बड़ी विनम्रता से परोसा साथ ही उन्होंने अपने द्वारा पहले किए गए दिखावे के लिए क्षमा प्रार्थना भी की। ज्ञान और करुणा के अवतार गणेश जी ने कुबेर के हृदय परिवर्तन को पहचान लिया।

-डॉ. सूर्यकांत मिश्रा

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

ट्रंप के टैरिफ की काट है, स्वदेशी अपनाओ

देश पर जब भी कोई विपदा या परेशानी आई है तो पूरे देश ने मिलकर न केवल मुकाबला किया है बल्कि उस परेशानी का खात्मा करके ही दम लिया है। ऐसा ही समय एक बार फिर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर दिया है। भारत के खिलाफ ये टैरिफ 27 अगस्त यानी आज से लागू होंगे। आदेश में कहा कि बढ़ा हुआ शुल्क उन भारतीय प्रोडक्ट्स पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त 2025 की रात 12 बजकर एक मिनट या उसके बाद उपभोग के लिए लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है। ट्रंप के इरादों से साफ है कि वो भारत के खिलाफ सनक पाले हुए हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि टैरिफ से ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड इंडस्ट्रीज का मुनाफा घट सकता है। इससे 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 232 के तहत छूट मिली है। जब तक इसकी घोषणा नहीं होती, तब तक अमेरिका को निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, फार्मा पर मौजूदा टैरिफ जीरो फीसदी है, लेकिन ट्रम्प ने 18 महीने में 150 प्रतिशत और बाद में 250 फीसदी टैरिफ की धमकी दी है। जब तक ये लागू नहीं होता, तब तक छूट मिलती रहेगी। ऐसा लंबे समय तक होता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से ट्रंप प्रशासन फैसले ले रहा है, उससे तो साफ है कि वे किसी भी समय कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए तैयार रहें। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की तरफ भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने संबंधी नोटिफिकेशन के दो दिन पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकती। हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन कर लेंगे। इशारा साफ है कि भारत अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि विकल्प क्या है। सबसे पहले तो सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस या अन्य देशों में व्यापार बढ़ाना होगा। इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस करेगा। आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भारत ट्रेड डील कर चुका है। ये एक अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से बातचीत जारी है। भारत सीफूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। वहीं, हीरे और आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों की ओर रुख कर रहा है। सरकार इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक खास बात और भी कही है जो आपदा में अवसर होगी। स्वदेशी अपनाओ, इसी मंत्र से हम ट्रंप के टैरिफ को काट सकते हैं। टैरिफ का सबसे ज्यादा असर नौकरियों पर होगा। अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो जितनी नौकरियां प्रभावित होंगी, उससे कहीं ज्यादा हम अपनी खपत बढ़ाकर रोजगार सजृन कर सकते हैं। अगर त्योहारों के सीजन में ही संकल्प कर लें कि केवल स्वदेशी सामान की खरीद करेंगे तो ट्रंप के इस टैरिफ का हम पर कोई खास असर नहीं होने वाला। जरूरी यही है कि हम हमेशा के लिए देश के लिए खड़े हों और स्वदेशी को अपनाएं।

संघ शताब्दी वर्ष
अवधेश कुमार

मोहन भागवत की अगुवाई में महामंथन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष इस बार विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रहा है। पूरे 1 वर्ष तक संघ ने अपने विस्तार और सामाजिक आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत सघन कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। यह मानने में किसी को हिचक नहीं होगी कि सरसंघचालक मोहन भागवत का राजधानी दिल्ली में शताब्दी वर्ष का यह पहला कार्यक्रम अब तक के किसी भी संगठन के कार्यक्रमों से अलग ऐसे विषय, सोच और दिशा लिए हुए होगा जो लंबे समय तक चर्चा में तो रहेगा ही, भविष्य में संघ पर बात करने की दृष्टि से उद्धरण की भी भूमिका निभाएगा। साथ ही यह पूरे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की वैचारिक और क्रियात्मक आधारभूमि का पूर्वावलोकन भी होगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष इस बार विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर 2025 से आरंभ हो रहा है। पूरे 1 वर्ष तक संघ ने अपने विस्तार और सामाजिक आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत सघन कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इन्हीं में से एक कार्यक्रम सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का देश के चार प्रमुख शहरों राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में सक्रिय नागरिकों के साथ संवाद है। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति भवन में 26, 27 और 28 अगस्त को होगा। कोई संगठन अपने शीर्ष नेता का कुछ घंटे का एक दिन का संबोधन या प्रश्नोत्तर या फिर पत्रकार वार्ता का कार्यक्रम रख रहा है। आम सोच यही होगी कि डॉ. भागवत संघ पर लगने वाले आरोपों पर विस्तार से बात रखेंगे तथा अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे। अभी तक संघ के कारण प्रणाली में ऐसा कभी नजर नहीं आया कि संघ का चरित्र अन्य संगठनों की तरह लगने वाले आरोपों का त्वरित या किसी स्तर पर पत्रकार वार्ता आदि बुलाकर खंडन करना और आत्म प्रचार का हो। जब यह अभी तक संघ की कार्यप्रणाली में रहा ही नहीं तो शताब्दी वर्ष पर सरसंघचालक का राजधानी दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उपयोग वे इसमें करेंगे, ऐसी कल्पना निरर्थक है। तो फिर? स्वाभाविक ही तीन दिनों तक लगातार लोगों के सामने संघ की 100 वर्ष की यात्रा, वर्तमान भारत एवं विश्व की स्थिति , उत्पन्न प्रश्न एवं चुनौतियां, उन पर संघ का मत एवं उपस्थित समूह के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि शामिल होंगे। हां उपस्थित श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में शेष बातें आएंगी।

राजधानी दिल्ली के इस कार्यक्रम की ओर निश्चित रूप से संघ के स्वयंसेवकों व समर्थकों के अलावा देश भर के विरोधियों की भी दृष्टि होगी। शताब्दी वर्ष की दृष्टि से संघ का संगठन के बाहर देश के समक्ष शीर्षतम नेतृत्व द्वारा अपनी बात रखने का यह पहला कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से इसकी तैयारी भी उसी अनुसार दिखाई दी है। संघ के विरोधी भी यह मानते हैं कि उनका कार्यक्रम सुव्यवस्थित, सुलक्षित होता है। निष्पक्ष दृष्टि रखने वाले मानेंगे कि डॉ. भागवत का यह कार्यक्रम ऐसा होगा कि दूसरे संगठन भी इससे अपने महत्वपूर्ण अवसरों का उपयोग करने का तौर-तरीका सीखकर आगे अपनाते हुए दिख सकते हैं। सच कहा जाए तो यह देश के समक्ष केवल संघ को अपनी बात रखने का एक महत्वपूर्ण और बड़ा अवसर नहीं है, देश के लिए भी संघ को जानने समझने का अब तक का सबसे प्रामाणिक आयोजन है। हालांकि 2018 में भी मोहन भागवत ने इसी भवन में संवाद किया था और उसका भी असर हुआ। शताब्दी वर्ष की तैयारी को देखते हुए यह अभी तक का संघ की दृष्टि से सबसे अलग होगा। पिछले 23 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित प्रतिनिधि सभा के समापन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव नहीं मनाएगा बल्कि इसकी जगह हमने इस वर्ष के लिए तीन बिंदु सुनिश्चित किए हैं। एक, आत्मचिंतन करना, दो, संघ कार्य के लिए समाज द्वारा दिए समर्थन के लिए आभार प्रकट करना तथा तीन, राष्ट्र के लिए तथा समाज को संगठित करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करना है। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष में हम अधिक सावधानी, गुणवत्ता तथा व्यापकता से कार्य करने का संकल्प लेते हैं।

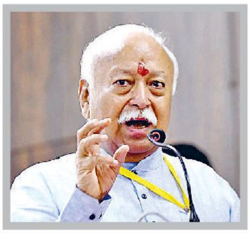

स्वाभाविक ही जीवंत सक्रिय संगठन 100 वर्ष की अपनी यात्रा पर आत्मचिंतन करेगा। आत्मचिंतन व्यापक आयाम वाला विषय है। आत्मचिंतन यानि हम जिन उद्देश्यों के लिए जिन परिस्थितियों में जिस तरह उत्पन्न हुए अभी तक अपने लक्ष्यों की दृष्टि से जो कुछ किया क्या वह संतोषजनक है, कुछ कमियां है तो उन्हें कैसे दूर करेंगे, वर्तमान काल और परिस्थिति में हमें और क्या करना है आदि आदि।

पिछले दिनों एक साक्षात्कार में मोहन भागवत ने कहा था कि 'डॉक्टर साहब, श्री गुरूजी या बाळासाहब के विचार सनातन परम्परा या संस्कृति से अलग नहीं हैं। प्रगाढ़ चिंतन व कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष प्रयोगों के अनुभव से संघ की पद्धति पक्की हुई और चल रही है। पहले से ही उसमें पोथी निष्ठा, व्यक्ति निष्ठा व अंधानुकरण की कोई जगह नहीं है। हम तत्वप्रधान हैं। महापुरुषों के गुणों का, उनकी बताई दिशा का अनुसरण करना है, परन्तु हर देश-काल-परिस्थिति में अपना मार्ग स्वयं बनाकर चलना है। इसलिए नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। सरसंघचालक का वक्तव्य संघ के लिए दिशाबोधक है। अगर वे पूर्व सरसंघचालक को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि मूल विचार को छोड़कर सब कुछ बदला जा सकता है तो इसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। पिछले 21 मार्च को अरुण कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि संघ एक संगठन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का बड़ा आंदोलन है। शताब्दी वर्ष में इसी को केंद्र में रखकर कार्यक्रम तय किए गए होंगे। जैसा पिछले काफी समय से पत्रकार वार्ताओं में संघ की ओर से बताया जा रहा है कि आगामी समय में सामाजिक परिवर्तन के पांच आयामों पर अपने कार्य को अधिक केन्द्रित करेगा । इन पांच आयामों में सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण, नागरिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। इस विषय में श्री होसबाले ने कहा था कि समाज में विभेद के विरुद्ध विमर्श खड़ा करना तथा समरसता के लिए निरंतर प्रयास करना इस कार्ययोजना का लक्ष्य है। अस्पृश्यता समाज के लिए पाप और कलंक है तथा संघ इसे मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। सात जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित प्रांत प्रचारक बैठक में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर के वक्तव्य की कुछ पंक्तियां इन्हें ज्यादा स्पष्ट करतीं हैं ' शताब्दी वर्ष के सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यापक आउटरीच है, भौगोलिक, सामाजिक दृष्टि से समाज के सभी लोगों तक जाना और सभी कार्यों में उनकी सहभागिता हो। यह अभियान एक तरह से सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी होगा।

देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक व तकनीकी प्रगति कर रहा है। केवल आर्थिक या तकनीकी दृष्टि से आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है। हमारे समाज की विशेषताएं, राष्ट्र के अपने विशेष गुणों के साथ ही समाज के सभी लोगों की चिंता करना, पर्यावरण की चिंता करना, परिवार में जीवन मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक जीवन में आपसी सद्भाव बना रहे, पंच परिवर्तन के इन विषयों शताब्दी वर्ष के सारे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में ले जाएंगे। शताब्दी वर्ष के सारे कार्यक्रम इन्हीं उद्देश्यों पर केंद्रित हैं इसलिए मोहन भागवत भी निश्चित रूप से इन बातों पर प्रबुद्ध समूह के बीच विस्तार से अपना मत रखेंगे। यह मानने में किसी को हिचक नहीं होगी कि सरसंघचालक मोहन भागवत का राजधानी में शताब्दी वर्ष का यह पहला कार्यक्रम अब तक के किसी भी संगठन के कार्यक्रमों से अलग ऐसे विषय, सोच और दिशा लिए हुए होगा जो लंबे समय तक चर्चा में तो रहेगा ही भविष्य में संघ पर बात करने की दृष्टि से उद्धरण की भी भूमिका निभाएगा। साथ ही यह पूरे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की वैचारिक और क्रियात्मक आधारभूमि का पूर्वावलोकन भी होगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

गणेश चतुर्थी
बाल मुकुन्द ओझा

पंच देवताओं में अग्रगण्य हैं भगवान गणेशजी

भारत त्योहारों का देश है। त्योहार देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बुनियाद को मजबूत बनाने और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। त्योहार जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमारे देश में बड़े ही धूमधाम और पूजा पाठ से मनाया जाता है। प्रत्येक घर और व्यापारिक संस्थान में तब तक कोई शुभ काम पूरा नहीं माना जाता, जब तक वहां भगवान गणेश की पूजा न हो। इसके पीछे मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस दिन करने से फल अच्छा मिलता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। कई लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने से भगवान गणेश खुश होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह दिन भगवान गणेश की पूजा, आदर और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक है। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के मूर्ति विसर्जन के बाद समाप्त होता है। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से गणेश उत्सव इस साल 27 अगस्त, बुधवार से शुरू होकर विसर्जन 6 सितंबर को होगा। पंचांग के अनुसार इस साल भगवान श्री गणेश की मध्यान्ह पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त 2027, बुधवार के दिन रहेगा। इस दिन गणेश भक्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से लेकर दोपहर एक बजकर 40 मिनट के बीच श्री गणेश जी की पूजा कर सकेंगे। इस प्रकार गणपति के भक्तों को उनकी पूजा करने के लिए लगभग ढाई घंटे मिलेंगे। भारतीय जनजीवन में गणेशजी का अद्वितीय स्थान है। पंच देवताओं में वे अग्रगण्य हैं। प्रत्येक उत्सव, समारोह अथवा अनुष्ठान का आरंभ उन्हीं की पूजा-अर्चना से होता है। वे विद्या और बुद्धि के देवता हैं। इसके साथ ही वे विघ्न-विनाशक भी हैं। भगवान गणेश का अवतार ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के रूप में हुआ है। इस कारण हमारे देश में किसी भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश का आह्वान एक आम बात है। साथ ही इस त्योहार से हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भाव ला सकते है। पंचदेवों में से एक भगवान गणेश सर्वदा ही अग्रपूजा के अधिकारी हैं और उनके पूजन से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्रीगणेश के स्वतंत्र मंदिर कम ही जगहों पर देखने को मिलते हैं परंतु सभी मंदिरों, घरों, दुकानों आदि में भगवान गणेश विराजमान रहते हैं। इन जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा, चित्रपट या अन्य कोई प्रतीक अवश्य रखा मिलेगा, लेकिन कई स्थानों पर भगवान गणेश की स्वतंत्र मंदिर भी स्थापित है और उसकी महता भी अधिक बतायी जाती है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी भगवान गणेश हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार मां पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसका नाम गणेश रखा। फिर उसे अपना द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर पहरा देने का आदेश देकर स्नान करने चली गई। थोड़ी देर बाद भगवान शिव आए और द्वार के अन्दर प्रवेश करना चाहा तो गणेश ने उन्हें अन्दर जाने से रोक दिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को काट दिया और द्वार के अन्दर चले गए। जब मां पार्वती ने पुत्र गणेश जी का कटा हुआ सिर देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गई। तब ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवताओं ने उनकी स्तुति कर उनको शांत किया और भोलेनाथ से बालक गणेश को जिंदा करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को स्वीकारते हुए एक गज के कटे हुए मस्तक को श्री गणेश के धड़ से जोड़ कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती जी हर्षातिरेक होकर पुत्र गणेश को हृदय से लगा लेती हैं तथा उन्हें सभी देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान देते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

कथनी और करनी में न हो कोई अंतर

संकलित
दर्शन

सभी के हित का ध्यान रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वाह करना कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य का पालन यदि समुचित रूप से किया जाता है तो जीवन पूर्णतः गौरवान्वित बनता है। जो कर्त्तव्यनिष्ठ है। वह अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। वह परमार्थ पोषक एवं प्रामाणिक होता है। वह जैसा रहता है, वैसा ही करता भी है। ऐसी कथनी-करनी की एकरूपता से वह समाज में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है और प्रत्येक उससे प्रेरणाएं ग्रहण करता है। कर्त्तव्य परिपालन की बात करना और कर्त्तव्य परिपालन के नाम पर शोर-शराबा मचाना अलग बात है और कर्त्तव्यों के क्षेत्र में बिना किसी शोर-शराबे के समर्पित हो जाना अलग बात है। आज हम देखते हैं कि कर्त्तव्यों के परिपालन के लिए अक्सर लम्बे-चौड़े उपदेश दिये जाते हैं, पर जब कर्तव्य निर्वाह का अवसर आता है तो व्यक्ति दायें-बायें देखने लगता है। कटु सत्य तो यह है कि आज कर्त्तव्यों की चर्चा करने वाले लाखों हैं, पर कर्त्तव्यों के पावन पथ पर गतिशील होने वाले विरले ही हैं। कई बार मुझे चिंतन के क्षणों में लगता है कि आज व्यक्ति कर्त्तव्यों से विमुख हो गया है। इस विमुखता के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता और अशांति का विस्तार हुआ है। कर्त्तव्यों के पावन क्षेत्र से भटककर कोई व्यक्ति कभी भी शांति का अहसास नहीं कर सकता। जीवन का गौरव और उसकी सार्थकता कर्त्तव्य पालन में ही है। कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति गुलाब का फूल है, वह कांटों में मुस्कराता है। *-कांतिलाल मांडोत*

मैं समुद्र के जल को समाप्त कर दूंगी

संकलित
प्रेरणा

अगस्त्य नाम के ऋषि थे वे समुद्र के किनारे कठोर व्रत कर रहे थे, वहां से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों को से रहा था। उसी समय समुद्र में तूफान सी लहरे उठने लगी पानी चढ़ने लगा और पानी अपने साथ अंडो को बहा ले गया, पक्षी बहुत दुःखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र के जल को समाप्त कर दूंगी और अपने चोंच में सागर के जल को भर भर कर फेंकने लगी ऐसा करते करते उसे काफी समय बित गया समुद्र का जल घटा ही नही। वह दुःखी मन से अगस्त्य मुनि के पास गई और अपनी व्यथा सुना समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि ने ध्यान से पक्षी की व्यथा सुनी और चिंता व्यक्त की। ऋषि विचार करने लगे की मैं कैसे इस पक्षी की सहायता कर सकता हूं। उन्हें चिंता होने लगी की मैं कैसे समुद्र के जल को पी कर सुखा सकूंगा। विचार करते हुए अगस्त्य मुनि ने गणेश जी का स्मरण किया और संकट चतुर्थी व्रत को पूरा किया। तीन मास व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेशजी ने मुनि का मार्ग प्रशस्त किया चौथ व्रत की कृपा से अगस्त्य मुनि ने प्रेम से समुद्र को पी कर सुखा दिया और पक्षी की प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रतिज्ञा पूरी होने से पक्षी भी खुश हुआ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अंतर्मन

आज की पाती

भारत, रूस और चीन भाई-भाई

वर्तमान में एशिया के लिए इसी प्रकार का एक और भ्रातृत्व अनिवार्य है यथा पश्चिमी देश अमेरिका की रहनुमाई में रह कर पूरी दुनिया के स्रोतों का दोहन कर रहे हैं और एक-एक करके सर्वत्र फूट डाल कर विवाद खड़े करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अमेरिका अब तक संसार में कई युद्ध करवा चुका है और भारत-चीन और रूस का कभी हित नहीं किया। अब अचानक फिर तराजू बंदर के हाथ आ गया है और अब वह भारी भरकम टैरिफ का डंडा भारत, रूस और चीन पर बरसा रहा है। वह चाहता है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल न खरीदे। भारत अपने हित-अहित जानता है और उक्त तीनों देश ट्रंप की हेकड़ी जरूर समाप्त करेंगे, आने वाले समय की यही पुकार है।

- सुरेश यादव, धमतरी

करंट अफेयर

द. अफ्रीका में सिक्खों के शांति पहल में धार्मिक नेता

सिख समुदाय द्वारा अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में शांति स्थापना के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में 300 से अधिक धार्मिक और सामुदायिक नेता एकत्र हुए। यह भव्य कार्यक्रम रविवार शाम सैंडटन में आयोजित किया गया जिसका विषय था 'विश्वासों को जोड़ना : अफ्रीका में अंतरधार्मिक सद्भाव के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना'। आयोजकों ने कहा कि अपनी तरह का यह पहला आयोजन पूरे महाद्वीप में शांति और सहयोगात्मक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने की दिशा में आधारशिला बनने की महत्वकांक्षा रखता है। गुरुद्वारा साहिब जोहानिसबर्ग, सिख काउंसिल ऑफ अफ्रीका, हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन ऑफ लाइट (एचडब्ल्यूपीएल) और गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख और अफ्रीकी पारंपरिक धर्म के नेता एक साथ आए। दक्षिण अफ्रीका के सहकारी शासन एवं पारंपरिक मामलों के उप मंत्री डॉ. नामाने डिक्सन मासेमोला ने कहा कि 1996 में अपनाया गया दक्षिण अफ्रीका का संविधान सभी धर्मों और आस्थाओं को मान्यता देता है। मासेमोला ने कहा- धार्मिक नेता शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

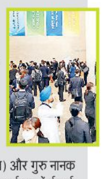

ऑफ बीट

आत्महत्या के सटीक जवाब देने में कारगर नहीं एआई चैटबॉट

एक अध्ययन तीन लोकप्रिय कृत्रिम मेधा चैटबॉट्स पर यह जानने के लिए किया गया कि वे आत्महत्या से जुड़े सवालों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें

पाया गया कि वे आमतौर पर ऐसे सवालों का जवाब देने से बचते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम वाले होते हैं, जैसे कि आत्महत्या करने के तरीकों से जुड़ी विशिष्ट जानकारी। हालांकि कम गंभीर लेकिन नकुसान पहुंचाने वाले सवालों पर ये जवाब देने में उतने कारगर नहीं है। ओपनएआई के चैटजीपीटी, गूगल के जेमिनी और एंथ्रोपिक के क्लाउड में 'और अधिक सुधार' की जरूरत बताई गई है। आरएएनडी कॉर्पोरेशन ने यह अध्ययन किया है और इसका (अध्ययन का) वित्तपोषण अमेरिका के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ने किया है। अनुसंधान में चिंता व्यक्त की गई है कि बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए एआई चैटबॉट पर निर्भर हैं। अध्ययन में इस बात के लिए मानक स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि कंपनियां इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। अनुसंधान पत्र के प्रमुख लेखक तथा आरएएनडी के वरिष्ठ नीति अनुसंधानकर्ता रयान मैकबेन ने कहा, हमें कुछ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

ट्रेंड

वंदे भारत एक्सप्रेस

मराठवाड़ा के विकास को गति देने के लिए, हम गतिशील परिवहन समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज, 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ने नांदेड़ को मुंबई के और करीब ला दिया है, जिससे इस क्षेत्र के लिए अवसरों और समृद्धि के नए द्वार खुल गए हैं।

-देवेंद्र फडणवीस, सीएम, महाराष्ट्र

नक्सलवाद

नक्सलवाद ही कांग्रेस का 'संविधान' है। वामपंथी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उसने इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन यह समझ ले कि अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक नक्सलियों को साफ करने का बीड़ा उठा लिया है।

-केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

एजेंसीज का दुरुपयोग

सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। जिस तरह "आप" को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

वैकल्पिक संभावनाएं

उद्योग जगत के नेता/सीईओ एआई के कारण 'नौकरियों के नुकसान' का शोर मचा रहे हैं। उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनकी 'नौकरियाँ' या पद ज्यादा खतरे में हैं। क्योंकि अब कर्मचारियों को वैकल्पिक संभावनाएं तलाशने का मौका मिल गया है।

-शेखर कपूर, फिल्मकार

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

सही समय की प्रतीक्षा में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है

ट्रंप की चुनौती का सामना

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल करके ही माने। उन्होंने यह मनमाना अतिरिक्त टैरिफ इस आरोप में जुर्माने के रूप में थोपा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तरह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में उसकी मदद कर रहा है। यह है तो नितांत निराधार निष्कर्ष, लेकिन ट्रंप ऐसे ही बेतुके आरोप लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा है कि भारत पहले दिन से ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति का मुकाबला करने की दृढ़ता दिखा रहा है। अब इस दृढ़ता के अनुरूप हरसंभव कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ पहले ही इसलिए लगा दिया था, क्योंकि तय समयसीमा में द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हो पाया। यह इसीलिए नहीं हो पाया, क्योंकि भारत उनकी मनमर्जी वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था। इसी से चिढ़े ट्रंप ने एक तो यह राग अलापना शुरू किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया और दूसरे, इस हास्यास्पद आरोप के साथ सामने आ गए कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है।

ट्रंप ने उस चीन को बख्श दिया है, जिसके खिलाफ वह गर्जन-तर्जन करते रहते हैं और जो भारत के मुकाबले रूस से कहीं अधिक तेल खरीदता है। चूंकि ट्रंप में इतना साहस नहीं कि वे चीन पर भारत जितना टैरिफ लगा सकें, इसलिए उनके सहयोगी तरह-तरह के कुतर्क देने में लगे हुए हैं। इसके कारण उनकी जगहंसाई ही हो रही है, पर शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं। जो भी हो, भारत को जहां आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों को गति देनी होगी, वहीं स्वदेशी के मंत्र को भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ उनकी निरंतर समीक्षा भी करनी होगी। इसलिए करनी होगी, क्योंकि स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की बातें कोविड महामारी के बाद से ही हो रही हैं और सब जानते हैं कि उनके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। कम से कम अब तो वांछित नतीजे हासिल करने के लिए ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए। ये उपाय तब सफल होंगे, जब हमारे कारोबारी ट्रंप की ओर से पेश की गई टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। वे सरकार से सहायता की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लड़ाई केवल कारोबार की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। सरकार, कारोबार जगत के साथ देश की आम जनता को इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि ट्रंप का भारत विरोधी रवैया लंबे समय तक कायम रह सकता है।

सुरक्षा की अनदेखी

परिवहन नियमों की अनदेखी कर ट्रैक्टर-ट्रालियों का यात्री परिवहन के रूप में इस्तेमाल कितना घातक हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हुई कासगंज-बुलंदशहर दुर्घटना इसका एक दुखद अनुस्मारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर स्थानीय परिवहन ऐसे ही साधनों के भरोसे है। विशेष रूप से मेले और धार्मिक पर्यटन के लिए ट्रैक्टर-ट्रालियों का उपयोग सस्ते और सुलभ साधन के रूप में आम है। चूंकि, गांव-कस्बों में ऐसी दुर्घटनाएं कम होती हैं, इसलिए अनदेखी होती रहती है, लेकिन जब परिवहन राजमार्गों से एक राज्य से दूसरे की ओर हो रहा हो तो प्रश्न स्वाभाविक है कि प्रवर्तन एजेंसियां कहां सो रही थीं? यात्रा के लिए जो ट्राली इस्तेमाल हो रही थी, उसमें लकड़ियों के तख्ते एवं पालीथिन का इस्तेमाल कर दो मंजिलें तैयार की गई थीं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग केवल कृषि और माल परिवहन के लिए अनुमन्य है, यात्री परिवहन के लिए नहीं। ट्रैक्टर-ट्राली कासगंज से बुलंदशहर पहुंच गई और रास्ते में किसी ने नहीं रोका? इस तरह का यह न तो पहला और न ही अंतिम मामला है। समय-समय पर ऐसे हादसे होते ही रहते हैं और उनसे कोई सीख-सबक भी नहीं लिए जाते। तीन साल पहले कानपुर में एक ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से 24 लोगों की मौत हुई थी। इसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के निर्देश दिए थे, कुछ दिन अभियान चलाकर चालान किए गए और फिर सारी सख्ती फुर्र हो गई। सतत सतर्कता नहीं बरती गई तो ऐसी दुर्घटनाएं बार-बार होती रहेंगी।

> ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग केवल कृषि और माल परिवहन के लिए अनुमन्य है, यात्री परिवहन के लिए नहीं

अमेरिका नहीं चाहता भारत का उभार

दिव्य कुमार सोती

अब अमेरिकी सोच यह है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से उसे कोई लाभ नहीं। यही ट्रंप के मनमाने टैरिफ का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है

भारत द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव न होते देख और चीन एवं इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर एशिया की भूराजनीति चलाना संभव नहीं है। हालांकि उस दौर में दोनों देशों के संबंधों में इतनी कटुता आ चुकी थी कि एकदम से सब कुछ सामान्य हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भारत और अमेरिका कैसे एशिया की अगली सदी को मिलकर गढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टालबोट और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच 11 दौर की गुप्त वार्ता विश्व में अलग-अलग स्थानों पर हुई। इन वार्ताओं से अमेरिका में यह सहमति बनी कि भारत के सामरिक उदय को सुनिश्चित किया जाना पूरे एशिया और समूचे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह कुछ-कुछ वैसा ही था, जैसा निक्सन और किसिंजर द्वारा 1970 के दशक में यह तय करना कि अमेरिका सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन का उदय सुनिश्चित करेगा। टालबोट-जसवंत वार्ता की परिणति ही भारत के ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत की ओर झुकाव के रूप में दिखाई दी। भारत के उदय को सुनिश्चित करने की इस नीति के पक्षधर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही बने। क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार की और उसे मूर्त रूप भी दिया गया। इसके जरिये भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना भी जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकारा गया और अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया।

द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही। दोनों देशों के बीच 2005 में बनी रणनीतिक साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में समग्र वैश्विक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया। भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी किए। यह सिलसिला एक बड़ी हद तक ट्रंप के पहले कार्यकाल और बाइडन के दौर तक चलता रहा, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल विशेषकर आपरेशन सिंदूर के बाद के परिदृश्य में अमेरिकी रवैया बदल गया। कुछ लोग इसे भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा बार-बार खारिज करने से भी जोड़कर देख रहे हैं। यह पूरी तरह सही नहीं। अमेरिका में एक तबका भारत से कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता आया है। ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान से जुड़ी है। वहां एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत उसके मुकाबले में सहायक बने, मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भाड़े पर लड़ने वाला देश नहीं बन सकता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही। यह उसकी समझ से बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौतों के बाद भी कोई देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है? भारत के मामले में ऐसा होते देख अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी पड़ी है।

अवधेश राजपूत

भारतीय मामलों पर वाशिंगटन में एक बड़ी आवाज माने जाने वाले एश्ले टैलिस ने 2023 में ही एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को ही दर्शा रहे थे। यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था, इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में लेने का फैसला लिया गया। तब से ही यही नीति जारी है। बस बाइडन और ट्रंप के तरीके अलग हैं। बाइडन प्रशासन भारत को दबाव में लेने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलता रहा। कनाडा की ट्रूडो सरकार के जरिये भारतीय नेतृत्व पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप लगाए गए। इतने से बात नहीं बनी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप भी मढ़े गए।

जब ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी प्रारंभ कर दी थीं। जब पहलगाम हमला हुआ, तब उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टोकरेंसी डील की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में यह सोचना एक भूल है कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर का श्रेय न मिलने से क्रुद्ध ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। वाशिंगटन में अब यह सोच बन चुका है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय का समर्थन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। अमेरिका को लगता है कि जब चीन से निपटना ही उसे भारी पड़ रहा है तो सामरिक रूप से स्वायत्त महाशक्ति के रूप में भारत का उदय तो भविष्य में उसके वैश्विक प्रभुत्व के लिए चुनौती बढ़ाने का ही काम करेगा। अमेरिका भारत को अगला चीन बनते नहीं देखना चाहेगा।

अमेरिकी अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स कहते हैं कि भारत को सफल होते देख अमेरिका उसका विरोध करेगा, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। इसी कारण पहले अमेरिका रूस का विरोध कम्युनिज्म के नाम पर करता था। अब कम्युनिज्म के पतन के बाद भी उसका विरोध जारी है, क्योंकि अभी भी रूस एक बड़ी भूराजनीतिक शक्ति है और वह कभी अमेरिकी कठपुतली नहीं बनेगा। भारत के चमत्कारिक आर्थिक विकास के चलते यही अमेरिकी रवैया अब भारत के प्रति दिखने लगा है। ऐसे में यदि भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा जारी रखनी है तो हमारे उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों और छात्रों को चौगुनी शक्ति से काम करना होगा।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से जुड़े सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अटका हो तो

राजीव सचान

राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर तय समय में फैसला लेना जरूरी है तो हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं?

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ राष्ट्रपति की ओर से संदर्भित ऐसे प्रश्नों पर विचार कर रही है कि जब संविधान में विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है तो क्या अदालत समयसीमा तय कर सकती है? राष्ट्रपति ने इस और इस जैसे कुल 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को इसलिए संदर्भित किए थे, क्योंकि इसी वर्ष अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्यपाल की ओर से दस विधेयकों को लंबे समय तक रोक कर रखना और उन पर कोई निर्णय न लेना अवैध और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके रखने की कोई वीटो पावर नहीं। इसे ऐतिहासिक बताए जाने वाले फैसले ने इसलिए हैरान किया, क्योंकि एक तो ऐसा आदेश देते हुए राज्यपाल के पास लंबित सभी दस विधेयकों को स्वीकृत करार दिया गया और दूसरे, यह आदेश दो सदस्यीय पीठ ने दिया। इसमें यह भी व्यवस्था दी कि राज्यपालों के लिए विधेयकों पर एक माह में फैसला लेना होगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आदेश में यह भी कहा गया कि विधेयकों पर फैसला लेने के मामले में राज्यपालों की तरह राष्ट्रपति के समक्ष भी समयसीमा है। इसने और हैरान किया। वास्तव में इसी कारण राष्ट्रपति की ओर से इस फैसले के खिलाफ 14 प्रश्न संदर्भित किए गए।

इस संवैधानिक मामले में राजनीतिक दलों और विधि विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। एक पक्ष विधेयकों पर फैसले लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उचित मान रहा है और दूसरा पक्ष उसे शीर्ष अदालत की ओर से न्यायिक सीमा एवं स्वतंत्रता का अतिक्रमण बता रहा। फिलहाल दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के वकील कह रहे हैं कि संविधान ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है और जिसकी जरूरत संविधान ने नहीं महसूस की, उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया? इसी पहलू पर जोर देने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कुछ समस्याओं का समाधान राजनीतिक तरीके से भी होता है। यहां यह स्मरण करना आवश्यक है कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब यह प्रचलित था कि वे ऐसा मानते थे कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। पता नहीं आज कितने लोग इससे सहमत होंगे, लेकिन देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि विधेयकों पर निर्णय लेने के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकता है?

सुप्रीम कोर्ट को भी देने होंगे कुछ सवालों के जवाब। फाइल

पिछले दिनों इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल किए कि यदि संवैधानिक पदाधिकारी यानी राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों पर कोई फैसला नहीं करते तो क्या अदालत के हाथ बंधे हैं? क्या अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती? क्या वह शक्तिहीन है? मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई का प्रश्न था, यदि राज्यपाल बिना किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संविधान पीठ की ओर से ऐसे उचित प्रश्न भी उठाए गए कि यदि कोई पीड़ित राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या राज्यपाल की निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है और अगर किसी विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए लंबित रखे तो क्या होगा?

उक्त प्रश्नों को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता और यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ राज्यपाल किस तरह विधेयकों को दबाए बैठे रहते हैं। गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब-तब इसकी शिकायत भी करते रहते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था तो ऐसी ही शिकायत भाजपा शासित राज्य करते थे। स्पष्ट है कि इन सवालों का अपना महत्व है, लेकिन क्या किसी और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे सवालों का जवाब है कि यदि उसके समक्ष कोई मामला लंबित है और उस पर फैसला होने में देर हो रही हो यानी एक तरह की निष्क्रियता सी व्याप्त हो तो क्या कोई यह प्रश्न करने की भी स्थिति में है कि फैसले में देरी से पीड़ित लोग क्या करें? क्या पीड़ितों की ओर से संसद या सरकार या फिर अन्य कोई यह पूछ सकता है कि क्या लंबित मामले लंबे समय तक अनसुने रह सकते हैं? क्या कोई किसी का दरवाजा खटखटा सकता है? यह तो सुप्रीम कोर्ट को ज्ञात ही होगा कि हाई कोर्ट के साथ उसके समक्ष भी लाखों मामले लंबित हैं। एक आंकड़े के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 80 हजार से अधिक है। इनमें से सात हजार से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जो एक दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मुस्कान का माधुर्य

हमारे चेहरे की भाव-भंगिमाएं हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। कई बार हम चेहरा देखकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। व्यक्ति की सरलता, सहजता या कुटिलता अथवा उसका भोलापन सब कुछ उसके चेहरे पर अंकित रहता है। प्रायः मधुर मुस्कान से आप्लावित मुखमंडल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। चेहरे की मुस्कान ऊर्जा देती है। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए बात करता है तो संवाद का आकर्षण बढ़ जाता है। उसके प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इससे संवाद सार्थकता प्राप्त करता है। संवाद के उद्देश्य की पूर्ति होती हुई प्रतीत होने लगती है। वहीं निराश, हताश एवं मुस्कान रहित मुखमंडल वाले व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता। संवाद से पहले ही एक तरह की नकारात्मकता छाने लगती है। संवाद उद्देश्य रहित लगने लगता है। ऐसे लोगों से स्वतः दूरी बनाने का मन करने लगता है। कठोर मुखमंडल एवं नीरस व्यक्ति यदि किसी बड़े पद पर बैठा हो तो भी लोग अथवा फरियादी उसके पास जाने से कतराते हैं। उसका व्यक्तित्व लोगों को नकारात्मक लगने लगता है। भले वह बड़े पद वाला व्यक्ति हृदय से सरल हो, पर मुस्कान का अभाव उसके व्यक्तित्व को नीरस बना देता है।

हमें सबसे अधिक ऊर्जा मंदिरों में मिलती है। वहां रखी भगवान की प्रतिमा प्रायः मुस्कुराती हुई बनाई जाती है, क्योंकि वह प्रतिमा सकारात्मकता एवं ऊर्जा का अप्रतिम स्रोत है। वह हमारे अंतस को अथाह सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रतिमा को देखते ही मन शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार मधुर मुस्कान का धनी व्यक्ति जीवन में ऊर्जा एवं सकारात्मकता बिखेरता है। उसके व्यक्तित्व की सुगंध से सभी आनंद की अनुभूति करते हैं। हम सभी अपने व्यक्तित्व में मुस्कान का गुण समाहित करें। मुस्कान का माधुर्य जीवन के लालित्य को प्रभावी बना देता है।

ललित शौर्य

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

पर्यटन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण

सुधीर कुमार

पर्यटन देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के साथ एक सशक्त उद्योग के रूप में विकास के इंजन की भूमिका भी निभाता है

मलेशिया की मेजबानी में आज विश्व पर्यटन दिवस 'टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफार्मेशन' (पर्यटन और सतत परिवर्तन) थीम के साथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वर्ष 1980 से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पर्यटन की विविध महत्ता को समझना और इसे समावेशी, समतामूलक और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को आनंददायक के साथ-साथ टिकाऊ और जिम्मेदार भी बनाया जा सके।

पर्यटन किसी देश की सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता के उन्नयन में ही सहायक नहीं है, बल्कि एक सशक्त उद्योग के रूप में आर्थिक विकास के इंजन की भूमिका भी निभाता है। किसी क्षेत्र में पर्यटन के विकास से रोजगार की लंबी श्रृंखला विकसित होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पर्यटन क्षेत्र पृथ्वी पर हरेक 10 में से एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन की मानें तो पर्यटन क्षेत्र का व्यवसाय तेल निर्यात, खाद्य उत्पादों या आटोमोबाइल के बराबर या उससे भी अधिक है। यूएन की 'वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर' रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली तिमाही में 30 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की, जो 2024 में इसी अवधि की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है। कोरोना की दस्तक से पहले दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत हिस्सा पर्यटन उद्योग से आता था। हालांकि एक ओर पर्यटन जहां आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलता है, वहीं ये स्थानीय पर्यावरण और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालने के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पर्यटन स्थलों की नैसर्गिकता को यथावत रखना जहां चुनौतीपूर्ण है, वहीं मानवीय गतिविधियां भी पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और पारितंत्र में अप्रिय बदलाव लाने का वाहक बन गई हैं। पर्यटन स्थलों के किनारे आर्थिक गतिविधियों के विकास से स्थानीय पर्यावरण की हानि होती है। इसमें वनों की कटाई से लेकर प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, भूमि, ध्वनि और वायु प्रदूषण में वृद्धि आदि शामिल हैं। पर्यटन-यात्रा से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन और पर्यटन स्थलों पर वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि आज माउंट एवरेस्ट जहां कचरे के पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है, वहीं अन्य पर्यटन स्थलों को भी साफ-सफाई पर अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। इसे रोकने के लिए नागरिकों में 'नागरिक बोध' का विकास जरूरी है। इस वर्ष की थीम पर्यटकों और नागरिकों को सतत पर्यटन को अपनाने को प्रेरित करती है। इस अवधारणा में प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर उसके सौंदर्य का अनुभव करने पर बल दिया जाता है, जिससे ये स्थल वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ियों की भी पर्यटन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता

'एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियां' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में बलबीर पुंज ने यह रेखांकित करने का प्रयास किया कि विदेशी फंडिंग से संचालित कई संगठन देश की विकास योजनाओं को बाधित करते हैं। यह पहलू सही है, किंतु आलेख में उन संवैधानिक प्रविधानों का उल्लेख नहीं किया गया जो ऐसी संस्थाओं के अधिकार और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(अ) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(स) संघ बनाने का अधिकार देता है। इसलिए केवल दमन या पाबंदी पर्याप्त नहीं, बल्कि कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है। आलेख में यह पहलू भी अनदेखा रहा कि देश में अनेक एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। उन्हें विकास विरोधी कह देना ऐसा ही है, जैसे पूरे जंगल को काटकर केवल कुछ सूखी टहनियों को दोष देना। यह रचनात्मक पक्ष नजरअंदाज होने से आलेख का संतुलन कमजोर पड़ गया। साथ ही, चुनाव आयोग की भूमिका का अभाव भी खटकता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाली शक्तियों पर सख्त नजर रखने का अधिकार है। यदि किसी एनजीओ का प्रभाव मतदाताओं तक पहुंचता है तो यह लोकतंत्र की नींव को सीधी चुनौती है। अंततः कहा जा सकता है कि आलेख ने ज्यादातर नकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला। यदि इसमें संवैधानिक संतुलन, चुनावी पारदर्शिता और सकारात्मक योगदानों की चर्चा शामिल होती तो यह अधिक तर्कसंगत बन पाता। लोकतंत्र का आधार आलोचना नहीं, बल्कि तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण का सह-अस्तित्व है। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना ही श्रेयस्कर है।

awanishg30@gmail.com

संसदीय प्रक्रिया से पलायन उचित नहीं

कई विपक्षी दल उस संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने से बच रहे हैं, जो आपराधिक मामलों में केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व मंत्रियों को पद छोड़ने संबंधी विधेयक पर विचार कर रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। लोकतंत्र की असली शक्ति संसदीय बहस और तर्कपूर्ण विमर्श में निहित होती है, न कि बहिष्कार या पलायन की राजनीति में। यदि विपक्ष किसी विधेयक से असहमति रखता है तो उसका समाधान चर्चा और ठोस तर्कों से ही संभव है। समिति से दूरी बनाकर विपक्ष न केवल अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, बल्कि जनता को यह संकेत भी दे रहा है कि उसकी एकजुटता केवल अवसरवादी है। वास्तव में, हाल के दिनों में विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए में आपसी मतभेद और असहमति के कई उदाहरण सामने आए हैं। इस तरह की परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि यह गठबंधन टिकाऊ न होकर केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए बना है। ऐसे में जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता कम होना स्वाभाविक है। जनमानस की अपेक्षा है कि चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। यदि विपक्ष बहस और विचार-विमर्श से ही पलायन करेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी।

sureshgoyal8@gmail.com

मर्यादा के अनुरूप हो आचरण

धर्म और अध्यात्म की राह दिखाने वाले व्यक्तित्व यदि आपसी मतभेदों को सार्वजनिक विवाद बना दें, तो इससे समाज को नकारात्मक संदेश जाता है। आज के समय में जब समाज पहले से ही विभाजन और तनाव से जूझ रहा है, तब संतों का कर्तव्य है कि वे लोगों को जोड़ने का काम करें, न कि अनुयायियों को भ्रमित करें। ऐसी परिस्थितियों में संतों को चाहिए कि वे एक-दूसरे की आलोचना से बचें और धर्म के उच्च आदर्शों को जीवित रखें। मतभेद होने पर भी संवाद और विवेक से उन्हें सुलझाएं, न कि सार्वजनिक मंचों पर विवाद बढ़ाएं। आज समाज को जोड़ने वाले संदेशों की आवश्यकता है, इसलिए संतों की वाणी में सौहार्द और मर्यादा का भाव होना आवश्यक है।

आराध्या सिंह, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

Join The Official Private Channel

I am Closing entry to my private channel now.

Support me by joining my private channel

AND GET EARLIEST AND RELIABLE SOURCE TO READ NEWSPAPERS DAILY.

Click below to

Join

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard

+All Editorial PDFs